राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 164

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 22 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

जयशंकर बोले, एच-1बी वीजा पर अमेरिका को मनाएगा भारत

>> 3

सरोकार

कहां गुम हो गई चंपा! ढूंढने निकल पड़ा पूरा भागलपुर

भागलपुर : बिहार की चंपा नदी 1966 में ही प्रदूषण का शिकार हो गई थी। भागलपुर में बहने वाली इस नदी पर सरकार ने लोहे का पुल बनवाया तो नामकरण किया गया-चंपा नाला ब्रिज। पौराणिक नदी को बचाने के लिए दैनिक जागरण ने छेड़ा है अभियान। (पेज-10)

जागरण विशेष

पद्मश्री भारत भूषण बता रहे कैसे करें किसानी...

हापुड़ : उन्नत कृषि के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के निवासी भारत भूषण त्यागी ने विकसित की है जैविक कृषि की कारगर पद्धति। वह लोगों को इस खेती के प्रति जागरूक करने में जुटे हैं। (पेज-10)

महाराष्ट्र में शिवसेना संग सरकार बनाने को तैयार कांग्रेस

असमंजस खत्म ▶ सरकार गठन पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की कार्यसमिति में बनी सहमति

कांग्रेस-राकांपा ने तैयार किया प्रारूप, शुक्रवार को शिवसेना से चर्चा के बाद एलान संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र में सरकार गठन पर जारी असमंजस पूरी तरह खत्म हो गया है। शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने पर कांग्रेस कांग्रेस कार्यसमिति ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा व शिवसेना नेताओं के बीच बैठक होगी और उसके बाद सरकार गठन की घोषणा कर दी जाएगी। कोशिश है कि नवंबर में ही नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाए।

महाराष्ट्र में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार गठन में सबसे बड़ा असमंजस कांग्रेस के अंदर ही था। दरअसल वह कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा वाली शिवसेना के साथ जाने में असहज थी। पार्टी के अंदर ही अलग-अलग सुर थे। एक सप्ताह से ज्यादा चले बैठकों के दौर में तीनों दलों के बीच यह सहमति बन गई है कि हर किसी को कुछ समझौता करना ही होगा। वर्तमान सियासी माहौल में सब महसूस कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में सत्ता में वापसी जरूरी है।

यूं तो बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेताओं के बीच बैठक के बाद ही सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया था। गुरुवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सरकार बनाने को सैद्धांतिक रूप से हरी झंडी दे दी गई।

उसके बाद दिल्ली में शरद पवार के आवास पर कांग्रेस के अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश तथा राकांपा की सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार समेत दूसरे नेताओं की बैठक हुई और प्रारूप पर चर्चा हुई। शुक्रवार को मुंबई में राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना की बैठक हो सकती है। संभव है कि उसके बाद सरकार बनाने की घोषणा हो जाए। शिवसेना को भी अनौपचारिक रूप से प्रारूप के बारे में जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि तीनों दलों की ओर से राज्यपाल को अलग-अलग पत्र देकर जानकारी दी जाएगी कि वे साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं।

ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री : अभी कांग्रेस और राकांपा नेताओं की ओर से सरकार के प्रारूप पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम पद पर 50:50 फार्मूला लागू होगा। यानी पहले ढाई साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और बाकी के ढाई साल राकांपा का। उपमुख्यमंत्री पद पूरे पांच साल कांग्रेस के पास रहेगा। मंत्री पद में संख्या बल के हिसाब से हिस्सेदारी होगी और अहम मंत्रालयों में भी तीनों दलों का प्रतिनिधित्व होगा। सरकार के लिए साझा कार्यक्रम तैयार होगा और समन्वय के लिए भी व्यवस्था तैयार की जा सकती है, ताकि विवाद की स्थिति न खड़ी हो।

महाराष्ट्र में सरकार गठन के मसले पर गुरुवार को भी नई दिल्ली में राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर कांग्रेस और राकांपा नेताओं की बैठक हुई। प्रेट्र

कांग्रेस को महाराष्ट्र में दफन कर देगा यह गठबंधन : निरूपम

मुंबई, प्रेट्र : कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने शिवसेना के साथ जाने के फैसले को पार्टी के लिए घातक बताया है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने कई साल पहले उत्तर प्रदेश में बसपा से गठबंधन करके गलती की थी। पार्टी आज तक वहां इससे उबर नहीं पाई है। हम वही गलती महाराष्ट्र में कर रहे हैं। शिवसेना सरकार में तीसरे नंबर की पार्टी बनना कांग्रेस के दफन हो जाने जैसा है। बेहतर होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष किसी दबाव में नहीं आएं।' इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि कांग्रेस को तब तक सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए, जब तक उसे भी मुख्यमंत्री पद न मिल जाए। आठवले ने कहा, कांग्रेस को दो साल शिवसेना और डेढ़-डेढ़ साल कांग्रेस-राकांपा के मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखना चाहिए।

राकांपा और कांग्रेस के बीच सभी मुद्दों पर सहमति है। गठबंधन के प्रारूप पर शुक्रवार को फैसला होगा। अंतिम एलान मुंबई में होगा।
-पी. चव्हाण (कांग्रेस नेता)

'विधायक खरीद की कोशिश हुई तो सिर फोड़ देंगे'

शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार ने भाजपा को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, 'भाजपा किसी भी विधायक की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएगी। जो भी विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश करेंगे, उनके सिर फोड़ दिए जाएंगे। हम अस्पताल में उनके इलाज की व्यवस्था भी करेंगे।'

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

चुनावी बांड को लेकर कांग्रेस का संसद में हंगामा

नई दिल्ली : चुनावी बांड और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के मुद्दे पर गुरुवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई एक घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा से कांग्रेस ने वाकआउट किया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

पुनर्विचार याचिका के पक्ष में नहीं महमूद मदनी गुट

नई दिल्ली : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद का महमूद मदनी गुट पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के पक्ष में नहीं है। गुट ने इसे अहितकर बताया है और याचिका की वकालत करने वालों को नुकसान होने की आशंका से सचेत भी किया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

रणनीतिक विनिवेश की सूची में शामिल हैं 30 और कंपनियां

नई दिल्ली : बीपीसीएल, एससीआइ और कानकॉर की रणनीतिक बिक्री के जरिये केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों की थाह लेने की कोशिश कर रही है। अगर यह बिक्री सफल रही तो संभव है कि 2020-21 और 21-22 में 30 अन्य कंपनियों का भी विनिवेश हो जाए।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

राष्ट्रपति गोतबाया ने बड़े भाई को दिलाई पीएम पद की शपथ

कोलंबो : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने गुरुवार को अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस द्वीपीय देश में पहले भी ऐसा हो चुका है, जब गोतबया और महिंदा एक साथ अहम पदों पर रहे।

टेस्ट की जंग

दूसरा टेस्ट	दोपहर 1:00 बजे से
भारत vs बांग्लादेश	स्थान : कोलकाता
	प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों से जुड़े हर सवाल का देना होगा जवाब : सुप्रीम कोर्ट

- याचिकाकर्ताओं ने विस्तार से बात रखी है, प्रशासन को उन्हें संतुष्ट करना होगा
- केंद्र ने कहा, एहतियात के तौर पर लगाए गए थे प्रतिबंध

नई दिल्ली, एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा कि उसे पूर्ववर्ती राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में हर सवाल का जवाब देना होगा। न्यायमूर्ति एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विस्तार से अपनी बात रखी है। 'मिस्टर मेहता, आपको याचिकाकर्ताओं के हर सवाल का जवाब देना होगा। आपके जवाबी हलफनामे से हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली है। यह संदेश न दें कि आप इस मामले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं।' मेहता ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिबंधों पर जो भी बात कही है, वह ज्यादातर 'गलत' है और अदालत में बहस के दौरान वह हर बात का हर पहलू से जवाब देंगे।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, उनके पास मामले की स्थिति रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने अभी वह अदालत में दाखिल नहीं की है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में रोज हालात बदल रहे हैं। रिपोर्ट दाखिल करने के समय वह एकदम वास्तविक हालात का ब्योरा देना चाहते हैं। इस बीच, प्रतिबंधों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इनके चलते न तो एक भी आदमी मारा गया न ही गोली चलाने की नौबत आई। केंद्र सरकार से इन प्रतिबंधों पर सवाल पूछे जाने के बजाय उसे पांच अगस्त के ऐतिहासिक फैसले के बाद स्थितियों से शानदार तरीके से निपटने के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

वेणुगोपाल ने कहा कि पांच अगस्त के बाद यदि इंटरनेट सेवा बहाल रहती, तो एक क्लिक में दसियों हजार संदेश अलगाववादियों और आतंकियों तक पहुंचते। इसका नतीजा होता कि व्यापक अराजकता फैल जाती और बड़ी हिंसक घटनाएं होतीं।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वेणुगोपाल ने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने यह एहतियाती कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2016 में बुरहान वानी समेत तीन आतंकी मारे गए थे। उस समय तीन महीने के लिए जब राज्य में प्रतिबंध लगाया गया, तो किसी ने मुकदमा नहीं किया। और इस बार प्रतिबंधों के खिलाफ 20 याचिकाएं दायर कर दी गईं।

वेणुगोपाल ने कहा कि भारत सरकार ने जिस तरह घटनाओं को संभाला, उसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। कश्मीर घाटी में हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से सीमापार से आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही थी। स्थानीय आतंकियों और अलगाववादियों ने आम नागरिकों को बंधक बना लिया था। ऐसे में यदि सरकार ने एहतियाती कदम नहीं उठाया होता, तो यह उसकी मूर्खता होती। वेणुगोपाल ने कहा कि अनुच्छेद 370 से आतंकियों और हुर्रियत कान्फ्रेंस को शह मिलती थी। इसे खत्म करने के बाद यदि बड़ा एहतियाती कदम नहीं उठाया जाता, तो बड़े पैमाने पर अराजकता फैल सकती थी।

बीजिंग ने 15 साल में प्रदूषण से मुक्ति पाई हम उससे पहले कर दिखाएंगे : जावडेकर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली सहित देश के बड़े हिस्से की बिगड़ी आबोहवा पर संसद ने जताई चिंता
- चर्चा के बहाने राजनीति करने वालों पर केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना

दिल्ली-एनसीआर सहित देश के बड़े हिस्से की बिगड़ी आबोहवा को लेकर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार चर्चा हुई। सांसदों ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जताई और इससे निपटने के लिए सरकार को काफी सुझाव भी दिए। हालांकि राज्यसभा में चर्चा के जवाब में सरकार ने इससे जल्द निपटने का भरोसा दिया। साथ ही कहा, बीजिंग ने ऐसे ही प्रदूषण से निपटने में 15 साल लगाए थे, लेकिन हम इससे पहले ही वायु प्रदूषण की समस्या से पार पा लेंगे। सरकार ने इसे लेकर गंभीर और जिम्मेदार पहल शुरू की है। इसका असर यह रहा कि पिछले तीन साल में इसमें सुधार भी दिखा है।

खास बात यह है कि राज्यसभा में गुरुवार को शुरू हुई अल्पकालिक चर्चा जहां कुछ घंटों में समाप्त हो गई, वहीं लोकसभा में यह चर्चा अभी भी जारी है। चर्चा की शुरुआत मंगलवार को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की थी। हालांकि यह बुधवार को लोकसभा की कार्यसूची में दूसरे विषयों के दर्ज होने के चलते नहीं हो पाई थी। जो गुरुवार को फिर शुरू हुई और शून्यकाल के बाद देर शाम तक चली। इस दौरान चर्चा में सभी दलों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि शुक्रवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री इस पर अपना जवाब देंगे।

इस बीच, राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए जावडेकर ने कहा कि वायु प्रदूषण कोई राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर मिल-जुलकर इससे निपटने पर ध्यान देना चाहिए।

राज्यसभा में गुरुवार को वायु प्रदूषण की समस्या पर बोलते केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर। प्रेट्र

उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोगों ने इस मामले को जिस तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, वह दुखद है।

जावडेकर ने कहा कि प्रदूषण से निपटने को दिल्ली-एनसीआर सहित देश के 122 शहरों को लेकर एक कार्ययोजना (नेशनल एक्शनप्लान फॉर क्लीन एयर) बनाई गई है। इसके तहत सभी को पैसा दिया गया है। साथ ही सभी शहरों से अपनी भौगोलिक और मौजूदा परिस्थितियों के लिहाज से योजना तैयार करने को कहा गया है। यह मुद्दा वैसे भी किसी दूसरे पर छोड़ने का नहीं है, खुद करने का है। उन्होंने कहा कि चर्चा में ज्यादातर सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की बात कही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत और चीन दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिनका ग्रीन कवर पिछले वर्षों में बढ़ा है। उन्होंने इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रहे सुधार का भी जिक्र किया और कहा कि पहले की तुलना में अब अच्छी हवा वाले दिनों की संख्या बढ़ी है। दोनों ही सदनों में चर्चा के दौरान सभी दलों के सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया।

किसी ने यज्ञ कराने, किसी ने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने का दिया सुझाव पेज>>3

व्यापम की सिपाही भर्ती परीक्षा में सभी 31 आरोपित दोषी करार

नईदुनिया, भोपाल

- सीबीआइ की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, 25 को सुनाई जाएगी सजा

मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा 2013 में सभी 31 आरोपितों (उत्तर प्रदेश के 14, मध्य प्रदेश के 17) को भोपाल की विशेष सीबीआइ अदालत ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का दोषी पाया है। सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। 25 तारीख को सजा सुनाई जाएगी। मामले की सुनवाई सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू की कोर्ट में हुई।

व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा की जांच एसटीएफ कर रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला दिसंबर 2015 में सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआइ ने जांच के आधार पर भोपाल की विशेष अदालत में अप्रैल 2017 में चालान पेश किया था। जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया था, उनमें 12 अभ्यर्थी, उनके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले 12 फर्जी उम्मीदवार तथा दलाल शामिल थे। सीबीआइ ने इनके खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

ऐसे किया था फर्जीवाड़ा : पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले दलालों ने असली अभ्यर्थियों से संपर्क किया था और कहा था कि उनके स्थान पर वे फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल कराएंगे, जिससे उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। इसके एवज में असली अभ्यर्थियों से दो लाख रुपये तक की राशि ली गई। परीक्षा देने के एवज में फर्जी अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये तक दिए गए। इसके लिए फर्जी तरीके से प्रवेश पत्र तक तैयार किए गए थे।

आज से दिखेगा गुलाबी गेंद का कमाल

अभिषेक त्रिपाठी, कोलकाता

- ईडन गार्डंस में भारत-बांग्लादेश के बीच डे-नाइट टेस्ट मैच आज से

कई वर्षों की ना-नुकुर और डर के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब भारतीय टीम गुलाबी गेंद से डे-नाइट टेस्ट मैच खेलने जा रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डंस स्टेडियम में शुक्रवार से यह मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का यह पहला डे-नाइट टेस्ट और इस सीरीज का दूसरा मैच होगा। भारत में पहली बार गुलाबी गेंद से टेस्ट खेला जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का यह 12वां डे-नाइट टेस्ट मैच होगा। भारत और बांग्लादेश को छोड़कर आठ प्रमुख टीमें पहले ही डे-नाइट टेस्ट मैच खेल चुकी हैं। नए टेस्ट देश अफगानिस्तान और आयरलैंड ने भी अभी कोई डे-नाइट टेस्ट नहीं खेला है।

देश में पहली बार किसी टेस्ट मैच में गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भारत में सभी टेस्ट मैच लाल गेंद से खेले गए थे। पारंपरिक टेस्ट मैच की तरह डे-नाइट टेस्ट में भी प्रतिदिन तीन सत्र का खेल खेला जाएगा, लेकिन यह सुबह नौ-साढ़े नौ बजे की जगह दोपहर एक बजे शुरू होगा। इस मैच में भी विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। भारत ने इस सीरीज के पहले मुकाबले में इंदौर में बांग्लादेश को पारी और 130 रनों से हराया था। (पेज-14 भी देखें)

स्टेडियम में अभ्यास के दौरान गेंद को लेकर बात करते रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। प्रेट्र

इस मैच के लिए विशेष इंतजाम

- टॉस दोपहर 12.30 पर होगा और पहले सत्र की शुरुआत 1.00 बजे होगी
- गावस्कर, तेंदुलकर, कपिल देव सहित कई महान क्रिकेटर यहां उपस्थित होंगे
- सौरव गांगुली के साथ ही राहुल द्रविड़ व अनिल कुंबले भी आएंगे
- चायकाल में पूर्व कप्तान विशेष गाड़ियों से स्टेडियम में चक्कर लगाएंगे
- पहले दिन संगीत कार्यक्रम भी होंगे और दिन के अंत में सम्मान समारोह होगा
- बांग्लादेश की गायक रूना लैला, बंगाल के गायक जीत गांगुली परफॉर्म करेंगे
- इस मैच को देखने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रहेंगी
- बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस दौरान उनके साथ रहेंगी

उप्र में जबरन धर्मांतरण पर रोक का बनेगा नया कानून

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश में जल्द ही नया कानून लागू किया जा सकता है। राज्य विधि आयोग ने 'उप्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल-2019' के नाम से बनाया गया मसौदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है।

विधि आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी द्वारा एक एजेंसी को दी गई जानकारी के मुताबिक, जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए नए कानून का मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। यह रिपोर्ट देश की आजादी से पहले और बाद के कानून के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के कानून का परीक्षण करते हुए तैयार की गई है। विधि आयोग का मत है कि जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक के लिए प्रदेश का मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह यहां भी विशेष कानून बनाने की जरूरत है।

व्यवस्था में बदलाव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बोले, अभी एनएच के 537 में से 520 प्लाजा पर फास्टैग टोल टैक्स कलेक्शन के इंतजाम, स्टेट हाईवे को भी फास्टैग प्रणाली के अंतर्गत लाने के प्रयास जारी

पहली दिसंबर तक मुफ्त में लें फास्टैग, वरना लगेगा दोगुना टोल टैक्स

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यदि आप पहली दिसंबर तक एनएचएआइ के प्वाइंट ऑफ सेल से फास्टैग खरीदेंगे तो ये आपको मुफ्त में मिलेगा। आपसे इसका मूल्य और सेक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाएगी। आपको केवल फास्टैग को रिचार्ज कराना होगा, ताकि जब आप किसी नेशनल हाईवे पर निकलें तो टोल टैक्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अदा हो जाए और आप बेरोकटोक आगे बढ़ जाएं। लेकिन यदि आप इसके बिना फास्टैग लेन में प्रवेश कर गए तो आपको कैश के तौर पर दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि कैश लेन से जाने वाले वाहन निर्धारित टोल टैक्स देकर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें कतार में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पहली दिसंबर से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग को अनिवार्य किया जा रहा है। अभी तक एनएच के 537 टोल प्लाजा में से 520 प्लाजा पर फास्टैग लायक इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स कलेक्शन के इंतजाम किए जा चुके हैं। मैन्युअल टोल कलेक्शन वाले 17 टोल प्लाजा में भी शीघ्र ही फास्टैग व्यवस्था लागू करने के इंतजाम किए जा रहे हैं।

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) प्रोग्राम के तहत शीघ्र ही प्रादेशिक राजमार्गों अथवा स्टेट हाइवे पर भी फास्टैग की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एनएचएआइ विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अनुबंध कर रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र समेत आठ राज्यों के साथ अनुबंध किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट हाईवे के 13 टोल प्लाजा पर फास्टैग स्वीकार किए जाने लगे हैं। देशभर में 2014 से अब तक 66 लाख फास्टैग की बिक्री हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट सेग्मेंट के 90 फीसद वाहनों में फास्टैग लग चुके हैं। नवनिर्मित वाहनों में 2017 से फास्टैग लगकर आ रहा है। केवल कारों, दोपहिया और तिपहिया सवारी वाहनों में फास्टैग अपनाए जाने की रफ्तार सुस्त है। (पेज-12 भी देखें)

लोकसभा में गुरुवार को चर्चा में हिस्सा लेते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। प्रेट्र

राज्यों के साथ बैठक जल्द

गडकरी ने कहा कि महानगरों को जाम और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए रिंग रोड बनाने की योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों से 50 प्रतिशत खर्च स्वयं वहन करने को कहा था। लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमने उन्हें दूसरे तरीकों से सहयोग करने को कहा है। इसके तहत वे मुफ्त जमीन समेत कई गतिविधियों के लिए टैक्स में छूट देकर मदद कर सकते हैं।

रोड-साइड सुविधाएं

हाईवे के किनारे स्थापित होने वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं (पेट्रोल पंप, होटल-मोटल, पार्किंग प्लाजा, हेलीपैड आदि) में निवेश की नीति में भी कुछ बदलाव किया गया है। अब लंदन की तर्ज पर टोल प्लाजा के ऊपर रेस्टोरेंट बनेंगे। इटालियन स्टाइल पार्किंग प्लाजा का निर्माण एनएचएआइ और एनएचआइडीसीएल करेंगी। इन दोनों को राज्यों में 50 पार्किंग प्लाजा के निर्माण के आर्डर भी मिले हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की माली हालत दुरुस्त है

गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की वित्तीय स्थिति दुरुस्त है। अगले दो-तीन साल में उसे सालाना 30 हजार करोड़ का टोल हासिल होने लगेगा। हमारा इरादा एनएचएआइ की आमदनी को बढ़ाकर सालाना एक लाख करोड़ रुपये करने का है। बुधवार को कैबिनेट ने टीओटी मॉडल के तहत बन चुके राजमार्गों के मौद्रीकरण के नियमों में ढील देकर एक से दो साल पहले बन चुकी सड़कों के भी मौद्रीकरण की इजाजत दे दी है।

प्रियंका के फैसलों से असंतुष्ट उप्र के वरिष्ठ कांग्रेसियों को नोटिस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के फैसलों पर असंतोष जताकर बदलाव की उम्मीद संजो रहे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसियों को झटका लगा है। प्रियंका की त्योरियां चढ़ने पर प्रदेश की अनुशासन समिति ने दो बैठकों में शामिल हुए ग्यारह वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

संगठन में सिर्फ युवाओं को ही तरजीह दिए जाने के प्रियंका के निर्णय से वे कांग्रेसी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जो पिछले कई दशकों से पार्टी में काम कर रहे हैं। इनमें पूर्व जनप्रतिनिधि, पूर्व पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने पिछले दिनों दो बैठकें कर अपना दर्द बयां किया और तय किया कि इस मुद्दे पर वे सोनिया गांधी से मुलाकात कर बताएंगे कि कैसे ये फैसले पार्टी के हित में नहीं हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी नाराजगी को गंभीरता से लेकर हाईकमान शायद निर्णय में कुछ बदलाव करे। बुधवार को हुई पूर्व विधायक व पूर्व प्रत्याशियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आश्वस्त भी किया था कि सभी वरिष्ठजनों को सम्मान होगा। इसी बीच गुरुवार को प्रियंका और अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर अनुशासन समिति के सदस्य अजय राय ने इन पुराने कांग्रेसियों को अनुशासनहीनता पर नोटिस जारी कर दिए। इन सभी से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इन्हें दिए गए नोटिस : पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी, पूर्व मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी, सत्यदेव त्रिपाठी, एआइसीसी सदस्य राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र, हाफिज मोहम्मद उमर, विनोद चौधरी, नेक चंद्र पांडेय, युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वयंप्रकाश गोस्वामी।

प्रियंका गांधी वाड्रा (फाइल)

दो बैठकें कर अपनी उपेक्षा पर बयां किया था दर्द

25 नवंबर को रेलवे ने भोपाल से हजरत निजामुद्दीन के लिए 02131 नंबर की विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। भोपाल से यह ट्रेन रात 10.50 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10.40 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 22 नवंबर 2019

जल गुणवत्ता विवाद ▸ बीआइएस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की आलोचना की

हमारे खिलाफ केजरीवाल का अनर्गल प्रलाप : पासवान

पानी की जांच के लिए गठित होने वाली 32 टीमों के लिए केंद्र ने जारी की सूची

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की गुणवत्ता रिपोर्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह राजनीतिक रंग भी पकड़ने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप पर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा, 'केजरीवाल एक गलती छिपाने के लिए कितनी गलतियां कर रहे हैं? इसीलिए हमारे खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।' पासवान ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को खुली चुनौती देते हुए कहा, 'अगर दिल्ली में नल का पानी शत प्रतिशत पीने लायक है तो भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के हिसाब से वैधानिक घोषित करें।'

पासवान ने स्वायत्तशासी संस्था भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करने पर केजरीवाल की कड़ी आलोचना की। इस संस्था ने अब तक 25 हजार मानक तैयार किए हैं, जिसकी वैश्विक पहचान है। देश के 21 राज्यों की राजधानी में पेयजल की गुणवत्ता जांची गई थी। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल थी। आमतौर पर सभी जगहों के पानी के नमूने बहुत खराब पाए गए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के पानी खराब की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए उपभोक्ता मंत्री पासवान पर कई आरोप मढ़ दिए।

दूषित जल आपूर्ति को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि राजधानी के पांच सौ स्थानों से पानी लेकर भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को पिलाने आए हैं, लेकिन पुलिस व प्रशासन की मदद से उन्हें रोक दिया गया। तीन माह बाद दिल्ली की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। जागरण

पासवान ने कहा कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों और 140 वार्डों के पानी की जांच के लिए इस महीने के आखिर तक सैंपल लिए जाएं। इसकी जांच में दिल्ली जल बोर्ड और बीआइएस के तकनीकी अधिकारी शामिल किए जाएं। उन्होंने जोर देकर फिर कहा कि लेकिन जांच करने वाली टीम में राजनीतिक लोगों को शामिल न किया जाए। पानी की जांच किसी मान्यता प्राप्त लैब से कराने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाए। हैरानी जताते हुए पासवान ने कहा कि केजरीवाल ने जांच के लिए 32 टीमें बनाने की घोषणा की थी, लेकिन टीमों का गठन नहीं हुआ। इसके लिए हमने बीआइएस के 32 तकनीकी अफसरों की सूची जारी कर दी है। पासवान ने कहा, 'केजरीवाल पानी की गुणवत्ता रिपोर्ट का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती है। पानी की जांच केवल दिल्ली की नहीं हुई है, यह तो सभी राज्यों की राजधानी में हुई है। फिर केजरीवाल क्यों बौखला रहे हैं।'

पासवान ने कहा कि देश का उपभोक्ता मंत्री होने के नाते उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। पासवान ने तल्ख लहजे में कहा, 'वह किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन कोई उनके मामले में हस्तक्षेप करता है तो चुप नहीं बैठेंगे।'

मोहनिया ने लगाया आरोप, लोजपा के कार्यकर्ताओं ने उठाए थे पानी के सैंपल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा, चुनावी फायदे के लिए पानी की गुणवत्ता पर उठाए जा रहे सवाल**

राजधानी में पानी की गुणवत्ता के मामले पर जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पानी की गुणवत्ता जांच के लिए लोजपा (लोक जनशक्ति पार्टी) के कार्यकर्ताओं से सैंपल उठवाए थे। बीआइएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के अधिकारी सैंपल उठाने नहीं गए थे। उन्होंने पानी के सैंपल उठाने से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक की प्रक्रिया को गलत बताया और कहा कि दूसरों के लिए मानक तय करने वाले बीआइएस ने खुद मानकों का पालन नहीं किया। दिल्ली में चुनाव नजदीक हैं। राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की रिपोर्ट तैयार करवाई गई है।

उन्होंने कहा कि बीआइएस की रिपोर्ट दिल्ली सरकार को मिल गई है। यह भ्रामक है। इसमें 11 सैंपल का जिक्र किया गया है। इसमें पहले नंबर पर दीपक कुमार के घर से सैंपल लेने की बात कही गई है। दीपक ने अपने घर से सैंपल लिए जाने से इन्कार किया है तो फिर यह रिपोर्ट कैसे तैयार हुई? दो सैंपल रामविलास पासवान के आवास व उनके दफ्तर से लिए गए हैं। एक सैंपल नंद नगरी में इलियास नामक व्यक्ति के घर से उठाया गया। उन्होंने बताया है कि सैंपल लेने के लिए बीआइएस का कोई अधिकारी नहीं आया। पीतमपुरा में जिस जगह से सैंपल लेने की बात कही गई, वह मौजूद नहीं है। वैसे भी सिर्फ 11 सैंपल से पूरी दिल्ली के पानी की गुणवत्ता तय नहीं की जा सकती। नियमानुसार जहां से सैंपल लिया गया, वहां सील लगाना चाहिए था। इसके अलावा रिपोर्ट में दर्ज किसी भी प्रदूषक तत्व का न्यूनतम मानक अंकित नहीं है। इस तरह जांच प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ।

117 जगहों पर है दूषित पानी की समस्या : दिनेश मोहनिया ने कहा कि 2300 जगहों की पहचान की गई थी, जहां गंदे पानी की समस्या थी। इसके बाद बड़ी संख्या में सीवर लाइन व पानी की लाइन बदली गई है। मौजूदा समय में 117 इलाके बचे हैं जहां दूषित पानी की समस्या रह गई है। पाइपलाइन में रिसाव के कारण ऐसी समस्या होती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भी पांच फीसद सैंपल में दूषित पानी की समस्या हो सकती है। दिल्ली में यह आंकड़ा महज डेढ़ फीसद के आसपास है। इसे और बेहतर किया जाएगा।

11 जगहों से सैंपल लेकर जल बोर्ड भी करा रहा जांच : केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय ने दिल्ली में जिन 11 जगहों से सैंपल लेकर पानी की गुण्वत्ता जांच कराई थी, उन सभी जगहों से जल बोर्ड ने भी सैंपल उठवाएं हैं। इनकी जांच चल रही है। 48 घंटे में उनकी रिपोर्ट आएगी। मोहनिया ने कहा कि उठाए गए सैंपल की रसायनिक व बायोलॉजिकल दोनों तरह की जांच कराई जा रही है। बायोलॉजिकल जांच की रिपोर्ट आने में 48 घंटे लगते हैं। इसके अलावा मीडिया चाहे तो दिल्ली जल बोर्ड कहीं से भी सैंपल लेकर पानी की गुणवत्ता की जांच कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड दिल्ली के सभी वार्डों से पांच-पांच सैंपल लेकर भी जांच कराएगा। वैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), केंद्र सरकार व नगर निगम भी सैंपल उठाकर समय-समय पर जांच करते हैं। निगम में 15 सालों से भाजपा सत्ता में है। निगम की रिपोर्ट में भी 97-98 फीसद पानी के सैंपल ठीक पाए गए हैं।

सुशील अंसल के पासपोर्ट का आवेदन देखने वाले पुलिसकर्मी जांच में नहीं हुए शामिल

जासं, नई दिल्ली : 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी करार दिए गए सिनेमाघर के मालिक सुशील अंसल को पासपोर्ट जारी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। दिल्ली पुलिस ने न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ के समक्ष हलफनामा दायर करके बताया कि पासपोर्ट का आवेदन देखने वाले पुलिसकर्मी अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं, ताकि यह पता चल सके कि दोषी करार दिए गए जाने के बाद भी अंसल को यात्रा दस्तावेज कैसे मिले। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दो में से किसी एक क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस ने अंसल के आवेदन पर लगी रोक को हटाया, जबकि उसके खिलाफ रिपोर्ट थी। वहीं किसी और ने इसे पुलिस विभाग को भेजा था। 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में एक हिंदी फिल्म के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सुशील अंसल को दोषी करार दिया गया था।

पुलिस ने पीठ को बताया कि एक पुलिसकर्मी मातृत्व अवकाश पर है, जबकि अन्य पुलिसकर्मी के वरिष्ठ अधिकारी ने पुलिस को बयान दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी है। पिछली तारीख पर न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने पूछा था कि आखिर कैसे एक दोषी के साथ वीवीआइपी की तरह उसे एफ-टोकन जारी किया गया। पीठ ने पूछा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस को भेजी गई दो रिपोर्ट के बावजूद कैसे प्री-वेरिफिकेशन रिपोर्ट को पोस्ट-वेरिफिकेशन से बदला गया और उसके पासपोर्ट आवेदन पर लगी रोक को हटाया गया। 17 दिसंबर 2018 को पीठ द्वारा दिए गए निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने सुशील अंसल व तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की थी।

न्यूज गैलरी

सीबीआइ ने उत्तरी निगम के दो अफसरों पर दर्ज किया मुकदमा

नई दिल्ली : सीबीआइ ने दिल्ली के एक उद्योगपति से रिश्वत मांगने के आरोप में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के दो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआइ ने रिश्वत को लेकर अधिकारियों की बातचीत को रिकार्ड किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में तैनात सहायक आयुक्त बलराज और अपर डिवीजन क्लर्क मनोज के खिलाफ सीबीआइ ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआइ से की गई 18 नवंबर की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने दिल्ली के खसरा, जौंटी स्थित एक फैक्ट्री से सील हटाने के लिए दो लाख रुपये की मांग की। सीबीआइ ने जांच में पाया कि फैक्ट्री छह महीने पहले सील की गई थी। मोलभाव के बाद रिश्वत की रकम 1.5 लाख रुपये तय हुई, जिसकी पहली किस्त के रूप में अधिकारियों को 75 हजार रुपये दिए जाने थे। शिकायतकर्ता और आरोपितों के बीच की बातचीत को सीबीआइ ने डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के जरिये रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डर स्वतंत्र गवाह की कमीज में लगाया गया था। (प्रेट्र)

पति ने खौलते पानी को पत्नी पर उड़ेला

नई दिल्ली : जीटीबी एंक्लेव इलाके में बुधवार को एक ही चूल्हे पर पहले खाना बनाने को लेकर पत्नी-पत्नी के बीच विवाद हो गया। पति ने चूल्हे पर उबल रहे चावल को पानी सहित पत्नी पर उड़ेल दिया। खौलते पानी की वजह से पीड़िता झुलस गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। उसे थाने जमानत दे दी गई। 42 वर्षीय पीड़िता परिवार के साथ जनता फ्लैट, जीटीबी एंक्लेव में रहती हैं। उनका पति से विवाद चल रहा है। रसोई घर में एक ही चूल्हे पर पति-पत्नी अलग खाना बनाते हैं। (जासं)

चालक व गार्ड को अगवा कर कैश वैन से 80 लाख रुपये लूटे

नई दिल्ली : द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिनदहाड़े एटीएम में नकदी जमा कराने पहुंची कैश वैन के चालक और गार्ड को चाकू की नोंक पर अगवा किया और करीब 80 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने पहले दोनों कर्मियों को बंधक बनाया और कैश वैन को अपने साथ ले गए। करीब तीन किलोमीटर दूर ले जाकर बदमाशों ने दोनों कर्मियों को पहले जमकर पीटा और फिर नकदी लूटने के बाद उन्हें छोड़ दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। (जासं)

दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग ने फिर की वापसी

जेएनएन, नई दिल्ली

▸ **आज हवा और बिगड़ने के आसार, गंभीर रहा एयर इंडेक्स**

▸ **पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के 1011 मामले आए सामने**

हवा का स्तर बहुत खराब होने के बाद गुरुवार को स्मॉग ने भी वापसी कर ली। दिन भर दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की परत छाई रही। एनसीआर के तीन शहरों में तो वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। शुक्रवार को हालात और बिगड़ने के आसार हैं। शनिवार से अगर हवा की गति बढ़ी तो ही थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एयर बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 366 रहा। बुधवार को यह इंडेक्स 301 था। शाम छह बजे हवा में पीएम 10 कणों की मात्रा 352 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 2.5 कणों की मात्रा 205 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। गाजियाबाद का एयर इंडेक्स 416, नोएडा में 402, ग्रेटर नोएडा में 400, फरीदाबाद में 390 और गुरुग्राम में 280 रहा।

जानकारी के मुताबिक इस बार भी हवा में प्रदूषण की मुख्य वजह पीएम 2.5 ही है जो तय मानकों से तीन से चार गुना तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। दरअसल, बीते 24 घंटों में ज्यादातर समय हवा शांत रही है। दिन में साढ़े ग्यारह बजे से लेकर साढ़े पांच बजे तक हवा ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन इस दौरान भी हवा की रफ्तार छह किमी प्रति घंटे तक ही रही। इसके चलते हवा में मिले प्रदूषक कणों का बिखराव बेहद धीमा हो गया है।

राजधानी में फिर से बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाकर चलने को मजबूर हुए लोग। जागरण

सफर के अनुसार शुक्रवार को राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर रह सकता है। शनिवार दोपहर से स्थिति में सुधार होने की संभावना है। दूसरी तरफ हवा में पराली के धुएं का असर अब भी बना हुआ है। गुरुवार को प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी पांच फीसद रही। सफर का अनुमान है कि पराली जलाने की घटनाएं तो ज्यादा हो रही हैं लेकिन हवा की दिशा अलग होने और गति बहुत सुस्त होने से अभी पराली का धुआं दिल्ली की ओर कम आ रहा है। शुक्रवार को यह चार फीसद तक प्रदूषित कर सकता है।

हरियाणा में नहीं रुक रहा पराली जलाना : तमाम प्रयासों के बावजूद हरियाणा में पराली जलाने पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इस कारण एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है। सोनीपत में एक स्थान पर, पानीपत में एक, जींद में एक, सिरसा में 11 स्थानों पर, कैथल में चार और फतेहाबाद में 26 स्थानों पर खेतों में आग लगाने की घटनाएं सेटेलाइट द्वारा चिह्नित की गईं। इस कारण हिसार व जींद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 रहा तो फरीदाबाद में 390 दर्ज किया गया। पंजाब में एक्यूआइ में सुधार जारी है। गुरुवार को राज्य के सभी शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम रहा। रोपड़ में सबसे ज्यादा 187 रहा।

फीस वृद्धि पर आंदोलन को बताया वामपंथी साजिश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **जेएनयू शिक्षक संघ से 113 शिक्षकों ने तोड़ा संबंध**

▸ **शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार पर चुप्पी साधने का लगाया आरोप**

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के 113 शिक्षकों ने खुद को जेएनयू शिक्षक संघ से अलग कर दिया है। गुरुवार को कुछ शिक्षकों ने कहा कि महिला शिक्षिका के साथ छात्रों द्वारा खराब बर्ताव किए जाने पर शिक्षक संघ ने चुप्पी साधी। एसोसिएट डीन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदना मिश्रा को आंदोलन कर रहे छात्रों ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज-2 की इमारत में करीब 30 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इससे पहले 28 अक्टूबर को छात्र डीन प्रो. उमेश कुमार कदम के साथ भी खराब व्यवहार किया गया। इस तरह के अमानवीय आपराधिक कृत्य पर जेएनयू शिक्षक संघ ने आंदोलन कर रहे छात्रों को नहीं रोका और न ही इसकी निंदा की। गुरुवार को विश्वविद्यालय के प्रो. अश्विनी मोहापात्रा, प्रो. बृजेश कुमार पांडेय, प्रो. मजहर आसिफ और डॉ. नागेंद्र श्रीनिवास ने विश्वविद्यालय में प्रेसवार्ता कर बताया कि शिक्षकों के साथ हुई हिंसक घटना के बाद शिक्षक संघ ने साजिशन तरीके से चुप्पी साधे रखी। लिहाजा कुल 113 शिक्षक जेएनयू शिक्षक संघ से नाता तोड़ रहे हैं।

साथ ही शिक्षकों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा जेएनयू में अकादमिक गतिविधियों के लिए सामान्य स्थित बहाल करने के लिए गठित की गई उच्चस्तरीय समिति को जेएनयू की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करार दिया है। शिक्षकों ने कहा कि जेएनयू प्रशासन एमएचआरडी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पास नहीं गया था। एमएचआरडी ने खुद से संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है।

प्रेसवार्ता में शिक्षकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश भर से वामपंथ का वैचारिक आधार खिसक रहा है। ऐसे में छात्रावास की फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने वैचारिक आधार को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। छात्रों हित सिर्फ एक बहाना है। असल में इन्हें व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है।

शिक्षक संघ का बयान : शिक्षक संघ के अध्यक्ष डीकेलोबियाल ने कहा कि शिक्षकों के किसी भी खंड द्वारा इस तरह का कोई निर्णय लेने की जानकारी हमारे पास नहीं है। जेएनयू शिक्षक संघ सभी शिक्षकों का सामूहिक निकाय है। सभी शिक्षकों की चिंताओं को उचित तरीके से देखा जाता है।

जेएनयू में छात्रावास की फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर संसद भवन थाने के पास एबीवीपी के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रा को हिरासत में लेती दिल्ली पुलिस। जागरण

ऐतिहासिक विरासतों को नया रंग-रूप देंगी फैशन डिजाइनर रितु बेरी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : अगले वर्ष फरवरी की शुरुआत में आयोजित होने वाले 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले को अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर रितु बेरी नया रंग-रूप देंगी। मेला प्राधिकरण ने रितु बेरी को हस्तशिल्प मेले के लिए मानद सलाहकार बनाया है। इस बार सूरजकुंड मेले की थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पार्टनर कंट्री उजबेकिस्तान है। रविवार को हिमाचल पर्यटन विभाग की टीम सूरजकुंड आएगी, जो हरियाणा पर्यटन के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। बैठक के बाद हिमाचल पर्यटन विभाग सूरजकुंड में अपनी तैयारी शुरू करेगा।

फिलहाल हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से अपने स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में रितु बेरी को अपने देश की शिल्पकला, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रमाणिकता में योगदान करने और उच्च स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा गया है। वर्ष 2016 में भारत सरकार के खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक आयोग की सलाहकार भी रह चुकी रितु बेरी कई बॉलीवुड और हॉलीवुड कलाकारों की ड्रेस डिजाइन कर चुकी हैं।

टाइट कपड़े में आठ घंटे चलाई कार तो पहुंचा अस्पताल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पीड़ित हुआ युवक**

▸ **45 मिनट सीपीआर देने के बाद युवक की हालत हुई स्थिर**

टाइट जींस में लगातार घंटों कार चलकर लंबी दूरी तय करना महंगा पड़ सकता है। दिल्ली के रहने वाले 30 वर्षीय युवक सौरभ शर्मा ने टाइट जींस पहनकर आठ घंटे तक कार चलाई जिसकी वजह से रक्तसंचार प्रभावित हुआ और ब्लड क्लॉट (थक्का) बन गया। इसके बाद बाएं पैर में दर्द होने के बावजूद उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। इस बीच उन्होंने एल्कोहल का इस्तेमाल भी किया था। दो दिन बाद सीढ़ी चढ़कर ऑफिस पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर गए। उन्हें शालीमार बाग स्थिति मैक्स अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ा। ब्लड क्लॉट दूर करने की दवा देने व 45 मिनट तक सीपीआर (कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन) करने के बाद धड़कन व सांस की गति स्थिर हुई।

अस्पताल के डॉक्टर इसका कारण लंबे समय तक टाइट जींस पहनकर कार चलाना बता रहे हैं। अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नवीन भामरी ने कहा कि सौरभ पल्मोनरी एम्बोलिज्म के शिकार हुए। इलाज के बाद पता चला कि इसका कारण आठ घंटे तक टाइट जींस में कार चलाना था। उन्होंने कहा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक जानलेवा बीमारी है। इसके 50 फीसद मामलों में हार्ट अटैक होता है। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉ. योगेश कुमार छाबड़ा ने कहा कि जब उन्हें यहां लाया गया था, उस समय उनका बीपी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। सांस बहुत कम चल रही थी। शरीर में ऑक्सीजन की कमी से शरीर नीला पड़ गया था। सीपीआर देकर उनकी जान बचाई गई। 24 घंटे में उनका ब्लड प्रेशर स्थिर हुआ। फिर भी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी। इस वजह से 24 घंटे तक डायलिसिस पर रखा गया। डॉ. देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बैठने पर पैर हिलाते रहना चाहिए। इससे रक्तसंचार बना रहता है। पैर में रक्त थक्का होने पर इसका असर दिल तक पड़ता है। पैर के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से परहेज करना चाहिए।

बच्ची को बचाने वाले मार्शल को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : क्लस्टर बस में तैनात एक मार्शल ने निजामुद्दीन स्टेशन से अपहृत बच्ची को बचा कर अपहरणकर्ता को थाने पहुंचा दिया। बच्ची को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक युवक ले भागा था। वह बच्ची को क्लस्टर बस संख्या 728 में लेकर जा रहा था। बच्ची के रोने पर मार्शल को शक हुआ। उसने युवक से बच्ची के संबंध में पूछा जिससे अपहरण की बात सामने आई। मार्शल ने कंडक्टर के सहयोग से बदमाश पकड़ कर नजदीकी पुलिस चौकी लेकर गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहादुर मार्शल से मुलाकात कर बधाई दी। मुख्यमंत्री इन्हें सम्मानित भी करेंगे।

पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि घटना बुधवार सुबह 11 बजे की है। बस में मार्शल अरुण कुमार तैनात थे। कंडक्टर वीरेंद्र थे। पालम फ्लाईओवर से एक 18 वर्षीय युवक चार साल की बच्ची को लेकर चढ़ा। बच्ची रो रही थी। इस पर अरुण को शक हुआ। बच्ची को लिए युवक धौलाकुआं पर उतरने की कोशिश करने लगा। मार्शल ने दरवाजा बंद कर कंडक्टर की मदद से बदमाश को पकड़ बच्ची को मुक्त कराया।

एबीवीपी ने निकाला मार्च मांगा निशंक का इस्तीफा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर गुरुवार को प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने मंडी हाउस से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) कार्यालय तक मार्च निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने छात्रों को संसद मार्ग थाने के पास रोक दिया। पुलिस ने 160 छात्रों को हिरासत में लिया, जिनमें से तीन दिव्यांग व कुछ छात्राएं शामिल थीं। एबीवीपी ने एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा गठित की गई उच्चस्तरीय समिति भंग की जाए। मार्च में एबीवीपी के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव, जेएनयू इकाई अध्यक्ष दुर्गेश कुमार, इकाई मंत्री मनीष जांगिड़ भी मौजूद थे। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि छात्रावास की बढ़ाई गई फीस पूरी तरह से वापस ली जाए।

दूसरी अडीयू के छात्रों एवं शिक्षकों ने भी जेएनयू के छात्रों का समर्थन किया है। डीयू के कुछ छात्रों ने ऑर्ट्स फैकल्टी में बुधवार और गुरुवार को जेएनयू के छात्रों के समर्थन में नारेबाजी भी की। छात्रों ने कहा कि जेएनयू प्रशासन बढ़ाई गई फीस तुरंत वापस ले।

जेएनयू छात्रों के समर्थन में उतरे संजय बारू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी विश्वविद्यालय को बचाने के लिए किफायती दर पर शिक्षा जरूरी है। जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें संजय बारू यह बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। संजय बारू जेएनयू के पूर्व छात्र भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लगभग हर साल हम विदेशों में पढ़ रहे भारतीयों पर लगभग छह बिलियन डॉलर (करीब 43 हजार करोड़ रुपये) खर्च कर रहे हैं तो सरकारी विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए यहां पर छात्रों को सस्ती दर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। बारू ने कहा कि एमएचआरडी की रैंकिंग के अनुसार, सर्वश्रेष्ठ सरकारी विश्वविद्यालयों में से जेएनयू एक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यहां पर अच्छे छात्र सस्ती लागत पर अध्ययन कर सकें।

मेले में अध्यात्म

मोबाइल जैसी डिवाइस में संपूर्ण रामायण को अजय मूंधड़ा की आवाज में किया गया स्वरबद्ध, संपूर्ण रामचरित मानस का गायन 21 घंटे में होता है खत्म

पढ़िए नहीं, अब रामायण सुनिए, वह भी चलते-फिरते

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

39वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बोलती रामायण भी दर्शकों के पैरों को ठिठका देती है। दुनिया के मेले में रामायण के श्लोक सुनकर हर कोई एकबारगी उसी ओर देखने लगता है, जहां से आवाज आ रही होती है। वहां पहुंचकर जब दर्शक छोटे से डिवाइस में रामायण की रिकार्डिंग सुनते और देखते हैं तो हैरान हुए बिना नहीं रहते।

बोलती रामायण के बारे में जानने के लिए आपको हॉल संख्या-11 में जाना होगा। मोबाइल जैसी एक डिवाइस में संपूर्ण रामायण को अजय मूंधड़ा की आवाज में स्वरबद्ध किया गया है। यह डिवाइस बैटरी से भी चलती है और बिजली से भी। इसमें संपूर्ण रामचरित मानस का गायन है जो 21 घंटे में खत्म होता है। इस डिवाइस में यह भी सुविधा है कि आप रामायण का जो भी अध्याय सुनना चाहें, उसी का नंबर दबा सकते हैं। बोलती रामायण का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स में भी दर्ज है।

इस डिवाइस में तुलसी रामायण का अक्षरशः गायन और बालकांड से उत्तर कांड तक की समस्त चौपाई और दोहे संपुट सहित उपलब्ध हैं। चूंकि डिवाइस मोबाइल फोन के आकार का है लिहाजा इसके जरिये रामायण पाठ चलते-फिरते भी सुना जा सकता है और अखंड पाठ के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। व्यापार मेले में बोलती रामायण का प्रचार अभय और श्रीकांता माहेश्वरी दंपती कर रहे हैं जो पेशे से कंपनी सेक्रेट्री हैं और अपने प्रोफेशनल जीवन से कुछ समय राम नाम और रामायण के लिए निकाल रहे हैं।

अंतराष्ट्रीय व्यापार मेले के एक मंडप में बोलती रामायण के बारे में जानकारी लेतीं महिलाएं। जागरण

आकर्षण का केंद्र है 80 हजार की साड़ी : आजमगढ़ से आए कारीगर तबिश की बनाई 80 हजार की साड़ी महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस साड़ी को देखने और खरीदने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। तबिश के अनुसार इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर यह खराब हो जाती है तो इसमें इस्तेमाल की गई जरी (जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है) को निकाल कर दोबारा साड़ी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। साड़ी को जलाने के बाद इसमें इस्तेमाल की गई जरी सुरक्षित तरीके से निकल जाती है। तबिश ने बताया कि आजमगढ़ के लोगों की कारीगरी लाजवाब है, जिसका नमूना यहां देखा जा सकता है।

आठवें दिन 35 हजार लोगों ने लिया मेले का आनंद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : प्रगति मैदान में आयोजित व्यापार मेले में गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों से स्कूली छात्र भी पहुंचे। मेला आयोजक भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (आटीपीओ) के अनुसार, शाम पांच बजे तक मेले में आने वाले पर्यटकों की संख्या 33 हजार का आंकड़ा छू गई थी। इसके बाद भी मेले में लोगों का आना-जाना लगा रहा। मेले के आठवें दिन विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी रंगारंग आयोजन किया गया।

47.25 करोड़ रुपये की लागत से लेह में स्थापित होगा तिब्बती चिकित्सा पद्धति का राष्ट्रीय संस्थान। मोदी सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा-रिग्पा (एनआइएसआर) की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

चुनावी बांड

हंगामा क्यों है बरपा

चुनावी बांड को औपचारिक भ्रष्टाचार का स्रोत बताते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद में हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्षी दल इसे बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के मकसद से लाए गए चुनावी बांड पर पेश है एक नजर:

क्या है चुनावी बांड?

केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में चुनावी बांड शुरू करने का एलान किया था। चुनावी बांड का इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं और भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। नकद चंदे के रूप में दो हजार से बड़ी रकम नहीं ली जा सकती है। सरकार की दलील है कि चूंकि बांड पर दानदाता का नाम नहीं होता है, और पार्टी को भी दानदाता का नाम नहीं पता होता है। सिर्फ बैंक जानता है कि किसने किसको यह चंदा दिया है। इसका मूल मंतव्य है कि पार्टी अपनी बैलेंसशीट में चंदे की रकम को बिना दानदाता के नाम के जाहिर कर सके।

कौन ले सकता है?

एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ रुपये की कीमत में उपलब्ध इन बांडों को जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत वे राजनीतिक पार्टियां ही भुना सकती हैं, जो पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम एक फीसद वोट हासिल की होती हैं। चुनाव आयोग द्वारा सत्यापित बैंक खाते में ही इस धन को जमा किया जा सकता है।

विशेष विंडो

एक आरटीआइ के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने वित्त मंत्रालय को दो मौकों पर राज्य विधानसभा चुनावों के लिए समय से पहले बिक्री को मंजूरी देने के लिए विशेष विंडो खोलने को कहा। जबकि नियम के मुताबिक बांड की बिक्री के लिए एक विशिष्ट वार्षिक अवधि निर्धारित है।

भाजपा को मिला सबसे ज्यादा बांड

2017-18 में सबसे ज्यादा 222 करोड़ रुपये (95 फीसद) के बांड भारतीय जनता पार्टी को मिले।

2018 और 2019 को बेचे गए बांड

	2018	2019
मार्च	222	1366
अप्रैल	115	2256
मई	101	822
जुलाई	33	45
अक्टूबर	402	232
नवंबर	184	-
जनवरी	-	350

आपत्तियां

एक अन्य आरटीआइ के जवाब से पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग ने इस योजना पर आपत्तियां जताई थीं, लेकिन सरकार द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। आरबीआइ ने 30 जनवरी, 2017 को लिखे एक पत्र में कहा था कि यह योजना पारदर्शी नहीं है, मनी लांड्रिंग बिल को कमजोर करती है और वैश्विक प्रथाओं के खिलाफ है। इससे केंद्रीय बैंकिंग कानून के मूलभूत सिद्धांतों पर ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। चुनाव आयोग ने दानदाताओं के नामों को उजागर न करने और घाटे में चल रही कंपनियों (जो केवल शेल कंपनियों के स्थापित होने की संभावनाएं खोलती हैं) को बांड खरीदने की अनुमति देने को लेकर चिंता जताई थी।

कानून मंत्रालय का सुझाव

एक अन्य आरटीआइ द्वारा प्राप्त किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, कानून मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि न्यूनतम वोट शेयर की आवश्यकता या तो 6 फीसद होनी चाहिए (मान्यता प्राप्त 52 राज्य और 8 राष्ट्रीय दलों के लिए) या बिल्कुल नहीं (वर्तमान आवश्यकता 1 फीसद है)। जबकि यह स्पष्ट नहीं है कि 2,487 गैर-मान्यता प्राप्त दलों में से 1 फीसद वोट शेयर कितनों का है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि चूंकि इन बांडों को बेचने वाला भारतीय स्टेट बैंक खरीदार की पहचान जानता है, इसलिए सत्ता में सरकार आसानी से यह पता लगा सकती है कि बांड किसने और किसके लिए खरीदा है। सुप्रीम कोर्ट इन बांड की वैधता पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

चुनावी बांड को लेकर संसद में कांग्रेस ने किया हंगामा

विरोध ▶ रास की कार्यवाही स्थगित, लोकसभा में कांग्रेस का वाकआउट

कांग्रेस ने चुनावी बांड मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चुनावी बांड और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के मुद्दे पर गुरुवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई एक घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा से कांग्रेस ने वाकआउट किया। कांग्रेस का कहना था कि चुनावी चंदे की आड़ में सरकार ने भ्रष्टाचार को औपचारिक स्वरूप दे दिया है। कांग्रेस ने इसकी जेपीसी से जांच की मांग की।

संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कांग्रेसी सांसदों ने चुनावी बांड और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से इसकी अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस सांसद आसन के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

शून्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी को अपनी बात रखने की इजाजत दी। मनीष तिवारी ने सरकार पर चुनावी बांड को औपचारिक भ्रष्टाचार का स्वरूप देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें यह नहीं पता होता है कि किसने चंदा दिया और वह चंदा किसको गया। उन्होंने कहा कि चुनावी बांड के जरिये आये धन का 95 फीसद भाजपा के खाते में गया है। तिवारी के अनुसार 2017 में चुनावी बांड की व्यवस्था लोकसभा चुनाव के लिए चंदा जुटाने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन 2018 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान इसका उपयोग किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की सक्रिय भूमिका है और आरटीआइ के तहत मिला जवाब इसका ठोस सुबूत है। अध्यक्ष ने यह कहते हुए बात समाप्त कर दी कि वह खुद आरटीआइ से मिले इस सबूत को देखेंगे। बोलने की इजाजत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसदों ने सदन से वाकआउट कर दिया। बाद में प्रेस कांफ्रेंस कर मनीष तिवारी ने चुनावी बांड की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है, तब तक वह इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।

गुरुवार को संसद भवन में अंबिका सोनी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी। प्रेट्र

चुनावी बांड पर आरोपों को भाजपा ने बताया बेबुनियाद

नई दिल्ली : कांग्रेस के आरोपों को भाजपा ने सिरे से खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था का विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं, जिन्हें वर्षों से भ्रष्टाचार के पैसे से राजनीति करने की आदत पड़ गई है। जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोपों को हवा दी जा रही है, उनमें कोई दम नहीं है। वे पहले से सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं और आरटीआइ के तहत सरकार की ओर से दिए गए हैं। गोयल ने कहा, मोदी सरकार ने चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड के रूप में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इससे पहली बार भ्रष्टाचार और बदनामी से जुड़ा हुआ पैसा पार्टियों को मिलना बंद हो गया है। इससे भ्रष्टाचार के पैसे से चलने वाली पार्टियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 'सिर्फ वही लोग चुनावी बांड का विरोध कर रहे हैं, जो कालाधन में विश्वास करते हैं और जिनको आदत पड़ गई है वर्षों तक चुनाव में कालाधन इस्तेमाल करने की।'

भाजपा को चुनावी प्रणाली में ईमानदार पैसे को प्रोत्साहन देने वाली पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा, आरबीआइ और चुनाव आयोग के साथ विचार-विमर्श के बाद चुनावी बांड की प्रणाली को इस तरह बनाया गया है कि इसके गलत इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं रहे। करदाताओं को चेक के माध्यम से दलों को चंदा देने में परेशानी नहीं हो।

निर्मल गंगा मिशन के लिए सरकार ने 305 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी : शेखावत

नई दिल्ली, प्रेट्र : निर्मल गंगा अभियान एक सतत प्रक्रिया है और सरकार ने 305 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों की अनुमानित लागत 28,613.75 करोड़ रुपये से अधिक है। जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा, गंगा नदी में जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, अभी तक सरकार ने कुल 305 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इनमें से 109 पूरे हो चुके हैं। शेष विभिन्न स्तरों पर हैं। सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सरकार ने मई 2015 में 20 हजार करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम लांच किया था। इसका लक्ष्य प्रदूषण को प्रभावी तरीके से निपटना, संरक्षण और गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का पुनर्जीवन है।

जल को मौलिक अधिकार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं : भाजपा सांसद हेमा मालिनी के एक सवाल पर शेखावत ने कहा, सबको साफ पानी उपलब्ध कराने को मौलिक अधिकार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हेमा ने पूछा था कि क्या सभी के पास साफ पानी की उपलब्धता को मौलिक अधिकार बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है?

एच1-बी वीजा पर अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहा भारत : जयशंकर

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि भारत एच1-बी वीजा के मसले पर अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहा है। भारत अमेरिका को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय टैलेंट (प्रतिभाओं) का दोहन या उपयोग दोनों देशों के आपसी हित में है। जयशंकर ने कहा, 'वीजा जारी करना अन्य देशों का संप्रभु अधिकार है, लेकिन साथ ही यह आर्थिक, व्यवसायिक व सामाजिक हितों के लिए बेहद जरूरी है। हम लगातार अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी सरकार और कांग्रेस (संसद) सदस्यों के संपर्क में हैं और उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय टैलेंट का इस्तेमाल दोनों देशों के आपसी हित में है।'

विदेश मंत्री ने कहा, भारत काफी हद तक अमेरिका को यह बात समझाने में सफल भी रहा है। अगर आप एच1-बी वीजा की संख्या देखें तो पिछले कुछ साल में इनकी संख्या बढ़ी है। पिछले साल अमेरिका ने 1.79 लाख एच1-बी वीजा जारी किए थे, इनमें से 1.25 लाख (69.9 फीसद) भारतीयों को जारी किए गए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या सात प्रमुख भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को अमेरिका ने एच1-बी वीजा के लिए अयोग्य करार दे दिया है, तो जयशंकर ने कहा, किसी को अयोग्य नहीं ठहराया गया है, लेकिन पिछले दो साल में उन्हें जारी वीजा की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा, सिर्फ भारतीय कंपनियों को ही नहीं, दुनियाभर की कंपनियों के लिए जारी वीजा में कमी आई है। उक्त सातों कंपनियों को पिछले साल 3,828 नए एच1-बी वीजा जारी किए गए थे और उन्हें जारी 15,230 वीजा का नवीनीकरण किया गया था। जयशंकर ने बताया कि अमेरिका में कार्यरत लोगों के जीवनसाथियों को वहां काम करने के लिए जारी होने वाले एच4 वीजा में भारतीयों की हिस्सेदारी 93 फीसद है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी है कि यह वीजा कार्यक्रम जारी रहेगा अथवा नहीं। अमेरिकी अदालत का आदेश है कि इसे जारी रहना चाहिए, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

▶ **काफी हद तक मना पाए इसीलिए पिछले साल एच1-बी वीजा पाने वालों में 70 फीसद भारतीय थे**

शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को रास में बोलते विदेश मंत्री एस. जयशंकर। प्रेट्र

पीएम की विदेश यात्राओं के दौरान चार्टर्ड फ्लाइट्स पर 225 करोड़ खर्च : विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया कि पिछले तीन साल में पीएम की विदेश यात्राओं के दौरान चार्टर्ड फ्लाइट्स पर 225 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 2019-20 में इस मद पर किए गए खर्च का बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

पांच साल में फर्जी भर्ती एजेंसियों के खिलाफ 750 शिकायतें : मुरलीधरन ने बताया कि पिछले पांच साल में फर्जी भर्ती एजेंसियों के खिलाफ 750 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 18 नवंबर तक 1,418 लाइसेंसी भर्ती एजेंसियां सक्रिय थीं।

संसद में चर्चा के दौरान किसी ने यज्ञ कराने तो किसी ने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने का दिया सुझाव

प्रथम पृष्ठ से आगे

संसद में चर्चा के दौरान दोनों सदनों में सदस्यों की ओर से कुछ रोचक सुझाव भी आए। लोकसभा में भाजपा सदस्य सत्यपाल सिंह ने इससे निपटने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी तो राज्यसभा में सपा सदस्य जया बच्चन ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी हो गया है कि सरकार क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करे। राज्यसभा में राकांपा सदस्य वंदना चव्हाण ने कहा कि शहरों में अर्बन फॉरेस्ट की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए क्योंकि शहरों में जिस रफ्तार से लोग आ रहे हैं, उस रफ्तार से पेड़ नहीं लग रहे हैं।

चर्चा में नोकझोंक, भगवंत मान ने किया पराली जलाने का समर्थन : चर्चा के दौरान राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के पीछे जहां पराली को बड़ी वजह बताया, वहीं लोकसभा में चर्चा के दौरान भगवंत मान ने पराली जलाने की समर्थन किया। उन्होंने कहा, पंजाब-हरियाणा के किसानों के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने कभी उन्हें दूसरी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। दोनों सदनों में उनके बयान को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए। विजय गोयल समेत भाजपा सांसदों ने कहा, पराली से ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में खुद पैदा हो रहा है जिसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है।

केंद्र सरकार के विभागों में करीब सात लाख पद रिक्त

▶ **कार्मिक राज्य मंत्री ने रास को लिखित उत्तर में दी जानकारी**

▶ **वित्त वर्ष में एक लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद**

राज्यसभा में जवाब देते कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। प्रेट्र

रोजगार सृजन में कमी इस बात का संकेत है कि देश में विकास का पहिया थम गया है। निर्माण क्षेत्र में लगभग 35 लाख लोगों की नौकरी गई है। बड़ी आइटी कंपनियां भी लगभग 40 लाख नौकरियां खत्म करने जा रही हैं।
-प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस महासचिव

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले साल एक मार्च तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब सात लाख पद रिक्त थे। गुरुवार को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या 6,83,823 है। इनमें से 5,74,289 पद ग्रुप सी में रिक्त हैं। ग्रुप बी में रिक्त पदों की संख्या 89,638 तथा ग्रुप ए में 19,896 है। उन्होंने कहा, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 2019-2020 में 1,05,338 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सिंह ने बताया कि 2017-18 के दौरान रेल मंत्रालय एवं रेलवे भर्ती बोर्ड ने नई और दो साल में रिक्त होने वाले पदों के लिए ग्रुप सी तथा लेवल-1 पदों की 1,27,573 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की थी। ग्रुप सी एवं लेवल-1 पदों के लिए 1,56,138 रिक्तियों के संबंध में अन्य पांच केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना साल 2018-19 में जारी की गई। पदों से जुड़े विभागों ने भी विभिन्न ग्रेड की 19,522 रिक्तियों को भरने लिए परीक्षाओं का आयोजन किया। कुछ पदों पर एसएससी के माध्यम से भर्ती की गई। सिंह ने बताया कि एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के जरिये 4,08,591 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कई पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि कार्मिक मंत्रालय 10 मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7,782 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6,903 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 10,859 पद रिक्त थे।

सीबीआइ में एक हजार से अधिक पद खाली

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) में एक हजार से अधिक पद खाली हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि जांच एजेंसी में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 5,532 हैं। इनमें 4,503 पद भरे हुए हैं। इस तरह 1,029 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए जांच एजेंसी कदम उठा रही है। सिंह ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में सीबीआइ ने सरकारी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ 160 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें 54 मामले संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ, 50 मामले बैंकों या सार्वजनिक उपक्रमों में बोर्ड स्तर के अधिकारियों के खिलाफ और 56 मामले राजनेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं।

वक्फ बोर्ड की 17 हजार संपत्तियों पर अतिक्रमण, सबसे ज्यादा पंजाब में

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश भर में वक्फ बोर्ड की 17 हजार संपत्तियां अतिक्रमण की जद में हैं। बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्तियों पर अतिक्रमण पंजाब में हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बोर्ड की 373 संपत्तियों का अतिक्रमण हुआ है।

भाजपा सांसद अजय निषाद के सवाल का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि वक्फ बोर्ड की कुल 16,937 संपत्तियां अतिक्रमण की जद में हैं, जिनमें 5,610 सिर्फ पंजाब में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश (3,240), बंगाल (3,082), तमिलनाडु (1,335) और कर्नाटक (862) का नंबर आता है। मंत्रालय की तरफ से तैयार 24 राज्यों की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं।

नकवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रक्षा और उन्हें अतिक्रमण से बचाने के लिए खास पोर्टल विकसित किया गया है। अब तक इस पोर्टल पर 5,94,139 संपत्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। जुलाई से अक्टूबर तक चले अभियान में 98.99 फीसद रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है। वक्फ एक्ट की धारा 51 (एआइ) के तहत वक्फ संपत्तियों को बेचना, बदलना, उपहार में देना या हस्तांतरित करना प्रतिबंधित है।

रक्षा समिति में प्रज्ञा ठाकुर और फारूक अब्दुल्ला

▶ **मालेगांव की आरोपित को शामिल करने पर कांग्रेस को एतराज**

▶ **जन सुरक्षा कानून के तहत फारूक अरसे से हैं नजरबंद**

प्रज्ञा ठाकुर

फारूक अब्दुल्ला (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, प्रेट्र : मालेगांव विस्फोट में आरोपित भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और जम्मू-कश्मीर में नजरबंद पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को रक्षा मंत्रालय की 21 सदस्यीय संयुक्त सलाहकार समिति में नामित किया गया है। नई रक्षा समिति में इन दोनों नेताओं को लिए जाने से नए विवाद शुरू हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति में 12 सदस्य लोकसभा और नौ राज्यसभा के होंगे।

भोपाल से पहली बार सांसद निर्वाचित साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वर्ष 2008 के मालेगांव बम धमाके में आरोपित हैं और मौजूदा समय में वह जमानत पर बाहर हैं। गैरकानूनी गतिविधियां प्रतिबंध कानून (यूएपीए) के तहत विभिन्न आरोपों में उन पर मुकदमा चल रहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने कई विवादास्पद बयान भी दिए थे जिसमें सबसे विवादित बयान महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोंडसे को देशभक्त बताना है। दूसरी ओर, नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और तीन दफा जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके 81 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला विगत पांच अगस्त से श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने उन्हें अब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया है। उन पर विवादास्पद जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस कानून के तहत उन पर श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में जनता को भड़काने कर माहौल खराब करने में सक्षम बताया गया है। उन पर आम जनता को देश के खिलाफ भड़काने का भी आरोप है।

नड्डा, पवार, सुले भी हैं सदस्य : संसदीय मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सलाहकार समिति के अन्य सदस्यों में रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद येस्सो नाइक, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राकांपा के नेता शरद पवार भी शामिल हैं। इस समिति में तृणमूल नेता सौगत राय, द्रमुक के ए.राजा (2जी घोटाले में आरोपित रहे हैं), भाजपा के छेदी पासवान, राकांपा की सुप्रिया सुले (पुणे के जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप) भी हैं। 21 सांसदों के अलावा समिति में संसदीय मामलों के दो राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी.मुरलीधरन भी बतौर पदेन सदस्य शामिल हैं। पदेन सदस्यों के पास मताधिकार नहीं होता है।

प्रज्ञा पर कांग्रेस को आपत्ति, लेखी ने किया स्वागत : कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रज्ञा ठाकुर को समिति में शामिल किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि देश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंक का प्रसार करने आरोपित सांसद को रक्षा मामलों की समिति में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिल से माफ करने में असमर्थता जताई लेकिन उन्हें देश के रक्षा जैसे गंभीर मुद्दे की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। जबकि भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रज्ञा ठाकुर को नामित किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि आप किसी पर आरोप लगने से उसे दोषी नहीं करार दे सकते। वहीं, ट्विटर पर यूजर्स ने रक्षा समिति में प्रज्ञा ठाकुर को बतौर सदस्य नामित किए जाने पर मोदी सरकार का मजाक बनाया गया। दूसरी ओर, ट्विटर पर 'बीजेपीलाइज' हैशटैग और 'मोदी है तो मुमकिन है' हैशटैग इस्तेमाल करते हुए एक यूजर ने तंज किया है कि अब भारत कड़ी निंदा (राजनाथ सिंह) और मारक शक्ति (प्रज्ञा ठाकुर) दो भीषण मिसाइलें दाग सकेगा। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।

निशंक बोले

केंद्रीय मंत्री ने कहा, गहन विचार विमर्श के बाद तैयार होने वाली दुनिया की पहली नीति होगी, हर सुझाव पर गंभीरता से हो रहा विचार, सांसदों, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और विशेषज्ञों से भी किया जा रहा है संपर्क

नई शिक्षा नीति पर मिले हैं दो लाख से ज्यादा सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार को नई शिक्षा नीति (एनईपी) पर दो लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इन सुझावों को देखा जा रहा है और नई समग्र नीति लाने के लिए राज्यों के साथ गहन विचारविमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति विस्तृत परामर्श के बाद तैयार होने वाली दुनिया की पहली नीति होगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

संसद के ऊपरी सदन में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए निशंक ने कहा, 'के कस्तूरीरंगन द्वारा तैयार किए गए एनईपी मसौदे को लोगों की पहुंच में रखा गया है। मसौदे पर दो लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। हर सुझाव पर गंभीरता से गौर किया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि सांसद और विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के अलावा सचिवों और विशेषज्ञों से संपर्क किया जा रहा है। मसौदे में सभी सुझाव शामिल हैं। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मातृभाषा ही प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनी रहेगी।

लाभ-हानि रहित है 10वीं, 12वीं परीक्षा शुल्क में वृद्धि : एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में निशंक ने कहा कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा शुल्क में वृद्धि लाभ-हानि रहित आधार पर की है।

यूजीसी, एआइसीटीई के विलय पर अभी फैसला नहीं : एक सवाल के जवाब में निशंक ने बताया बताया कि यूजीसी और एआइसीटीई के विलय पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। पिछले साल एचआरडी मंत्री ने ट्वीट में कहा था कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग एकल नियामक होगा और यह यूजीसी और एआइसीटीई की जगह लेगा। विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक तैयार किया गया है और अक्टूबर में मंत्रिमंडल के सामने लाया जाएगा।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में नई शिक्षा नीति पर सदस्यों के सवालों का जवाब देते केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। प्रेट्र

संसद में उठी बिरसा मुंडा को भारत रत्न देने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : झारखंड विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच संसद में बिरसा मुंडा को भारत रत्न देने की मांग उठी। खास बात यह है कि यह मांग झारखंड के किसी नेता ने नहीं, बल्कि महाराष्ट्र से शिवसेना के एक लोकसभा सदस्य ने उठाई है। उन्होंने वीर सावरकर को भी भारत रत्न देने की मांग की।

शून्यकाल में पालघर के सांसद राजेंद्र गावित ने कहा, बिरसा मुंडा जैसे वीर सपूत को सम्मानित किए जाने से भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। गावित ने बताया कि किस तरह मुंडा ने कम उम्र में ही आदिवासियों के धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंका था। उन्होंने जमींदारी प्रथा और जमींदारों के खिलाफ भी आवाज उठाई। मुंडा के आंदोलन के नतीजा था कि उस समय अंग्रेज उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे थे। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा के योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से भारत रत्न का ही सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

16 प्रत्याशियों की सूची जारी की है झारखंड में भाकपा माले ने। गुरुवार को राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। कुछ सीटें दूसरे वामदल से टकराई हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 22 नवंबर 2019

'पिछड़े समाज का आरक्षण बढ़ाएंगे, बनाएंगे कमेटी'

बोले शाह ▸ कांग्रेस ने आदिवासियों से सिर्फ वोट लेने का काम किया

झारखंड के लातेहार और लोहरदगा में भाजपा अध्यक्ष की चुनावी रैली

जेएनएन, लातेहार

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में लातेहार और लोहरदगा की धरती से भाजपा के दमदार चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए राज्य की जनता से ऐसी सरकार चुनने का आह्वान किया जिसमें जंग न लगे। लोहरदगा में पिछड़ा समाज का आरक्षण बढ़ाने का वादा करते हुए शाह ने कहा, भाजपा अपने घोषणा-पत्र में इसका जिक्र करेगी। सरकार बनने के बाद कमेटी का गठन कर आरक्षण बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।

अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड निर्माण के लिए कितने ही नौजवान शहीद हुए, लेकिन कांग्रेस टस से मस नहीं हुई। अटल जी ने जब झारखंड का निर्माण किया तब राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भी निशाने पर लिया। कहा, सत्ता सुख हासिल करने को हेमंत किसके साथ बैठे हैं, जिन्होंने युवाओं पर गोलियां चलवाई। शाह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ गरीबी की बात करती है, गरीबी दूर करने की नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार गरीबी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

झारखंड के विकास, गरीबों, दलितों, आदिवासियों के लिए संकल्पित है। यह संकल्प पूरा करना है, इसलिए प्रचंड बहुमत से कमल फूल की सरकार बनाएं। देश के आदिवासियों के लिए भाजपा खुले दिल से काम कर रही है।

झारखंड के लोहरदगा में गुरुवार को भाजपा की चुनावी रैली के दौरान दैनिक जागरण अखबार पढ़ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जागरण

कांग्रेस ने अयोध्या मामले में अड़चनें पैदा कीं

लातेहार के मनिका में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, कोर्ट के फैसले से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और अब वहां आसमान छूने वाला भव्य मंदिर बनेगा। कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या मामले में अड़चनें पैदा कीं। कांग्रेस पार्टी केस ही नहीं चलने देती थी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लालच में मामले को 70 साल से लटकाए थी। लेकिन पीएम मोदी ने इस कलंक को हटा कश्मीर के विकास के रास्ते खोल दिए हैं।

प्रकाश जावडेकर के बयान की होगी जांच, आयोग ने मांगा वीडियो

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

राज्य ब्यूरो, रांची

प्रकाश जावडेकर। फाइल

- केंद्रीय मंत्री ने की थी भारतीय वन कानून में संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा
- आयोग ने दोहराया, झारखंड के 19 जिले अब भी नक्सल प्रभावित
- इनमें से 13 जिले अति नक्सल प्रभावित

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन कानून, 1927 में संशोधन प्रस्ताव वापस लेने संबंधित बयान की जांच होगी। एक राजनीतिक दल द्वारा इससे आचार संहिता का उल्लंघन होने की शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित बयान का वीडियो मंगाकर आयोग के समक्ष रखने का आदेश दिया है, ताकि उसकी जांच हो सके। रांची में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने इस संबंध में आयोग के पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के समय अपने उस कथन को दोहराया कि झारखंड में अभी भी 24 में से 19 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें से 13 अति नक्सल प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना में ही इसका स्पष्ट उल्लेख है। यहां तक कि केंद्र ने नक्सल समस्या से निपटने के लिए स्वीकृत 775 करोड़ रुपये में झारखंड को ही 340 करोड़ रुपये विशेष सहायता राशि के रुप में दिए हैं। राज्य सरकार के नक्सल समस्या से मुक्ति के दावे के सवाल पर उन्होंने कहा कि उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई बैठक में मिले फीडबैक से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। उसमें तो यह भी बात आई है कि नक्सली चुनाव में बाधा डालने के लिए कई नए साधन अपना सकते हैं। फिलहाल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।

बहाली निकालने पर हिंदुस्तान कॉपर के अफसर तलब : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 47 पदों पर बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन की शिकायत मिलने पर इस लोक उपक्रम के अफसरों को तलब किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि दिल्ली जाकर वे इसकी जांच करेंगे कि बहाली निकालने के लिए आयोग से अनुमति ली गई थी या नहीं? इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश आयोग के पदाधिकारियों को दिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठिए द्वारा फर्जी मतदान की एक राजनीतिक दल आशंका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि जो मतदाता योग्य हैं, वही वोट दे पाएंगे।

अनिवार्य सेवा देने वाले कर्मियों के लिए भी पोस्टल बैलेट

राज्य ब्यूरो, रांची : आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से अनिवार्य सेवा देनेवाले कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा बहाल की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रांची में गुरुवार को कहा कि इसे लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि कौन-कौन सी सेवाएं अनिवार्य श्रेणी में आएंगी। आयोग ने पहली बार झारखंड विधानसभा चुनाव से दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए यह सुविधा बहाल की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी सात विधानसभा क्षेत्रों बोकारो, धनबाद, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा तथा राजमहल में ही इसे लागू किया गया है।

टीएन शेषन की स्मृति में विजिटिंग चेयर : भारत निर्वाचन आयोग के अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन की स्मृति में निर्वाचन अध्ययनों के प्रति अंतर अनुशासनिक एप्रोच पर एक विजिटिंग चेयर स्थापित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालास्वामी को इस चेयर की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी तथा यह अगस्त-सितंबर 2020 तक अस्तित्व में आ जाएगा।

पूर्व मंत्री लालचंद को डूमरी, संजय को रांची से जदयू का टिकट

राज्य ब्यूरो, रांची : विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपने दस अन्य उम्मीदवारों की घोषणा गुरुवार को कर दी। इसके तहत पूर्व मंत्री लालचंद महतो को डुमरी से टिकट दिया गया है। संजय सहाय को रांची से उम्मीदवार बनाया गया है। इधर, हटिया से एनुल हक को टिकट देने से नाराज पार्टी महासचिव भगवान सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। एनुल हक ने गुरुवार को ही जहां नामांकन कर दिया, वहीं भगवान सिंह ने भी पार्टी के नाम से नामांकन पत्र खरीद लिया है। सिंह ने कहा है कि वे काफी पहले से ही चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया।

प्रचार से प्रियंका का इन्कार, राहुल जाएंगे विदेश

आशीष झा, रांची

- उम्मीदवारों की मांग पर स्टार प्रचारकों की दूसरी सूची में प्रियंका भी शामिल
- अब सोनिया गांधी ने भरोसा दिया, एक बार जरूर आएंगी चुनाव के दौरान

झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए तैयार स्टार प्रचारकों की सूची में उम्मीदवारों की मांग पर प्रियंका गांधी का नाम भी जोड़ा गया है लेकिन उनकी ओर से साफ तौर पर झारखंड आने से इन्कार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के विदेश जाने की तिथि भी तय होने की सूचना है जिसके बाद हताश कांग्रेसियों के लिए सोनिया गांधी ने एक बार प्रचार के लिए आने पर हामी भर दी है। पहले स्वास्थ्य कारणों से उनके चुनाव प्रचार से दूर रहने की बात कही जा रही थी लेकिन गांधी परिवार की मौजूदगी के नाम पर वे आएंगी। सूत्रों के अनुसार पूरे चुनाव में वे सिर्फ एक बार ही आएंगी। इसकी तारीख तय की जा रही है। स्टार प्रचारकों की दूसरी सूची में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, सचिन पायलट, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद समेत कई और नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में जोड़ दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर झारखंड आने से मना कर दिया है। संभवतः उनसे इस मुद्दे पर आगे बात भी नहीं होगी। सोनिया, मनमोहन और राहुल के बाद चौथे नंबर पर उनका नाम है। दूसरी ओर, राहुल गांधी इसी दौरान विदेश यात्रा पर जानेवाले हैं। इस कारण उनके आने की संभावना भी कम है। हालांकि कुछ कांग्रेस नेताओं के अनुसार विदेश जाने से तीन-चार दिन पहले अगले महीने की 10 तारीख के आसपास वे एक तारीख दे सकते हैं। इस बीच, सोनिया गांधी के आने की सूचना से कांग्रेसी खुश दिख रहे हैं। दूसरे चरण के अंत या तीसरे चरण में उनका आगमन होने की संभावना है।

एक दर्जन से अधिक नेता-मंत्री झारखंड में उतरे : कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पंजाब और राजस्थान के एक दर्जन से अधिक नेता और मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। पूरा कार्यक्रम माइक्रो लेवल पर चल रहा है और एक प्रखंड अथवा एक विधानसभा क्षेत्र में रहकर ये नेता किसी प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका के नहीं आने की संभावनाओं के बीच कांग्रेसियों के मन में यह बात घर करती दिख रही है कि हरियाणा की तरह झारखंड में भी पार्टी सत्ता के मुहाने पर ना अटक जाए।

कभी मतदान से डरते थे ग्रामीण और नेता, अब खूब होता है प्रचार

जुलकर नैन, चतरा

सुदूरवर्ती जंगलों के बीच बसे चतरा (झारखंड) के कुंदा प्रखंड का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका है। जहां कभी दहशतगर्दी के साए में वोट बहिष्कार का डंका बजता था, आज उसी धरती की हसीन वादियों में झारखंड व बिहार की ताल पर चुनाव के मधुर तराने गूंज रहे हैं। चहुंओर चुनाव प्रचार का खुमार है। पिछले तीन दशक तक इंसानी रक्त से रंजित यह धरती मानवता की रक्षा का त्राहिमाम संदेश दे रही थी। जनसंवाद की दुहाई देने वालों के हाथों नागरिक आजादी के कत्लेआम से जनतंत्र तार-तार था। माओवादियों ने इसे अपने सुरक्षित जोन में तब्दील कर रखा था। हालात के मद्देनजर लोग इसे उग्रवाद का जाफना कहने लगे थे। समय ने पलटी खाया और बदल गए कुंदा के हालात। माथे पर लगा उग्रवाद का कलंक लगभग मिट चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां इसकी गवाही दे रही हैं। चहुंओर उत्साह का आलम है। प्रशासन जनसहयोग से वोट प्रतिशत बढ़ाने, शांति और सुविधा पूर्ण मतदान कराने में जुटा है। जबकि चुनावी समर के योद्धा मतदाताओं को रिझाने में।

चुनाव प्रचार के संगीत ने मतदाताओं को चुनाव की खुमारी में डुबो दिया है। नागपुरी और भोजपुरी गीतों को प्रचार का माध्यम बनाया गया है। वोटरों के मन में अब नक्सल का भय नहीं है। कुंदा पंचायत की मुखिया रेखा देवी के पति लवकुश कुमार गुप्ता कहते हैं- मतदाता खुलकर अपने मतों का प्रयोग करते हैं। लवकुश गुप्ता कहते हैं कि 2000 के विस चुनाव में माओवादियों के बहिष्कार के बावजूद वोट किया था। दूसरे दिन ही उसका परिणाम मिल गया। माओवादियों के दस्ता ने उनके घर पर धावा बोल दिया और परिवार के सभी सदस्यों को बाहर निकाल कर ताला लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपने साथ ले गए। जन अदालत के बाद मामले का हल निकला।

छग में भाजपा सांसदों के निवास व कार्यालय पर ढोल बजाएगी कांग्रेस

नईदुनिया, रायपुर

- धान के मुद्दे पर टूटा सब्र का बांध, फिर से आंदोलन की राह पर

धान खरीद के मुद्दे पर कांग्रेस शुक्रवार से प्रदेश के भाजपा सांसदों के निवास और कार्यालय का घेराव करके ढोल-नगाड़ा बजाएगी। भाजपा के एक-एक सासंद के खिलाफ अलग-अलग तिथियों में तीन से चार बार कांग्रेस का यह प्रदर्शन होगा।

केंद्र सरकार ने उन राज्यों का चावल केंद्रीय पूल में लेने से मना कर दिया है, जो समर्थन मूल्य के साथ किसानों को धान पर बोनस देंगे। यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की सड़कों से लेकर दिल्ली के दोनों सदन तक में गूंज चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चार पत्रों के बाद भी प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस आंदोलन की राह पर निकल पड़ी है। पार्टी ने पूर्व निर्धारित आंदोलन की नीति बदल दी है, पहले मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ दिल्ली कूच करने और वहां धरना देने का निर्णय लिया गया था। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री गिरिश देवांगन ने जिला व शहर कमेटियों को जिम्मदारी दी है कि वे ब्लॉक कमेटियों का अलग-अलग समूह बनाकर अलग-अलग तिथियों पर घेराव-प्रदर्शन करें, क्योंकि किसी लोकसभा क्षेत्र में दो तो किसी में तीन या चार जिले आते हैं।

'भाजपा सांसदों ने सदन में की किसान विरोधी बात की' : प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री देवांगन का कहना है कि कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा सदस्यों ने दोनों सदनों में केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ का चावल लेने की मांग की है, लेकिन भाजपा के छत्तीसगढ़ के सांसदों ने किसान विरोधी चर्चा की है। उन्होंने 25 सौ पये में धान खरीदने का विरोध किया है।

सरकार गठन के बाद एक्शन मोड में आए सीएम मनोहर लाल

विजेंद्र बंसल, नई दिल्ली : हरियाणा में नई सरकार गठित होने के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में आ गए हैं। केंद्र सरकार के साथ हरियाणा के लंबित मामलों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री गुरुवार सायं नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के कई मामलों के निपटारे के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की।

कुरुक्षेत्र के इस्माईलाबाद से नारनौल तक एक्सप्रेस वे के लिए जींद और दादरी जिला में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर दोनों जिलों के किसान आंदोलनरत हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों जिलों के किसानों की नितिन गडकरी के साथ मुलाकात हुई थी मगर अभी तक यह मामला सुलझा नहीं है। किसान अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं ।गडकरी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि अब यह विवाद खत्म हो जाएगा।

बढ़ी तनातनी : धनखड़ ने कहा-राज्य का अंपायर हूं, गेंदबाज नहीं

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता सरकार पर साधा निशाना
- मंत्रियों को दी नसीहत, बॉस को खुश करने के लिए मुझ पर न करें प्रतिक्रिया
- कहा, मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ बयानबाजी के लिए नियुक्त कर दें एक विशेष मंत्री

बंगाल सरकार व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को राज्यपाल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनके मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। हालिया तनातनी पर टिप्पणी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि क्रिकेट टीम की तरह एक-एक करके जिस तरह राज्य सरकार मेरे खिलाफ बोलने के लिए बल्लेबाज उतार रही है, ऐसे में मैं कह देना चाहता हूं कि मैं गेंदबाज नहीं, बल्कि इस राज्य का अंपायर हूं। उनका इशारा राज्य के मंत्रियों की ओर था जो आए दिन उनके खिलाफ टिप्पणी करते हैं। राज्यपाल ने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपनी बॉस (ममता बनर्जी) को खुश करने के लिए उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने विभागों के काम पर ध्यान दें। स्पष्ट कहा कि उनके बयानों पर या तो मुख्यमंत्री खुद प्रतिक्रिया दें या फिर इस काम के लिए एक विभाग बनाकर विशेष मंत्री की नियुक्ति कर दें, जिससे अन्य मंत्री अपने विभागीय कार्यों को ठीक से कर सकें। राज्यपाल ने कहा, मैं मुख्यमंत्री के साथ किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार हूं, वो आएं तो सही। लेकिन, जिस तरीके से राज्य के अन्य मंत्री टिप्पणी करते हैं वह सही नहीं है।

जगदीप धनखड़ फाइल फोटो

राज्यपाल गुरुवार को पत्नी सुदेश धनखड़ संग सुबह की सैर पर कोलकाता के रवींद्र सरोवर पहुंचे थे जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य पर निशाना साधा। कहा, 'मैंने सुना है कि बहन चंद्रिमा मेरी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया कर रही हैं। मैं उनसे आग्रह करुंगा कि वह अपने विभाग पर ध्यान दें क्योंकि हम सब लोग उनके विभाग की असल हालत से अवगत हैं। उनके विभाग में ही गंभीर समस्याएं हैं।'

नहीं दिया था हेलीकॉप्टर : बता दें कि राज्यपाल का यह बयान तब सामने आया है जब एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद जाने के दौरान उन्हें तृणमूल कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। राज्यपाल ने याद दिलाया कि उन्होंने मुर्शिदाबाद जाने के लिए राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर मांगा था लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, असल में राज्य सरकार मेरी आवाजाही को नियंत्रित करना चाहती है लेकिन, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं यह मेरी संवैधानिक सीमाओं के दायरे में है। दूसरे लोग मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं।

एनआरसी को लेकर प्रशांत किशोर के ट्वीट पर बिफरे गिरिराज

राज्य ब्यूरो, पटना : राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर द्वारा किए गए ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तल्ख टिप्पणी की है। गुरुवार को यह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रही। केंद्रीय मंत्री ने सीधे-सीधे प्रशांत किशोर के ट्वीट पर पलटवार करते हुए यह सवाल किया कि आखिर अवैध से इतना प्रेम क्यों? विदित हो कि पूरे देश में एनआरसी लागू किए जाने के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने बुधवार को यह ट्वीट किया था कि पंद्रह से अधिक राज्यों में गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं और ये ऐसे राज्य हैं जहां देश की 55 फीसद से अधिक आबादी है। आश्चर्य यह है कि उनमें से कितने लोगों से एनआरसी पर विमर्श किया गया और कितने राज्य इसे लागू करने को तैयार हैं। इस ट्वीट पर गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा कि अमित शाह जब बोलते हैं तो कई लोगों को बुरा लगता है। कोई कहता है कि हम अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। इसमें सहमति और आम सहमति का क्या सवाल है? एनआरसी के माध्यम से तो उन्हें निकाला जाएगा, जो अवैध हैं।

ओडिशा विधानसभा में हंगामा

सदन में मंत्रियों के अनुपस्थित रहने पर गुरुवार को कांग्रेस विधायकों ने ओडिशा विधानसभा में जमकर हंगामा किया। कुछ विधायक वेल में घुस आए और कुर्सी पर चढ़कर स्पीकर सूर्य नारायण पात्रा के आसन तक पहुंच गए और पेपर खींचने की कोशिश की। उनका कहना था कि मंत्री सदन में उपस्थित नही रहते हैं, जिससे सवालों का जवाब नही मिल पाता। प्रेट्र

केरल विधानसभा में कांग्रेस के चार विधायकों पर प्रतिबंध

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन ने कांग्रेस के चार विधायकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चारों विधायक स्पीकर के डायस पर चढ़ गए और नारे लगाए। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के इस कदम को नियम भंग करना और सदन की मर्यादा पर आघात माना है। विपक्षी पार्टी ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को विधानसभा कार्यवाही का बहिष्कार किया।

जिन विधायकों को प्रतिबंधित किया गया है उनमें रोजी एम. जॉन, आइसी बलाकृष्णन, अनवर सादत और एलडोसे कुन्नापल्ली शामिल हैं। ये सभी पुलिस लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के मंच पर चढ़े थे। लाठीचार्ज में पलक्कड़ के विधायक शफी परांबिल और केरल छात्र संघ के कार्यकर्ता घायल हो गए थे।

गुरुवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष अपनी मांग पर अड़ गया। विपक्ष ने विधायक और छात्र संघ के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। इसके साथ ही विपक्ष मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन से जवाब चाहता था। मांग ठुकरा दिए जाने के बाद विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया।

सियासी जंग

राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी सरकार की खामियां गिनाने का कोई मौका चूक नहीं रहे हैं

दोतरफा लड़ाई से बंगाल में बनेंगे नए समीकरण

आनन्द राय, कोलकाता

- तृणमूल और भाजपा की लड़ाई में ओवैसी के आने से पारा चढ़ा
- मुस्लिम मतों के बिखराव के संकेत से ममता की बढ़ी नाराजगी

बंगाल विधानसभा का चुनाव 2021 में होना है लेकिन राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस राज्य में अपनी तीसरी पारी खेलने के लिए बिसात बिछा रही है जबकि लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे चुकी भाजपा उसकी राह रोकने में जुट गई है। सत्ताधारी तृणमूल और भाजपा की लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुसलमीन (एआइएमआइएम) ने तड़का लगा दिया है। तीन तरफ से शुरू हुई यह रार मिशन 2021 की बुनियाद बन रही है। उधर, राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी सरकार की खामियां गिनाने का कोई मौका चूक नहीं रहे हैं।

तृणमूल प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखे तीरों की बौछार के साथ ही ओवैसी को भाजपा की बी टीम और दलाल कहकर दोहरा मोर्चा खोल दिया है। यह दोतरफा लड़ाई नए समीकरण की बुनियाद बन रही है। दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, वीरभूम, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर समेत कुछ इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। ओवैसी की पार्टी ने बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है। जाहिर है कि इससे तृणमूल के जनाधार में सेंधमारी होगी। ओवैसी का बंगाल में भले कोई जनाधार नहीं है लेकिन सभी सीटों पर चुनाव लड़कर वह वोटों के बिखराव का सबब बनेंगे। दो बार सत्ता हासिल करने में मुस्लिम मतदाता ममता के सहयोगी रहे हैं।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का मुद्दा तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से ही टकराव का अहम बिंदु बना हुआ है। भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह एक अक्टूबर के कोलकाता दौरे में एनआरसी को लेकर अपना रुख साफ कर गए थे। गत दिवस उन्होंने राज्यसभा में पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही तो ममता ने यह कहने में तनिक भी देर नहीं लगाई कि वह बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। ममता ने इस तेवर से एक खास वर्ग को साधने की मुहिम शुरू की है। दूसरी तरफ हिंदू चरमपंथी और मुस्लिम अतिवाद का मुद्दा उठाकर वह लोकसभा चुनाव में हुई क्षति की भरपाई करने की कोशिश भी कर रही हैं। ध्यान रहे कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता ने जय श्रीराम के नारे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उसका उन्हें कुछ खास लाभ नहीं मिला था। इसीलिए अब उन्होंने हिंदू चरमपंथियों के साथ मुस्लिम अतिवाद पर तेवर दिखाकर बात बराबर करने की पहल की है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 18 सीटों पर विजयश्री हासिल कर चुकी है। अगर ओवैसी का पश्चिम बंगाल में उभार हुआ तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा।

ममता बनर्जी

अमित शाह

असदुद्दीन ओवैसी (सभी फाइल फोटो)

किसी पार्टी से समझौता नहीं, अकेले लड़ेंगे चुनाव : अखिलेश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

अखिलेश यादव फाइल

सपा अध्यक्ष ने चाचा शिवपाल पर किया टाल मटोल, भाजपा पर चलाए सियासी तीर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। किसी भी दल से समझौता न करने की बात कहते हुए चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) को भी दो टूक जवाब दिया। हालांकि, उन्होंने प्रसपा के समाजवादी पार्टी में विलय के सवाल को यह कहकर टाल दिया कि बाद में बात करेंगे। उन्होंने भाजपा पर भी सियासी तीर चलाए।

विधायक विजमा यादव की बेटी के विवाह समारोह में आए अखिलेश ने विजमा और उनकी बेटी को बधाई दी। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। कहा कि भाजपा की सरकारें लोगों को डराकर, एक-दूसरे में नफरत फैलाकर राजनीति करना चाहती हैं। भाजपा लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतीकरण कर रही है। पत्रकारों से खुद ही सवाल पूछा कि प्रदेश में सड़कें गड्ढामुक्त हो पाई क्या? नौजवानों को नौकरी नहीं मिल सकी। बैंकों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने इलाहाबाद बैंक का अस्तित्व खत्म किए जाने का प्रश्न भी उठाया। कहा कि देश और प्रदेश में मंदी है और इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि पहले सरकारों को यह बताना चाहिए कि कितने नौजवानों को नौकरी दी, कितने किसान खुशहाल हुए और किसानों का धान सरकार कब खरीदेगी। चुनाव के बाबत कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अभी से ही प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

28 नवंबर को को तीन घंटे वृंदावन के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस दौरान वह सेवाश्रम में शारदा ब्लॉक का शुभारंभ भी करेंगे।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के छह सदस्य पांच एकड़ जमीन लेने के पक्ष में

होगा फैसला ▸ 26 को होगी बोर्ड की बैठक

पुनर्विचार याचिका दाखिल करने व पांच एकड़ जमीन न लेने के समर्थन में सिर्फ दो सदस्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सुन्नी वक्फ बोर्ड की 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में अयोध्या में पांच एकड़ जमीन लेने का फैसला पास हो सकता है, क्योंकि अध्यक्ष जुफर फारुकी सहित बोर्ड के छह सदस्य जमीन लेने के पक्ष में हैं। बोर्ड बैठक से पहले केवल दो सदस्य पांच एकड़ जमीन न लेने के समर्थन में सामने आए हैं। यह सदस्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के भी पक्ष में हैं।

दरअसल, सुन्नी वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष जुफर फारुकी सहित कुल आठ सदस्य हैं। इनमें विधायक अबरार अहमद, मुहम्मद जुनैद सिद्दीकी, अधिवक्ता अब्दुल रज्जाक खान, अधिवक्ता इमरान महमूद खान, मौलाना सैयद अहमद अली उर्फ खुशनूद मियां, अदनान फारूख शाह व मुहम्मद जुनीद शामिल हैं।

इनमें से दो सदस्य अब्दुल रज्जाक खान व इमरान महमूद खान शुरुआत से इस मसले पर अध्यक्ष जुफर फारुकी के खिलाफ हैं। अब्दुल रज्जाक खान कहते हैं कि 26 नवंबर की बैठक में वे पांच एकड़ जमीन न लेने व पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात रखेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं जानता हूं कि बोर्ड में अध्यक्ष का बहुमत है, इसके बावजूद बैठक में अपनी बात रखूंगा।'

वहीं, चार सदस्य अबरार अहमद, अदनान फारूख शाह, मुहम्मद जुनीद व मुहम्मद जुनैद सिद्दीकी अध्यक्ष के समर्थन में हैं। ऐसे में बहुमत अध्यक्ष की तरफ ही है। जुफर फारुकी कहते हैं कि बोर्ड के सभी सदस्यों को बैठक का पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने गुरुवार को फिर कहा, 'सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती है। हम किसी भी तरह की पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे। 26 नवंबर की बैठक में पांच एकड़ जमीन लेने या न लेने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें जो भी निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा।'

पुनर्विचार याचिका के पक्ष में नहीं है महमूद मदनी गुट

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद का महमूद मदनी गुट पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के पक्ष में नहीं है। गुट ने रणनीतिक दूरी बनाते हुए इसे अहितकर बताया है और याचिका की वकालत करने वालों को नुकसान होने की आशंका से सचेत भी किया है। हालांकि, स्पष्ट किया है कि वह याचिका दायर करने के विभिन्न संगठनों के फैसले का विरोध भी नहीं करेगी।

जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी गुट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लेने के बाद महमूद मदनी गुट पर दबाव था कि वह भी अपना रुख स्पष्ट करे। बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाजी महबूब के खुलकर सामने आने से यह दबाव और बढ़ गया था।

वैसे, महमूद मदनी के करीबी बताते हैं कि वह पुनर्विचार याचिका के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए इस पर आम राय बनाने को लेकर लखनऊ में हुई विभिन्न मुस्लिम संगठनों की बैठक को बीच में छोड़कर चले गए थे। हालांकि, सवाल अपने समर्थकों को स्पष्ट संदेश देने का था तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक में बीच का रास्ता चुनना तय हुआ। वहीं, बुधवार को आइटीओ स्थित जमीयत के मुख्यालय में हुई बैठक में काफी गहमागहमी रही। बैठक में आए देशभर के कार्यकारिणी सदस्यों व वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच मैराथन बैठक हुई। आखिरकार रणनीतिक रूप से न तो पुनर्विचार याचिका का समर्थन करने और न ही विरोध करने का फैसला लिया गया। गुरुवार को जारी बयान में जमीयत ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बदले अयोध्या में पांच एकड़ जमीन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

अयोध्यावासी बने सारथी, नाचे राम बराती

▸ गाजेबाजे और फूलों की बरसात के बीच रथ पर सवार होकर जनकपुर निकले राम

▸ फैसले के बाद पूरी चटखी से बिखरा सीता-राम विवाहोत्सव का उल्लास

जागरण संवाददाता, अयोध्या

विहिप के स्थानीय मुख्यालय कारसेवकपुरम से गुरुवार को जनकपुर के लिए राम बरात धूमधाम से रवाना हुई। गाजे-बाजे और फूलों की बरसात के बीच विहिप के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेशचंद्र ने बरात को भगवा ध्वज दिखाया।

प्रत्येक पांच वर्ष पर निकाली जाने वाली बरात की छटा इस बार निराली दिखी। रामलला के हक में सुप्रीम फैसला आने का उत्साह भी झलका। यही कारण था, पूर्व की तुलना में बरातियों की संख्या दोगुनी तक जा पहुंची। वहीं, कारसेवकपुरम में बरात रवाना करने के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा।

बरात में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के स्वरूप सहित राजा दशरथ के रूप में संत समिति के अध्यक्ष कन्हैयादास रामायणी, वशिष्ठ के रूप में महंत वैष्णवदास एवं विश्वामित्र के रूप में डॉ. रामेश्वरदास, विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज के अलावा दो सौ के करीब संत एवं श्रद्धालु शामिल हुए। बरात के केंद्र में रथ की शक्ल में मिनी ट्रक रही, जिस पर भगवान राम सहित चारो भाइयों के स्वरूप आरूढ़ हुए। जबकि अन्य दर्जन भर वाहनों पर संत एवं श्रद्धालु बराती के रूप में सवार होकर रवाना हुए।

कारसेवकपुरम से करीब दो सौ मीटर के फासले पर मणिरामदासजी की छावनी के सामने रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास ने अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ बरात का अभिनंदन किया। बरात आजमगढ़, बक्सर, पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा होती हुई बरात मटिहानी के रास्ते 27 नवंबर को नेपाल की सीमा में प्रवेश करेगी। 28 नवंबर को शाम राम बरात जनकपुर पहुंचेगी। वहीं, 29 नवंबर को सुबह 10 बजे जनकपुर के दशरथ मंदिर प्रांगण में बरात का स्वागत प्रस्तावित है। जहां, दोपहर तिलकोत्सव की रस्म निभेगी। 30 नवंबर को मारवाड़ी सेवा समिति- जनकपुर की ओर से कन्या पूजन किया जाएगा। एक दिसंबर को शाम जनकपुर के सुप्रसिद्ध जानकी मंदिर में धनुष यज्ञ-जयमाल के प्रसंग का मंचन, बरात का नगर भ्रमण एवं पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होगा। दो दिसंबर को राम कलेवा की रस्म के साथ अभावग्रस्त कन्याओं का सामूहिक विवाह संयोजित है। तीन दिसंबर को बरात वापस होगी और मोतिहारी, गोपालगंज, कुशीनगर होती हुई चार दिसंबर को अयोध्या लौटेगी।

कारसेवकपुरम से जनकपुर के लिए निकली रामबरात में बस पर सवार साधु-संत। जागरण

आइए कल्पवास कीजिए, चूल्हे तैयार हैं

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज : संगम की रेती की अद्भुत महिमा है। बिना चिट्ठी-पत्री के ही सबको खबर हो गई है कि माघ मेला लगने वाला है। गांव-गिरांव में कल्पवासी ताना-बाना बुनने लगे हैं तो प्रशासन उनके लिए संगम क्षेत्र में पांटून पुल, टेंट नगरी सहित अन्य व्यवस्थाएं करने में जुट गया है। कल्पवासियों का कल्पवास पूरी सुचिता और शुद्धता के साथ पूर्ण हो, इसके लिए दारागंज में गंगा किनारे की बस्ती में मिट्टी के चूल्हे तैयार कर रहीं महिलाएं कह रही हैं कि आइए कल्पवास कीजिए, चूल्हे तैयार हैं।

तंबुओं के नगर में एक माह कल्पवास करने वालों के टेंट में वैसे तो गैस सिलिंडर के प्रयोग होने लगे हैं, मगर अब भी ऐसे कल्पवासी और साधु-संत हैं, जो मिट्टी के चूल्हे पर बना भोजन ही ग्रहण करते हैं। संत स्वामीनाथ कहते हैं कि कल्पवास में शुद्धता को पहली प्राथमिकता माना जाता है। इसके लिए मिट्टी के बने चूल्हे और गोबर के बने उपले शुद्धता की कसौटी पर खरे माने जाते हैं। यह बात वर्षों से गंगा तट पर मिट्टी का चूल्हा तैयार करने वाली इन महिलाओं को भलीभांति पता है। लगभग 60 वर्ष से चूल्हा और गोरसी (अंगीठी जैसा) बनाने वाली कोमल निषाद कहती हैं कि वह अब भी रोज 40-50 चूल्हे बना लेती हैं। इस साल वह तीन हजार चूल्हे बनाएंगी।

राम वनगमन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाएगी छग सरकार

▸ पहले चरण में 51 शोध स्थलों में से आठ स्थलों का किया जाएगा विकास

▸ माता कौशल्या के मंदिर से होगी शुरुआत, भूपेश मंत्रिमंडल में हुआ फैसला

नईदुनिया, रायपुर

वनवास काल में भगवान राम छत्तीसगढ़ के जिन स्थानों से गुजरे, उन चिह्नित 51 स्थलों में से अभी पहले चरण में आठ स्थलों का विकास किया जाएगा। गुरुवार को भूपेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना पर मुहर लगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि विकास कार्यों की शुरुआत राम के ननिहाल चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर से होगी। राज्य सरकार राम वनगमन मार्ग के स्थलों को विकसित करने का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फलक पर इन्हें पहचान दिलाना है।

विधानसभा भवन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राम वनगमन मार्ग के स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव आया। इस पर यह निर्णय लिया गया है कि चरणबद्ध तरीके से चिह्नित स्थलों का विकास किया जाएगा। सरकार ने मन्नूलाल यदु की 'दंडकारण्य रामायण' और डॉ. हेमू यदु की 'छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ' किताब को आधार माना है कि वनवास काल में राम ने 14 में से 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए थे। इन्हीं शोध किताबों के अनुसार राम ने प्रदेश के 75 स्थलों का भ्रमण किया, लेकिन 51 स्थलों पर ककर उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। जहां राम रुके थे, उन्हीं स्थलों को विकसित करने के लिए सूची बनाई गई है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं से भी राशि लेने का प्रयास करेगी।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार के रामायण सर्किट में केवल जगदलपुर को स्थान दिया गया है, लेकिन मान्यता यह है कि वनवास के 14 वर्षों में से 10 वर्ष भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में ही गुजारे थे।

भूपेश बघेल। फाइल

पहले चरण में इन स्थलों का होगा विकास

जिला	स्थल
कोरिया	सीतामढ़ी हरचौका
सरगुजा	रामगढ़
जांजगीर चांपा	शिवरीनारायण
बलौदाबाजार भाटापारा	तुरतुरिया
रायपुर	चंदखुरी
गरियाबंद	राजिम
धमतरी	सिहावा (सप्त ऋषि आश्रम)
बस्तर	जगदलपुर

राम मंदिर निर्माण में अब कोई बाधा नहीं : कल्याण सिंह

जागरण संवाददाता, बदायूं

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का गहरा नाता रहा है। शुक्रवार को बदायूं आगमन पर अयोध्या फैसले को लेकर बातचीत हुई तो बोले कि राम मंदिर निर्माण में अब कोई बाधा नहीं है।

एक निजी कार्यक्रम में शमिल होने के लिए गुरुवार शाम शहर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसमावेशी फैसला सुनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। सर्वोच्च अदालत का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदुस्तान के सभी वर्गों ने फैसले को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, फैसला आने के बाद पूरे देश में कहीं कोई विवाद या संघर्ष नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि फैसला पूरी तरह से सही है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने के संकेतों के बारे में पूछे जाने पर कल्याण सिंह ने कहा, पांच सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा सर्व सम्मति से इस बारे में फैसला दिया गया है। अतः इस बारे में चर्चा का अब कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाकर अयोध्या में मंदिर का निर्माण कराएगी और वित्तीय प्रबंधन भी देखेगी। उल्लेखनीय है कि कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में मंदिर आंदोलन चरम पर था। उन्हीं के कार्यकाल में कारसेवकों ने अयोध्या में सबसे बड़ा आंदोलन किया था। ढांचा ध्वंस के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

कल्याण सिंह। फाइल

▸ बोले-सर्वसमावेशी फैसला सुनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया

▸ हिंदुस्तान के सभी वर्गों ने फैसले को स्वीकार किया है

रामलला को मिलेगी फैसले की प्रति

जागरण संवाददाता, अयोध्या : देश का सबसे बड़ा फैसला जिन रामलला के हक में आया हैं, उन्हें इस फैसले की प्रति भी सौंपी जाएगी। रामलला को यह प्रति सौंपने दिल्ली से वही दिग्गज अधिवक्ता आ रहे हैं, जिनकी प्रखर-प्रभावी पैरवी से यह फैसला संभव हुआ है। न्यायिक मान्यता है कि जिसके हक में फैसला आया, उस तक फैसले की समुचित जानकारी पहुंचाई जाए। हालांकि रामलला स्थूल रूप से हमारे बीच नहीं हैं, इसके बावजूद आस्था की दृष्टि से वह जहां करोड़ों भक्तों के लिए सनातन-शाश्वत हैं, वहीं अदालत ने भी उन्हें जीते-जागते अस्तित्व के रूप में मान्यता दी। अदालत में रामलला के सखा की अवधारणा भी रामलला की चैतन्यता की परिचायक है। इस विश्वास के साथ कि रामलला अस्तित्वगत हैं, किंतु वे नाबालिग हैं और उनकी चिंता के लिए पूर्ण स्वस्थ-सयाने शुभचिंतक की स्वाभाविक तौर पर जरूरत है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि दिल्ली से आ रहे अधिवक्ताओं का दल शनिवार को फैसले की प्रति सौंपेगा या रविवार को पर इतना तय है कि दो दिवसीय प्रवास के दौरान अधिवक्ता रामलला का दर्शन करने के साथ उन्हें फैसले की प्रति सौंपेंगे। रामलला की ओर से प्रति अधिगृहीत परिसर के पदेन रिसीवर मंडलायुक्त मनोज मिश्र स्वीकारेंगे।

फिरोज के विरोध में धरना जारी, समर्थन में पहुंचे विमुक्तेश्वरानंद

जागरण संवाददाता, वाराणसी

काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कुलपति आवास के सामने सात नवंबर से चल रहे धरने का समर्थन करते हुए गुरुवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरनारत छात्रों से मिलने पहुंचे। छात्रों से बातचीत के बाद उन्होंने विरोध को जायज ठहराया। कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए मालवीय जी ने जिस विभाग की स्थापना की थी, उसमें किसी गैर हिंदू का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यह किसी मुसलमान का विरोध नहीं है, बल्कि 'धर्म विज्ञान संकाय' में एक गैर हिंदू की नियुक्ति का विरोध है। विवि प्रशासन संग शिक्षकों की वार्ता हुई। गुरुवार दोपहर बाद संकाय का ताला 15वें दिन खुला। शैक्षणिक कार्यों में जहां शिक्षकगण व्यस्त हो गए, वहीं सेमेस्टर परीक्षा को लेकर संकाय प्रमुख प्रो. विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र ने शिक्षकों संग बैठक की।

ट्वीट से मचा हंगामा : दोपहर बाद करीब 3.25 बजे विवि प्रशासन की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया है और संकाय भी खुल गया है। वहां जाकर देखने पर संकाय तो खुला मिला, लेकिन वीसी आवास के बाहर छात्रों का धरना जारी रहा। छात्रों ने विवि के ट्वीट को झूठा करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी।

वाराणसी में बीएचयू स्थित कुलपति आवास के सामने धरनारत छात्रों से बात करते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जागरण

सिगरा स्थित भारत माता मंदिर परिसर में गुरुवार को ज्वाइंट एक्शन कमेटी-बीएचयू व साझा सांस्कृतिक मंच की बैठक हुई। वक्ताओं ने कहा कि देश में धर्म के आधार पर भेदभाव कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, 'भारत के मुस्लिमों का डीएनए हिंदुओं के पूर्वजों जैसा ही है। यदि कुछ नियम हैं तो इसे बदलने की जरूरत है।' वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लिखा 'हमारी भाषाएं और संस्कृति हमारी विशेषता हैं, हमारी मजबूती हैं। विवि में संस्कृत कोई भी अध्यापक पढ़ा सकता है। सरकार और विवि को इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।' राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संदर्भ में तीन ट्वीट किए। लिखा 'मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति संस्कृत का शिक्षक बना है तो ऐसे में सभी को इसका स्वागत करना चाहिए था। फिरोज को लेकर जो विवाद बना हुआ है, वह जल्द समाप्त किया जाना चाहिए।' वहीं विवि के चांसलर न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय ने लिखा, 'संस्कृत विभाग में प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति के विरोध में छात्रों का स्टैंड गलत है। बीएचयू के संस्थापक, पंडित मदन मोहन मालवीय की व्यापक सोच थी। यदि वह जीवित होते, तो निश्चित रूप से नियुक्ति का समर्थन करते।'

फर्जी तरीके से हुई नियुक्ति

एब वीपी के प्रदेश मंत्री सुधांशु शेखर सिंह ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर दावा किया कि बीएचयू में डा. फिरोज खान की नियुक्ति योजनाबद्ध एवं फर्जी तरीके से की गई है।

पीएमओ ने फिरोज प्रकरण की मांगी रिपोर्ट

विवाद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी गंभीरता से लिया है। इस मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब करने के साथ ही बीएचयू परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश यात्रा पर होने के बावजूद मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट लेकर प्राथमिक सूचना से पीएमओ को अवगत करा दिया है। रिपोर्ट जिला प्रशासन भेजेगा।

जब मुनीर बख्श आलम ने समझा गीता का तत्वज्ञान

जासं, सोनभद्र : बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में सहायक प्रोफेसर डा. फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। जबकि इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं, जिन्होंने देवभाषा कही जाने वाली संस्कृत से न सिर्फ प्रेम किया है बल्कि इसके माध्यम से रचनाएं-अनुवाद आदि उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। इसी पंक्ति में शामिल हैं सोनांचल के स्व. मुनीर बख्श जिन्होंने स्वामी अड़गड़ानंद के सानिध्य में रहकर न सिर्फ संस्कृत सीखी, बल्कि उनकी रचना यथार्थ गीता का हकीकी गीता नाम से उर्दू में अनुवाद भी किया।

एक जुलाई, 1943 को शाहगंज थाना के बनौरा गांव में जन्मे आलम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक की उपाधि ली। इसके बाद हिंदी में परास्नातक और बीएड करने के बाद सीमेंट फैक्ट्री चुर्क स्थित इंटर कॉलेज में संस्कृत शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई। मुनीर बख्श आलम के बड़े पुत्र खुर्शीद आलम बताते हैं कि पिताजी को संस्कृत भाषा से विशेष लगाव था। जिसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए वह स्वामी अड़गड़ानंद के सानिध्य में भी रहे। जहां उन्होंने गीता का सारगर्भित अध्ययन किया। साथ ही स्वामी अड़गड़ानंद की रचना यथार्थ गीता का भी अध्ययन किया। जिसके बाद 2000 में उन्होंने यथार्थ गीता का उर्दू अनुवाद हकीकी गीता नाम से किया।

बाबा ने कहा था मुस्लिम भी बीएचयू के लिए हिंदू : जस्टिस मालवीय

गुरुदीप त्रिपाठी, प्रयागराज

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र और बीएचयू के कुलाधिपति (चांसलर) जस्टिस गिरधर मालवीय संस्कृत धर्म विद्या संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति के बाद उपजे विवाद से आहत हैं। उनका कहना है कि बाबा (महामना) का कभी ऐसा दृष्टिकोण नहीं था। छात्र-छात्राओं को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। महामना की बगिया तो सभी के लिए खुली है। बाबा कहते थे कि मुस्लिम भी बीएचयू के लिए हिंदू हैं।

दैनिक जागरण से बातचीत में जस्टिस मालवीय ने बताया कि महामना बीएचयू के निर्माण के लिए दान मांगने हैदराबाद के निजाम के पास गए थे। उन्होंने दान देने से मना कर दिया था। तब महामना ने कहा, हम तो बिना कुछ लिए जाते नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। पहले गिरफ्तार करने को कहा। फिर बताया गया कि वह उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जब महामना वहां से लौटने लगे तो उनकी चप्पल उठा लाए और नीलाम करने की बात कही। इस पर निजाम ने महामना को दोबारा बुलवाया और पूछा कि आखिर मैं दान क्यों दूं, आप हिंदू हैं और मैं मुस्लिम। इस पर महामना ने निजाम से कहा था कि हमारे लिए मुस्लिम भी हिंदू हैं। बीएचयू के लिए भी मुस्लिम हिंदू हैं। उन्होंने बताया कि बाबा के साथ मैं 10 वर्ष की आयु से रहने लगा था। उन्हें बहुत करीब से जाना है। वह ऐसे संकीर्ण भाव मन में नहीं रखते थे। उन्होंने कहा था स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते...।

जस्टिस मालवीय ने कहा कि योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए। बोले, छात्र किस आधार पर फिरोज खान का विरोध कर रहे हैं, यह समझ से परे है। पहली बात तो यह है कि फिरोज खान को कर्मकांड पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि साहित्य पढ़ाने के लिए रखा गया है। दूसरा यह कि यदि कर्मकांड के लिए भी नियुक्ति हुई है तो छात्रों को विरोध करने के बजाय पढ़ना चाहिए।

जस्टिस गिरधर मालवीय। जागरण

नजीर

जुबानों की सियासत को शीबा-सुशीला की नसीहत- भाषा को धर्म के आधार पर न बांटा जाए

शीबा संस्कृत तो सुशीला दे रहीं उर्दू की शिक्षा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत धर्म विद्या संकाय में प्रो. फिरोज खान की नियुक्ति पर विरोध के स्वर बुलंद करने वालों के लिए तालीम के शहर देवबंद की बेटियां शीबा और सुशीला एक नजीर हैं। शीबा विद्यार्थियों को संस्कृत के श्लोक कंठस्थ करा रही हैं, तो सुशीला बच्चों को उर्दू का कायदा सिखा रही हैं। जुबानों की सियासत करने वालों को शीबा और सुशीला की नसीहत है कि भाषा को धर्म के आधार पर न बांटा जाए।

गंगा-जमुनी तहजीब अपने भीतर संजोए देवबंद की सरजमीं में सभी जुबानें आपस में गलबहियां करती हैं। यहां पावन शक्तिपीठ श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर के बगल में श्रावणी उपाकर्म और कर्मकांड सिखाने वाला संस्कृत महाविद्यालय है तो इस्लामी तालीम में दक्षता प्रदान करने वाला विश्वविख्यात केंद्र दारुल उलूम देवबंद भी है। जुबानों का मेल देवबंद की पहचान रहा है। इल्म-ओ-अदब की इस नगरी में संस्कृत जुबान की ज्ञाता शीबा और उर्दू भाषा की माहिर सुशीला बच्चों को अपने-अपने विषय में शिक्षित करने का काम कर रही हैं।

डा. शीबा परवीन रणखंडी गांव के ठा. कृपाल सिंह डिग्री कालेज में पिछले करीब 10 सालों से संस्कृत की प्राध्यापक हैं। मूलरूप से सहारनपुर की रहने वाली शीबा का बचपन से ही संस्कृत भाषा के प्रति लगाव रहा। अपनी लगन और दृढ़निश्चय के बूते शीबा ने संस्कृत से पीएचडी की। इस विषय में दक्षता हासिल कराने में शीबा के घरवालों ने भी साथ दिया। शीबा का मानना है कि जुबानें आपसी कटुता को समाप्त कर दिलों को जोड़ती हैं। इसलिए इनका विरोध किसी मायने सही नहीं है।

सुशीला शर्मा व डा. शीबा परवीन। जागरण

24 सालों से कर रहीं उर्दू की खिदमत

वहीं, ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुशीला शर्मा बच्चों को उर्दू भाषा का ज्ञान दे रही हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय नंबर एक में अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहीं सुशीला पिछले 24 सालों से उर्दू की खिदमत कर रही हैं। सुशीला बताती हैं कि उर्दू टीचर के रूप में उनकी नियुक्ति वर्ष 1994 में हुई थी और उर्दू बीटीसी एंट्रेंस में उन्होंने जिला टॉप किया था। बचपन से ही उन्हें उर्दू जुबान से एक अजीब सी मोहब्बत रही। सुशीला का कहना है कि जुबान किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। जुबानों की मुखालफत करना गलत है। धर्म से ऊपर उठकर योग्यता को वरीयता दी जानी चाहिए।

अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे 'जामुन का पेड़' की कहानी

अमित तिवारी, मेरठ

सरकारी व्यवस्था पर चोट करती कहानी 'जामुन का पेड़' के बारे में अब स्कूलों के बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआइएससीई) की ओर से आइसीएसई (10वीं) के हिंदी सिलेबस से कृष्ण चंदर लिखित इस कहानी को हटा दिया गया है। बीच सत्र में काउंसिल से आए निर्देश के लिए स्कूल पहले से तैयार नहीं थे। हिंदी सिलेबस में लघु कथाओं में शामिल यह कहानी कई स्कूल बच्चों को पढ़ा भी चुके थे। इसके स्थान पर कोई नई कहानी जोड़े जाने की जानकारी नहीं दी गई है।

स्कूलों में सत्र 2019-20 की पढ़ाई एक अप्रैल को शुरू हो गई थी। छह महीने की पढ़ाई होने के बाद एक नवंबर को काउंसिल की ओर से जारी सर्कुलर में कहानी को हटाने की जानकारी दी गई है। फिलहाल सत्र 2021 और 2022 के लिए इस कहानी को हटाया गया है। इसके बाद कहानी को सिलेबस में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में भी कोई जानकारी स्कूलों को नहीं दी गई है। स्कूल शिक्षकों का कहना है कि व्यवस्था पर चोट करती यह कहानी बच्चों में काफी लोकप्रिय थी।

सरकारी महकमों की कार्यशैली है बयां: कहानी सचिवालय परिसर में गिरे एक जामुन के पेड़ और उसमें दबे शायर के इर्द-गिर्द घूमती है। पहले जामुन के पेड़ के गिरने का अफसोस, फिर दबे हुए आदमी के जिंदा होने की जानकारी मिलने पर उसे निकालने की जद्दोजहद में सरकारी महकमों की कार्यशैली को बयां किया गया है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे शायर का शेर 'हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक' कहानी के पूरे मर्म को बयां करता है। गुजरांवाला (अब पाकिस्तान में) के वजीराबाद में कृष्ण चंदर का जन्म 1914 को हुआ था और 1977 में उनका निधन हो गया था। उपन्यास व कहानी लेखन में उन्हें 1977 में पद्मभूषण से नवाजा गया।

बृजेश ठाकुर को संरक्षण देने वाले जेल अधीक्षक पर गिरी गाज

राज्य ब्यूरो, पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपित बृजेश ठाकुर को जेल में रहने के दौरान संरक्षण देने और नियमों का उल्लंघन कर जेल अस्पताल में रखने के मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक राजीव कुमार झा पर सरकार की गाज गिरी है। गृह (कारा) विभाग ने राजीव कुमार के खिलाफ आरोप पाए जाने के बाद विभागीय कार्रवाई चलाने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में सहायक कारा महानिरीक्षक के पद पर तैनात राजीव कुमार झा पर आरोप हैं कि मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय जेल में बंद बृजेश ठाकुर को उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए मदद की। 11 अगस्त 2018 को जेल में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान प्रशासन को 12 मोबाइल, चार चार्जर, तीन सिम और नशीली एवं प्रतिबंधित दवाएं मिली। कैदियों को लंबे समय तक बार-बार जेल अस्पताल में नियम विरुद्ध रखे जाने और बृजेश को जेल अस्पताल वार्ड में रखने जाने की जानकारी भी मिली।

21 आधार सेवा केंद्र काम कर रहे हैं देश भर में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के। सरकार इसकी संख्या बढ़ाकर 114 करना चाहती है। यह जानकारी यूआइडीएआइ ने गुरुवार को दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 22 नवंबर 2019

कश्मीर में आतंकियों से जुड़ी छह संपत्तियों पर ईडी ने लिया कब्जा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कश्मीर में कथित आतंकियों से जुड़ी छह भू-संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कब्जा ले लिया है। वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी ने इस साल मार्च में ऐसी 13 संपत्तियों को जब्त किया था। इस कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी ने हाल ही में उक्त आदेश को बरकरार रखा था जिसके बाद कब्जे का नोटिस जारी किया गया। ईडी के मुताबिक, ये संपत्तियां अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामुला जिलों में स्थित हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों मुहम्मद शफी शाह, तालिब लाली, गुलाम नबी खान, जफर हुसैन भट, अब्दुल मजीद सोफी, नजीर अहमद डार व मंजूर अहमद डार के नाम पर हैं। जब्त की गईं सभी 13 संपत्तियों की कुल कीमत 1.22 करोड़ रुपये है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक बाकी संपत्तियों पर भी जल्द ही कब्जा ले लिया जाएगा।

केसर क्रांति में बदलेगी कश्मीर के किसानों की किस्मत

रजिया नूर, श्रीनगर

कश्मीर की शान हैं बर्फ से लदी खूबसूरत वादियां और लाल केसर की महकती क्यारियां। केंद्र सरकार केसर क्रांति के बूते कश्मीर के किसानों की किस्मत बदलने में जुटी है। साथ ही सैफरॉन मिशन के बूते अगले कुछ वर्षों में केसर का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। इसका असर भी दिखा और इस बार पिछले दस वर्षों का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जगाई जा रही थी पर मौसम ने झटका दे दिया है। नवंबर माह के आरंभ में हुई बर्फबारी ने केसर की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया।

कश्मीर का केसर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी वजह से भारत केसर उत्पादन में ईरान के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। बाजार में केसर की कीमत डेढ़ से तीन लाख रुपये प्रति किलो है। आतंकवाद प्रभावित इस क्षेत्र में केंद्र सरकार केसर के बूते किसानों का बेहतर भविष्य बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद स्पाइसेज बोर्ड ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर केसर निर्यात एवं विकास एजेंसी का गठन किया और राज्य का बागवानी विभाग भी सक्रिय हुआ।

सब मौसम पर निर्भर

केसर उत्पादक एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि समय पर बारिश होना मतलब केसर की अच्छी पैदावार। इस साल भी अच्छी फसल होने की उम्मीद थी लेकिन बफर्बारी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वानी ने कहा, अगर केसर के खेतों में बोर वेल लगाए जाएं तो हम अगस्त से ही खेती शुरू कर दें और अक्टूबर तक पैदावार समेट लें।

सूक्ष्म सिंचाई फायदेमंद

शेर-ए-कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के प्लांट पैथालोजी विभाग के विज्ञानी अरशद अहमद टॉक ने कहा कि कई वर्षों में समय पर बारिश न होने के चलते केसर के उत्पादन को काफी धक्का पहुंचा था। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई से किसानों को केसर की मोड़ा जा सकता है।

कश्मीर में नवंबर में हुई बर्फबारी ने केसर की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। जागरण

दक्षिण व मध्य कश्मीर में होती है काश्त

केसर की काश्त दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा और मध्य कश्मीर के बड़गाम में अधिक की जाती है। घाटी में 3700 हेक्टेयर जमीन (3650 हेक्टेयर पुलवामा तथा बड़गाम जिले में 50 हेक्टेयर जमीन पर केसर की खेती शुरू की गई) और इसमें से 95 फीसद (23 टन) केसर पुलवामा में उत्पादन होता था। पुलवामा में केसर उत्पादन प्रति हेक्टयेर पांच किलोग्राम के आसपास रहा है। वहीं श्रीनगर में यह दो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कश्मीर में करीब 32 हजार किसान केसर की खेती से जुड़े हैं।

मिशन केसर की चुनौतियां मौसम की बाधा : केसर के फूलों का संचय अक्टूबर-नवंबर माह में होता है और पिछले कुछ वर्षों से नवंबर माह के पहले सप्ताह में बर्फबारी हो जाती है। इससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। किसान अगर अगस्त माह में इसका रोपाई का कार्य कर लें तो अक्टूबर माह में फूल ले सकते हैं और ऐसे में बर्फबारी से पहले अपनी फसल ले पाएंगे। पर केसर की खेती ढलान वाले क्षेत्रों में होती है और वहां पानी ठहरता नहीं। ऐसे में बारिश के बाद किसान खेती शुरू करते हैं। प्रशासन टपका प्रणाली से सिंचाई को प्रोत्साहित कर रहा है।

घटता रकबा : 20 वर्षों में केसर के उत्पादन में कुछ कमी आई है। करीब 3700 हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए केसर मिशन शुरू किया गया था, लेकिन बाद में यह दायरा सिकुड़कर 2700 हेक्टेयर तक जा पहुंचा। हालांकि एक समय में यह रकबा पांच हजार हेक्टेयर के करीब पहुंच गया पर उत्पादन गिरने पर बहुत से किसानों ने इससे किनारा कर लिया। पहले वर्ष 2014 के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब ने सैफरान बड (कश्मीरी में कोंग मोंड) 60 फीसद तक नष्ट कर दी। सेफरान बड से 8-10 वर्षों तक केसर के फूल लिए जा सकते हैं। दो वर्षों में मौसम थोड़ा अनुकूल रहा और वक्त पर बारिश भी हुई और इससे पैदावार में फिर बढ़ोतरी की उम्मीद पैदा हो गई।

अल्ताफ हुसैन के शरण मांगने पर भारत चुप

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : लंदन में निर्वासित जिंदगी बीता रहे पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने भारत में शरण मांगने की पेशकश की है, लेकिन भारत का रवैया फिलहाल बहुत सकारात्मक नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि भारत विश्व बिरादरी को यह संदेश नहीं देना चाहता कि वह पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नेताओं को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी वजह यह है कि हुसैन की छवि काफी चर्चा में रही है। हालांकि अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के नेता हुसैन ने आधिकारिक तौर पर शरण मांगी है अथवा नहीं।

इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्हें बेहद ठंडी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में गृह मंत्रालय ही बेहतर तरीके से बता सकेगा। दूसरी तरफ, गृह मंत्रालय अल्ताफ हुसैन को लेकर एकदम चुप्पी साधे हुए। हुसैन ने पिछले दिनों एक भारतीय टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह भारत में शरण लेना चाहते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से यह भी कहा था कि अगर वह भारत में आते हैं तो यहां राजनीति से दूर रहेंगे।

धोखाधड़ी रोकने के नए तरीके खोजें ऑडिटर

बोले पीएम ▶ देश को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ऑडिटर्स की अहम भूमिका

कैग को केवल कमियां खोजने वाले ऑडिटर की तरह नहीं, थिंक टैंक की तरह सोचने का सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑडिटर्स से धोखाधड़ी पर लगाम लगाने और सरकारी विभागों की दक्षता बढ़ाने के नए तौर-तरीके खोजने की अपील की। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने देश को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ऑडिटर्स से भूमिका निभाने को कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें धोखाधड़ी को चुनौती देनी होगी। आंतरिक एवं बाहरी दोनों स्तर पर कार्यरत ऑडिटर्स को धोखाधड़ी पकड़ने के नए तौर-तरीके खोजने चाहिए।' मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। प्रमाणों पर आधारित नीति निर्माण को प्रशासन का हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऑडिटर्स को तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इससे संस्थानों में धोखाधड़ी के मामले पकड़ना आसान होगा।

नई दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालेखाकार (अकाउंट्स जनरल) और उप महालेखाकार संगोष्ठी को संबोधित किया। प्रेट्र

2016 के बाद दूसरी बार कैग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 'देश पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इसमें आपकी (आडिटर्स की) बड़ी भूमिका है। आप जो भी करेंगे, उससे हमारे नीति निर्माण, दक्षता, निर्णय प्रक्रिया, कारोबार, निवेश, कारोबारी सुगमता एवं अन्य पहलुओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।' मोदी ने कैग को केवल गलतियां पकड़ने वाले ऑडिटर की तरह नहीं, थिंक टैंक की तरह सोचने को कहा। मोदी ने कहा, 'कैग कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का ऑडिट करती है और अन्य देशों को भी तकनीकी सहायता मुहैया कराती है। इसलिए आप ऐसी संस्थागत व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जिससे ऐसी कंपनियों का ऑडिट करने वाली टीम उन देशों व संस्थानों से जुड़े अपने अनुभव साझा कर सकें।' इससे पहले मोदी ने कैग परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया।

हैकाथन आयोजित करे कैग

प्रधानमंत्री ने दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने तथा विभिन्न चुनौतियों का तकनीकी समाधान पाने के लिए कैग को हैकाथन आयोजित करने का सुझाव भी दिया। हैकाथन के जरिये देशभर में टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े युवा समस्याओं का डिजिटल समाधान मुहैया कराने में मदद कर सकेंगे। मोदी ने कैग को विभिन्न देशों की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों अपनाने और भारत में उन पर काम करने को भी कहा। मोदी ने कहा, 'कैग को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहते हुए अच्छे प्रशासन (गुड गवर्नेंस) का उत्प्रेरक बनना होगा। आप कैग को कैग प्लस बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं और इससे देश को भी लाभ हुआ है।'

बंगाल में गाय चोर के संदेह में पीट-पीटकर दो की हत्या

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सरकारी सख्ती के बावजूद बंगाल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला कूचबिहार जिले का है। यहां गाय चोरी के संदेह में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। घटना गुरुवार सुबह की है। मृतकों की पहचान प्रकाश दास और बाबला मित्र के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों सुबह पिकअप वैन से गाय लेकर जा रहे थे। कूचबिहार में फुलेश्वरी के पास उन्हें कुछ लोगों ने रोक दिया और पूछताछ करने लगे। इसके बाद वे लोग उन्हें गाय चोर बताकर मारने-पीटने लगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हमलावर भीड़ से छुड़ाकर साथ ले गई। दोनों घायलों को कूचबिहार जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों के परिवारों ने हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों को गाय चोर समझकर हमला किया गया। गंभीर चोट लगने के कारण दोनों की मौत हुई है। आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सेवानिवृत्ति आयु बढ़े तो जज और काम करना चाहेंगे : सीजेआइ

- चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा-अटॉर्नी जनरल की राय से हूं सहमत
- वेणुगोपाल की सीजेआइ का कार्यकाल तीन साल करने की दलील

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्च न्यायालयों के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर चर्चा के बीच देश के नए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा है कि अगर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाएगी तो जज लंबे समय तक काम करने के इच्छुक हैं। इसी 18 नवंबर को भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने वाले चीफ जस्टिस बोबडे ने गुरुवार को अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के सुझाव पर ऐसा कहा। हालांकि खुद वेणुगोपाल का कहना है कि ऐसा उन्होंने बार एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते कह रहे हैं, नाकि देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के तौर पर कह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायर होने की उम्र 65 साल है जबकि हाई कोर्ट के जज 62 साल के होने पर सेवानिवृत्त होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने सीजेआइ के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि 70 और 80 साल से अधिक के वकील अदालतों में पूरे जोश-ओ-खरोश से जिरह करते हैं। इसलिए जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सुप्रीम कोर्ट के लिए 70 साल तक की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 68 वर्ष होनी चाहिए। बार के सदस्यों को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि आप अपने मुवक्किलों को बताएं कि वह अपना काम जारी रखना चाहते हैं। जस्टिस बोबडे ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि हमारी न्यायापालिका और बार दोनों ही स्वतंत्र हैं। हर मौके पर हम यह पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि भूत और भविष्य में न्यायापालिका ने अर्थपूर्ण तरीके से दायित्वों का निर्वाह किया है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस बोबडे ने न्यायपालिका के लिए चिंता के विषय उठाते हुए कहा कि लंबित मामले बढ़े हैं। आधारभूत ढांचे और रिक्तियों के मुद्दे हैं। इन्हें मिलजुलकर दुरुस्त करने की जरूरत है।

वहीं वेणुगोपाल ने अपने संबोधन में दलील दी कि देश के मुख्य न्यायाधीश का कम से कम तीन साल का तय कार्यकाल होना चाहिए। ताकि उनके नेतृत्व में शुरू किए गए सुधारवादी फैसलों को उनके ही कार्यकाल में अमल में लाया जा सके। एससीबीए अध्यक्ष और वेणुगोपाल दोनों ने ही वकीलों के और चैंबर बनाए जाने की मांग को पूरा करने और कोर्ट परिसर में और अधिक गलियारे बनवाने पर बल दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने पाक से फिर की दोनों भारतीयों को लौटाने की मांग

- विदेश मंत्रालय ने जताई उम्मीद, नहीं किया जाएगा दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल

नई दिल्ली, एजेंसियां : अनजाने में सीमा पार करके 2016-17 में पाकिस्तान चले गए दो भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को आश्चर्य व्यक्त करते हुए दोनों को काउंसलर एक्सेस देने और उन्हें वापस भेजने की मांग दोहराई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि भारत ने कई महीनों पहले ही प्रशांत वैंदम और बारी लाल के अनजाने में सीमा पार करने की संभावना के बारे में पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। लिहाजा पाकिस्तानी मीडिया में उनकी अचानक गिरफ्तारी की खबर से भारत को आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि इन दोनों भारतीय नागरिकों को पाकिस्तानी दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल या उसका पीड़ित नहीं बनाया जाएगा।'

रवीश कुमार ने बताया कि बारी लाल (मध्य प्रदेश निवासी) के सीमा पार करने की संभावना के बारे में भारत ने पाकिस्तान को पिछले साल दिसंबर में और प्रशांत वैंदम (तेलंगाना निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर) के बारे में इस साल मई में सूचित किया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा, 'जब यह मीडिया में आया तो हमने उसी दिन पाकिस्तान सरकार से संपर्क किया और उन्हें तत्काल काउंसलर एक्सेस दिए जाने का अनुरोध किया।' रवीश कुमार ने बताया कि ऐसे कई अन्य भारतीय भी हैं जो संभवतः अनजाने में सीमा पार करके पाकिस्तान चले गए हैं। जब भी ऐसे मामले विदेश मंत्रालय के संज्ञान में आते हैं तो पाकिस्तान से संपर्क किया जाता है।

बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसी हफ्ते की शुरुआत में खबर दी थी कि पंजाब प्रांत के पूर्वी शहर बहावलपुर से दो भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। वे वहां बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे।

करतारपुर कॉरिडोर के मद्देनजर पंजाब में पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार

रवीश कुमार ने बताया कि करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद यात्रा दस्तावेजों के लिए बढ़ते आवेदनों के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने पंजाब में पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार किया है। उन्होंने कहा, 'पासपोर्ट सेवाओं को आसान बनाया गया है। पंजाब में अब तीन पासपोर्ट कार्यालय, पांच पासपोर्ट सेवा केंद्र और छह पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। इनके अलावा डेरा बाबा नानक समेत कई नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं।' मालूम हो कि करतारपुर साहिब जाने के लिए पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट अनिवार्य है।

वेतन घोटाले में लखनऊ के होमगार्ड कमांडेंट गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ : होमगार्ड विभाग में वेतन घोटाले की आंच आखिरकार राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई। लखनऊ में होमगार्डों की फर्जी ड्यूटी लगाकर वेतन हड़पने का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद गोमतीनगर पुलिस ने जिला होमगार्ड कमांडेंट कृपा शंकर पांडेय को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया।

कूटरचित दस्तावेज से मस्टर रोल तैयार कर सरकारी धन का गबन करने के आरोप में जिला कमांडेंट को गिरफ्तार किया गया है। यह जालसाजी विभूतिखंड थाने में तैनात होमगार्डों के नाम पर भी हुई है। मामले में इंस्पेक्टर गुडंबा रीतेंद्र प्रताप सिंह ने गोमतीनगर थाने में जिला कमांडेट होमगार्ड कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। आरोप है कि जुलाई और अगस्त 2019 में गुडंबा थाने में होमगार्डों की वास्तविक तैनाती के अपेक्षा तीन गुना से अधिक वेतन का भुगतान करा लिया।

जांच में पता चला कि अगस्त में गुडंबा थाने में कुल 23 होमगार्ड आवंटित किए गए थे। इनमें महज आठ ही ड्यूटी पर भेजे गए। इंस्पेक्टर गुडंबा ने उन्हीं आठ होमगार्ड के वेतन की रिपोर्ट बनाकर भेजी। बावजूद इसके जिला होमगार्ड कमांडेंट ने कुल 23 होमगार्ड के नाम पर भुगतान प्राप्त कर लिया। जुलाई और अगस्त में सिर्फ गुडंबा थाने में होमगार्डों की ड्यूटी में खेल कर चार लाख 99 हजार रुपये का गबन हुआ।

सैन्य काफिले को उड़ाने की आतंकी साजिश नाकाम

कश्मीर के जिला कुलगाम में जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर आतंकियों की ओर से लगाई गई आइईडी का सुरक्षाबलों ने समय रहते पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। पीआरओ डिफेंस

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सुरक्षा बलों की सतर्कता से गुरुवार को दक्षिण कश्मीर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैन्य काफिले और नागरिक वाहनों को उड़ाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई।

जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कुलगाम के अंतर्गत वनपोह में अल-स्टाप के पास एक आइईडी लगा रखी थी। जांच के दौरान इसका पता चलते आवाजाही रोक दी गई। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। दस्ते ने सुरक्षित जगह पर ले जाकर आइईडी को निष्प्रभावी कर दिया।

बैग में रखा गया था विस्फोट : अधिकारियों ने बताया कि आइईडी को एक बैग में विस्फोटकों से भरे दो छोटे टीन के डिब्बे और बिजली के तारों से फिट किया गया था। आसपास रहने वाले लोगों और दुकानदारों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन कोई भी आइईडी रखने वालों के बारे में जानकारी नहीं दे पाया है।

त्राल में दुकानदारों को धमका रहा हिजबुल का ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के त्राल में लोगों को डरा-धमका कारोबार बंद रखने के लिए मजबूर कर रहे तत्वों के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ लिया है। भारी मात्रा में धमकी भरे पोस्टर, आतंकी संगठन के लैटरहेड व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आरोपित आसिफ अहमद बट लारू जगीर पर त्राल पुलिस स्टेशन में लोगों के साथ मारपीट, धमकियां देने, दंगा भड़काने, आगजनी के कई मामले दर्ज हैं। आसिफ त्राल और आसपास के इलाकों में लोगों को हड़ताल करने के लिए उकसा रहा था। वह दुकानें खोलने वालों के साथ मारपीट करता था। उसने कुछ जगहों पर खुली दुकानों को आग लगाने की साजिश की थी। पुलिस ने कई बार उसके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। सुबह पुलिस ने उसे दबोच लिया। उससे गत सप्ताह त्राल में एक दुकानदार की हत्या के मामले में पूछताछ होगी।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को हौसले पस्त दिख रहे हैं। कुछ दिन की पाबंदियों के बाद हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में आतंकवादी संगठन लगातार दुकानदारों को डरा रहे हैं ताकि बाजार बंद रहे।

पुंछ में पाक गोलाबारी में बीएसएफ का जवान घायल

जासं, पुंछ : पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की है। इसमें सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। जवान की पहचान 168 बटालियन के संजय कुमार के रूप में हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत में सुधार है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में सीमा पार काफी नुकसान हुआ है।

चिंता

हवाला कारोबार और आतंकी गतिविधियों के कारण लगी रोक, भारी कर्ज में फंसे जम्मू कश्मीर के व्यापारी, कारोबार चौपट

क्रॉस एलओसी ट्रेड बंद होने से गुलाम कश्मीर में लाखों फंसे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

तौसीफ जफर रोज सुबह नई उम्मीद लेकर घर से करीब 12 किलोमीटर दूर सलामाबाद जाते हैं और फिर मायूस होकर लौट आते हैं। जेहलम किनारे स्थित सलामाबाद क्रॉस एलओसी ट्रेड फैसिलटेशन सेंटर में अधिकारियों से गुलाम कश्मीर में फंसे पैसे निकालने का कोई रास्ता बताने को कहता है। अधिकारी सांत्वना देते हैं कि हौसला रखो, जल्द ही ट्रकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। रोज यही आश्वासन लेकर घर लौट आता है। वह अकेला नहीं है उस जैसे करीब 180 व्यापारी हैं, जिनका लाखों रुपया गुलाम कश्मीर के व्यापारियों पर है।

उड़ी निवासी तौसीफ जफर का कहना है कि जब क्रास एलओसी ट्रेड शुरू हुआ तो बताया गया कि यह हम लोगों की तकदीर बदल देगा, लेकिन आज हम लोग सड़क पर हैं। 70 लाख का माल अप्रैल की शुरुआत में भेजा था बदले में चकोटी मुजफ्फराबाद के व्यापारियों को मुझे सामान भेजना था। वह सामान भेजते उससे पहले ही 18 अप्रैल को क्रॉस एलओसी व्यापार पर रोक लगा दी गई। छह ट्रक माल यहां रखा था जिसे 19 अप्रैल को भेजना था। वह कहते हैं कि एक बार किसी तरह से पैसा वापस आए। उसके बाद इससे तौबा ही कर लूंगा।

श्रीनगर के जहूर अहमद बताते हैं कि कि अप्रैल के अंत में 30 लाख के मसाले खरीदे थे, जो गुलाम कश्मीर भेजने थे और बदले में मिस्वाक की दातुन मंगानी थी। मई में पाक रमजान में मिसवाक की यहां खूब खपत होती है, लेकिन अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में यह व्यापार बंद हो गया और मैं कर्ज में दब गया।

केंद्र ने हमारी सुनी नहीं : सलामाबाद-चकोटी क्रास एलओसी ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हिलाल तुर्की ने कहा कि हम तो शुरू से केंद्र सरकार से कहते थे कि वह इस व्यापार को हवाला और आतंकवादियों की चंगुल से आजाद रखने के लिए ट्रेड फैसिलटेशन सेंटर पर ट्रक स्कैनर उपलब्ध कराए। सभी व्यापारियों की स्क्रीनिंग हो। यह व्यापार बार्डर ट्रेड जिसमें सामान के बदल-सामान का आदान-प्रदान होता है, बंद करने और नकद लेन-देन की व्यवस्था के लिए आग्रह कर रहे थे। केंद्र ने हमारी यह मांग पूरी नहीं की।

300 मजदूर बेरोजगार हो गए : सलामाबाद का बाजार दिनभर सूना रहता है। दो सौ ट्रक चालक बेकार हैं। अब श्रीनगर, बारामुला व कस्बों में काम तलाश रहे हैं। ट्रेड फैसिलटेशनसेंटर में 300 मजदूर काम करते थे, जो बेकार हैं। इनमें से कई कश्मीर से बाहर रोजी रोटी कमाने चले गए हैं। लोगों का कहना है कि दोनों देशों की तनातनी से मजदूरों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दोनों देशों की सरकार से इस दिशा में पहल करने की अपील है। उनका कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच भाईचार भी बढ़ेगा।

प्रशासन तक बात पहुंचा दी : सलामाबाद ट्रेड फैसिलटेशन सेंटर के कस्टोडियन रियाज अहमद मलिक ने कहा कि व्यापार कब शुरू होगा यह केंद्र सरकार तय करेगी। स्थानीय व्यापारियों की पीड़ा प्रशासन तक पहुंचा दी है।

18 अप्रैल 2018 को बंद हुआ व्यापार

गत मार्च में क्रास एलओसी ट्रेड को कुछ दिन स्थगित रखने के बाद बहाल किया गया, लेकिन 18 अप्रैल को गृहमंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसे अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया।

वर्ष 2008 में शुरू हुआ था क्रास एलओसी ट्रेड

भारत-पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत अक्टूबर 2008 में जम्मू कश्मीर और गुलाम कश्मीर के बीच ड्यूटी फ्री क्रास एलओसी ट्रेड की अनुमति दी गई थी। इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर और गुलाम कश्मीर के व्यापारी ही हिस्सा ले सकते थे। दोनों तरफ से 21 वस्तुओं का ही आयात-निर्यात हो सकता था। यह पूरी तरह से बार्टर ट्रेड था। कश्मीर के व्यापारी सलामाबाद के रास्ते अमन कमान सेतु के पार गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के लिए माल भेजते थे और मंगाते थे। जम्मू के व्यापारी पुंछ में चक्कां दा बाग के रास्ते रावलकोट माल भेजते थे। यह व्यापार सप्ताह में चार दिन होता था।

उप्र के पीएफ घोटाले में दो और सीए सहित पांच से पूछताछ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र में बिजलीकर्मियों के भविष्य निधि घोटाले में दिल्ली के दो और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से लंबी पूछताछ की गई है। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ब्रोकर फर्मों के जरिये हुए करोड़ों के कमीशन का लखनऊ कनेक्शन भी खोज निकाला है।

सूत्रों का कहना है कि लखनऊ के महानगर क्षेत्र निवासी ब्रोकर फर्म संचालक अश्वनी भसीन व राहुल भसीन सहित तीन फर्म संचालकों से लंबी पूछताछ की गई। अश्वनी भसीन व राहुल भसीन की चार ब्रोकर फर्में, जिनमें दो फर्में लखनऊ व दो फर्में दिल्ली के पतों पर रजिस्टर्ड हैं। दोनों को कमीशन के रूप में करीब सवा करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया है कि श्रीन कंसलटेंट व एरीज एंड कंपनी नाम से रजिस्टर्ड फर्मों के जरिये भी निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में निवेश कराया गया था। उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को पानीपत की फर्जी ब्रोकर फर्म के संचालक से लंबी पूछताछ की थी। अब तक की जांच में ब्रोकर फर्मों से जुड़े रहे दिल्ली के कई सीए की भूमिका भी सामने आई है। दिल्ली के चार सीए से बुधवार को पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को दो अन्य सीए से भी लंबी पूछताछ की। फर्जी फर्मों के खातों से किए गए ट्रांजेक्शन की पड़ताल में सामने आये कई बैंक खातों के बारे में भी सिलसिलेवार छानबीन की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि छानबीन में दलाल फर्मों व पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के बीच सीधे संबंध भी सामने आए हैं। ईओडब्ल्यू इसके साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। 4122.70 करोड़ के भविष्य निधि घोटाले की जांच शासन ने ईओडब्ल्यू को सौंपी है। ईओडब्ल्यू अब तक आरोपित तत्कालीन निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी, सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता, एमडी एपी मिश्र, पीके गुप्ता के बेटे अभिनव व फर्जी ब्रोकर फर्म संचालक आशीष चौधरी को गिरफ्तार कर चुकी है।

7 अलग-अलग जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में रोजवैली चिटफंड घोटाले को लेकर छापेमारी की हैं। इसमें रोजवैली ग्रुप के मालिक गौतम कुंडू की पत्नी शुभ्रा कुंडू का आवास भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सदन में मौजूद रहने की हिदायत दी

सख्त रुख ▸ लोस में पीएम के नाम अंकित प्रश्न के दौरान सदन से गायब थे अधिकांश मंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद में गैरमौजूदगी को लेकर भाजपा सांसदों से कई बार अपनी नाराजगी जता चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मंत्रियों को भी आगाह कर दिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि लोकसभा में जब उनके नाम से प्रश्न अंकित था तब भी सदन से अधिकतर मंत्री गायब थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सामान्य दिनों में मंत्रियों की मौजूदगी कितनी कम होती होगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

दरअसल बुधवार को लोकसभा में कुछ प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछे गए थे। सवालों का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की ओर से दिया गया, आमतौर पर यही परंपरा भी रही है। लेकिन उस समय सदन में स्वयं प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त लोकसभा में मंत्रियों की संख्या बहुत कम थी।

सूत्र बताते हैं कि उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि वह अपनी प्राथमिकताएं किस तरह तय करते हैं। क्या सदन की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? उन्होंने खास तौर से प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों की संसद में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने की ओर इशारा किया। उनकी इस हिदायत का तत्काल असर भी दिखा और गुरुवार को सदन में मंत्रियों की अच्छी खासी संख्या मौजूद थी।

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार को इसके माध्यम से लोक हित में लिए गए अपने विभिन्न फैसलों को रखने का मौका मिलता है।

नरेंद्र मोदी। फाइल

संसदीय समिति की बैठकों में सदस्यों से मौजूद रहने को कहेंगे राज्यसभा सभापति

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू सभी पार्टियों के फ्लोर लीडरों से संसदीय समितियों की बैठकों में अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कहेंगे। यदि लगातार दो बैठकों में सदस्य बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें समिति से हटाया जा सकता है। यह जानकारी गुरुवार को सूत्रों ने दी। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर शहरी विकास पर संसद की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में केवल चार सदस्य मौजूद थे। सभापति ने इसे गंभीरता से लिया है। राज्यसभा सचिवालय के सूत्र ने कहा कि यदि कोई सदस्य संसदीय समिति की बैठक में भाग नहीं लेता है तो उसे समिति से हटाया जा सकता है।

सरकार ने सरोगेसी विधेयक प्रवर समिति को भेजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : विपक्ष की मांग मानते हुए सरकार ने किराए की कोख से संबंधित सरोगेसी विनियमन विधेयक प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने गुरुवार को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने संसद के ऊपरी सदन में इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। प्रवर समिति इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन सदन के पटल पर पेश करेगी।

उच्च सदन ने जब इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित करने की अनुमति दे दी तो सभापति एम. वेंकैया नायडू ने समिति को यह भी निर्देश दिया कि वह अपनी रिपोर्ट के साथ इस बात का ब्योरा संलग्न करे कि समिति के किस किस सदस्य ने इसकी कितनी बैठकों में भाग लिया।

सदन में सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों पर खुलकर चर्चा की। सदस्यों ने कई प्रावधानों में मौजूद विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था। प्रस्तावित कानून को मजबूती देने के मकसद से सरोगेसी के लिए इच्छुक दंपती की पांच साल के वैवाहिक जीवन की शर्त की अवधि को कम करने और 'निकट रिश्तेदार' वाले प्रावधान को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का सुझाव दिया।

एनआरसी को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में केंद्र को घेरा

- सांप्रदायिक आधार पर बांटने की हो रही कोशिश : अधीर रंजन
- माकपा ने भाजपा पर देश में भय और दमन का माहौल बनाने का आरोप लगाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है।

गुरुवार को कांग्रेस सदस्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बगैर एनआरसी को अपडेट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार में एनआरसी को लेकर स्पष्टता नहीं है। वहीं असम में भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार एनआरसी के जरिए धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के एक धड़े को देश से निकालना चाहती है। जबकि अवैध रूप से रह रहे भाषाई अल्पसंख्यक समूह को देश में बसाए रखना चाहती है।

एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मूल याचिकाकर्ता असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्लू) ने अमित शाह की घोषणा का स्वागत किया है। शाह ने कहा था कि पूरे देश में एनआरसी अपडेट होने के दौरान ही असम में फिर से एनआरसी को अपडेट किया जाएगा।

इस बीच, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने भाजपा पर एनआरसी की प्रक्रिया के जरिए देश में भय और दमन का माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने एनआरसी को नागरिकता संशोधन बिल से जोड़ने का भी भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी फिर से लोगों को डराने का काम कर रही है।

वहीं, कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि अगर एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा तो पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध में तनाव आएगा। गौड़ा ने कहा कि सरकार इसे लागू करने के परिणामों पर विचार नहीं कर रही है। इससे नासिर्फ देश में समस्याएं खड़ी होंगी बल्कि दूसरे देशों के साथ रिश्ते भी गंभीर हो जाएंगे।

शाह ने विगत बुधवार को राज्यसभा में कहा था कि देश के सभी नागरिकों को एनआरसी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिर चाहे वह किसी भी धर्म के क्यों न हों। उन्होंने यह भी कहा था कि एनआरसी की प्रक्रिया नागरिकता संशोधन बिल से अलग है। उन्होंने यह भी कहा था कि एनआरसी की प्रक्रिया असम में फिर अपडेट होगी। उसी दिन असम के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि राज्य सरकार ने अमित शाह से अपील की है कि वह मौजूदा स्वरूप में एनआरसी को खारिज करें।

मप्र की सभी चयन परीक्षाओं में लागू रहेगा आर्थिक आधार पर सवर्ण आरक्षण

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में दो जुलाई 2019 के बाद होने वाली सभी चयन परीक्षाओं में कमजोर आर्थिक वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। भर्ती चाहे राज्य लोकसेवा आयोग (पीएससी), प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) या फिर अन्य एजेंसी के माध्यम से हो, सभी में सवर्ण आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। यह बात कमलनाथ सरकार में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति को भी दूर किया जाएगा।

मालूम हो कि राज्य लोकसेवा आयोग ने हाल ही में चार विभागों के 389 पदों की भर्ती निकाली है। खाद्य, वाणिज्यिक कर, श्रम सहित अन्य विभागों के पदों के लिए होने वाली भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण नहीं रखा गया। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के उस आदेश को आधार बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि दो जुलाई 2019 के बाद खाली होने वाले पदों पर ही दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। जबकि, 14 अगस्त को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया, उसमें यह शर्त नहीं रखी गई। डॉ. सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि दो जुलाई के बाद जो भी भर्ती होगी, उसमें नई आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। किसी को कोई भ्रम न हो, इसके लिए एक-दो दिन में आदेश भी जारी हो जाएंगे।

न्यूज गैलरी

चिदंबरम से जेल में पूछताछ करेगा ईडी

नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ करेगा। जांच एजेंसी के अधिकारी 22 और 23 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक और उसके बाद दोपहर ढाई से शाम चार बजे तक तिहाड़ जेल में चिदंबरम से पूछताछ करेंगे। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की अदालत में ईडी ने अर्जी दायर कर रहा था कि कुछ दस्तावेजों के बारे में चिदंबरम से पूछताछ करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने अर्जी को मंजूर कर लिया। इस मामले में चिदंबरम 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत मे हैं। पिछले दिनों हाई कोई ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जमानत अर्जी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आरोप है कि चिदंबरम के वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुई। सीबीआइ की जांच के बाद ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। (जासं)

लता मंगेशकर की हालत में तेजी से सुधार

मुंबई : भारतीय सिनेमा की महान गायिका लता मंगेशकर की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि, वह इस समय भी आइसीयू में भर्ती हैं। 90 वर्षीय मंगेशकर को सांस लेने में तकलीफ के बाद पिछले सप्ताह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता की भतीजी रचना शाह ने बताया कि उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। कृपया हमारी निजता का सम्मान कीजिए। अस्पताल के सूत्रों ने भी पार्श्व गायिका के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से कुछ कहने से इन्कार कर दिया। अपनी सात दशक लंबी संगीत यात्रा में लता ने 30,000 से ज्यादा गाने विभिन्न भाषाओं में गाए हैं। (प्रेट्र)

वायनाड में क्लास में सांप के काटने से छात्रा की मौत, शिक्षक निलंबित

- केरल में अस्पताल ले जाते समय दस साल की शहला ने दम तोड़ा
- शिक्षक ने अस्पताल ले जाने से किया था मना
- सरकारी स्कूल की कक्षा में डेस्क के पास बिल में छिपा था सांप

वायनाड, प्रेट्र : केरल के एक सरकारी स्कूल की कक्षा में सांप के काटने से एक 10 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। यह घटना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के सुल्तान बतेरी कस्बे की है। छात्रा का नाम शहला शरीन है जो सुल्तान बतेरी के शासकीय सर्वजन व्यावसायिक स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ती थी। इस घटना में शिक्षक की घोर लापरवाही के कारण उसे निलंबित कर उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

इस बीच, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने इस घटना पर चिंता जताते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराइ विजयन को चिट्ठी लिखकर कहा कि स्कूलों का आधारभूत ढांचा बहुत ही खराब है और राज्य सरकार को इस पर तत्काल गौर करने की जरूरत है।

बताया जाता है कि दस वर्षीय छात्रा शहला शरीन का पैर क्लास में उसकी डेस्क के पास जमीन पर स्थित एक छोटे से बिल में फंस गया। बच्ची दर्द में तड़पकर चिल्लाती रही कि उसे सांप ने काटा है, लेकिन उसके टीचर ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और पढ़ाना जारी रखा। अध्यापक ने कहा कि गड्ढे में पैर घुसने से उसे कोई कील लग गई है या फिर खरोंच आ गई है। सहपाठियों का आरोप है कि सभी के पास कार है लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसके पिता के स्कूल आने का इंतजार किया गया। लेकिन उसके पिता के आने से पहले ही शहला का पूरा पैर नीला पड़ चुका था।

परिजनों और सहपाठियों के मुताबिक शहला को बुधवार को दोपहर तीन बजे कक्षा में सांप के काटने के एक घंटे से भी अधिक समय की देरी से अस्पताल ले जाया गया था। स्कूल में शिक्षक ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। शहला को उसके परिजन स्कूल पहुंचने के बाद एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां से उसे 90 किलोमीटर दूर स्थित कोझिकोड मेडिकल कालेज के लिए रेफर किया गया। शहला की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसने कोझिकोड मेडिकल कालेज पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना दम तोड़ दिया। शहला के पिता ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें यह नहीं बताया था कि बच्ची को सांप ने काटा है। वह उसे चार अस्पतालों में ले गए लेकिन सांप के काटने का कोई इलाज नहीं किया गया।

शिक्षा विभाग को इस घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर सी. रवींद्रनाथ ने जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में शिक्षक शिजिल की लापरवाही सामने आई, क्योंकि उसने शहला के बिगड़ते स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया। इसके चलते शिजिल को निलंबित कर दिया गया।

वायनाड के जिला कलेक्टर अदीला अब्दुल्ला ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बच्ची के इलाज में देरी को लेकर शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से रिपोर्ट देने को कहा गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को स्कूल का दौरा करने को कहा गया है। कक्षाओं में ऐसे गड्ढों को तत्काल भरने का आदेश दिया गया है। बच्चों का आरोप है कि क्लास में जूते-चप्पल पहने की इजाजत नहीं है। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। दूसरी ओर, राज्य के पीडब्लूडी मंत्री जी.सुधाकरण ने पैरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन (पीटीए) पर दोषारोपण करते हुए कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह क्लास में गड्ढे वाले फर्श में सीमेंट भरवाएं।

रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों की वापसी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों समेत सभी प्रकार के घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील एवं भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर संज्ञान लिया है। याचिका में कहा गया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए 'यहां के नागरिकों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं।' इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा, 'इसे (जनहित याचिका) चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कीजिए।' अपनी याचिका में उपाध्याय ने केंद्र के रुख का समर्थन किया है। केंद्र ने भारत में गैरकानूनी रूप से रह रहे करीब 40,000 रोहिंग्या मुस्लिमों की पहचान करने और उन्हें म्यांमार वापस भेजने की बात कही है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को सभी घुसपैठियों की पहचान, हिरासत और उन्हें वापस भेजने का निर्देश देने की मांग की गई है। घुसपैठ के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

कांग्रेस विधायक अदिति और अंगद परिणय सूत्र में बंधे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- हिंदू और सिख रीति-रिवाज से हुई शादी

पंजाब के नवांशहर से कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह गुरुवार को यहां परिणय सूत्र में बंध गए। शादी की रस्में हिंदू और सिख रीति-रिवाज से संपन्न हुईं।

छतरपुर के जोरबा बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह में उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दिल्ली से भी लोग शामिल हुए। जयमाल में लोगों ने पुष्प वर्षा कर नवदंपती को आशीर्वाद दिया। दूल्हे ने क्रीम कलर की शेरवानी और दुल्हन ने क्रीम कलर का लहंगा पहन रखा था। वैवाहिक कार्यक्रम में भाजपा नेता जगदंबिका पाल, अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडेय, विधायक प्रतीक भूषण समेत तमाम राजनीतिक और पारिवारिक मित्र मौजूद रहे।

उप्र के रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह गुरुवार को नई दिल्ली में पंजाब के नवांशहर से कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी के साथ विवाह बंधन में बंध गईं। जागरण

'इंडियन आइडल' से हटे संगीतकार अनु मलिक

- राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से चैनल को नोटिस भेजे जाने के बाद लिया निर्णय

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

मीटू के आरोपों से घिरे संगीतकार अनु मलिक ने सोनी चैनल पर प्रसारित हो रहे सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल-11' से किनारा कर लिया है। शो से जुड़े सूत्रों ने उनके हटने की जानकारी दी है। उनकी जगह कौन लेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।

दरअसल, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुरुवार को सोनी टीवी को भेजे नोटिस को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। नोटिस में लिखा गया है कि आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए सोनी एंटरटेनमेंट टीवी को नोटिस भेजा है। नोटिस में गायिका सोना महापात्रा के ट्वीट का भी जिक्र है। चैनल से पूछा गया है कि उसने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

सोना महापात्रा ने अनु मलिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गुरुवार को उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लिखे खुले खत में अनु मलिक मामले में दखल देने की गुहार लगाई थी। दरअसल, मंगलवार को ईरानी ने कहा था कि सरकार ने यौन अपराधियों का डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है। इस पर सोना ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए ऐसे संस्थानों को लेकर सवाल उठाया, जो यौन उत्पीड़न के आरोपितों को काम दे रहे हैं। सोना ने खत में लिखा, 'यौन अपराधियों का डेटाबेस बनाने की पहल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। लेकिन, उन संस्थानों का क्या, जो आरोपों के बावजूद लोगों को अपने यहां काम दे रहे हैं। इनमें सोनी टीवी भी एक है, जिसने कई महिलाओं के आरोपों को नजरअंदाज करते हुए अनु मलिक को राष्ट्रीय टीवी पर इंडियन आइडल के लिए युवाओं का जज बना दिया।' सोना ने लिखा, 'क्या यौन उत्पीड़न ही कहानी बताने वाली कई आवाजें कोई मायने नहीं रखतीं? क्या सोनी टीवी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए?'

अनु मलिक। फाइल

भड़काऊ भाषण देने के मामले में तय नहीं हुए आरोप

मुजफ्फरनगर दंगा

जासं, मुजफ्फरनगर : छह वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर के शहीद चौक पर आयोजित सभा में भड़काऊ भाषण देने व अन्य आरोपों के तहत पूर्व सांसद, विधायकों सहित 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। संबंधित मामले में आरोपितों के गुरुवार को कोर्ट में उपस्थिति न होने के कारण आरोप तय नहीं हो सके। सुनवाई की अगली तिथि 12 दिसंबर तय की गई है।

27 अगस्त 2013 को कवाल में शाहनवाज व मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन व गौरव की हत्या से माहौल गरमा गया था। 30 अगस्त 2013 को खालापार मोहल्ले के शहीद चौक पर जुमे की नमाज के बाद एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए थे। इसके बाद नंगला मंदौड़ में भी पंचायत हुई थी, जिसके बाद दंगा भड़क गया था। इस मामले में गुरुवार को आरोप तय होने थे, लेकिन आरोपित पूर्व सांसद कादिर राना व सईदुज्जमां, पूर्व विधायक नूरसलीम राना तथा अहसान कुरैशी पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया।

कैरेबियाई टापू खरीद शाही अंदाज में जिंदगी जीना चाहता था नित्यानंद

- एक पूर्व शिष्या ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, पुलिस को संदेह, विदेश भाग निकला स्वयंभू भगवान

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

आश्रम से दो युवतियों के लापता होने के बाद फिर से चर्चा में आए नित्यानंद स्वामी एक कैरेबियाई द्वीप खरीदकर शाही जिंदगी जीने की योजना बना रहा था। उसकी एक पूर्व शिष्या साराह लेंड्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। कैरेबियाई टापू पर अपनी युवा शिष्याओं के साथ शाही जिंदगी बिताने के लिए नित्यानंद भारत के बड़े शहरों से धन बटोरने में जुटा था। पुलिस को संदेह है कि नित्यानंद देश से फरार हो चुका है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसके पास स्वयंभू भगवान के विदेश भाग जाने की औपचारिक सूचना नहीं है।

महिलाओं के साथ संबंध व अश्लील सीडी को लेकर पहले भी विवादों में रहा नित्यानंद बेंगलुरु की दो बहनों को अहमदाबाद आश्रम लाने के बाद फिर से चर्चा में आया। लड़कियों के पिता जनार्दन शर्मा ने अहमदाबाद पहुंच कर नित्यानंद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अहमदाबाद के हाथीजण इलाके में स्थित आश्रम सर्वाज्ञपीठम में नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर रखने व बेंगलुरु की दो लड़कियों को लेकर गुजरात पुलिस ने नित्यानंद के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आश्रम की दो संचालिकाओं को गिरफ्तार कर लिया है और अब हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

सीबीएसई ने स्कूल की जमीन पट्टे पर देने के बारे में रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बिना अनुमति नित्यानंद के आश्रम के लिए स्कूल की जमीन पट्टे पर देने के मामले में गुजरात शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। सीबीएसई के एक अधिकारी ने बताया, 'बोर्ड ने राज्य शिक्षा विभाग को बिना अनुमति के स्वामी नित्यानंद आश्रम को डीपीएस मणिनगर, अहमदाबाद की भूमि पट्टे पर देने के मामले में जांच करने के लिए पत्र लिखा है। तेजी से जांच करने के लिए कहा गया है और रिपोर्ट के परिणामों तथा सीबीएसई संबद्धता हासिल करने के लिए राज्य द्वारा स्कूल को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की स्थिति से अवगत कराने को कहा है।'

पुलिस ने नित्यानंद आश्रम मामले में केलोरेक्स ग्रुप की दिल्ली पब्लिक सकूल के प्राचार्य हितेश पुरी व बिल्डर बकुल गुणवंत ठक्कर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।

एक आइएएस अधिकारी का नाम चर्चा में

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : विवादों में फंसे नित्यानंद आश्रम की स्थापना में गुजरात के एक आइएएस अधिकारी का नाम चर्चा में है। मुख्यमंत्री रूपाणी ने इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. जेएन सिंह को तलब कर रिपोर्ट मांगी है। आश्रम मामले की जांच पुलिस, शिक्षा विभाग सहित तीन अलग अलग टीमें कर रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिल के ट्वीट के बाद सरकार हरकत में आई और नित्यानंद से संबंध रखने वाले और उसके आश्रम की स्थापना के लिए डीपीएस के साथ करार कराने में अहम भूमिका निभाने वाले आइएएस अधिकारी के बारे में रिपोर्ट मांगी है।

जनमत

मुद्दा

क्या समुचित जल प्रबंधन का अभाव देश में बाढ़, सूखा और पेयजल किल्लत की वजह बन रहा है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

अहम बैठक

केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में जेएनयू प्रकरण, अनुच्छेद 370, मंदिर निर्माण के प्रस्तावों पर हुई चर्चा

अभाविप का राष्ट्रीय अधिवेशन कल से, प्रस्तावों पर हुआ मंथन

जागरण संवाददाता, आगरा

आगरा कॉलेज मैदान में बसाए गए गुरुनानक देव नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार 23 नवंबर को शुरू होगा। गुरुवार को इसके लिए हुई केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस सुब्बैया ने कहा कि 30 हजार परिसर इकाई का गठन किया गया है। इस तरह 60 हजार कार्यकर्ता जुड़े हैं। ऐसे में अनुच्छेद 370, रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण सहित ऐतिहासिक फैसलों से देश में वैचारिक लहर उठी है। इनकी राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्य में कैसे भागीदारी होगी, उसके बारे में विचार मंथन किया जाएगा।

उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहकर कार्यसमिति के सदस्यों में जोश भरा। शाम तक बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, व्यवस्था प्रमुख डॉ. अमित अग्रवाल सहित 40 प्रांतों के कार्यसमिति के 110 सदस्य शामिल रहे।

आगरा में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में विचार व्यक्त करते राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस. सुबय्या। जागरण

वामपंथियों के साथ संघर्ष करने में कोई समस्या नहीं : अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस सुबैय्या ने जेएनयू में चल रहे फीस प्रकरण पर कहा कि अभाविप को वामपंथियों के साथ संघर्ष करने में कोई समस्या नहीं है।

जेएनयू प्रकरण में वामपंथियों के साथ अभाविप भी प्रदर्शन कर रही थी लेकिन, भारत के टुकड़े-टुकड़े के नारे लगाने, अभाविप और संघ के खिलाफ प्रदर्शन करने और शिक्षिका को 30 घंटे तक बंधक बनाए रखने की घटनाएं हुईं तो अभाविप अलग हो गया। यह विरोध का तरीका नहीं होना चाहिए, छात्रों की समस्या को शांतिपूर्वक तरीके से सामने रखा जा सकता है। यह आंदोलन का अंतिम चरण होता है लेकिन जेएनयू में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। कुछ राष्ट्रदोही शक्तियां हैं जो ऐसा काम करा रहीं हैं। इसके चलते इस तरह का विरोध किया जा रहा है।

छात्र हित के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी अभाविप : अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने बताया कि छात्रों की समस्याओं के निस्तारण और छात्र हित के लिए सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किए जाएंगे। जेएनयू प्रकरण में यूजीसी और एमएचआरडी का निर्णय गलत रहा, इसके विरोध में अभाविप ने आंदोलन शुरू कर दिया है।

आइपीएस अधिकारी ने अंग्रेजी में लिखी फरियाद, पुलिस का एफआइआर से इन्कार

निशांत यादव, लखनऊ

तकनीक के सहारे 'स्मार्ट' बनने का दावा करने वाली राजधानी पुलिस अंग्रेजी के चंद शब्दों के आगे बेबस नजर आई। वह भी तब, जब दुनिया की सबसे ज्यादा बोली और लिखी जाने वाली भाषा में शिकायत आमजन ने नहीं, बल्कि गुजरात कैडर के आइपीएस ने की थी, जिसे देखकर स्थानीय पुलिस ने यह भी जानना उचित नहीं समझा कि शिकायतकर्ता कौन है? आखिरकार जब मामला एसएसपी तक पहुंचा तो दिन बाद मुकदमा दर्ज हो सका।

विनोद कुमार मल 1986 बैच के गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी हैं। वह गुजरात में एडीजी (पुलिस रिफार्म) के पद पर तैनात हैं। उनका चिनहट के सतरिख में प्लॉट है। जिस पर उन्होंने सागौन व अन्य पेड़ लगा रखे हैं। कुछ दिन पहले प्लॉट से सागौन के दो पेड़ चोरी हो गए, जिसकी सूचना परिवारीजनों द्वारा दिए जाने पर एडीजी ने अंग्रेजी में तहरीर लिखकर भिजवा दी। जब तहरीर चिनहट पुलिस के सामने पहुंची तो उसने शिकायतकर्ता से दो टूक कह दिया कि अंग्रेजी नहीं, हिंदी में लिखकर लाओ शिकायत तब दर्ज करेंगे। जानकारी मिलने पर आइपीएस विनोद कुमार मल ने एसएसपी कलानिधि नैथानी को पूरे प्रकरण की जानकारी दी। तब जाकर बुधवार को चोरी का मामला दर्ज हो पाया। हालांकि, इस मामले में एसएचओ सचिन कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने किसी रिपोर्ट को दर्ज करने से मना नहीं किया है।

> मामले की जानकारी हुई है। यह गंभीर है कि शिकायत को अंग्रेजी में नहीं लिया गया। इस मामले में इंस्पेक्टर से जवाब मांगा गया है।
> –कलानिधि नैथानी, एसएसपी लखनऊ

दैनिक जागरण

ईश्वर के प्रत्येक कार्य में कोई विशेष प्रयोजन अवश्य होता है

चुनावी बांड पर हंगामा

संसद के दोनों सदनों में चुनावी बांड को लेकर जो हल्ला हुआ उससे यही इंगित होता है कि मकसद हंगामा खड़ा करना अधिक था, न कि समस्या के सही समाधान पर चिंतन करना। हालांकि दो साल पहले जब चुनावी बांड संबंधी योजना लाई गई थी तभी यह स्पष्ट था कि यह व्यवस्था चुनावी चंदे को लेकर उठने वाले सभी सवालों का समाधान नहीं करती, लेकिन विपक्षी दलों ने न तो तब चुनावी चंदे की बेहतर व्यवस्था को लेकर कोई ठोस सुझाए दिए और न ही अब दे रहे हैं। यह भी कोई छिपी बात नहीं कि चुनावी बांड पर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी आपत्ति जताई थी। अब यह कहा जा रहा है कि चुनावी बांड पर रिजर्व बैंक की भी राय सरकार के रुख से अलग थी। ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनावी चंदे की व्यवस्था तय करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है? यह काम तो राजनीतिक दलों का है। यदि चुनावी बांड की व्यवस्था में खामियां हैं तो आवश्यक यह है कि राजनीतिक दल उन्हें दूर करने के उपाय बताएं। आखिर जब वे यह मान रहे हैं कि चुनावी बांड से पहले की व्यवस्था भी खामियों से भरी थी तो फिर केवल हंगामा खड़ा करने से क्या हासिल होने वाला है?

विपक्षी दलों को इस पर आपत्ति है कि चुनावी बांड खरीदकर राजनीतिक दलों को देने वालों की पहचान गोपनीय रहती है, लेकिन वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जब पहचान उजागर करने का चलन था तो राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों और खासकर उद्योगपतियों को किस तरह निशाना बनाया जाता था। कई बार तो ऐसा राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया जाता था। यह कहना एक सीमा तक ही सही है कि चुनावी बांड की व्यवस्था से सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ मिल रहा है, क्योंकि कोई भी दल सदैव सत्ता में नहीं रहता। चूंकि चुनावी बांड वाली व्यवस्था का निर्माण करते समय सरकार ने यह वायदा किया था कि इसमें सुधार के सुझाव सामने आए तो उन्हें शामिल किया जाएगा इसलिए बेहतर होगा कि इस पर ईमानदारी से विचार-विमर्श किया जाए कि चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था कैसे बने? क्या यह विचित्र नहीं कि राजनीतिक दल यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि उन्हें मिलने वाले चंदे की पारदर्शी व्यवस्था कैसे बने? ऐसा तब है जब वे यह अच्छे से जान रहे हैं कि चुनावों में कालेधन की भूमिका बढ़ती जा रही है। जब पैसे के बलबूते चुनाव लड़ने का सिलसिला तेज होता जा रहा हो तब जरूरत चुनावी बांड पर हंगामा करने की नहीं, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाने की है।

...ताकि हमले रुकें

पूर्ण शराबबंदी के बाद बिहार में पुलिस पर हमले बढ़े हैं। हर दूसरे दिन ऐसी शिकायतें राज्य के विभिन्न हिस्सों से आती रहती हैं। इसमें दो राय नहीं कि अवैध शराब के कारोबारी अपने काले धंधे को चलाने के लिए हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार हैं। यह अलग बात है कि कानून के शिकंजे में आने के बाद उनकी दशा खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति तब है जब गांव-गांव से शराब के खिलाफ आवाज उठी थी। विशेषकर महिलाओं ने शराबबंदी लागू कराने के लिए सीधे मुख्यमंत्री से आग्रह किया था। उन्हें दिए गए आश्वासन का ख्याल करते हुए राज्य सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की। कानून में संशोधन किए गए। शराबबंदी के बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निबटने के लिए उपाय किए गए। शराब के लती लोगों की स्थिति न खराब हो इसके लिए नशामुक्ति केंद्र खोले गए। इन केंद्रों में लोगों का इलाज भी होता रहा, लेकिन सतर्कता के मोर्चे पर कहीं न कहीं चूक होती रही। इस अभियान को शुरुआत के दिनों में जिस प्रकार गांव-समाज का सहयोग मिलता रहा, वह अब नहीं दिखता। शराब के धंधे के खिलाफ महिलाओं का प्रचंड विरोध भी शिथिल होने लगा है। जाहिर है, जागरूकता और सतर्कता का पक्ष कहीं न कहीं कमजोर हुआ है। शुरुआती दिनों में विशेषकर अवैध शराब भट्ठियों के खिलाफ महिलाएं ही इस कदर विरोध में आ रही थीं कि पुलिस का काम खुद ब खुद हो जा रहा था। समाज के समझदार लोग भी इसमें सहयोग कर रहे थे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ा। ऐसे कार्य वहां भी हुए जहां पुलिस का पहुंचना कठिन था। ये हालात अब बदल रहे। अब सुदूर इलाका हो या खुला बाजार, अवैध कारोबारी पुलिस पर हमलावर हो जा रहे हैं। मंगलवार को भी वैशाली जिले के कर्णपुरा गांव में उत्पाद टीम पर शराब माफिया हमलावर हो गए। बताया गया कि इस हमले में कुछ ग्रामीण भी शरीक हो गए। टीम के सदस्यों को जान बचाकर भागना पड़ा। हालांकि अन्य थानों की टीम के वहां पहुंचने पर हमलावर भाग निकले। गौर करने वाली बात है कि यदि ग्रामीण शराब के अवैध कारोबारियों के पक्ष में नहीं आते तो संभवतः वे हमलावर नहीं होते।

> अवैध शराब के खिलाफ अभियान को और सुदृढ़ करने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। इसके लिए जागरूकता अभियान को मजबूत करना होगा। लोग सजग होंगे तभी राज्य में शराबबंदी की योजना सफल हो सकेगी

राजनीति के दुष्चक्र में फंसा जेएनयू

शंकर शरण

> चूंकि महान शिक्षा चिंतकों ने कभी यह अनुशंसा नहीं की कि विश्वविद्यालयों को 'राजनीति की नर्सरी' बनाया जाए इसलिए उसे रोकना उचित ही नहीं, अनिवार्य भी है

अवधेश राजपूत

यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की स्थापना का पचासवां साल है। ऐसे में उसकी उपलब्धियों की पड़ताल की जानी चाहिए। आज तक वहां से किसी चर्चित शोध, अध्ययन या लेखन संबंधी कोई समाचार सुनने को नहीं मिला। न केवल ज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि खेलकूद, रंगमंच, कला या राष्ट्रीय नीति-निर्माण में भी उसका कोई योगदान नहीं रहा। जबकि पश्चिम के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सामाजिक चिंतन, शोध, वैदेशिक अध्ययन आदि में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। इसीलिए वे प्रसिद्धि पाते हैं, किंतु जेएनयू से आज तक कोई ऐसी पत्रिका तक प्रकाशित नहीं हो सकी, जिसे कोई जानता हो। सवाल है कि ऐसा क्यों? दरअसल जहां राजनीति का सर्वाधिकार हो वहां गंभीर अध्ययन, लेखन नहीं पनप सकता। इसीलिए केवल वामपंथी राजनीति के समाचारों से ही जेएनयू चर्चा में रहा है। नवीनतम समाचार स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अपमान है, जिसे रफा-दफा करने के लिए फीस वृद्धि को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। पिछली बार भी 'भारत तेरे टुकड़े होंगे...!' और 'अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं' वाली कुख्याति को दबाने के लिए वामपंथियों ने राष्ट्रवाद पर भड़कीली बहस की मुहिम चलाई थी। दरअसल असली बात को दबाकर ध्यान बंटाने की वामपंथी तकनीक इसलिए सफल हो जाती है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वियों में समझ का अभाव है। उन्होंने मामले को सिर से पकड़ने के बजाय लजाते हुए 'राष्ट्रवाद' की अपनी नीति को स्थापित करने की कोशिश की है। फलतः वामपंथी निश्चिंत होकर हमले करते रहते हैं। इस प्रकार जिन्हें सफाई देनी थी, वही कोतवाल बन जाते हैं और जिन्हें हिसाब लेना था, वही अपना हिसाब देने लगते हैं। कायदे से वामपंथियों को कठघरे में खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि वे आरंभ से ही जेएनयू के शैक्षिक वातावरण को विषाक्त करते रहे हैं।

एक बार भारत-पाक क्रिकेट मैच के दौरान जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे थे। भारत की जीत पर खुशी मनाने वालों पर हमला हुआ था। उससे पहले अशोक स्तंभ वाले राष्ट्रीय चिन्ह को जूते के नीचे मसले जाते पोस्टर लगाए गए थे। करगिल युद्ध लड़ने वाले सैनिकों को जेएनयू में पीटा गया था, क्योंकि उन्होंने वहां एक मुशायरे में चल रही पाकिस्तानपरस्ती एवं भारत-निंदा का विरोध किया था। एक बार नक्सलियों द्वारा 70 सुरक्षाकर्मियों की हत्या किए जाने पर जेएनयू में जश्न मनाया गया था। ऐसे ही समाचारों से जेएनयू सुर्खियों में आता है। वहां आरंभ से ही देसी-विदेशी भारत निंदकों को मंच मिलता है, किंतु देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तक को बोलने नहीं दिया जाता। ऐसा कोई भाजपा के मंत्रियों के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि इंदिरा गांधी और पी. चिदंबरम भी ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं। उनके विश्वविद्यालय में आगमन तक के विरुद्ध आंदोलन हुआ था।

देखा जाए तो जेएनयू में स्वतंत्र या देशभक्त स्वरों को वैसा सम्मान नहीं मिला, जैसा माओवादियों, जिहादियों को मिला है। जेएनयू में वामपंथियों को अरुण शौरी जैसे विशिष्ट विद्वान का व्याख्यान नागवार गुजरता था, जबकि स्टालिन, माओ और अराफात के लिए वे आहें भरते थे। वहां के नामी प्रोफेसर 'स्टालिन या त्रॉत्सकी' पर 'रात भर चलने' वाली बहसों के सिवा कुछ याद नहीं कर पाते कि उन्होंने वहां दशकों तक क्या किया?

दरअसल जेएनयू में बेहतरीन सुविधाओं के कारण यह बात छिपी रही है कि ज्ञान हासिल करने के नाम पर वहां बताने के लिए कुछ नहीं है। कुछ वर्ष पहले जब किसी पत्रकार ने जेएनयू की चार दशक की उपलब्धियों के बारे में वहां के रेक्टर से पूछा तो उनका जवाब था कि जेएनयू से अब तक सिविल सर्विस में इतने छात्र चुने गए हैं। सवाल है कि क्या इसीलिए यह विश्वविद्यालय बना था कि वहां नौकरी की तैयारी या माओवादियों, जिहादियों तथा विविध देशद्रोही, उग्र राजनीतिबाजी के आरामदेह अड्डे बनें? आखिर जिन छात्रों ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, उन्हें किन संगठनों और सीखों ने ऐसा करने को प्रेरित किया? सरकार को यही चिंता करनी चाहिए कि वहां सामाजिक विषयों की शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता है और क्या नहीं? यही मूल गांठ है, जिसे खोलने पर ऐसी लज्जास्पद घटनाओं के दोहराव से मुक्ति मिलेगी। सरकार को जेएनयू में सियासी गतिविधियों और छात्रसंघ को खत्म कर देना चाहिए, जिसके जरिये वहां देश विरोधी राजनीतिक गतिविधियां होती रही हैं। अभिभावक भी ऐसे छात्रसंघ को समाप्त करने के पक्ष में होंगे, जो उनके बच्चों को देश विरोधी या हानिकर गतिविधियों में खींच कर उनका समय या जीवन खराब करता रहा है।

राजनीतिक नारे लगाने वाले छात्रों को शायद ही किसी समस्या का वास्तविक ज्ञान रहता है। वे कश्मीर, इस्लामिक स्टेट या हिंदुत्व के बारे में उतना ही जानते हैं, जितना जेएनयू में चहकने वाले पंछी। इसलिए उनका इस्तेमाल बाहरी, भारत-विरोधी, हिंदू-विरोधी रणनीतिकार करते हैं। अबोध उग्र छात्र भावना, जोश और अज्ञानता में अदृश्य ताकतों की सेवा कर रहे हैं। चूंकि देश-विदेश के महान शिक्षा चिंतकों ने कभी यह अनुशंसा नहीं की है कि विश्वविद्यालयों को 'राजनीति की नर्सरी' बनाया जाए इसलिए उसे रोकना उचित ही नहीं, अनिवार्य भी है। यदि ऑक्सफोर्ड जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में जेएनयू जैसे छात्रसंघ नहीं हैं तो वहां के छात्र कोई वंचित-पीड़ित तो नहीं हैं। छात्रों की भलाई के लिए भी विश्वविद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों का खात्मा जरूरी है।

छात्रों को केवल साहित्य, कला, संगीत, खेलकूद आदि के लिए ही सुविधाएं, प्रोत्साहन मिलने चाहिए। साथ ही समाज विज्ञान और मानविकी विषयों के पाठ्यक्रम की समीक्षा भी जरूरी है। जेएनयू में वामपंथी राजनीति का जीवन स्रोत यही रहा है। इन विषयों में पढ़ाई का मुख्य लक्ष्य छात्रों में एक खास राजनीतिक मनोभाव भरना है। इसे बदले बिना इतिहास, दर्शन, साहित्य के मामूली शिक्षक भी पैदा नहीं हो सकते, विद्वान बनना तो दूर की बात है। यहां पढ़ाए जाने वाले साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि में वामपंथी और हिंदू-विरोधी मतवाद के तत्व जगह-जगह, सुचिंतित रूप से जमाए गए हैं। किसी महान लेखक, पुस्तक या महत्वपूर्ण प्रसंग को हटाकर मामूली पाठ या प्रसंग इसीलिए डाले गए हैं, ताकि छात्रों में इससे 'प्रगतिशील' यानी हिंदू-विरोधी मनोभाव को बल मिले। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में समाज विज्ञान और मानविकी के संपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यसूची, शोध-दिशा आदि की आमूल समीक्षा होनी चाहिए। इसके बिना केवल जहां-तहां विवेकानंद की मूर्तियां लगवाकर उनका अपमान करवाना कोई समझदारी नहीं है। विश्वविद्यालयों में एक एक्टिविज्म का जवाब दूसरे एक्टिविज्म से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि तमाम राजनीतिक एक्टिविज्म को खत्म करके शुद्ध शिक्षा को स्थापित किया जाना चाहिए। यही शिक्षा का वातावरण बनाने का सही रास्ता है।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

एंटीबायोटिक का अनावश्यक इस्तेमाल

केनेथ आइ जस्टर

> एंटीबायोटिक के अत्यधिक इस्तेमाल से उपजी समस्या का अमेरिका और भारत मिलकर समाधान निकाल सकते हैं

आखिर किसने सोचा होगा कि फफूंदी लगे खरबूजे में लाखों लोगों की जान बचाने की कुंजी छिपी हुई है? पेन्सिलीन नाम का पहला एंटीबायोटिक ब्रिटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजा था। फिर भी 1942 तक इसका व्यापक रूप से उत्पादन संभव नहीं हो पाया। इस बीच अमेरिकी दवा उद्योग ने खरबूजे में एक खास तत्व की मदद से यह संभव कर दिखाया। इसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तमाम सैनिकों की जान बचाई जा सकी। इस चमत्कारिक दवा के चलते प्रथम विश्व युद्ध के दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकी। असल में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के दौरान मिले घावों के बजाय उनमें संक्रमण के चलते अधिक सैनिकों की जान गई थी। सामान्य स्थितियों में भी न्यूमोनिया और त्वचा संक्रमण के चलते लोगों की मौत के मामले कम हुए हैं। इस बीच तमाम लोगों ने सोचा कि संक्रामक रोगों के खिलाफ जंग जीत ली गई है, मगर पेन्सिलीन के बेअसर होने के संकेत भी मिले। इन संकेतों का जवाब नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज ने दिया। 1985 के अंत में इनफेक्शियस डिजीज सोसायटी ऑफ अमेरिका की वार्षिक बैठक के एक प्रमुख व्याख्यान में संक्रामक रोग विशेषज्ञों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। इस बीच 35 वर्षों से भी कम समय में एक नई वास्तविकता यह सामने आ रही है कि ये जीवनरक्षक दवाएं अब बेअसर हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एंटी-माक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर का नाम दिया है। इसे सुपरबग भी कहा जाता है।

जब बीमारियों पर दवाओं का असर खत्म हो जाता है तब सुपरबग वाली स्थिति बन जाती है। इसे मानव स्वास्थ्य पर शीर्ष दस खतरों में शुमार किया गया है। इसी सुपरबग के चलते सालाना तकरीबन 2,14,000 नवजात शिशु काल के गाल में समा जाते हैं। दुनिया भर में एएमआर का यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। ऐसे में यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो एंटीबायोटिक प्रतिरोध हमें फिर से उस स्थिति में पहुंचा सकता है जहां सामान्य से संक्रमण में व्यक्ति की मौत तक हो जाती थी। स्पष्ट है कि हमने एंटीबायोटिक्स के अनमोल खजाने को बेवजह लुटाया है। हम मानव एवं पशुओं में बेतरतीब तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह समस्या गलत धारणाओं से उपजी है। जैसे कि आम सर्दी या फ्लू में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि तथ्य यही है कि ऐसे विषाणु पर ये बेअसर हैं। ऐसी गलत धारणाओं ने एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित उपयोग को जन्म दिया है। वास्तव में इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिवर्ष नवंबर माह में एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाता है।

एक अनुमान है कि अस्पतालों में प्रयुक्त आधे से अधिक एंटीबायोटिक अनावश्यक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। जानवरों में भी एंटीबायोटिक्स का अनुचित उपयोग होता है। इनमें से तमाम दवाओं का इस्तेमाल स्थिति बेहतर बनाने के बजाय और बिगाड़ता ही है। इस मोर्चे पर यह बहुत चिंताजनक है कि बीते चालीस वर्षों में एंटीबायोटिक दवाओं का कोई नया वर्ग विकसित नहीं किया गया है। भारत और अमेरिका एएमआर खतरे के प्रति चिंतित हैं। अमेरिका में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं भारत में कुल एंटीबायोटिक उपभोग काफी अधिक है। यह चुनौतीपूर्ण स्थिति अवश्य है, लेकिन सुधार की उम्मीद शेष है। अमेरिका और भारत में साथ मिलकर किसी भी समस्या का संभावित समाधान खोजने की अपार क्षमताएं हैं। जहां दवा उद्योग में नए आविष्कारों और संक्रामक रोगों पर निगरानी प्रणाली के मामले में अमेरिका अग्रणी देश है। वहीं भारतीय दवा उद्योग भी बहुत अच्छी स्थिति में है। यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी बढ़िया है। बहरहाल इस समस्या से निपटने के लिए हम कई स्तरों पर काम कर रहे हैं। इसके तहत अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण को मजबूत बनाने के साथ ही रोगाणुरोधी-प्रतिरोधी संक्रमणों की निगरानी प्रणाली बनाई जा रही है। वैज्ञानिकों और एएमआर के लिए समाधान तलाशने वाले वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है। साथ ही नए शोध एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी बढ़ाया जा रहा है। यह प्रतिबद्धता पिछले महीने तब दोहराई गई जब मैं एएमआर संबंधी अनुसंधान और नीति के एक नए केंद्र का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता गया। मेरे साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव भी शामिल थे। वहां मैंने संकल्प लिया कि एएमआर का मुकाबला करने में हम भारतीय सहयोगियों के साथ अपनी सक्रियता और बढ़ाएंगे। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैसे सहयोगी शामिल हैं। जब हमारी सरकारें इस समस्या को सुलझाने में जुटी हैं तो इसके व्यापक समाधान के लिए सामूहिक भागीदारी भी जरूरी होगी। हमें एंटीबायोटिक लेने से पहले एक योग्य डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा ताकि संक्रमण न फैल सके। अच्छी तरह से हाथ साफ करना, मुंह पर हाथ रखकर खांसना और बीमार होने पर बेहतर हो तो घर में ही रहने जैसे उपाय करने होंगे। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को संक्रमण नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए मान्य दिशानिर्देशों को अपनाया जाए। दवाओं में अनावश्यक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने से बचें। साथ ही संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाए। किसानों को भी अपने मवेशियों का टीकाकरण कराना चाहिए। इसमें यह ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया किसी कुशल पशु चिकित्सक की देखरेख में ही संपन्न हो।

दवा उद्योग का भी यह दायित्व है कि वह नए एंटीबायोटिक की खोज करे। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनके साथ सुपरबग वाली स्थिति भी उत्पन्न न हो। हमें इस चुनौती का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तरों जवाब देना होगा। एएमआर से मुकाबले में अमेरिका और भारत के साझा प्रयास दोनों देशों के अलावा पूरी दुनिया के लिए लाभ के प्रतीक होंगे।

(लेखक भारत में अमेरिका के राजदूत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

झगड़ा

झगड़ा करना विनाश को न्योता देना होता है और मूर्ख ही झगड़ा करते हैं। भक्त अगर झगड़ा करें तो वे भक्त नहीं कहे जा सकते हैं। वे ढोंगी होते हैं। वे नहीं जानते हैं कि भगवान की भक्ति किसलिए की जाती है और भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? भक्ति का उद्देश्य समझ लेना भक्त का सबसे पहला कार्य है। भक्ति करके ही ज्ञान को पाया जा सकता है। जो भक्त ज्ञानी होता है वह समस्त जीव-जंतुओं में अपने आराध्य की सत्ता को विद्यमान देखता है। फिर वह कैसे अपने आराध्य से द्वेष-द्वंद्व कर सकता है। भक्त के लिए तो प्रत्येक प्राणी, जीव-जंतु, वृक्ष, वनस्पति, पत्थर, पहाड़ सब पूज्य होते हैं। भला वह पूज्य वस्तु को कैसे अनादर कर सकता है?

मानव जीवन की परिपूर्णता-सार्थकता तो प्रत्येक जीव-प्राणी से प्रेम विकसित करने पर ही सफल मानी जाती है। इसके अभाव में तो भगवान भी स्वयं अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा-विश्वास समर्पण की भावना ही नहीं होती है। तुच्छता का भाव ही झगड़ा-झंझट की स्थिति-परिस्थिति की रचना का सूत्रधार बनता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना प्रत्येक प्राणी को सुख-आनंद देने के उद्देश्य से की है और यह संभवतः प्रेम को हृदय में विकसित करने से ही संभव हो पाता है। प्रेम पवित्रता को अपनाने से होता है। पवित्रता श्रद्धा से आती है। श्रद्धा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा पुण्य की प्रबलता से प्राप्त होती है। पुण्य की प्राप्ति से सत्कर्म और सद्ज्ञान की वृद्धि होती है। सत्कर्म और सद्ज्ञान की वृद्धि से मनुष्य देवता की श्रेणी में पहुंच जाता है। और जो देवता होते हैं उन्हें ईश्वर अपने गले का हार बनाकर रखता है, क्योंकि सृष्टि की सुरक्षा देवता गण के द्वारा होती है।

जहां की सभ्यता-संस्कृति देवत्व संपन्न होती है वहीं सुख-शांति की वर्षा होती है। अमन-चैन आता है। झगड़ा-झंझट तो असुर संस्कृति की पहचान है। प्रत्येक मनुष्य को इन दुर्गणों से बचना ही विवेकशील होने की पहचान है। झगड़ा करने से संस्कृति दूषित हो जाती है। इससे बचने की जरूरत है।

मुकेश ऋषि

उम्मीद जगाता दायित्वबोध

डॉ. मोनिका शर्मा

> सोशल मीडिया के साथ सामाजिक जवाबदेही भी जुड़ी है। यूजर्स के दायित्वबोध का यही व्यवहार अयोध्या निर्णय पर देखने को मिला है

देश में सोशल मीडिया यूजर्स की बढ़ती संख्या ने उनके वैचारिक प्रभाव की अहमियत बढ़ा दी है। अभिव्यक्ति की आजादी वाले हमारे देश में हर तबके, हर आयु वर्ग के लोग इन आभासी मंचों पर मौजूद हैं। फेसबुक, वाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की सूचनाएं पढ़ने, देखने और शेयर करने की आदत बढ़ी है। इंटरनेट और स्मार्ट गैजेट्स की पहुंच के चलते बड़े शहरों में ही नहीं, अब गांवों-कस्बों में भी लोग सोशल मीडिया के जरिये देश-दुनिया की खबरों से जुड़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहां हर हफ्ते यूजर्स का औसतन 17 घंटे का समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीत रहा है। कुछ समय पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु के परिवारों पर किए गए एसोचैम के सर्वेक्षण में करीब 80 फीसद प्रतिभागियों ने कहा कि सुबह-सुबह परिवार के युवा सदस्य विभिन्न सोशल साइटों पर जुटे रहते हैं, जहां उनकी रुचि से संबंधित जानकारियों और खबरों का भंडार है। इन माध्यमों के जरिये समाचार और सूचनाएं क्लिक भर में लोगों तक पहुंच रही हैं।

इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स को भी संबंधित विषयों पर अपने विचार रखने का मंच मिलता है। हर विषय पर लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। ऐसे में अहम न्यायिक फैसलों, सरकारी नीतियों और सामाजिक विषयों को लेकर यहां विचार-विमर्श होता रहता है। कई बार इन विषयों से जुड़ी बातें कटुता और द्वेष भी लिए होती हैं। सहमति-असहमति का भाव हद दर्जे की आलोचना और व्यक्तिगत टीका-टिप्पणियों तक पहुंच जाता है। पल भर में कितनी ही आधारहीन खबरें वायरल कर दी जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दुनिया के 22 देशों में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 64 फीसद भारतीयों को फर्जी खबरों का सामना करना पड़ता है। दुखद है कि आभासी दुनिया में फैली ऐसी अफवाहों पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में वाट्सएप पर फैली बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते भीड़ ने कई लोगों की जान तक ले ली है। कितनी ही नकारात्मक खबरें समाज में खून-खराबे का कारण तक बनी हैं।

निःसंदेह सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ सामाजिक जवाबदेही भी जुड़ी है। यूजर्स के दायित्वबोध का यही व्यवहार अयोध्या निर्णय के समय देखने को मिला है। अभिव्यक्ति के इन मंचों का आमजन द्वारा किया गया सधा और सकारात्मक इस्तेमाल एक नई उम्मीद जगाता है। स्वच्छंद और अराजक अभिव्यक्ति के बजाय लोगों ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की सोची। मनमानी से परे आत्मनियमन का यह व्यवहार कोलाहल के बजाय संवाद करने के अर्थपूर्ण हालात बनाने की बात कहता है। तकनीकी विकास के जरिये मिली सुविधाओं को बेहतरी और बदलाव का माध्यम बनाने की स्थितियों को सामने रखता है। सबसे अहम बात यह कि इसमें देश की आम जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी है। आशा है कि सोशल मीडिया यूजर्स की यह परिपक्वता और समझदारी आगे भी देखने को मिलेगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

लागू हो शिक्षण शुल्क की समान नीति

शिक्षा संस्थानों की फीस का सवाल शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रो. निरंजन कुमार ने जेएनयू कैंपस में शुल्क वृद्धि को लेकर उभरने वाले छात्र आक्रोश के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थानों की शुल्क वृद्धि से संबंधित जो सुझाव दिए हैं, वह इस समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। वस्तुतः इस समस्या के निराकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण शुल्क की एक समान नीति लागू की जानी चाहिए। जिसमें सभी छात्रों के लिए शुल्क भुगतान की एक नीति और प्रकिया निर्धारित हो। ऐसे में जो अति गरीब छात्र विश्वविद्यालय का निर्धारित शुल्क भुगतान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे प्रतिभाशाली गरीब विद्यार्थी अर्थाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न हो सकें। यह रास्ता ब्याज मुक्त बैंक शिक्षा ऋण का भी हो सकता है, जो न केवल गरीब विद्यार्थियों को मुफ्तखोरी की अपसंस्कृति से दूर रखेगा, अपितु व्यवसायरत होने के बाद ऐसे सभी गरीब विद्यार्थी स्वाभिमान पूर्वक शिक्षा ऋण के रूप में लिया गया बैंक का मूलधन भी आसान किस्तों में वापस कर सकेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकार द्वारा अनुदानित इन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की एक निर्धारित आयु सीमा हो, जो अधिकतम 30 वर्ष से अधिक न हो। इससे जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में उन उम्रदराज छात्र/छात्राओं के प्रवेश पर रोक लग सकेगी जो 40 या उससे अधिक आयु तक बेवजह विश्वविद्यालयों में रुककर छात्र राजनीति का हिस्सा बनते हैं। इस समय शुल्क वृद्धि की ओट में जेएनयू के छात्रों द्वारा जो शोरगुल किया जा रहा है, उसमें ऐसे उम्रदराज छात्रों की संख्या ही अधिक है। यही छात्र टुकड़े-टुकड़े गैंग का सदस्य बनकर देश विरोधी राजनीति का हिस्सा बनते हैं, जो देशहित में नहीं है। देश की युवा पीढ़ी राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सके, ऐसा प्रयास विश्वविद्यालयी शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मिलावटखोरी बड़ा अपराध

देश की राजधानी दिल्ली में केवल वायु और पानी ही प्रदूषित नहीं हैं, जो लोगों को बीमार बना रहे हैं। यहां शुद्ध खाने-पीने की चीजें भी हासिल करना मुश्किल काम है। अधिक पैसा कमाने की होड़ में हर चीज में मिलावट की जा रही है। पैसा देने के बाद भी दूध-घी, मसाला, फल सब्जी कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा। आयुर्वेद में जिन चीजों को स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बताया जाता है, वे भी बाजार में नकली मिल रहे हैं। भला उसे खाकर कोई कैसे स्वस्थ रह सकेगा। पूर्व में चाय की पत्ती में क्या-क्या मिलाकर बेचने की खबर आई ही थी, अब नकली जीरा भी बाजार में मिल रहा है। इस जीरे से छौंकी दाल कैसे सुगंधित और पौष्टिक होगी? डॉक्टर जिस फल को खाने को कहते हैं, उसमें हानिकारक रसायन चिपके होते हैं। पता नहीं जड़ी बूटियां बाजार में असली बिक रही हैं या वे भी नकली हैं। कायदे में मिलावट करना बड़ा अपराध माना जाना चाहिए और उसी के अनुरूप इसमें दोषी पाए जाने पर मिलावटखोरों को सजा भी होनी चाहिए।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

विरोध असंवैधानिक

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में डॉक्टर फिरोज खान की नियुक्ति पर हमें गर्व क्यों न हो? मूर्ति को गुरु मान कर शिक्षा प्राप्त करने की परंपरा सनातनी विरासत का हिस्सा है, जहां गुरु की पहचान उसकी जाति, धर्म और वेशभूषा नहीं, बल्कि उसकी योग्यता होती है। देवतुल्य गुरु के धार्मिक आचरण पर संदेह करने से पहले अपना आचरण परखना जरूरी है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत डॉक्टर खान का चुनाव हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचय देता है। बात-बात पर मुस्लिम देश चले जाने की सलाह देने वालों को इस बात से राहत मिलनी चाहिए कि हमारी भाषा को हमसे बेहतर जानने वाला एक मुस्लिम धर्मावलंबी है। फिरोज खान का मूल्यांकन उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बजाय भाषा के प्रति व्यक्तिगत समर्

30 करोड़ लोग देश भर में किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़े हैं और समूचे देश में लगभग आठ लाख सहकारी संस्थाएं विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनका अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान है।

अयोध्या मामला

पुनर्विचार याचिका के फैसले का निहितार्थ

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला देने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का जो निर्णय किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण, दुखदायी और क्षोभ पैदा करने वाला तो है, लेकिन इसमें आश्चर्य का कोई पहलू नहीं है। फैसले के साथ ही यह साफ दिखने लगा था कि कुछ चेहरे, जिनका वजूद ही अयोध्या विवाद पर टिका है और जो देश में स्वयं को मुसलमानों का एकमात्र नेता बनने का ख्वाब पाल रहे हैं, वे इस मुद्दे को यूं ही हाथ से जाने नहीं देंगे

अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से देश के बहुमत ने यह सोचते हुए राहत की सांस ली कि लगभग पांच सदी के विवाद का बेहतरीन हल निकल आया है। किंतु कुछ ही समय बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी यह कहते हुए सामने आ गए कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, और इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय पर भी जिस तरह की टिप्पणियां कीं और अभी भी कर रहे हैं वो सब देश के सामने है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला करना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा।

वास्तव में फैसले के बाद आम मुसलमानों की प्रतिक्रिया यही थी कि अब इस मामले को यहीं समाप्त किया जाए। लेकिन इसके विरुद्ध ये लोग सक्रिए हो गए। जब याचिकाकर्ता कहने लगे कि हम अपील नहीं करेंगे तो उन पर प्रत्यक्ष-परोक्ष दबाव बनाने की पूरी कोशिश हुई और आज अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चार पक्षकार अपील के लिए तैयार हैं तो इसके पीछे निहित स्वार्थी तत्वों का दबाव ही है। जिलानी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर याचिकाकर्ताओं में से कोई नहीं जाएगा तब भी मुस्लिम समाज से कोई याचिका डाल सकता है, क्योंकि यह पूरे समुदाय का मसला है। पुनर्विचार याचिका में जाना हर वादी-प्रतिवादी का हक है। किंतु ये जिन तर्कों के साथ पुनर्विचार के लिए जा रहे हैं उन सबका उच्चतम न्यायालय पहले ही जवाब दे चुका है। न्यायालय ने इस संबंध में दस तर्क दिए हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी की ओर से मस्जिद का निर्माण कराया गया था। दूसरा, वर्ष 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की तीन गुंबदों वाली इमारत और अंदरूनी हिस्सा मुस्लिमों के कब्जे में माना गया है। तीसरा, न्यायालय ने माना है कि बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी यानी वह मस्जिद के रूप में थी। चौथा, न्यायालय ने माना है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को चोरी से या फिर जबरदस्ती मूर्तियां रखी गई थीं। पांचवां, गुंबद के नीचे कथित राम जन्मभूमि पर पूजा की बात नहीं कही गई है। ऐसे में यह जमीन फिर रामलला विराजमान के पक्ष में क्यों दी गई? छठा, न्यायालय ने खुद अपने फैसले में कहा है कि राम जन्मभूमि को पक्षकार नहीं माना जा सकता। फिर उसके आधार पर ही फैसला क्यों दिया गया? सातवां, न्यायालय ने माना है कि छह दिसंबर 1992 को मस्जिद को गिराया जाना गलत था तो मंदिर के लिए फैसला क्यों दिया गया। आठवां, न्यायालय ने कहा कि हिंदू सैकड़ों वर्षों से पूजा करते रहे हैं, इसलिए जमीन रामलला को दी जाती है, जबकि मुस्लिम भी तो वहां इबादत करते रहे हैं। नौवां, जमीन हिंदुओं को दी गई है, इसलिए पांच एकड़ जमीन दूसरे पक्ष को दी जाती है। न्यायालय ने संविधान के संबंधित नियमों का हवाला देते हुए यह बात कही। इसमें वक्फ एक्ट का ध्यान नहीं रखा गया, उसके मुताबिक मस्जिद की जमीन कभी बदली नहीं जा सकती है। और दसवां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर ही न्यायालय ने यह माना कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था।

सच यह है कि इन दसों प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय के 40 दिनों की बहस में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क और तथ्य दिए थे। फैसले में इन सबका जवाब दिया गया है। सबसे अंतिम तर्क मस्जिद के लिए जमीन के प्रश्न को लीजिए। न्यायालय ने इसे क्षतिपूर्ति नहीं कहा है। केवल इतना कहा है कि न्यायालय अगर मुस्लिमों के हक को नजरअंदाज करती है तो न्याय नहीं होगा। संविधान हर धर्म को बराबरी का हक देता है और सहिष्णुता तथा परस्पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हमारे देश और यहां के लोगों की धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। संविधान पीठ ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यह नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन न्यायालय ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम पक्षकारों द्वारा सर्वेक्षण की रिपोर्ट खारिज किए जाने के सारे तर्क अमान्य करार दिए।

मौजूदा न्याय प्रणाली को जिस तरह के प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता होती है उसकी बात न्यायालय ने कही है। न्यायालय ने साफ कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड यह साबित नहीं कर पाया कि विवादित जगह पर उसका बिना किसी बाधा के लंबे समय तक कब्जा रहा। व्यवधान के बावजूद साक्ष्य यह बताते हैं कि प्रार्थना पूरी तरह से कभी बंद नहीं हुई। मुस्लिमों ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, जो यह दर्शाता हो कि वे 1857 से पहले मस्जिद पर पूरा अधिकार रखते थे। इस बात के पूरे सबूत हैं कि राम चबूतरा और सीता रसोई पर हिंदू 1857 से पहले भी पूजा करते थे। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में कराया था, लेकिन यह स्थल दशकों से निरंतर संघर्ष का केंद्र रहा। पीठ ने कहा कि 1856-57 में सांप्रदायिक दंगा भड़कने से पहले हिंदुओं को परिसर में पूजा करने से नहीं रोका गया। वर्ष 1856-57 के दंगों के बाद पूजा स्थल पर रेलिंग लगाकर इसे बांट दिया गया ताकि दोनों समुदायों के लोग पूजा कर सकें। इसके स्पष्ट साक्ष्य हैं कि हिंदू विवादित ढांचे के बाहरी हिस्से में पूजा करते थे। कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने परिसर को भीतरी और बाहरी बरामदे में विभाजित करते हुए छह से सात फुट ऊंची ग्रिल-ईंट की दीवार खड़ी की। भीतरी बरामदे का इस्तेमाल मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए और बाहरी बरामदे का इस्तेमाल हिंदू पूजा के लिए करने लगे।

बोर्ड का कौन सा प्रश्न अनुत्तरित है जिसके लिए ये पुनर्विचार याचिका लेकर जा रहे हैं? न्यायालय ने हर उस पहलू की जांच की है जो इससे जुड़े हैं। श्रीरामलला विराजमान के बारे में न्यायालय ने कहा कि 1989 में श्रीरामलला विराजमान की ओर से दायर याचिका बेवक्त नहीं थी। फैसले में राम जन्मभूमि के पक्ष में ऐसे-ऐसे साक्ष्य और तर्क हैं जिनको किसी सूरत में खारिज नहीं किया जा सकता। इन सबको यहां प्रस्तुत करना संभव नहीं। जानबूझकर ये खत्म हो चुके विवाद को बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न है क्यों? इससे तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। आवश्यक है कि विवेकशील मुस्लिम निहित स्वार्थी नेताओं की मुखालफत करें। मुस्लिम समाज की ओर से मुखर विरोध ही इनका बेहतर जवाब हो सकता है।

गंगा जमुनी तहजीब के परीक्षण का वक्त

प्रवीण गुगनानी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

हो जाए गर शाहे खुरासान का इशारा,
सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीं पर।।

अल्लामा इकबाल की ये पंक्तियां और यह समय, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि वह राम जन्मभूमि मामले पर सर्वोच्च निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका लगाएगी, दो सर्वाधिक सटीक विषय हैं 'गंगा जमुनी तहजीब' पर बात करने के। यदि भारत के पिछले पांच सौ वर्षों में सबसे बड़ा सामाजिक छलावे का कोई शब्द गढ़ा गया है तो वह है 'गंगा जमुनी तहजीब'! इस कथित तहजीब के हिसाब किताब का यह सटीक समय है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका लगाने का निर्णय लिया है। लखनऊ में आयोजित इस बैठक में बोर्ड ने पांच एकड़ भूमि अन्यत्र स्थान पर लेने से भी इन्कार कर दिया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि इस्लामी शरीयत हमें इजाजत नहीं देती कि हम मस्जिद के बदले में जमीन या कुछ और लें।

देश का सामान्य मुस्लिम जहां इस विवाद से मुक्ति पाना चाहता है और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता है, वहीं देश के चंद नेता किसी भी प्रकार से इस विवाद को जिंदा रखकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाते रहना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत से सदस्य भी पुनर्विचार याचिका लगाए जाने के विरोध में हैं। बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी पुनर्विचार याचिका दायर करने के विरोध में हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुस्लिम नेता मोहसिन रजा ने भी पुनर्विचार याचिका पर मंथन के लिए लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संस्था देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम समाज मंजूर कर चुका है तो इस प्रकार की मीटिंग का औचित्य क्या है। मोहसिन रजा ने यह भी कहा कि इतने संवेदनशील समय में इस बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश में ना रखकर दिल्ली या हैदराबाद में भी किया जा सकता था।

आज मुस्लिम समाज भी इस बात को समझ चुका है कि पुरातात्विक खोदाई से इस स्थान पर विशाल मंदिर के होने व मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद निर्माण के प्रमाण मिल गए हैं। इस स्थान से अनेक ऐसी चीजें हासिल हुई हैं जिनसे यहां हिंदू मंदिर होने की धारणा पुष्ट हो गई है। किंतु कट्टरपंथी मुसलमान व वोट बैंक की राजनीति कर रहे चंद मुस्लिम नेता इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं।

सामान्य भारतीय मुस्लिम इस बात को समझ चुका है कि बाबर (जिसके नाम पर वह बदनुमा दाग रूपी बाबरी मस्जिद थी) महज एक विदेशी आक्रमणकारी व लुटेरा था। भारतीय मुस्लिमों की रगों में बाबर का खून नहीं, बल्कि उनके भारतीय पुरखों का रक्त बहता है। भारतीय मुसलमान उस समाज से हैं जिनके पुरखों ने कभी मजबूर होकर, कभी भयभीत होकर तो कभी बेटी-बहू और संपत्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से जबरिया बाबर और औरंगजेब का इस्लाम ग्रहण किया था। जब हमारे पुरखे एक हैं तो आज हमें हमारा भविष्य भी एक ही बनाना चाहिए। गत वर्ष जब सर्वोच्च न्यायालय ने परस्पर चर्चा व मध्यस्थता से इस विवाद का समाधान तलाशने को कहा था तब भी सामान्य मुस्लिम इस विवाद को हल करने का इच्छुक था व राम जन्मभूमि को नजराने के तौर पर हिंदू समाज को भेंट करना चाहता था, किंतु विघ्नसंतोषी और राजनीति की दुकान वाले चंद मुस्लिम नेताओं ने यह नहीं होने दिया था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने तब भी सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को नकार ही दिया था और हर जगह दूध में दही डालने वाले मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी न्यायालय की पहल को सुनने से ही इन्कार कर दिया था। आज भी ये दोनों और इनके जैसे कुछ अन्य मुस्लिम नेता सामान्य मुस्लिम वर्ग की भावनाओं की उपेक्षा कर इस विषय को पुनर्विचार याचिका की ओर धकेल रहे हैं।

खरी-खरी

जूते हैं... तो जय है!

जवाहर चौधरी

जूतों का आविष्कार पैरों में पहनने के लिए किया गया था। लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ जूते उतारने की आदर्श परंपरा भी विकसित हुई। जूता उतारना जूता पहनने की अपेक्षा कठिन और हिम्मत का काम है। सदियों से जो लोग जूता पहना रहे हैं, उन्हें समाज से जाति सूचक संबोधनों के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन जो समय-असमय उतारते रहे हैं उन्हें हुजूर, मालिक से लगाकर माई-बाप तक का रुतबा हासिल हुआ।

खानदानी जूतेदार बताते हैं कि जूता-व्यवहार दो तरह का होता है। एक सूखा, दूसरा गीला। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। जैसे नरम दल और गरम दल। दोनों अंग्रेजों को देश से खदेड़ना चाहते थे। बड़े वाले यानी हुजूर, मालिक, महाराज टाइप के अन्नदातानुमा दबंग लोग जूता पहनते नहीं, जूतों पर सवार रहते हैं। जूते जितना चलते हैं, उनका सिक्का उतना चलता है। मामूली आदमियों के लिए जरूरी होता है कि अपनी बात कहते हुए वे नजरें उनके जूतों पर रखें, क्योंकि जूतों की नजर उन पर रहती है। इसे शिष्टाचार कहने से ग्लानि नहीं गर्व पैदा होता है। हुजूरों के बुलावे पर जो जाते हैं, वे अक्सर जूता-प्रसादी खा कर आते हैं और जो नहीं जाते, बाद में भर पेट 'खाते' रहते हैं। हमारे यहां लोग भले ही गरीब हों पर कोई यह नहीं कह सकता कि उसे कभी 'खाने' की कमी रही। गरीब का सिर बार-बार काम में लिए जा सकने वाले प्लास्टिक की तरह होता है और कोई भी व्यवस्था इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती। कई बार जूतों पर नाक रगड़ाने या जूता चटवाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। यह सुविधा है, जिसे फेसिलिटी भी कहा जाता है। सोचिए, बुरे वक्त में फंसे व्यक्ति की नाक क्रेडिट कार्ड की तरह काम आ जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गरीब आदमी की नाक दबंगों के कब्जे में रहती है। कई बार मन होता है कि नाक हुजूर के कब्जे से मुक्त कर लें, लेकिन वे खाल उतरवा कर जूता बनवाने की मंशा जता देते हैं! दबंगों की समानांतर सत्ता को अभी किसी लौह पुरुष ने गंभीरता से नहीं लिया है।

खुशफहम सोचते थे कि देश आजाद हो गया तो सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है। ईश्वर ने कुछ लोगों को जूते दिए और कुछ को सिर। जब तक गरीबी नहीं मिटती, होंडा सिटी पर सवार जूते जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। बीच में कहीं कानून भी होता है, लेकिन वह अपने लंबे हाथों से बिना झुके जूतों पर पड़ी धूल साफ करता रहता है। जय हो।

ट्वीट-ट्वीट

महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की प्रस्तावित सरकार ठीक से चले, इसके लिए सुपर कमेटी बनेगी। केंद्र में जब संप्रग सरकार थी तब भी सुपर कमेटी थी। तब आलोचना होती थी कि मनमोहन सिंह सिर्फ रबर स्टैंप हैं और सरकार तो सोनिया गांधी चला रही हैं। क्या महाराष्ट्र में भी रबर स्टैंप मुख्यमंत्री होगा?
अखिलेश आनंद@akhileshanandd

मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे स्वर्गीय राहत अली जी और स्वर्गीय हुसैन जी जैसे मुस्लिम गुरु मिले जिन्होंने मुझे संगीत सिखाया। उन्होंने मुझे शिव, राम और कृष्ण के भजन सिखाए तो मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत भी किया। राहत साहब ने तो अपनी दोनों बेटियों की शादी भी हिंदू लड़कों से की।
मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

भारत में 15 से अधिक राज्यों की 55 प्रतिशत से अधिक आबादी गैर-भाजपा शासित राज्यों में है। मुझे हैरानी है कि राष्ट्रव्यापी एनआरसी की चर्चा से पहले केंद्र ने इन राज्यों के कितने मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके उन्हें भरोसे में लिया होगा।
प्रशांत किशोर@PrashantKishor

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

सत्ता, सियासत, सुदेश और सरयू

कानपुर शहर से कभी भी किसी तरह का जिनका वास्ता रहा है, और वह मिठाई खाने के शौकीन हैं, तो वहां की एक मशहूर दुकान को जरूर जानते हैं- ठग्गू के लड्डू। इनके लड्डू की खासियत तो वही जानते हैं जिन्होंने इसे खाया है, लेकिन अपने ब्रांड को प्रमोट करने का उनका नुस्खा काफी नायाब है। दरअसल वह दावा करते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बेशक, उन्होंने अपने किसी सगे-संबंधी को नहीं ठगा हो, लेकिन इसे झारखंड की सियासत पर फिट कर दें तो शत प्रतिशत सच साबित होगा।

झारखंड राज्य गठन के बाद से ही यहां के राजनीतिक दल, नेता छोटे-छोटे स्वार्थ के लिए अपने-पराये किसी को भी ठगने में गुरेज नहीं करते रहे हैं। बीते एक सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी- आजसू के बीच गठबंधन को लेकर हुई रार और रघुवर सरकार में लगभग पांच वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे सरयू राय के बगावती तेवर समेत तमाम नेताओं के दल-बदल से यह एक बार फिर जगजाहिर हो गया है, और यह तो बस शुरुआत है।

अगर मतदाता थोड़ा भी भ्रमित हुआ तो 23 दिसंबर के बाद अपनों को ठगने का जो दौर शुरू होगा, वह कम दिलचस्प नहीं होगा। पांच वर्षों तक भाजपा सरकार में साथी रही आजसू पार्टी आखिरी समय तक मोल-भाव में जुटी रही। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो इसमें काफी माहिर माने जाते हैं। उनका यह भी इतिहास रहा है कि वह कभी सत्ता से दूर नहीं रहे हैं। जिसकी सत्ता, सुदेश उसके साथ। इसीलिए झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उन पर हमलावर हैं। वह कह रहे हैं कि वह भाजपा की बी टीम हैं और चुनाव बाद वह रघुवर की गोद में बैठ जाएंगे।

खैर, मतदाता इस पर कितना ध्यान देगा पता नहीं, लेकिन सुदेश महतो ने जिस तरह से भाजपा को आखिर तक उलझाए रखा, इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा जो नौ सीटें आजसू के लिए छोड़कर चल रही थी, वहां कोई पहले से बहुत तैयारी नहीं की। यही वजह

सुदेश महतो

है कि वहां भाजपा बहुत मजबूत प्रत्याशी देने की स्थिति में नहीं है। पांच वर्षों तक सत्ता में साथी रहे सुदेश अब बिजली सहित कई अन्य मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार से सवाल कर

सरयू राय

रहे हैं। वे इस बात को भूल रहे हैं कि मतदाता उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। सरकार में थे, तब आपने क्या किया? वैसे माना तो यह भी जाता है कि मतदाताओं की याददाश्त बहुत ज्यादा नहीं होती है। यह बार-बार, चुनाव दर चुनाव जाहिर होता रहता है।

कुछ ऐसा ही हाल रघुवर दास सरकार में पांच साल तक कैबिनेट मंत्री रहे सरयू राय का भी है। वह पिछले आठ-दस महीने से बगावती तेवर अपनाए हुए थे। कई बार सरकार के साथ-साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास को सीधे घेरते रहे हैं। सरकार और संगठन पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफे का नाटक भी करते रहे, लेकिन दिया नहीं। सरकार का पूरा सुख भोगा और टिकट वितरण में भी आखिर तक इंतजार किया। जब समझ गए कि प्रदेश से लेकर केंद्रीय संगठन ने उनके इस 'बगावती आचरण' को गंभीरता से लिया है और बात नहीं बनने वाली है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोंक कर खड़े हो गए। अब उन्हें बहुत कुछ याद आ रहा है जो वह आने वाले दिनों में मतदाताओं के सामने रखेंगे, लेकिन वह यह भूल रहे हैं कि मतदाता यह भी तो पूछ सकते हैं कि पांच वर्ष तक जब आप सरकार में शामिल थे, तब विरोध करते हुए सत्ता क्यों नहीं त्यागी?

खैर, राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक यही नाटक चल रहा है। झारखंड में चुनाव से ठीक पहले लगभग सभी दलों में पाला बदलने का एक सिलसिला सा चला हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अभी तक अपने सभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। वह इंतजार कर रही है कि भाजपा की पूरी सूची आ जाए, ताकि उनकी घोषणा के बाद पार्टी के विक्षुब्ध कहीं उधर ही न खिसक जाएं। हकीकत भी है, इस चुनाव में दो दर्जन विधायक अब तक अपना दल बदल चुके हैं।

प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे नेता कपड़े की तरह दल बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी झामुमो, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखेदव भगत भाजपा, एक और पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू आजसू का दामन थाम चुके हैं। वहीं, कांग्रेस के ही एक और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार अब राज्य में आम आदमी पार्टी के झंडाबरदार हैं। निष्ठा ताक पर है, स्वार्थ की राजनीति चरम पर।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या राज्यसभा के मार्शलों के लिए सैन्य पोशाक की व्यवस्था उचित है?

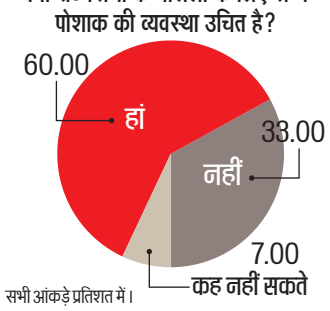

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या टेलीकॉम कंपनियों को मिली राहत से दूरसंचार क्षेत्र की परेशानियां दूर होंगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

इक भाई पीएम बना, दूजा राष्ट्राध्यक्ष,
राज चले परिवार का, अब देखो प्रत्यक्ष।
अब देखो प्रत्यक्ष राजपक्षे का डंका,
दो भाई के राज चलेगा अब श्रीलंका।
गोतबाया के भ्रात महिंदा की बन आई,
इक भाई के साथ राज करता इक भाई।
– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

सहकारिता में लागू हो आरटीआइ

आलोक कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारिता का व्यापक योगदान है, लेकिन बीते वर्षों में इसमें अनेक अनियमितताएं सामने आई हैं जिस कारण इसे भी आरटीआइ के दायरे में लाने की जरूरत है

उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय के तहत देश के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय तक को सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के अधीन कर दिया। लेकिन देश की सहकारी संस्थाओं में आरटीआइ कानून लागू नहीं है। इफको, कृभको, नेफेड, एनसीसीएफ, सभी सहकारी बैंक, डेयरी और विपणन से जुड़ी लाखों सहकारी संस्थाएं आरटीआइ कानून के दायरे में नहीं हैं।

उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सहकारी संस्थाओं पर भी आरटीआइ लागू करने का दबाव बढ़ेगा। सहकारी संस्था आरटीआइ से अलग क्यों है? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआइ) के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव कहते हैं, 'सहकारी संस्थाएं लोगों की उद्यमी समूह हैं। समूह सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। सहकारी कानून में कोई सदस्य अपनी संस्था के बारे में हर तरह जानकारी हासिल कर सकता है। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति को संस्था की सूचना देने की जरूरत नहीं है। इसलिए सहकारी संस्थाओं पर आरटीआइ कानून लागू नहीं है।'

एनसीयूआइ देश के सहकारी संस्थाओं की एपेक्स बॉडी है। एनसीयूआइ देशव्यापी सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को खुद से अलग किए जाने के मामले को लेकर सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट में उलझी पड़ी है। सहकारी संस्थाओं पर आरटीआइ कानून का लागू नहीं होना, भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों को उजागर होने से बचाने में कवच का काम करता है।

सहकारिता के बारे में उल्लेखनीय है कि यह सदियों से भारत में स्वयं सहायता समूह के तर्ज पर मौजूद है। योजना बनाने वालों ने सहकारिता को देश के विकास का आधार माना था। उस पर चलते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना तक सहकारी संस्थाओं को सरकारी संरक्षण हासिल था। वर्ष 1997 तक सहकारी उपक्रमों को आयकर में छूट हासिल थी। नतीजन रोजगार पैदा करने में सहकारिता ने अतुलनीय योगदान दिया। आज भी देश भर में आठ लाख से ज्यादा सहकारी संस्थाएं मौजूद हैं। सहकारिता से 30 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में जुड़े हैं।

सहकारिता का क्षेत्र व्यापक है। इसका वास्ता सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है। बल्कि बैंकिंग, उर्वरक, उत्पादन, विपणन आदि किसी भी क्षेत्र में उद्यम करने की इच्छा रखने वाला समूह सहकारी संस्था जिला, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर निर्बंधित करा सकता है। संस्था को कानून का पालन करते हुए सभी पदाधिकारियों का सावधिक चुनाव कराना होता। सहकारिता की एक खूबी यह भी है कि इसका लाभ उद्यमी समूह में शामिल सभी सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है।

कृषि मंत्रालय के साथ मौजूद सहकारिता विभाग के मातहत संचालित सहकारी बैंक को वित्त मंत्रालय से, उर्वरक विपणन और उत्पादन करने वाली सहकारी संस्थाओं को उर्वरक मंत्रालय से, डेयरी से जुड़ी सहकारी संस्थाओं राष्ट्रीय डेयरी डेवलमेंट बोर्ड से वास्ता रखना होता है। ऐसे में सहकारिता संचालन के लिए सिंगल विंडो की जरूरत बनी हुई है। देश के विकास में सहकारी संस्थाओं ने कई प्रतिमान गढ़े हैं। सरकारी बैंकों के घाटों के खुलासे के दौर में कई सहकारी बैंकों के सफल संचालन से आने वाले नतीजे सबक में लिए जा रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन की हरित क्रांति और वर्गीज कूरियन की श्वेत क्रांति ने सहकारी संस्थाओं के योगदान का प्रतिमान कायम किया है। लेकिन मौजूदा प्रतिद्वंदिता के दौर में सहकारी संस्थाओं को सरकार से न के बराबर मिल रहा संरक्षण, नए मिसाल गढ़ने की राह में रोड़ा बना हुआ है।

देश भर में सहकारिता कानून की एकरूपता के लिए संसद से पारित 97वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 से अदालत की तारीख के झमेले में अटका पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में इसके सख्त पैरवी की जरूरत है। सहकारिता से जुड़े नेताओं का मानना है कि इसके लागू होते ही सहकारी संस्थाओं के आंतरिक लोकतंत्र को बहाल करने में आ रही दिक्कतों का समाधान हो सकता है। सहकारी संस्थाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। हर क्षेत्र में सहकारी संस्था बनाकर उद्यम खड़ा करने की नई क्रांति लाई जा सकती है।

एनसीयूआइ के मुख्य अधिशासी एन सत्यनारायण बताते हैं कि अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में सहकारी आंदोलन पूरी तरह से सक्षम है। बस जरूरत है कि सरकार का सहकारी आंदोलन में भरोसा लौट आए व 1997 से पूर्व की स्थिति बहाल हो, यानी सहकारी संस्थाओं की आमदनी पर आयकर छूट की व्यवस्था हो।

लेबर कॉपरेटिव फेडरेशन के नेता अशोक डबास के मुताबिक सहकारी संस्थाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिवर्ष दो करोड़ लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हैं। बस जरूरत सहकारिता में मौजूद भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाने का प्रबंध करने की है। कृषि कॉपरेटिव से जुड़े प्रमुख नेताओं की राय में सहकारी संस्थाओं के सही प्रयोग से वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करना मुमकिन है।

सहकारिता से जुड़ी असीमित संभावनाओं के बीच सहकारी संस्थाओं को आरटीआइ के दायरे में लाने का प्रयास अटका पड़ा है। आरटीआइ के दायरे में आने से बचने के लिए सहकारी नेताओं की दलील की अपनी जगह है। लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि आम नागरिक भी छोटी सी शुल्क अदा कर सहकारी संस्थाओं के कामकाज से जुड़ी जानकारी हासिल कर ले। यह वक्त की जरूरत है। खासकर तब जब कई सहकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। हजारों करोड़ के घोटाले हो चुके हैं। सहकारिता से घोटालेबाज माफियाओं की कहानियां जुड़ी हैं। सहकारिता का जिक्र होते ही लोगों के जेहन में घोटाले और घपले की कहानियां सामने आने लगती हैं, ऐसे में सहकारी संस्थाओं को आरटीआइ के दायरे में लाने की मांग गैर वाजिब नहीं लगती। इससे सहकारी संस्थाओं को भ्रष्टाचार के संदेह से दूर करने में मदद मिल सकती है। साथ ही सरकारी सहयोग की आकांक्षा रखने वाली सहकारी संस्थाओं की दावेदारी बढ़ेगी।

प्रतीकात्मक

117 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं प्रवर्तन निदेशालय ने मैसुरु के महाराजा के करीबी को ठगने वाले अश्व प्रशिक्षक माइकल एफ. ईश्वर की। जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें 70 बहुमूल्य ट्रॉफी के अलावा शीशम के फर्नीचर, मैसुरु के हैदर अली रोड स्थित एक घर आदि शामिल हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 22 नवंबर 2019

पद्मश्री भारत भूषण बता रहे कैसे करें किसानी...

भारत भूषण त्यागी। जागरण

- गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कर चुका है डॉ. ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित
- उन्नत कृषि के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए बुलंदशहर, उप्र निवासी भारत भूषण त्यागी ने विकसित की है जैविक-सामूहिक कृषि की कारगर पद्धति

मनोज त्यागी, हापुड़

जागरण विशेष

एक साधारण किसान, जिसने जैविक खेती में कारगर प्रयोग कर नागरिक अलंकरण पद्मश्री तक का सफर तय किया। जिसे उन्नत कृषि तकनीकों के विकास के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड ने डॉ. ऑफ साइंस की मानद उपाधि से नवाजा, आज देश-विदेश के किसानों के लिए गुरू का काम कर रहा है। किसान के लिए कम लागत से ज्यादा मुनाफा कमाना बड़ी चुनौती है। पर जिला बुलंदशहर, उप्र की तहसील स्याना के गांव बीहटा निवासी किसान भारत भूषण त्यागी ने यह कर दिखाया है। खुद तो किया ही साथ में साठ हजार किसानों को भी सिखाकर तरक्की की राह दिखाई। स्थिति यह है कि देश-विदेश से कृषक उन तक पहुंचते हैं। प्रशिक्षण लेने के लिए आने वाले प्रशिक्षुकों को वे अपने यहां रहने-खाने की मुफ्त सुविधा देते हैं। उद्देश्य साफ है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।

यूं तो भारत भूषण त्यागी ने भी खेती की शुरुआत कीटनाशक दवाइयों और रसायनिक खाद से की थी। किंतु दो साल बाद ही उन्हें आभास हो गया कि यह खेती उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। उन्हें समझ आ गया कि खेती को मैनेजमेंट की दृष्टि से देखना होगा। प्रकृति के अनुरूप अभ्यास अपनाना होगा। मिट्टी की उत्पादन क्षमता के अनुरूप इंतजाम करने होंगे। जहां जैसी जलवायु है वहां के अनुसार काम करना होगा। उन्होंने प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था का शोध किया। समझ आया कि चार कंपोनेंट जरूरी हैं- उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और बाजार। इनकी समझ किसान को भलीभांति होना चाहिए।

त्यागी बताते हैं कि किसान को उत्पादन से लेकर बाजार तक अपनी पहुंच बनानी होगी। उत्पादन से ज्यादा आय बढ़ाने पर जोर देना होगा। यह सामूहिक प्रयास से संभव है। संगठित होकर खेती करें तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। रसायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं से बचना होगा। ये सब चीजें लोगों को रोगी बना रहे हैं। हमें स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है। इसी सोच को लेकर वह आगे बढ़े। उन्होंने बताया, जैविक खेती के लिए खेत को तीन भागों में बांटना जरूरी है। पहला बफर जोन, जिसे बाउंड्री या कवच भी कह सकते हैं। यह कवच बाहर से आने वाले कीट-पतंगों से लेकर बाहरी पानी से भी बचाव करेगा।

दो मीटर के इस कवच एरिया में लेमन ग्रास, दो मीटर के बाद बकायन के पौधे, केले के पौधे, लहसुन, प्याज उपजाए जा सकते हैं। फिर छह मीटर और तीन मीटर का डायाग्राम बनाकर इसमें छह मीटर वाले क्षेत्र में साल भर में दो बार फसल बोई जाए और तीन मीटर वाले क्षेत्र में एक वर्ष में तीन से चार बार फसल बोने की व्यवस्था की जाए। देसी गाय के गोबर को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे खेतों में कीड़ा भी नहीं लगता है। फसल अच्छी होती है। खेत से कच्चे उत्पाद को बाजार के अनुरूप तैयार करें। जैसे हल्दी को पीसकर, अनाजों का दलिया बनाकर, सरसों का तेल निकालकर...। अच्छी पैकिंग करें। इसके बाद उसे बाजार पहुंचाएं। इससे किसान को इन जैविक उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा। अनेक फसलों के बारे में पहला काम समझ विकसित करने का है। किस समय पर, कितनी दूरी पर, यह विज्ञान समझ में आ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। कई फसलों को साथ-साथ लगाना जमीन के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कीट और खरपतवार किसान का दुश्मन नहीं है यह प्रकृति की व्यवस्था है। हमें नियंत्रण को समझना होगा।

त्यागी कहते हैं कि अपनी खेती आज भी आठ एकड़ ही है, पर आस-पास के किसानों के साथ मिलकर इस समय 45 एकड़ जमीन पर उन्नत जैविक कृषि कर रहे हैं। इनका मानना है कि छोटे किसानों के लिए जैविक खेती सबसे अच्छा विकल्प है। यदि किसानों के पास जमीन कम है तो कई किसानों को जोड़कर 50 एकड़ में खेती की जा सकती है। पहले उत्पादन कुछ कम हो सकता है, लेकिन दो वर्ष बाद उत्पादन बढ़ जाता है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

कहां गुम हो गई चंपा! ढूंढने निकल पड़ा पूरा भागलपुर

पौराणिक नदी को बचाने के लिए दैनिक जागरण ने छेड़ा अभियान, उठने लगे सवाल, नदी का नाम नाला क्यों

अश्विनी, भागलपुर

अपनी धारा में पौराणिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेज सदियों से बह रही आस्था की एक नदी नाला बन गई। इससे नदी होने की पहचान छीन ली गई। इसका नाम है चंपा...चंपा नदी! सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर (बिहार) की नदी। सवाल एक नदी के गुम होने का है, जल-जीवन संरक्षण का है। इसलिए दैनिक जागरण ने इसके अस्तित्व और पहचान को बरकरार रखने के लिए समाचारीय अभियान छेड़ा है- कहां गुम हो गई चंपा!

जल संरक्षण

वाल्मीकि रामायण से लेकर पुराण आदि ही इस नदी के अति प्राचीन अस्तित्व की गवाही दे रहे हैं। भले ही भगवान बुद्ध और भगवान वासुपूज्य इसके तट पर कभी ध्यान लगाकर बैठे हों, पर दशकों से कीचड़ में लथपथ यह नदी लोगों की जुबान पर नाले के ही रूप में चढ़ चुकी है। दुर्भाग्य ही है कि इस नदी को लोग चंपा नाला बोलते हैं।

1966 में ही हो गई थी प्रदूषण का शिकार, भागलपुर में इस पर लोहे का पुल बना तो नामकरण किया गया- चंपा नाला ब्रिज

भागलपुर, बिहार के नाथनगर में जब चंपा नदी पर लोहे का पुल बना तो उसका नामकरण किया गया 'चंपा नाला ब्रिज'। जागरण

1966 में भागलपुर के नाथनगर में इस पर लोहे के पुल के निर्माण के बाद नामकरण किया गया- चंपा नाला ब्रिज! इस नाम के साथ वह नाला बन चुकी थी, पर नदी का स्वरूप तब पूरी तरह नहीं मिटा था। हाल के वर्षों में नाले के नामकरण का असर हुआ और सारा कूड़ा-कचरा, गाद-कीचड़ इसी में बहा-बहाकर इसे नाला ही बना दिया गया।

नदी पर टिका थी बड़े भूभाग की अर्थव्यवस्था : इस नदी से प्राचीन अंग क्षेत्र यानी भागलपुर प्रक्षेत्र की बिहुला विषहरी की कथा जुड़ी है। मशहूर मंजूषा कला के रिश्ते भी इसी नदी की धारा से जुड़े रहे हैं। दुनिया भर में मशहूर भागलपुरी सिल्क के धागों को इसी नदी ने धो-धोकर अलग चमक दी। यह इतिहास में दर्ज है कि मौर्यकाल से ब्रिटिशकाल तक यह नदी व्यापारिक जलमार्ग थी। देश-विदेश में मशहूर यहां के कतरनी चावल की खुशबू इसी नदी के पानी की देन थी।

चूंकि नदी नाला बनती चली गई, तो इसका असर खेती पर भी पड़ा और पैदावार बुरी तरह प्रभावित होती गई। यानी, एक नदी के नाले में परिवर्तित होने का जबर्दस्त असर पूरे क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक स्वरूप पर भी पड़ा।

मिलने तक जारी रहेगा जागरण

यह अभियान शुरू करने से पहले विशेषज्ञों, इस क्षेत्र के जानकारों, ग्रामीणों, नदी तट पर रहने वाले लोगों से बात की गई। नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके बिगड़ते स्वरूप के कारणों की तलाश भी। लोगों ने जो कुछ बताया और दिखा, वह झकझोर देने वाला था। पिछले दस सालों में इस नदी में दस लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा कूड़ा-कचरा गिराकर इसके अस्तित्व को मिटा दिया गया। बहरहाल, अब इस नदी को बचाने के लिए समाज के लोग न सिर्फ आगे आने लगे हैं, बल्कि गांव से शहर तक जागरूकता की पहल भी शुरू हो है। यह उम्मीद की एक नई किरण है। नदी को नवजीवन मिलने तक जागरण का यह अभियान जारी रहेगा।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

रहते हैं भारत में, पर नेपाल से पानी लाकर बुझाते प्यास

परेशानी ▸ भारत-नेपाल सीमा पर बसे भिखनाठोरी के लोगों को है पेयजल की समस्या

दो घंटे जाया कर नेपाल के ठोरी से लाते पानी, सुबह हर घर के एक सदस्य का यही काम

प्रभात मिश्र, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)

सुबह होते ही पेयजल की चिंता। भिखनाठोरी के हर घर का एक सदस्य पेयजल के लिए दो किलोमीटर की दूरी तय कर नेपाल जाता है। पेयजल के लिए आने-जाने में दो घंटे का समय जाया होता है। कई सालों से ग्रामीण इस संकट को झेल रहे, इसके बावजूद स्थायी निदान के लिए प्रयास नहीं हुआ।

भारत-नेपाल सीमा पर बसे गौनाहा प्रखंड की धमौरा पंचायत के भिखनाठोरी की आबादी तकरीबन 800 है। पहाड़ी क्षेत्र होने से यहां पेयजल बड़ी चुनौती है। साधारण हैंडपंप काम नहीं करते। गांव के बगल में ही पंडई नदी बहती है। दैनिक कार्यों के लिए लोग इसका पानी उपयोग करते हैं। भोजन व पीने के लिए पानी लाने दो किलोमीटर दूर नेपाल के ठोरी गांव जाते हैं। वहां अमृतधारा नामक पहाड़ी से बहने वाले पानी को भरकर लाते हैं। वर्ष 2016 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचईडी) ने पेयजल आपूर्ति के लिए तकरीबन 18 लाख खर्च कर दो सोलर पंप लगाए। 2017 की बाढ़ में एक बेकार हो गया। दूसरे में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती है। ग्रामीण पुन्ना सिंह और मोती पासवान का कहना है कि विभाग ने टैंकर से पानी आपूर्ति की व्यवस्था की, मगर संवेदक को समय से भुगतान नहीं होने से वह भी ठप है।

नेपाल से पानी लेकर आता बालक। जागरण

यहां के ग्रामीण जंगल से लाते पानी : धमौरा पंचायत का एक और गांव है भतूजला। एक हजार की आबादी वाले इस गांव में भी पेयजल की समस्या विकराल है। यहां के ग्रामीण भी करीब दो किलोमीटर दूर वाल्मीकि रिजर्व टाइगर के जंगल से होकर बहने वाली भंवरी नदी का पानी लाकर प्यास बुझाते हैं। यहां भी विभाग ने करीब 16 लाख खर्च कर सोलर पंप लगाया। इससे कीचड़नुमा और गंदा पानी आता है।

मुखिया राम बिहारी महतो का कहना है कि हर घर नल का जल योजना के तहत भिखनाठोरी में एक साल पहले काम शुरू हुआ। पाइपलाइन बिछा दी गई है। टंकी भी लग गई है। जल्द पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। भतूजला में इस योजना पर कार्य नहीं हुआ है। सहायक अभियंता, पीएचईडी बालमुकुंद कुमार का कहना है कि बंद सोलर पंपों को जल्द चालू किया जाएगा। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थल जांच कर अवगत कराएं।

कंक्रीट के जंगलों ने दूर की धूप, हड्डियां हो रही कमजोर

रामेश्वरी ठाकुर, शिमला

- आइजीएमसी में बढ़ने लगे हड्डी दर्द के मरीज, 90 फीसद मरीजों में विटामिन डी की कमी
- सामान्य होते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण, लोग लेते हैं हल्के में

आधुनिक जीवनशैली में लोगों का रहन-सहन बिल्कुल बदल गया है। बहुमंजिला इमारतों और घने होते जा रहे मोहल्लों में धूप न मिलने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा घर के अंदर रहने और दफ्तर में अधिक समय बिताने से लोगों में विटामिन डी की कमी तेजी से बढ़ रही है।

शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल (आइजीएमसी) में ऑर्थो ओपीडी में 90 फीसद मरीज विटामिन डी की कमी से ग्रस्त पाए जाते हैं। इस ओपीडी में रोजाना 250 मरीज हड्डी दर्द संबंधी रोग का इलाज करवाने पहुंचते हैं। वहीं मेडिसिन ओपीडी में विभिन्न रोगों से ग्रसित मरीजों में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। विटामिन-डी शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाती है। अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें इस विटामिन की कमी है। विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन डी की कमी से कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग, अस्थमा, टीबी सहित अन्य बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी के लक्षण सामान्य होते हैं, इस कारण लोग इन्हें हल्के में लेते हैं या दूसरी बीमारियों के लक्षण समझ लेते हैं।

आइजीएमसी के प्रधानाचार्य डॉ. मुकुंद लाल का कहना है कि धूप की कमी से विटामिन डी की कमी होना आम है। लोगों को चाहिए कि पर्याप्त समय धूप में रहें।

विटामिन डी की कमी से बचाव : अंडे का पीला भाग खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानि गाय का दूध, पनीर, दही, मक्खन का सेवन करें। हरी सब्जी के अलावा गाजर का जूस, सोया, मशरूम और मखाने को भोजन में शामिल करें। सबसे जरूरी दिन में कम से कम आधा घंटा धूप में बैठें।

विटामिन डी की कमी के लक्षण

बिना शारीरिक श्रम पसीना आना, हड्डियों में दर्द, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, शरीर में एनर्जी लेवल कम होना, थकावट महसूस होना, बीपी बढ़ना, पाचन संबंधी परेशानियां होना, मांसपेशियों में दर्द रहना और तनाव रहना विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। धूप का कम मिलना, संसक्रीन का अत्यधिक इस्तेमाल करना करना, मोटापा होना विटामिन डी की कमी के कारण बनते हैं। इस विटामिन की कमी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

शीतकाल में वन्य जीवों की सुरक्षा वन विभाग के लिए बनी चुनौती

हरीश बिष्ट, गोपेश्वर(चमोली)

- तस्कर सक्रिय, वन विभाग कर रहा कैमरा ट्रैप के भरोसे वन्य जीवों की सुरक्षा के दावे
- ऊंचाई पर अधिक बर्फबारी होने के कारण निचले स्थानों का रुख कर रहे दुर्लभ वन्य जीव

शीतकाल के दौरान चमोली जिले में वन्य जीवों की सुरक्षा वन विभाग के लिए चुनौती बन जाती है। जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद तस्कर वन्य जीव बहुल इलाकों में डेरा डाल देते हैं। हैरत देखिए कि इस सबके बावजूद वन विभाग सिर्फ कैमरा ट्रैप के भरोसे वन्य जीवों की सुरक्षा के दावे कर रहा है। जबकि, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते निचले इलाकों के प्रवास पर आए वन्य जीवों के जीवन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है।

चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में कस्तूरा मृग, काला भालू, भूरा भालू, हिम तेंदुआ, रेड फॉक्स, भरल, घुरड़ आदि के अलावा लुप्तप्राय प्रजाति के कई वन्य जीवों का वास है। इन दिनों उच्च हिमालयी इलाकों में लगातार बर्फबारी के कारण वन्य जीव ठंड से बचने को अपने प्राकृतिक वास छोड़ निचले इलाकों का रुख कर रहे हैं। तस्कर इसी ताक में रहते हैं कि वन्य जीव कब निचले इलाकों में आएं और वह उनका शिकार करें।

खासकर नेपाली मूल के वन्य जीव तस्करों की सक्रियता इन दिनों चमोली जिले में देखी जा रही है। ये तस्कर कस्तूरी मृग व गुलदार की खाल समेत अन्य जानवरों के अंगों की तस्करी करते हैं। वन विभाग की ओर से शीतकाल में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगलों में कैमरा ट्रैप से निगरानी रखने की बात की जा रही है। लेकिन, आज तक एक भी वन्य जीव तस्कर इन कैमरों में कैद नहीं हुआ। कारण, तस्कर भली-भांति जानते हैं कि कैसे उन्हें कैमरों की जद में आने से बचना है। हां! यह जरूर है कि इन कैमरा ट्रैप में दुर्लभ वन्य जीवों की तस्वीरें अक्सर कैद होती रही हैं।

नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के उप प्रभागीय वनाधिकारी (एसडीओ) टीएस शाही कहते हैं कि शीतकाल में अधिकतर वन क्षेत्र बर्फ से आच्छादित रहता है। ऐसे में जंगलों में जाना भी मुश्किल होता है। इसलिए वन्य जीवों की सुरक्षा को कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। इसके अलावा विभाग लंबी दूरी की गश्त की रणनीति भी बना रहा है। कहा कि वन्य जीव तस्करों से निपटने के लिए वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है।

तैराक पिता को 'डूबते' देखा तो किनारे पर ही टूट गई उम्मीद

प्रशांत कुमार, पटना

'मैंने बिहार को राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताओं में आठ पदक जीतकर दिए। सरकार किसी की भी रही मगर मेरी प्रतिभा को सम्मान नहीं मिला। भूखे मरने की नौबत आ गई थी। दो दशक से चाय दुकान चलाकर पेट पाल रहा हूं। मेरे बेटे सोनू कुमार यादव और सन्नी कुमार यादव, दोनों ही बेहतरीन तैराक हैं, लेकिन वे मेरी तरह चायवाला बनकर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तैराकी छोड़ दी।'

पटना में 1998 से चाय दुकान चला रहे नेशनल तैराक गोपाल प्रसाद यादव के पास जब जागरण की टीम पहुंची तो उनका दर्द कुछ यूं छलक पड़ा। गोपाल कहते हैं, 1987 से 89 तक लगातार तीन साल बिहार को दो स्वर्ण पदक समेत आठ बार सम्मान दिलाया। 1990 में प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाया, क्योंकि खाने के लिए मात्र दस रुपये मिलते थे। इस बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजनों में शरीक हुआ। चौथे, पांचवें स्थान पर रहा। इसका कारण यह है कि हम गंगा में तैराकी करते थे और वहां स्विमिंग पूल मिलता था।

फाइल उठाकर फेंक देते थे अफसर : मुझे याद है 1974-75 की बात। तब तैराकी के लिए 1500 रुपये दिए जाते थे। 1990 में घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, तब सरकारी नौकरी के लिए प्रयास शुरू किया। पोस्टल विभाग की नौकरी के लिए संत माइकल स्कूल में इंटरव्यू देने गया, मगर वहां के अधिकारी ने फाइल उठाकर फेंक दी। 1998 में नया टोला के मुहाने पर चाय का स्टॉल लगाया। दो-चार पैसे आने लगे। दो वक्त का खाना मिलने लगा।

पटना के नया टोला में अपनी दुकान में चाय बेचते राष्ट्रीय तैराक गोपाल यादव। जागरण

मुख्यमंत्री भी आए, मगर नहीं मिली नौकरी : गोपाल कहते हैं, दर्जनों पत्र- पत्रिकाओं में मेरी व्यथा पर लेख छपे। जब मैंने चाय दुकान खोली, तब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। वह मेरी दुकान पर आए और मुझे गाड़ी में बिठाकर सचिवालय ले गए। मुझसे पूछा गया कि कहां तक पढ़े हो। बताया, नौवीं पास हूं। जवाब मिला, आपको नौकरी का पत्र भेजा जाएगा। कुछ महीने बाद तत्कालीन खेल मंत्री भी आए। फिर आश्वासन मिला पर आज तक नौकरी नहीं मिली।

रविवार को देते हैं तैराकी का मुफ्त प्रशिक्षण : मेरी हालत के लिए तैराकी नहीं, बल्कि सरकारें दोषी हैं। दोनों बेटों को तैराकी सिखाया। सन्नी (छोटा बेटा) में नेशनल स्तर पर खेलने की क्षमता है, लेकिन मेरा हाल देखकर दोनों ने तैराकी छोड़ दी। बड़ा बेटा सोनू कोरियर कंपनी में काम करता है। सन्नी प्रिंटिंग के काम से जुड़ा है। एक बेटी है, जिसकी शादी करनी बाकी है। मैंने तैराकी नहीं छोड़ी। आज भी हर रविवार को मुफ्त में तैराकी का प्रशिक्षण देता हूं।

अब हाथ की बनी चाय ही पहचान

गोपाल की चाय दुकान पर आने वाले ग्राहक पहले उनके आठों पदकों को निहारते हैं, जिन्हें उन्होंने स्टॉल के ऊपर टांग रखा है। पीछे नेशनल तैराक का बड़ा बैनर लगा है। गोपाल कहते हैं, मैं नाम कमाने का शौकीन हूं। तैराकी ने नाम दिलाया, अब मेरे हाथ की बनी चाय पहचान बन गई है।

पटना में देश का पहला खादी मॉल हुआ 'खाली'

नीरज कुमार, पटना : पटना में इसी माह खुला देश का पहला अत्याधुनिक खादी मॉल 15 दिनों में ही लगभग खाली हो गया है। 5 नवंबर से अब तक 70 फीसद सामान बिक चुके हैं, मगर नए सामान की आपूर्ति नहीं हो रही है। कई शो-केस और रैक खाली पड़े हैं। शर्ट, कुर्ता, बंडी, टोपी, साड़ियां आदि के रेंज बहुत कम बचे हैं। बकाया होने के कारण नए सामान देने से खादी संस्थाओं ने इन्कार कर दिया है। खादी मॉल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। खादी आयोग से पंजीकृत राज्य की 84 खादी संस्थाओं को खादी मॉल को सामान की आपूर्ति करनी है। उद्घाटन से पहले संस्थाओं ने खादी बोर्ड के माध्यम से मॉल के लिए पांच करोड़ रुपए का सामान उधार दिया था। उस समय बोर्ड का कहना था कि एक सप्ताह में राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है।

पहले तुरंत मिल जाती थी 50 फीसद राशि : खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कहना है कि पूर्व में खादी बोर्ड को सामान देने पर एक सप्ताह के अंदर 50 फीसद राशि का भुगतान कर देता था और शेष राशि दो माह में मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में बोर्ड ढाई माह से संस्थाओं को भुगतान नहीं कर रहा है।

तैयारी

पानी के सैंपल भी लिए, पक्षियों की देखरेख लिए ग्रामीणों को बनाया 'हरिके मित्र', आपात स्थिति से निपटने के लिए वेटरनरी डॉक्टरों की सूची तैयार

हाई अलर्ट पर हरिके वेटलैंड, पक्षियों की जांच

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर

राजस्थान की सांभर झील में हजारों विदेशी पक्षियों की मौत के बाद वन्य जीव विभाग ने हरिके वेटलैंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पक्षियों पर निगरानी व देखभाल के लिए छह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। प्राथमिकता के तौर पर पक्षियों की जांच करवाई जा रही है। पता किया जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार का कोई वायरस या बीमारी पक्षियों में तो नहीं आ रही है। इस मुस्तैदी के साथ ही विभाग ने हरिके वेटलैंड में हरिके मित्र भी तैनात किए गए हैं, जिन्हें वेटलैंड के आसपास नजर रखने को कहा गया है। वीरवार को सेंचुरी के पानी की जांच के लिए पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। हालांकि संबंधित अधिकारियों का कहना है कि पानी के सैंपल लेने का काम रूटीन प्रक्रिया है।

डीएफओ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कल्पना ने कहा कि वेटलैंड में किसी भी पक्षी के मरने की खबर नहीं है। विभाग ने वेटरनरी विशेषज्ञों की सूची तैयार की है, ताकि जरूरत के समय उनकी सहायता ली जा सके। पक्षियों का इलाज करना या उनका मेडिकल आदि करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले से ही इंतजाम किए गए हैं। विभाग ने हरिके मित्रों से मदद के तौर पर कहा है कि अगर उन्हें कहीं कोई मृत पक्षी मिलता है तो उन्हें तुरंत सूचित करें, ताकि उसका मेडीकल करवाया जा सके। हरिके वेटलैंड में करीब 60 हजार से ज्यादा विदेशी पक्षी पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि इनकी संख्या एक लाख से ऊपर जाएगी। पिछले दस दिनों से सभी कर्मचारियों की 24 घंटे की ड्यूटी कर दी गई है। पक्षियों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी अनहोनी से होने से पहले रोका जा सके।

हरिके वेटलैंड में पहुंचे विदेशी पक्षी। जागरण

दावा : दूषित नहीं हैं हिमाचल की नदियां

मुकेश मेहरा, कुल्लू

हिमाचल प्रदेश की नदियों को कुछ समय पहले पड़ोसी राज्यों की सैंपलिंग रिपोर्ट में दूषित बताया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट में नदियों में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) की मात्रा अधिक बताई गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जब मॉनिटरिंग की तो यह आंकड़ा कम आया। अब सीपीसीबी की टीम पानी की संयुक्त जांच करेगी।

एनजीटी में एक मामले में यह रिपोर्ट सामने आई थी कि हिमाचल की ब्यास, सरसा, अश्वनी, पब्बर, गिरी, सुखना व मारकंडा नदियों में प्रदूषण अधिक है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी के सैंपल भरे। इनमें प्रदूषण बेहद कम आया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मामला सीपीसीबी के समक्ष रखा। अब हर स्तर पर सैंपलिंग की जा रही है।

बीओडी की उचित मात्रा होना जरूरी : नदियों में रसायन को खत्म करने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखा जाता है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में ब्यास की 6.0 से 10 बीओडी बताई थी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में यह मात्र 0.1 से 02 निकली। सीपीसीबी के मापदंडों में ब्यास, पब्बर, सुखना, सतलुज चौथे से पांचवें रैंक पर हैं।

> अब सीपीसीबी नदियों की संयुक्त जांच करेगी। इसमें प्रदेश की टीम भी शामिल होगी। पड़ोसी राज्यों से भी पानी के सैंपल लिए जाएंगे।
>
> **- अजीत नेगी, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, शिमला**

ब्यास नदी। फाइल

यहां-यहां भरे गए थे सैंपल

पानी गुणवत्ता की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर महीने करता है। आंकड़े वर्ष 2017-18 व 2018-19 मार्च तक के हैं।

पब्बर : रोहड़ू, स्वारकुंड, सीमांत क्षेत्रों से सैंपल, बीओडी 0.1 से 0.3।

अश्वनी : यशवंत नगर से सैंपल, बीओडी 0.2।

गिरी : सतौन, राजगढ़, बाड़ू, राजबन, एडब्ल्यूएसएस सैंज में सैंपल, बीओडी 0.2 से 0.4।

सतलुज : रामपुर, ठियोग, भाखड़ा, सलापड़ व सीमांत क्षेत्र से सैंपल, बीओडी 0.1 से 0.3।

ब्यास : आलमपुर, पौंग डैम, नादौन, मंडी, लारजी, औट, देहरा, मनाली, कुल्लू में सैंपल, बीओडी 0.1 से 0.2।

मारकंडा : पांवटा साहिब, सलाली नाला, कालाअंब से सैंपल, बीओडी 0.4।

सरसा : सीतोमाजरी, नालागढ़ ब्रिज, नालागढ़ शहर में सैंपल, बीओडी 6.0 रही।

दैनिक जागरण
सबरंग
प्लान वीकेंड के
नई दिल्ली, शुक्रवार, 22 नवंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

खुरदरे हाथ

'खुरदरे हाथों' ने भरे जिंदगी में 'खुशियों के रंग'

जिंदगी की कहानियां जब मंच पर सजती हैं तो अलग ही अनुभव देती हैं। थोड़ी खुशी और थोड़ा गम देती हैं। हर पात्र में खुद की तलाश होती है। वैसे भी जिंदगी के चार रंग आयोजन तो किताबी कहानियों से निकाल पात्रों को मंच पर रच रहा था। सबरंग के इस अंक में चार रंग उत्सव से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

नाटक रोशनी का एक दृश्य। सभी फोटो : पारस कुमार

नाट्य मंचन

जिंदगी की उलझनों में हम ऐसे उलझ जाते हैं मानों अपने ही बुने जाल में फंस गए हों। उसे सुलझाने के बजाए उसमें उलझते चले जाते हैं जबकि उसके लिए किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत नहीं बल्कि छोटी-छोटी घटनाएं और प्रयास जिंदगी में बड़े परिवर्तन ला देती हैं। चार रंग आयोजन में ऐसी ही कहानियां थीं जिन्हें नाट्य मंचन के जरिए प्रस्तुत किया गया। ये घटनाएं तो बड़ी सीधी-सरल और सपाट सी दिखती हैं लेकिन असर बहुत गहरा करती हैं। चार दिवसीय चार रंग में खुरदरे हाथ, रोशनी, अलग रास्ते, किरदार, बस एक बार, भटकती जिंदगी का नाटक, फुहार और बारिश के अक्षर जैसे नाटकों का मंचन हुआ। हिंदी कहानियों पर आधारित साहित्य नाट्य उत्सव में दिल्ली ने खूब आनंद के साथ हिस्सा लिया। खूब सराहा।

...और झुमकी समझ गई मां का कोई मोल नहीं : हल्की नीली रोशनी में दोस्तों संग लंगड़ी कूद खेलते हुए नन्ही नटखट झुमकी आती है... जो अपनी जिंदगी में मस्त है, दीन दुनिया से बेखबर है। इसकी जिंदगी मां और दोस्तों के इर्दगिर्द कटती है। अगले शॉट में झुमकी की मां बनी निर्देशिका प्रियंका शर्मा का आगमन होता है तो सभी बच्चे डर सहम जाते हैं। प्रियंका, बच्चों को डांटकर उनके घर भगा देती है। बच्चे निराश हो चेहरा लटकाए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मां चंद मिनट के लिए अपनी छोटी बेटी के पास जाती है झुमकी के दोस्त फिर से आ जाते हैं और फिर धमाचौकड़ी मचाते है और फिर बाद में घर का सारा काम भी कर देते हैं। ऐसा देख मां खुश हो जाती है। नाटक आगे बढ़ता है तो मां-बेटी के बीच नटखट वार्तालाप बच्चों को खूब हंसाती है...भावुक भी करती है। यहां पता चलता झुमकी की मां की जिंदगी संघर्षों से भरी है पति मारता-पीटता था बेटी पैदा होने पर भी प्रताड़ित किया। डर से बेटियों को ले प्रियंका घर छोड़कर भाग गई। अब वो जैसे तैसे घरों में काम कर बच्चियों को पाल रही है। उसकी ख्वाहिश है कि वो चंद पैसे इक्ट्ठा कर ले ताकि झुमकी का स्कूल में दाखिला हो जाए। इसके लिए वो दो घरों में काम करना शुरू की है लेकिन तभी देर रात एक महिला उसे यह बताने आती है कि दादी जी वापस आ गई हैं। दादी जी..वो हैं, जिनके यहां प्रियंका काम करके परिवार का भरण पोषण करती है। तड़के सुबह ही दादी अपनी नई नवेली बहू के साथ आने वाली होती हैं। इसलिए प्रियंका को भी तड़के सुबह पहुंचने को कहा जाता है। लेकिन उसकी आंख लग जाती है और वो देर से जगती है। डर के चलते वो झुमकी को भेजती है। यहां दो दृश्य दिल को छू लेते हैं। पहला दादी का परिचय कराता दृश्य। जिसमें दादी, पूजा कर रही हैं लेकिन उन्हें घर की चिंता ज्यादा है। पूजा करते हुए भी वो सहायकों को डांटती रहती हैं। दूसरा दृश्य, प्रियंका द्वारा झुमकी को दादी के घर भेजते समय उसे तैयार करने का। जिसमें वो उसे नए कपड़े पहनाती है, बाल बनाती है। झुमकी, दादी के घर पहुंचती है तो पहली बार नई नवेली दुल्हन देखती है। दुल्हन की जूती पहन चलने की कोशिश के दौरान वो गिर जाती है। दादी का आदेश है कि दुल्हन पहले दिन अपने हाथ से खाना बनाए लेकिन दुल्हन को बनाना नहीं आता है। झुमकी पूरा खाना अकेले बनाती है। यहां से झुमकी और नई नवेली दुल्हन के बीच दोस्ती हो जाती है। झुमकी को दुल्हन अंग्रेजी भी सिखाना शुरू कर देती है। नाटक के दौरान हर दृश्य पर कब कैसे कितनी रोशनी होनी है कब कहां ध्वनि का इस्तेमाल होना है बेहतर सामजस्य दिखाई पड़ता है।

झुमकी की दोस्ती इस कदर परवान चढ़ती है कि एक दिन सुबह सुबह जब वो हवेली जा रही होती है और मां जाने से रोकती है तो मां के खुरदरे हाथों को लेकर ताना मार देती है। कहती है, आपके हाथ खुरदरे हैं। मेरा शरीर छिल जाता है। जबकि भाभी तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन इसी दिन भाभी की एक साड़ी झुमकी से खराब हो जाती है। महंगी साड़ी खराब होने पर दादी जब झुमकी को डांट रही होती है तो प्रियंका आगे आकर हर्जाने की भरपाई कर देगी, ऐसा कहती है। दादी उसे लगातार दो साल तक काम करने को कहती है। प्रियंका यह मान जाती है। तब झुमकी की मदद को दुल्हन आगे नहीं बढ़ती। झुमकी को एहसास हो जाता है कि मां की ममता का कोई मोल नहीं है।

हक की आवाज बुलंद करती रोशनी : रिश्ते किस तरह औरतों के लिए बेड़ियां बन जाते हैं उसी पर रोशनी डालता है यह रोशनी नाटक। समाज में पुरुषों की दकियानूसी सोच पर करारा कटाक्ष है किस तरह एक पत्नी को उसका पति विवश करता है उसे नौकरी और पति में से किसी एक को चुनने के लिए। कहानी का पात्र है अच्छी खासी पढ़ी लिखी अनामिका। उसकी बेटी है पीहू। पति आनंद, भी अच्छे पद पर हैं। नाटक का पहला दृश्य बेटी के जन्मदिन पर होता है उसी दिन अनामिका को अच्छी नौकरी का ऑफर लेटर भी मिलता है। लेकिन पति अनामिका की अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा को दबाना चाहता है और उसके सामने नौकरी या पति में से किसी एक को चुनने की शर्त रखता है। अनामिका अपनी बेटी पीहू की दुहाई देती रह जाती है लेकिन आनंद के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो अनामिका को चंडीगढ़ छोड़ देने को कहता है। अनामिका उससे कहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। पैसे कमाने के साथ वो पीहू की अच्छे से देखभाल करेगी। परिवार को आर्थिक मदद भी करेगी लेकिन आनंद उसकी एक नहीं सुनता है। कहानी आगे बढ़ती है, अनामिका को दिल्ली में एक स्कूल में हिंदी अध्यापिका के तौर पर नौकरी मिल जाती है। यहां क्लास की बच्चियों में रोशनी नाम की लड़की में उसे पीहू दिखती है। रोशनी, कक्षा में बिल्कुल शांत रहती है। उसे ड्राइंग बनाने का शौक है।

एक दिन जब उसके टेस्ट रिजल्ट आते हैं तो अनामिका परेशान हो जाती है। दरअसल, उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब होता है। पूछने पर रोशनी बिफर कर रोने लगती है। बताती है कि उसकी मां की मौत सालों पहले हो चुकी है। पिता ने दूसरी शादी की है। दादी और उसे घर से निकल अब दूसरी जगह रहना पड़ रहा है। दादी और अपना पेट भरने के लिए रोशनी शाम के समय सब्जी बेचती है। इस पर अनामिका रोशनी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती है एवं उसे और दादी को अपने साथ घर पर रखती है। कहानी में अब आनंद की एंट्री होती है। वो रिटायर हो चुका है। पीहू लेक्चरर हो चुकी है। उसकी अपने पिता से बहस होती है तो वो कहती है कि वो अनामिका यानी उसकी मां को कभी समझ नहीं पाया। इधर, अनामिका भी अब काफी बुजुर्ग हो चुकी है। उसे एक दिन पत्र आता है कि रोशनी और उसका पति भारत लौट आए हैं। पता चलता है कि रोशनी अब डॉक्टर बन गई है। उसका पति भी डॉक्टर है। दोनों आस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करते थे लेकिन अब स्वदेश लौट आए हैं।

रोशनी, नाटक में अपनी एक महिला मित्र से बात करते हुए बताती है कि वो एक जानने वाले के कैंसर अस्पताल में अब काम करेगी। अस्पताल का आज शाम उद्घाटन होने वाला है जिसमें उसने अपनी मां यानी अनामिका को बुलाया है। यहां वो अनामिका को एक सरप्राइज भी देगी। तय समय पर अनामिका भी पार्टी में पहुंच जाती है जहां मां-बेटी का भावुक कर देने वाला मिलन होता है। रोशनी ने यहां आनंद को भी बुलवाया था। आनंद, अनामिका से अपनी दकियानूसी सोच के लिए माफी मांगता है। पीहू मां से कभी नहीं बिछड़ने का वचन लेती है और इस तरह अनामिका को उसका परिवार मिलता है।

इस बार यहां चलें

मंदिरों की व्याख्या

सिद्धार्थ दास स्टूडियो द्वारा आयोजित मंदिरों की व्याख्या प्रदर्शनी जगन्नाथ मंदिर एवं लिंगनाथ मंदिर की खासियत से रूबरू कराती है। प्रदर्शनी ना सिर्फ मंदिर की विशेषताओं को दर्शकों के सामने रखती है, बल्कि इसके वास्तु के बारे में भी बताती है।

- **कहां** : इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोदी रोड, दक्षिणी दिल्ली।
- **कब** : 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक। सुबह दस से शाम सात बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

तिजि फेस्टिवल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अपने 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसमें तिजि फेस्टिवल खास है। नेपाल का यह आर्ट दिल्ली वालों को भी पसंद आएगा। सेमिनार ऑन पैनोरमा ऑफ इंडियन कल्चर, फोक म्यूजिक कॉन्सर्ट, महात्मा गांधी पर केंद्रित प्रदर्शनी खास है।

- **कहां** : आइजीएनसीए, जनपथ, नई दिल्ली। • **कब** : 18-24 नवंबर तक, सुबह दस से शाम सात बजे तक।
- **प्रवेश**-निश्शुल्क।

श्रीराम कवि सम्मेलन

विगत कई सालों से यह कवि सम्मेलन दिल्ली वालों का पसंदीदा कार्यक्रम रहा है। 49वां कवि सम्मेलन एक बार फिर हाजिर है। इसमें हास्य व्यंग्य के सुप्रसिद्ध कवि दीपक गुप्ता, गजल गायक आयुष चरग के अलावा अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। कवि अशोक चक्रधर कार्यक्रम के संयोजक होंगे।

- **कहां** : मॉर्डन स्कूल, बाराखंबा, नई दिल्ली।
- **कब** : 23 नवंबर, शाम साढ़े छह बजे।
- **प्रवेश** : आमंत्रण द्वारा।

सामापा संगीत सम्मेलन

सामापा संगीत सम्मेलन का कारवां अब कमानी ऑडिटोरियम पहुंच गया है। तीन दिवसीय सम्मेलन में पंडित अजय पोहानकर, पंडित भजन सोपोरी, पंडित विश्वभर नाथ मिश्रा, विदुषी मालिनी अवस्थी, अभय रुस्तम सोपोरी, गुरु नलिनी कमिलिनी, पंडित कुशल दास को सुनने का मौका मिलेगा।

- **कहां** : कमानी ऑडिटोरियम, कापरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली।
- **कब** : 22-24 नवंबर, शाम साढ़े छह बजे। • **प्रवेश** : निश्शुल्क।

मक्के की रोटी संग पिज्जा का मेल

जायका

पंमक्के की रोटी संग पिज्जा का मेल, मिठाई में हरी सब्जी और करी पत्ता का स्वाद, ढोकले के टिक्के, घेवर में चीज का इनफ्यूज, पारंपरिक फिरनी में कीवी का उपयोग, गाजर हलवे की चीज बर्फी...पढ़कर हैरान हो गए न...। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मेल है? ये तो संभव ही नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल संभव है और आप भी इसे अपने किचन में जरूर ट्राई करिए। घर में सभी को पसंद भी आएगा। इन डिशेज को स्टेप बाई स्टेप समझकर बनाने के लिए सोशल मीडिया पर शेफ इंदर देव को फॉलो करना होगा। देश-विदेश में पंचतारा होटल व कैफे में काम करने के बाद इंदर अब नई डिशेज इजाद कर लोगों को फ्यूजन डिशेज का हेल्दी स्वाद चखा रहे हैं।

खास हैं इंदर की रेसिपीज : दही से भरे कच्चे केले के कबाब, सरसों वाले सोया चाप दे टिक्के, तरबूज की शिकंजी जैसी डिशेज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले इंदर का कहना है कि वे हर डिश को अलग ही अंदाज में बना रहे हैं। जो पहले कभी नहीं बनाए गए। इतना ही नहीं, वे मॉर्निंग सांभर, गिलॉय की चाय, कीवी फिरनी, जुकीनी सीक कबाब, ढोकले के टिक्के, गाजर हलवा चीज बर्फी, मिस्सी रोटी का पिज्जा, गोंद और चिया सीड के लड्डू, करी पत्ते का हलवा, बेक्ड चीज घेवर और चॉकलेट के काले जामुन सहित लगभग एक हजार डिशेज हैं जिन्हें फ्यूजन डिशेज के रूप में इंदर ने बनाया और लोगों को इसे बनाने का तरीका सिखाया है।

सरसो वाले सोया चाप दे टिक्के

शेफ इंदर देव

अनुभव लेने के बाद शोध में उतरे : बीते दो दशकों से भारतीय फूड मार्केट में जहां विदेशी जायके की खुशबू फैल रही थी, वहीं अब कुछ लोगों ने लुप्त होते जा रहे भारतीय भोजन की फिर से तलाश शुरू कर दी है। इंदर उन्हीं लोगों में से हैं। पिछले तीन दशकों से फूड इंडस्ट्री में कार्यरत इंदर अब तक 17 होटलों में बतौर शेफ और चार होटल्स में बतौर हेड शेफ काम कर चुके हैं। देश विदेश के होटलों में हर तरह के क्यूजीन का अनुभव लेने के बाद अब वे अपने स्तर पर भारतीय व्यंजनों के उस खजाने की तलाश में हैं, जो एक दौर में परंपराओं की खुशबू में लिपटा था।

तलाश रहे भारतीय जायके के रहस्य : पारंपरिक भारतीय जायके को फिर से जीवंत बनाने के लिए वे अब क्षेत्रीय व्यंजनों की तलाश कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यंजन जो अब नहीं बनते। इसके लिए देश के छोटे छोटे गांवों में जाकर वहां के बुजुर्गों से मिल रहे हैं और उनके स्वाद को री-क्रिएट कर रहे हैं। लोग भी इन रेसिपीज को जान सकें इसके लिए वे हर रोज एक नई रेसिपी बना कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इस मुहिम को वे 'एव्रीडे अ न्यू रेसिपी' के नाम से चला रहे हैं जिसमें अब तक नौ सौ डिशेज को बनाकर वे पोस्ट कर चुके हैं।

बचपन में ही किचन से जुड़ गया नाता : केटरिंग के पारिवारिक व्यवसाय के चलते बचपन से ही उनका नाता किचन से जुड़ गया। उसके बाद तो उन्हें नये-नये व्यंजन बनाने का ऐसा शौक चढ़ा कि उन्होंने इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। मुंबई से होटल मैनेजमेंट में डिग्री लेने के बाद होटल व फूड सर्विस मैनेजमेंट में जापान से कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने पंचतारा होटलों के लिए 'इंडिया ऑन माय पैलेट' के नाम से कॉन्सेप्ट का इजाद किया, जिसमें भारतीय जायके को शामिल किया। देश विदेश में इसे खूब सराहना मिली।

– प्रियंका दुबे मेहता

हासिल की उपलब्धियां

जायके के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन के लिए इंदर को कई सम्मान मिल चुके हैं। 2017 में आउटस्टैंडिंग शेफ ऑफ द ईयर, 2018 में शेफ ऑफ द ईयर और 2019 में गुरुग्राम अचीवर अवॉर्ड के अलावा देश विदेश में वे कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं।

समाजसेवा भी

इंदर कमजोर व वंचित वर्ग के लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। वे मानेसर स्थित दृष्टि दिव्यांग स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। इंडियन कलनरी फोरम का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने वंचित वर्ग के ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देकर शेफ बनाया है जिनके पास मूलभूत शिक्षा के संसाधान तक नहीं थे।

दिल के तार हो जाएंगे झंकृत

संगीत समारोह

तबले की थाप संग बांसुरी की सुरीली धुन सुन कदम अपने आप थिरकने लग जाएंगे। सितार के तार से निकलती स्वर लहरियां...दिग्गज संगीतकारों की दिलकश आवाज...दिल के तारों को झंकृत कर जाएंगे। शोर-शराबे से इतर मन को शांति और सुकून देने वाले भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ फुर्सत के चंद पल गुजारने का मौका मिल जाए तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। इस वीकेंड संगीत की ऐसी ही शाम ऐतिहासिक सुंदर नर्सरी में सजने जा रही है। तीन दिवसीय इस समारोह में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों की दमदार प्रस्तुति होगी।

संगीत के जरिये श्रद्धांजलि : प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अमजद अली खान दिल्ली में प्रस्तुति को लेकर खासा उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि दिल्ली में प्रस्तुति बहुत ही खास होती है। यहां दर्शक शास्त्रीय संगीत को बड़े इत्मीनान से सुनते हैं। किसी कलाकार के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कलाकार के लिए अच्छे श्रोता मिलना बहुत ही प्रेरित करने वाला होता है। शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता में बड़े गुलाम अली खां, आमिर खान, बेगम अख्तर, रविशंकर, विलायत खां समेत अन्य कलाकारों का अतुलनीय योगदान है। ऐसे ही 12 कलाकारों के उपर मैंने मास्टर ऑफ मास्टर्स किताब लिखी है। इन 12 कलाकारों को सुनकर ही लोगों में शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता बढ़ी है। यह मेरी उनको श्रद्धांजलि है।

फुर्सत में सुनने का अलग ही मजा : सोशल मीडिया समेत यू-ट्यूब पर वीडियो की बाढ़ से हैरान उस्ताद अमजद अली कहते हैं कि आज के कलाकारों को देख ऐसा लगता है मानो इन्हें गाने की जल्दी है। सभी कलाकार खड़े होकर गाने लगे हैं, जबकि संगीत तो फुर्सत में सुनने की चीज है। संगीत का इसका मजा भी तभी है, जब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सब कुछ भूल संगीत में खो जाएं।

दिल के करीब है दिल्ली : दिल्ली को दिल के बेहद करीब मानते हुए वसीफुद्दीन डागर कहते हैं कि मुझे सन् 1989 का वो दिन आज भी याद है जब पहली बार मैंने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी थी। दरअसल, मेरे पिता और चाचा समारोह में हर बार एक साथ प्रस्तुति देते थे। लेकिन पिता जी की मौत होने की वजह से उस साल मैंने अपने चाचा के साथ प्रस्तुति दी थी। उस प्रोग्राम को याद कर भावुक हो जाता हूं। वहीं राजेंद्र प्रसन्ना कहते हैं दिल्ली साहित्य कला परिषद द्वारा पहले पहल आयोजित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में मैंने रागश्री गाया था। यह पहला कार्यक्रम सन् 1978 में हुआ था। उस समय मेरी उम्र करीब 20 साल की रही होगी। जबकि दिल्ली में मैंने अपनी पहली प्रस्तुति 1974 में दी थी। मेरे पिता के एक दोस्त ने यह मौका दिया था। जब मैंने पहला राग पेश किया तो दर्शकों ने खूब सराह। इसके बाद दर्शकों की तरफ से राग पहाड़ी की फरमाइश आने लगी। मैं राग पहाड़ी नहीं जानता था। पिता के दोस्त आए और स्टेज के बगल में ले जाकर वहीं राग पहाड़ी गाकर सुनाए। मैंने उसे सुनकर स्टेज पर उसे गाया तो खूब तारीफ हुई।

मन को मोह लेगी दिग्गजों की प्रस्तुति : संगीत की इस महफिल में पहले दिन उस्ताद अमजद अली खान, विदुषी पद्मा तलवालकर और पंडित जसराज की प्रस्तुति होगी तो दूसरे दिन अपूर्वा गोखले-पल्लवी जोशी, बांसुरी वादक राजेंद्र प्रसन्ना, ध्रुपद गायक उस्ताद वसीफुद्दीन डागर की। आखिरी दिन पंडित कैवल्य कुमार, पंडित हरीश तिवारी अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीतेंगे।

–संजीव कुमार मिश्र

हरीश तिवारी

अपूर्वा गोखले

कैवल्य कुमार

राजेंद्र प्रसन्ना

- **आयोजन** : दिल्ली शास्त्रीय संगीत समारोह।
- **कहां** : सुंदर नर्सरी, निजामुद्दीन।
- **कब** : 23 से 25 नवंबर तक, शाम छह बजे से।
- **प्रवेश**- निश्शुल्क।

महात्मा गांधी के सिद्धांत

महात्मा गांधी की जिदंगी पर आधारित यह प्रदर्शनी उनके आदर्शों, सत्य के प्रयोग को कैनवस पर उकेरती है। प्रदर्शनी की खासियत पेंटिंग के जरिये गांधी के आदर्शों को चरितार्थ करना है। एक कलाकार के नजरिये से गांधी के जीवन को देखना समझना चाहते हैं तो प्रदर्शनी का रुख कर सकते हैं।

- **कहां** : ललित कला अकादमी, रविंद्र भवन, कापरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।
- **कब** : 21 से 27 नवंबर, सुबह दस से शाम सात बजे तक। • **प्रवेश** : निश्शुल्क।

वियतनाम फूड फेस्टिवल

यदि आप दिल्ली में बैठ वियतनाम के लजीज जायकों का लुत्फ उठाना चाह रहे हैं तो वियतनाम फूड फेस्टिवल से बेहतर कुछ भी नहीं। फेस्टिवल में न केवल वियतनाम के बेहतरीन जायके का स्वाद चख सकेंगे, बल्कि शेफ वो थी डीयम से इन जायकों की रेसिपी भी जान सकेंगे।

- **कहां** : होंक, पुलमैन, नई दिल्ली एयरोसिटी।
- **कब** : शाम सात बजे से।
- **शुल्क** : उपयोग आधारित।

कबाब फेस्टिवल

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले कबाब का एक ही छत के नीचे स्वाद चखना भी एक सुखद अनुभव है। अगर आप भी इसका आनंद लेना चाहते हैं तो कबाब फेस्टिवल जरूर जाएं। यहां कबाब और बीयर का कॉकटेल होगा। पनीर टिक्का, चाट खुंबू, तंदूरी मलाई ब्रोकली, मकई और प्याज की सीक, तंदूरी समेत अन्य जायके मेन्यू में होंगे।

- **कहां** : इंडिया ग्रिल, साकेत, दक्षिणी दिल्ली।
- **कब** : शाम सात से ग्यारह बजे तक।
- **शुल्क** : 899 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

किरण मजुमदार ने इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में की सुलह

नई दिल्ली, प्रेट्र : बायोकॉन की संस्थापक व चेयरपर्सन किरण मजुमदार-शॉ ने इन्फोसिस की शेयरहोल्डिंग से जुड़े मामले में सेबी के साथ समझौता कर लिया है। मजुमदार पर इन्फोसिस का बोर्ड सदस्य होने के बावजूद कंपनी में शेयरधारिता पैटर्न की समय पर जानकारी नहीं देने का आरोप था। इनसाइटडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के इस मामले में शॉ को तीन लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया गया है। पूंजी बाजार नियामक ने इस मामले में जांच के बाद मजुमदार द्वारा जान-बूझकर जानकारी देने में देर किए जाने की बात कही थी।

हम सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षा रख लेते हैं। इससे बेहतर यह होगा कि हम कानून का पूरी तरह पालन करें और अपने लिए अवसरों की तलाश खुद करें।

— हर्ष मारीवाला
चेयरमैन, मारिको

सेंसेक्स 40,575.17 ▼ 76.47	निफ्टी 11,968.40 ▼ 30.70	सोना प्रति दस ग्राम ₹ 39,007 ▼ ₹53	चांदी प्रति किलोग्राम ₹ 45,830 ▼ ₹20	$ डॉलर ₹ 71.76 ▼ ₹0.05	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $ 62.18

कारपोरेट हलचल

ड्रग पीड़ितों की मदद का आह्वान

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चंद गहलोत ने कहा है कि नशे की लत में पड़ चुके लोगों को समाज का हिस्सा बनाने में केवल सलाह और शिक्षा ही काफी नहीं है। उन्हें पूरी चिकित्सा और देखभाल की जरूरत है और लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सभी लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हों। वह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन की तरफ से आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।

डांगे को इंडिया यूरोपीयन बिजनेस फोरम अवार्ड

इंडियन यूरोपीयन बिजनेस फोरम ने वैभव डांगे को आइईबीएफ एक्सिलेंस अवार्ड प्रदान किया है। लंदन में संसद भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें यह अवार्ड दिया गया। इस मौके पर पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव, व्यवसायी जीपी हिंदुजा, लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल और आइईबीएफ के विजय गोयल मौजूद थे।

कन्नूर में स्कूल की आधारशिला

केरल के कन्नूर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की बिल्डिंग की आधारशिला राज्यसभा सदस्य केके रागेश ने रखी। इस अवसर पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पीपी दिव्या और पीएफसी के निदेशक पीके सिंह और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (सीएसआर) दिनेश विज भी उपस्थित थे।

छह दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिता

दिल्ली संस्कृत अकादमी की तरफ से दिल्ली मंडल की छह दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के सलाहकार गोपाल राय ने कहा कि सभी भाषाओं की मूल संस्कृत है। इस अवसर पर दिल्ली संस्कृत अकादमी के सचिव डॉ. जीतराम भट्ट ने कहा कि प्रतियोगिताओं में सभी को एक मंच मिलता है।

ओआइएल का सिस्मिक सर्वे

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआइएल) ने राजस्थान के सियासर ब्लॉक में सिस्मिक सर्वे डाटा सहित कई एक्सप्लोरेशन गतिविधियां शुरू की हैं। यह ब्लॉक राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर जिले में स्थित है। इन एक्सप्लोरेशन गतिविधियों के चलते ओआइएल पहली ऑपरेटर बन गई है जिसने कमिटेड वर्क प्रोग्राम (सीडब्ल्यूपी) के तहत यह काम शुरू किया है।

एआइआइएसएच फेकल्टी को आइसीएमआर फेलोशिप

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग (एआइआइएसएच) के इलेक्ट्रॉनिक विभाग में प्रोफेसर डॉ. अजिश कुमार अब्राहम को आइसीएमआर-डीएचआर शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल फेलोशिप मिली है। यह फेलोशिप उन्हें सीनियर बायोमेडिकल साइंटिस्ट की श्रेणी में मिली है। एआइआइएसएच से यह फेलोशिप पाने वाले डॉ. अब्राहम पहले फैकल्टी हैं।

रणनीतिक विनिवेश की सूची में 30 और सरकारी कंपनियां

तैयारी ▶ अगले वित्त वर्ष और तेज होगी पीएसयू निजीकरण की रफ्तार

सरकार ने बनाई है 35 कंपनियों की सूची, पांच के विनिवेश की हो चुकी घोषणा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआइ) व कंटेनर कॉरपोरेशन (कानकॉर) की रणनीतिक बिक्री के जरिये केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों की गहराई की थाह लेने की कोशिश कर रही है। अगर इन तीनों कंपनियों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री सफलतापूर्वक हो गई तो अगले वर्ष यह प्रक्रिया और तेज की जाएगी। योजना यह है कि वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में रणनीतिक बिक्री के लिए चयनित 30 अन्य कंपनियों का भी विनिवेश हो जाए।

सूत्रों के मुताबिक सीसीईए की तरफ से बुधवार को पांच सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक बिक्री के फैसले के बाद अब सारी प्रक्रिया वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाला समूह (ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म) पूरा करेगा। यह समूह ही पीएसयू के रणनीतिक विनिवेश के समय, शेयरों की संख्या और मूल्य तय कर सकेगा। इस बारे में पिछली सरकार ने इस वर्ष मार्च में ही फैसला कर लिया था। यह मैकेनिज्म वर्ष 2017 से ही काम कर रहा था। लेकिन इस वर्ष इसे विनिवेश को लेकर सारे अधिकार सौंप दिए गए हैं। अब विनिवेश से जुड़े हर छोटे बड़े फैसलों के लिए सीसीईए की इजाजत जरूरी नहीं है। वित्त मंत्री के अलावा सड़क परिवहन मंत्री इसके सदस्य हैं, जबकि संबंधित पीएसयू के प्रशासनिक विभाग के मंत्री को इसमें बतौर आमंत्रित सदस्य रखा गया है। मसलन, बीपीसीएल से जुड़े फैसले करने के लिए समूह में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शामिल किया जाएगा।

प्रतीकात्मक

मंगलवार को बीपीसीएल, एससीआइ, कॉनकोर के अलावा दो अन्य कंपनियों टीएचडीसीआइएल और नीपको में भी सरकार रणनीतिक बिक्री करने जा रही है। सिर्फ इन पांच कंपनियों से ही चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.05 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। टीएचडीसीआइएल व नीपको को सरकारी क्षेत्र की ही एक अन्य पावर कंपनी एनटीपीसी को बेचा जाएगा। उक्त पांचों कंपनियां नीति आयोग की तरफ से तैयार उन 35 कंपनियों की सूची में शामिल हैं जिनकी रणनीतिक बिक्री की जानी है। इस सूची में पवनहंस, एयर इंडिया, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, स्कूटर इंडिया, भारत पंप कंप्रेसर्स तथा सेल की भद्रावती, सालेम और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं। एयर इंडिया में भी सरकारी इक्विटी की रणनीतिक बिक्री की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसमें अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। एयर इंडिया की विफलता देख ही बीपीसीएल, एससीआइ जैसे लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को रणनीतिक बिक्री के लिए आगे किया गया है। इससे विनिवेश का माहौल बनेगा और देसी-विदेशी कंपनियों के मन में भरोसा बनेगा। इसके अलावा सरकार पहले ही हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट, एचएलएल लाइफ केयर और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पीएसयू के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दे चुकी है।

लोन मेले का दिखा असर, बैंकों ने 2.52 लाख करोड़ के कर्ज बांटे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कर्ज बांटकर उपभोक्ता मांग बढ़ाने में जुटी केंद्र सरकार की कोशिशों का असर होता दिख रहा है। पिछले महीने त्योहारों के मौसम में सरकारी बैंकों की तरफ से शाखाओं और लोन मेले के जरिये कुल 2.52 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गए। ये कर्ज 374 जिलों में वितरित हुए। यह पहला मौका था जब सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस दौरान नए बैंकों ने ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा किया। सरकार के निर्देश पर बैंकों ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी इस दौरान फंड उपलब्ध कराने में उदारता दिखाई और उन्हें कुल 19,627.26 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे। वित्त मंत्री ने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक कर देश भर में लोन मेला लगाने का निर्देश दिया था।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कुल 2,52,589 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गए हैं। इसमें से 1,05,599 करोड़ रुपये का कर्ज पहली बार बने ग्राहकों को दिए गए हैं। जबकि 46,800 करोड़ रुपये की राशि बतौर कर्ज वर्किंग कैपिटल के तौर पर छोटे व मझोले उद्यमियों को दिए गए हैं। सरकारी बैंकों ने पहला लोन वितरण अभियान पहली से नौ अक्टूबर तक और दूसरा 31 अक्टूबर तक चलाया था। पहले चरण में 81.695 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 1,70,893 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गए। इस दौरान 12,166 करोड़ रुपये की राशि होम लोन के रूप में और 7.085 करोड़ रुपये की राशि वाहन लोन के मद में बांटी गई। बैंकों ने इस अवधि में शिक्षा लोन के मद में 425 करोड़ रुपये, पर्सनल लोन के तौर पर 15,250 करोड़ रुपये, एमएसएमई लोन के मद में 37,210 करोड़ रुपये और कृषि लोन के मद में 40,504 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

इन आंकड़ों के आने के बाद माना जा रहा है कि देश में उपभोक्ता उत्पादों खासतौर पर घरेलू उपकरणों की मांग में थमी सुस्ती का दौर कुछ हद तक दूर होगा। अक्टूबर के महीने के दौरान वाहन बिक्री की रफ्तार भी थोड़ी सुधरी है, जिसमें ज्यादा बंटे आटो लोन की बड़ी भूमिका मानी जा रही है।

प्रतीकात्मक

लेखा-जोखा

- अक्टूबर में 374 जिलों में बैंकों ने लोन बांटने के लिए लगाए कैंप
- 19,627 करोड़ रुपये एनबीएफसी को भी दिए बैंकों ने

राज्यों की सलाह से बनेगी राष्ट्रीय कपड़ा नीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार राज्यों के सलाह मशविरे के साथ राष्ट्रीय कपड़ा नीति तैयार कर रही है। इसके तहत घरेलू मैन्यूफैक्चरर के साथ-साथ टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा राष्ट्रीय कपड़ा नीति पर अभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। एक पूरक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ाने की दिशा में मौजूदा बाजारों के साथ साथ 12 नए बाजारों की पहचान भी की गई है। इरानी ने कहा कि सरकार इस बात के प्रयास भी कर रही है कि छोटे निर्यातक सरकार की मदद से मझोली कंपनियों में तब्दील हो सकें।

कपड़ा मंत्री ने सदन को बताया कि छह हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज के एलान के बाद एटीयूएफएस स्कीम के तहत अब तक 1868 आवेदन मिल चुके हैं। इनमें 13,612 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। एक लिखित जवाब में ईरानी ने कहा कि स्पेशल पैकेज के तहत अपैरल का निर्यात अक्टूबर 2016 से अगस्त 2019 के दौरान 327895 करोड़ रुपये का रहा।

टैरिफ बढ़ाए बिना टेलीकॉम कंपनियों को राहत नहीं

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

वित्तीय संकट में फंसी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की तरफ से भले ही राहत मिल रही हो, लेकिन बिना टैरिफ बढ़ाए कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर के जानकारों और विश्लेषकों का मानना है कि कंपनियों का प्रति यूजर औसत रेवेन्यू जब तक साल 2015 के स्तर पर नहीं आएगा, सरकार की तरफ से मिलने वाले किसी राहत पैकेज का लाभ नहीं होगा।

बुधवार को ही केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम शुल्क भुगतान को दो वर्षों तक के लिए टाल दिया है। हालांकि अभी एजीआर की अदायगी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और सचिवों की समिति उस पर विचार कर रही है। बावजूद इसके टेलीकॉम सेक्टर के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस क्षेत्र के अन्य बकाया मुद्दों का हल ढूंढने के साथ-साथ टैरिफ दरों में बढ़ोतरी को अब टाला नहीं जा सकता।

दरअसल जानकारों का मानना है कि टेलीकॉम सेवाओं और डाटा को सस्ता करने की होड़ में कंपनियों की वित्तीय स्थिति बिगड़ती चली गई। साल 2015 में जब प्रति यूजर औसत रेवेन्यू 200 रुपये था, तब कंपनियां ठीक स्थिति में थीं। लेकिन वर्तमान में यह गिरकर एयरटेल के लिए 128 रुपये और वोडाफोन के लिए 107 रुपये रह गया है। इसका मतलब यह है कि एयरटेल प्रति ग्राहकों से हर महीने सिर्फ 128 रुपये और वोडाफोन आइडिया 107 रुपये का राजस्व हासिल कर रही है। मॉर्गन स्टेनले के पराग गुप्ता के मुताबिक इसे वापस 2015 के स्तर पर लाना होगा।

यद्यपि टेलीकॉम सेक्टर की तीनों बड़ी कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया टैरिफ दरों में वृद्धि करने की मंशा जता चुकी हैं। लेकिन इंडस्ट्री के के जानकारों का कहना है कि अगर 200 रुपये का प्रति यूजर औसत रेवेन्यू पाने के स्तर तक पहुंचना है तो कंपनियों को मौजूदा दरों से टैरिफ में 30 परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ब्रिकवर्क रेटिंग के निदेशक (रेटिंग) विपुल शर्मा का कहना है कि टैरिफ दरों में 10 परसेंट की वृद्धि भी कंपनियों के घाटे में 30 परसेंट तक की कमी ला सकती है।

टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर ट्राई फिलहाल टैरिफ दरों में संशोधन पर विचार कर रहा है। मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जियो टैरिफ दरों में बढ़ोतरी का समर्थन पहले ही कर चुकी है। क्रेडिट सुइस के मुताबिक यह ट्राई पर निर्भर करेगा कि वह कितनी वृद्धि की सिफारिश करता है। क्रेडिट सुइस मानती है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह 20 परसेंट से अधिक होनी चाहिए।

टेलीकॉम सेक्टर के जानकारों का मानना है कि टैरिफ दरों में वृद्धि और सरकार के शुल्कों में कमी पूरे सेक्टर की दशा को सुधारने में मदद कर करेगी। पूरा सेक्टर करीब सात लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा है। यही नहीं, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ने ही चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड घाटा दर्ज किया है। एयरटेल को 23,045 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया ने 50,921.9 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। दोनों कंपनियों पर एजीआर बकाया मद में 81000 करोड़ रुपये चुकाने की तलवार भी लटक रही है।

टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सीओएआइ के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज का मानना है कि भुगतान में राहत के साथ साथ सेक्टर के अन्य मुद्दों को भी सुलझाना आवश्यक है। वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियां अपने राजस्व का 30 परसेंट हिस्सा सरकारी टैक्स और शुल्कों के भुगतान पर खर्च कर रही हैं। इन शुल्कों व टैक्स दरों को तार्किक बनाना आवश्यक है।

- कंपनियों के प्रति यूजर औसत रेवेन्यू को साल 2015 के स्तर पर लाना जरूरी
- टैरिफ दरों में चरणबद्ध तरीके से 30 परसेंट की वृद्धि आवश्यक : टेलीकॉम एक्सपर्ट

प्रतीकात्मक

टोल प्लाजा पर जाम से मुक्ति दिलाता है फास्टैग

जेएनएन, नई दिल्ली

अगले महीने से नेशनल हाईवे (एनएच) पर स्थित सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित टोल कलेक्शन सुविधा शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर किसी वाहन पर फास्टैग नहीं लगा हो, तो उसे टोल से गुजरने में खासा वक्त जाया करना पड़ेगा। फास्टैग कोई तिलिस्म नहीं बल्कि सामान्य तकनीक है, जो टोल प्लाजा पर कई बार घंटों लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाता है। आइए, जानते हैं फास्टैग के बारे में कुछ बुनियादी बातें :

फास्टैग क्या है?

-यह अमूमन एक छोटा सा, बेहद पतला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई भी क्रेडिट, डेबिट कार्ड होता है। आकार-प्रकार में यह क्रेडिट कार्ड के आधे या उससे भी छोटा होता है। इसे कार के अगले शीशे पर चिपकाया जाता है। इसमें एक चिप लगा होता है, जिसमें उस वाहन के बारे में सभी सूचनाएं दर्ज होती हैं। टोल प्लाजा पर फास्टैग की सूचना एकत्र करने वाले उपकरण लगे होते हैं, जो उस फास्टैग के संपर्क में आते ही वाहन की सभी सूचना एकत्र कर लेते हैं।

प्रतीकात्मक

फास्टैग कहां-कहां मिलता है?

-पहली दिसंबर तक यह किसी भी एनएच के टोल प्लाजा से मुफ्त लिया जा सकता है। उसके अलावा यह एसबीआइ, एक्सिस बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और एचडीएफसी बैंक समेत कई बैंकों की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है। इसे पेट्रोल पंप के माध्यम से भी बेचने की योजना है। यह कई ऑनलाइन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

फास्टैग खरीदने के लिए क्या कोई दस्तावेज चाहिए?

-जी हां, इसके लिए आपके पास वाहन के कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी केवाईसी से जुड़े दस्तावेज चाहिए। केवाईसी में सरकार प्रमाणित कोई भी दस्तावेज मसलन आधार कार्ड या वोटर आइडी कार्ड, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं।

फास्टैग कितने में मिलता है?

-पहली बार इसके लिए ज्वाइनिंग फीस 100 रुपये लगती है। उसके बाद अलग-अलग वाहनों के लिए 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक सेक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। इसमें न्यूनतम 100 रुपये का बैलेंस रखना पड़ता है।

फास्टैग कहां-कहां से रिचार्ज कराया जा सकता है?

- इसे अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन तथा बैंक शाखाओं के अलावा टोल प्लाजा से रिचार्ज कराया जा सकता है। आप चाहें तो इसे अपने अकाउंट से लिंक भी करा सकते हैं।

फास्टैग लेने का फायदा क्या है?

- टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है, या रुकना पड़े भी तो बेहद कम समय लगता है। इससे ईंधन और समय की बचत होती है। बार-बार टोल प्लाजा पर कैश निकालने, देने और बैलेंस वापस लेने जैसे झंझटों से मुक्ति मिल जाती है।

मछुआरों को केसीसी बांटने की रफ्तार धीमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मछुआरों को किसान मानकर रियायती दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना की रफ्तार बहुत धीमी है। दो करोड़ मत्स्यपालकों में से अब तक केवल आठ हजार को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा सका है।केंद्रीय मत्स्य, पशुधन व डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने इस सुस्ती पर गहरी नाराजगी जताई है।

विश्व मात्स्यिकी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में सिंह ने मछुआरों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि समुद्र तटीय क्षेत्रों का जिस अंधाधुंध तरीके से दोहन हुआ है, उसका खामियाजा आज की पीढ़ी उठा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। प्रतिबंधित समय और क्षेत्र में भी मछली पकड़ने का कुप्रभाव है कि तट से 12 समुद्री मील तक मछली ही नहीं बची। उन्होंने कहा कि मरीन कल्चर के लिए कानून बनाया जा रहा है। दूसरे देशों के मछुआरे हमारी सीमा से मछली पकड़ लेते थे, जिस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

सिंह का कहना था कि मत्स्यपालकों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जिन राज्यों में खारा पानी है, अब वहां झींगा मछली का पालन होगा। 19,509 किलोमीटर लंबाई की नदियों में मछली पालन की योजना है। देश में 25 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा में पोखर, तालाब और जलाशय हैं। इनमें उत्पादन केवल तीन टन प्रति हेक्टेयर है, जिसे बढ़ाने की संभावनाएं है।

मछली पालन को लेकर केंद्रीय मत्स्य, पशुधन व डेयरी राज्यमंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह केवल दक्षिणी क्षेत्र में ही काम करता है। इसे अब उत्तरी राज्यों में काम करने की जरूरत है। उत्तरी राज्यों के तालाब और पोखर बहुत खस्ताहाल हैं।

सुस्ती

विनिवेश योजना और टेलीकॉम सेक्टर को राहत का नहीं दिखा असर, यूएस-चीन व्यापार समझौते में देरी से चिंतित रहे दुनियाभर के बाजार

विनिवेश योजना पर ग्लोबल चिंता भारी, बाजारों पर ब्रेक

मुंबई, प्रेट्र : लगातार दो सत्र में बढ़त दर्ज करने के बाद गुरुवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। सरकार की नई सुधार घोषणाएं शेयर बाजार को उत्साहित करने में विफल रहीं। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 76.46 अंक यानी 0.19 परसेंट की गिरावट के साथ 40,575.17 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 30.70 अंक लुढ़ककर 11,968.40 पर बंद हुआ।

गुरुवार को सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। इसके शेयर 3.35 परसेंट तक लुढ़क गए। यूरोपीय परिचालन में तीन हजार कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा के बाद से कंपनी के शेयर अस्थिर हैं। जानकारों के मुताबिक कंपनी की इस योजना को कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से टाटा स्टील के भविष्य को लेकर निवेशकों में निराशा देखी गई।

भारती एयरटेल, यस बैंक, ओएनजीसी और आइटीसी के शेयर 2.52 परसेंट तक की गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर एचयूएल, एलएंडटी, बजाज ऑटो और एसबीआइ के शेयरों में 1.15 परसेंट तक का उछाल दर्ज किया गया। बीएसई में मेटल, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो सेक्टर के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं रियल्टी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंस, आइटी और टेक सेक्टर के शेयरों ने बढ़त दर्ज की।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की ओर बड़ा कदम बढ़ाते हुए बुधवार को पांच सरकारी कंपनियों के विनिवेश की घोषणा की थी। इसके अलावा कर्ज संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम का बकाया लौटाने के लिए दो वर्षों का अतिरिक्त समय दिया गया है। लेकिन इन सरकारी सुधारों से शेयर बाजार में किसी तरह का उत्साह नहीं देखा गया।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक यूएस-चीन में ट्रेड समझौते को लेकर हो रही देरी से दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है। भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग, टोक्यो और सियोल के शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के शेयर बाजारों में भी सत्र के शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गई।

प्रतीकात्मक

टेलीकॉम सेक्टर दबाव में

प्रॉफिट बुकिंग के चलते गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में बीएसई में वोडाफोन के शेयर 6.08 परसेंट लुढ़क कर 6.64 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बंद हुए। वहीं एयरटेल के शेयरों में भी 2.52 परसेंट की गिरावट आई। बीएसई में कंपनी के शेयर 426.25 रुपये के भाव पर बंद हुए। इससे पहले शुल्क बढ़ाने की घोषणा के बाद इन कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल आया था। गौरतलब है कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त समय दिया है। लेकिन शेयर बाजार इस घोषणा से उत्साहित नहीं दिखे।

विनिवेश घोषणा का असर

विनिवेश की घोषणा के बाद गुरुवार को इन सरकारी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआइ) के शेयर 6.29 परसेंट गिरावट के साथ 64.05 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के शेयर 5.66 परसेंट गिरावट के साथ 513.80 रुपये की कीमत पर बिके। गौरतलब है कि अब तक की सबसे बड़ी विनिवेश घोषणा के तहत सरकार ने पांच सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की बात कही है।

सराफा बाजार में मामूली सुस्ती

नई दिल्ली, प्रेट्र : गुरुवार को प्रमुख भारतीय सराफा बाजारों में सुस्ती का दौर रहा। दिन के कारोबार में पीली धातु 53 रुपये की गिरावट के साथ 39,007 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुई। वहीं चांदी 20 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 45,830 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के रिसर्च प्रमुख तपन पटेल के मुताबिक रुपये में मामूली सुधार के चलते सोने के भाव में सुस्ती आई। शादी का सीजन शुरू होने के कारण आने वाले दिनों में सोने के भाव में इजाफा होने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में सोना 1,472.70 रुपये और चांदी 17.10 रुपये प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिके।

एसबीआइ ने माना, कुछ निर्णयों में हुई गलती

मुंबई, प्रेट्र : देश के सबसे बड़े कर्जदाता एसबीआइ ने स्वीकार किया है कि पिछले कुछ समय के दौरान उससे कई फैसले लेने में गलती हुई है। हालांकि बैंक ने कहा है कि अन्य बैंकों की तुलना में इस वक्त अपने वैल्यूएशन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। सरकारी क्षेत्र के इस सबसे बड़े बैंक ने अपनी निर्णय प्रक्रिया में सुधार की जरूरत स्वीकार की है। एसबीआइ के एमडी अरिजीत बसु ने बताया कि बैंक प्रबंधन ने कुछ गलत व्यापारिक फैसले लिए हैं, जिनकी सामाजिक हित के नाम पर अनदेखी नहीं की जा सकती। एसबीआइ का बाजार पूंजीकरण काफी कम है। शुक्रवार को यह करीब 2.95 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इसी दौरान एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 7.02 लाख करोड़ रुपये था। कर्ज बांटने के मामले में भी एसबीआइ की सेहत बेहतर नहीं कही जा सकती। एचडीएफसी के लोन-खाते में नौ लाख करोड़ रुपये दर्ज हैं, जबकि एसबीआइ ने 22.48 करोड़ रुपये का लोन बांट रखा है। सेबी प्रमुख एम. दामोदरन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बसु ने एसबीआइ के दायित्व और व्यापारिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

4000 सैनिक वापस बुला सकता है अमेरिका दक्षिण कोरिया से। एक दक्षिण कोरियाई अखबार ने इस बात का दावा किया है। दक्षिण कोरिया में 28 हजार 500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हालांकि, अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने इस बात से इन्कार किया है।

राजनीतिक विज्ञापनों पर गूगल ने की और सख्ती

सैन फ्रांसिस्को, एएफपी

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भ्रामक सूचनाएं फैलाने का जरिया बनने से बचने के लिए गूगल ने अपने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नियमों में और सख्ती की है। इंटरनेट की दुनिया की दिग्गज कंपनी का कहना है कि उसके नियमों में पहले से ही किसी विज्ञापन में झूठे तथ्यों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इनमें राजनीतिक संदेश भी शामिल हैं। अब कंपनी ने अपनी नीतियों को और अधिक स्पष्ट किया है। इनमें ऐसे उदाहरण भी शामिल किए गए हैं कि छेड़छाड़ की गई तस्वीरों या वीडियो को किस प्रकार रोका जाएगा।

गूगल के विज्ञापन प्रबंधन विभाग से जुड़े वाइस प्रेसिडेंट स्कॉट स्पेंसर ने कहा, 'हम मानते हैं कि मजबूत राजनीतिक संवाद लोकतंत्र के लिए जरूरी है और कोई भी हर राजनीतिक दावे, प्रतिदावे व आरोप के सही-गलत की जांच नहीं कर सकता है। इसलिए हमें लगता है कि जिन राजनीतिक विज्ञापनों पर हम कार्रवाई करेंगे, उनकी संख्या काफी कम रहेगी। फिर भी हम स्पष्ट उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को रोकते रहेंगे।' गूगल के नए प्रावधानों के तहत विज्ञापनदाता उम्र, लिंग या लोकेशन के हिसाब से अपने ऑडियंस को टार्गेट कर सकेंगे। उन्हें उसी तरह विज्ञापन की अनुमति रहेगी जैसे प्रिंट, रेडियो और टीवी पर विज्ञापन आते हैं। स्पेंसर ने बताया कि हफ्तेभर में इन बदलावों को ब्रिटेन में लागू कर दिया जाएगा। साल के अंत तक पूरे यूरोपीय संघ में और छह जनवरी से बाकी दुनिया में इन बदलावों को प्रभावी किया जाएगा।

स्पेंसर ने कहा, 'किसी भी विज्ञापनदाता द्वारा झूठा दावा करना हमारी नीति के खिलाफ है। विज्ञापन में चाहे किसी कुर्सी की कीमत गलत बताई गई हो या ऐसा विज्ञापन हो कि इलेक्शन टल गया है, किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो गई है या दावा किया जाए कि एसएमएस भेजकर मतदान किया जा सकता है, इन सब पर प्रतिबंध है।' कंपनी की ओर से दिए गए उदाहरणों में कुछ प्रतिबंधित किए गए विज्ञापन व लिंक रखे गए हैं, जिनमें ऐसे झूठे दावे किए गए थे, जो मतदान के समय लोगों के विचारों में बदलाव का कारण बन सकते हैं।

छेड़छाड़ की गई तस्वीरों या वीडियो को रोका जाएगा। प्रतीकात्मक

- मतदाताओं को भरमाने वाले झूठे दावों को किया जाएगा प्रतिबंधित
- उम्र, लिंग या स्थान के आधार पर टार्गेट नहीं कर सकेंगे विज्ञापनदाता

अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कर रहे सख्ती

प्रतीकात्मक

फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट जैसे तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने यहां राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्ती कर रहे हैं। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध की बात कही है। हालांकि पिछले हफ्ते ट्विटर ने स्पष्ट किया था कि सामाजिक या पर्यावरण के मुद्दों से जुड़े अर्थपूर्ण (कॉज बेस्ड) संदेशों को नहीं रोका जाएगा। स्नैपचैट ने भी भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का एलान किया है। फेसबुक की नीतियां इस मामले में सबसे कमजोर मानी जा रही हैं।

कनाडा की नई कैबिनेट में हिंदू महिला समेत चार भारतवंशी

ओटावा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ हिंदू महिला सांसद अनीता आनंद। रायटर

ओटावा, प्रेट्र : कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नई कैबिनेट में पहली बार एक हिंदू महिला सांसद अनीता आनंद को जगह मिली है। ट्रूडो की 37 मंत्रियों की कैबिनेट में अनीता समेत चार भारतवंशी सांसद जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। ट्रूडो कैबिनेट में जिन सात नए चेहरों को जगह मिली है, उनमें टोरंटो विश्वविद्यालय की पूर्व लॉ प्रोफेसर अनीता भी शामिल हैं। ओंटेरियो के ओकविले से सांसद बनीं अनीता को सार्वजनिक सेवाएं और प्रबंध विभाग दिया गया है। भारतीय मूल के तीन अन्य मंत्रियों में सभी सिख हैं। इनमें नवदीप बैंस (42), बार्दिश छगर (39) और हरजीत सज्जन (49) शामिल हैं। कनाडा की सेना और वेंकूवर पुलिस में अपनी सेवाएं दे चुके हरजीत सज्जन को राष्ट्रीय रक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। उनके पास पहले भी यह मंत्रालय था। वहीं बैंस का नाम नवाचार, विज्ञान और उद्योग मंत्री के रूप में सामने आया है।

- राष्ट्रीय रक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए हरजीत सज्जन

जलियांवाला नरसंहार के लिए माफी मांगेगी लेबर पार्टी

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने 12 दिसंबर को होने वाले आम चुनाव के लिए गुरुवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें 100 साल पहले अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए भारत से माफी मांगने सहित देश के औपनिवेशिक अतीत की जांच कराने का संकल्प जताया गया है। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने इस नरसंहार के 100 साल होने पर इस घटना के लिए गहरा अफसोस जताया था। लेकिन, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। लेबर पार्टी के नेता जेरमी कोर्बिन ने 107 पन्ने का घोषणापत्र पेश किया है। पार्टी ने इस मामले पर माफी मांगने का संकल्प जताया है। कहा गया कि लेबर पार्टी ब्रिटेन के 'अतीत में हुए अन्याय' की जांच के लिए एक न्यायाधीश के नेतृत्व वाली समिति बनाएगी। घोषणापत्र का शीर्षक है 'इट्स टाइम फोर रीयल चेंज'। अलावा ऑपरेशन ब्लूस्टार में देश की भूमिका की समीक्षा की भी बात कही गई है। वर्ष 2014 में ब्रिटेन सरकार के सार्वजनिक हुए दस्तावेजों से पता चला था कि भारतीय सुरक्षा बलों को स्वर्ण मंदिर में घुसने से पहले ब्रिटिश सेना ने सलाह दी थी। ब्रिटेन के कुछ सिख समूह वर्षों से मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि किस तरह की सलाह दी गई थी।

न्यूज गैलरी

मलेशिया में धोखाधड़ी के आरोप में 680 चीनी गिरफ्तार

कुआलालंपुर : मलेशिया के अधिकारियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में 680 चीनी संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये ऑनलाइन धोखेबाजी के जरिए लोगों को उनके ही शहरों में ठगते थे। अप्रवासन विभाग के महानिदेशक खैरुल दजाइमी दौड ने बताया कि विभाग के 150 सदस्यों की टीम ने साइबरजाया में स्थित संदिग्धों के हैडक्वार्टर पर छापा मारा। उन्होंने बताया कि करीब 100 संदिग्ध भागने में कामयाब रहे। वहीं कुछ हाथापाई के दौरान घायल हो गए। बदमाश लोगों को बहुत जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने का लालच देते थे। इसके तहत ऑपरेटर मंदारिन भाषा में कस्टमर को एक कोड भेजता था। इसके बाद सभी लेनदेन वीचैट या चीनी बैंकों द्वारा होता था। आप्रवासन अधिकारियों के मुताबिक संभवत मलेशिया में यह चीनी बदमाशों द्वारा सबसे बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी है। (रायटर)

नेपाली प्रधानमंत्री ने नौ मंत्रियों को बाहर किया

काठमांडू : बीमार चल रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। इस फेरबदल में छह कैबिनेट और तीन राज्यमंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। माना जा रहा है कि फेरबदल के जरिये प्रधानमंत्री ओली की कोशिश सरकार पर अपनी पकड़ को मजबूत रखना और पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को कम करना है। ओली के आलोचकों का कहना है कि सहयोगी दल लगातार प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने वफादारों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ओली ने 2007 में भारत में किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। इसके बाद से ही उनकी सेहत खराब बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ओली जल्द ही इलाज करवा सकते हैं। उनके कार्यालय से कोई जानकारी नहीं दी गई है। (रायटर)

ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया : पेलोसी

वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान स्पष्ट हैं। उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल निजी हित के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया। इसलिए ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह बात अमेरिकी संसद (प्रतिनिधि सभा) की स्पीकर नेंसी पेलोसी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। पेलोसी ने कहा कि महाभियोग में लगे आरोपों की जांच कर रही संसदीय समिति को फैसला करना है कि वह प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएगी। महाभियोग के आगे का कार्यक्रम अभी अघोषित है। महाभियोग की अंतिम तारीख तय नहीं हुई है। इस बीच ट्रंप की रूसी मामलों की पूर्व सलाहकार फिओना हिल ने कहा है कि विपक्षी सांसद महाभियोग मामले में झूठे आरोपों का खेल बंद करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी महाभियोग की जांच को दुर्भावना से प्रेरित बता चुके हैं। इसे विपक्ष की साजिश बताया है। (रायटर)

राष्ट्रपति गोतबाया ने बड़े भाई महिंदा को दिलाई प्रधानमंत्री पद की शपथ

संभाला पदभार ▶ श्रीलंका की सत्ता पर राजपक्षे परिवार पूरी तरह से हुआ काबिज

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका की सत्ता पर राजपक्षे परिवार पूरी तरह काबिज हो गया है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने गुरुवार को अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। गोतबाया गत रविवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इस द्वीपीय देश में पहले भी ऐसा हो चुका है, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अहम पदों पर एक ही परिवार के लोग काबिज रहे।

राष्ट्रपति सचिवालय में 74 वर्षीय महिंदा ने श्रीलंका के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वह अगले साल अगस्त में होने वाले आम चुनाव तक इस पदभार को संभालेंगे। शपथ लेने के बाद महिंदा ने कहा, 'मैं श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं सभी श्रीलंकाई नागरिकों के लिए काम करूंगा और हम नए दृष्टिकोण के साथ अपने देश को आगे लेकर चलेंगे।' इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेन और पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी मौजूद थे। राष्ट्रपति चुनाव में गोतबाया की जीत के बाद रानिल ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 70 वर्षीय गोतबाया ने राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के उम्मीदवार सजित प्रेमदासा को हराया था। महिंदा राजपक्षे पर श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के खिलाफ सैन्य अभियान में सुरक्षा बलों द्वारा यौन शोषण और बंदियों की हत्याओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगे थे। यह गृहयुद्ध मई, 2009 में समाप्त हुआ था। उन पर सत्ता में रहने के दौरान अपने विरोधियों पर कार्रवाई का भी आरोप है। उनके समर्थक सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों की हत्या में भी कथित तौर पर शामिल थे।

चंद्रिका कुमारतुंगा ने मां को बनाया था पीएम : श्रीलंका की राष्ट्रपति रहते चंद्रिका कुमारतुंगा ने अपनी मां सिरिमाओ भंडारनायके को प्रधानमंत्री बनाया था। चंद्रिका 1994 से 2005 तक राष्ट्रपति रहीं, जबकि उनकी मां 1994 से 2000 तक पीएम रहीं। सिरिमाओ 1970 से 1977 और 1960 से 1965 तक भी पीएम रही थीं। वह पीएम बनने वाली दुनिया की पहली महिला थीं।

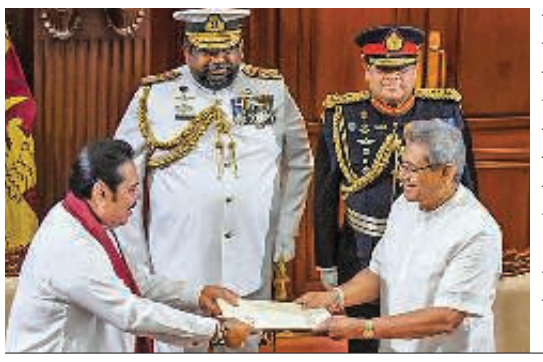

दो बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके महिंदा राजपक्षे ने गुरुवार को कोलंबो में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने अपने बड़े भाई महिंदा को इस पद पर नियुक्त किया था। एएफपी

कौन हैं महिंदा राजपक्षे

- वकालत छोड़ सियासत में कदम रखा और चमत्कारिक नेता के तौर पर उभरे
- 24 साल की उम्र में 1970 में पहली बार संसद में कदम रखा
- 2005-2015 तक श्रीलंका के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे
- लिट्टे के साथ तीन दशक से चल रहे गृहयुद्ध को 2009 में खत्म कराया
- 26 अक्टूबर से 15 दिसंबर, 2018 तक प्रधानमंत्री भी रहे

सरकार के साथ काम करने को इच्छुक भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यहां कहा कि भारत, श्रीलंका की नई सरकार के साथ बेहद निकटता के साथ काम करने को इच्छुक है। साथ ही उम्मीद भी जताई कि यह सरकार श्रीलंका में रह रहे तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भ्रष्टाचार मामलों में आरोपित

यरुशलम, रायटर : इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भ्रष्टाचार मामलों में आरोपित किया गया है। इस आशय का एलान गुरुवार को देश के अटॉर्नी जनरल अवीचाई मांडेल्बिट ने किया। इजरायल में ऐसा पहली बार हुआ है जब पद पर काबिज प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार मामले में आरोपित किया गया है।

अटॉर्नी जनरल के इस फैसले से देश में राजनीतिक अनिश्चितता का कुहासा और घना हो गया है। दो बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने के चलते तीसरी बार चुनाव की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन देश के सबसे बड़े कद वाले नेता नेतन्याहू के भ्रष्टाचार मामले में फंसने से अनिश्चितता और बढ़ने की आशंका है। अटॉर्नी जनरल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू पर रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और विश्वास तोड़ने के आरोप हैं। नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों से इन्कार किया है। इजरायल के कानून के अनुसार जरूरी नहीं है कि आरोप लगने के बाद प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़े। लेकिन आने वाले समय में नेतन्याहू कोई महत्वपूर्ण एलान कर सकते हैं।

शुरुआती जांच में नेतन्याहू को दोषी पाए जाने पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर मुकदमा चलाने की सिफारिश अटॉर्नी जनरल से फरवरी में की थी। जांच में नेतन्याहू को गलत तरीके से 2,64,000 डॉलर (करीब तीन करोड़ रुपये) मूल्य के उपहार लेने का दोषी पाया गया है।

इजरायल में साल भर के अंदर तीसरी बार हो सकते हैं चुनाव

यरुशलम, आइएएनएस : इजरायल में संसदीय चुनाव के दो माह बाद भी नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद विपक्षी नेता बेनी गेंट्स भी सरकार बनाने में विफल हो गए। राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन ने गेंट्स को 28 दिन का समय दिया था। यह समयसीमा खत्म होने पर गेंट्स ने बुधवार मध्यरात्रि एलान किया कि वह सरकार बनाने में नाकाम रहे। गेंट्स के इस बयान से इजरायल में एक साल के अंदर तीसरी बार चुनाव होने के आसार बढ़ गए हैं। पूर्व सेना प्रमुख और ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी के नेता गेंट्स ने साझा सरकार बनाने में मिली विफलता के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है। गेंट्स ने कहा, 'नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार मामलों की जांच में छूट की मांग को छोड़ने से मना कर दिया। इन मामलों में वह मुख्य संदिग्ध हैं।' उन्होंने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वह अभियोग से बचने के लिए पिछले एक साल से अंतरिम सरकार चला रहे हैं। राष्ट्रपति ने सबसे पहले नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए 28 दिनों की मोहलत दी थी। नेतन्याहू के नाकाम होने पर गेंट्स को मौका दिया गया था।

सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर पाकिस्तान की चर्चा को भारत ने किया खारिज

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर का मसला उठाने के पाकिस्तान के कदम को खारिज कर दिया है। कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उस पर पाकिस्तान या किसी अन्य देश की बात नहीं सुनी जा सकती। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का राजदूत नियुक्त होने के बाद मुनीर अकरम ने सुरक्षा परिषद की बैठक में पहली बार हिस्सा लेते हुए बुधवार को कश्मीर का मसला उठाया था। अकरम ने कहा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले मसलों पर ध्यान देने और उनका निदान करने की सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। लेकिन जम्मू-कश्मीर पर लंबे समय से बरती जा रही निष्क्रियता से पाकिस्तान की चिंता बढ़ी है।

अकरम के बयान का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने कहा, हम पाकिस्तान के अवांछित वक्तव्य को खारिज करते हैं। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस मसले पर दोनों देश बातचीत करने का समझौता पूर्व में कर चुके हैं। ऐसे में इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोई तुक नहीं है। उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत सरकार के कदम से पाकिस्तान बौखला गया है। वह अंतरराष्ट्रीय मंचों और हर प्रमुख देश से जम्मू-कश्मीर मसले पर अपने विरोध का समर्थन करने की गुहार लगा चुका है। लेकिन उसे कहीं से तवज्जो नहीं मिली।

संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका समेत दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर मसले पर भारत के साथ ही बातचीत करने की सलाह दी। भारत का साफ कहना है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान सीमा पार से वहां आतंकी भेजना बंद करे, तभी उससे बातचीत की जाएगी। आतंक के माहौल में कोई बातचीत नहीं होगी।

370 हटने से खुले भारतीयों के लिए समानता के द्वार : अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के एक सांसद ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाना 'सभी भारतीयों के लिए समानता' के दरवाजे खोलता है और यह घाटी में शांति की दिशा में बढ़ाया गया कदम हो सकता है। भारत के कदम का स्वागत करते हुए रिपब्लिकन सांसद पेट ओलसोन ने बुधवार को कहा, 'इस वर्ष भारत की संसद ने पुष्टि की कि अनुच्छेद-370 खत्म होना चाहिए और यह खत्म हो गया। इससे जम्मू-कश्मीर की जनता को सभी भारतीय की तरह समान अधिकार मिले हैं। यह राज्यसभा में 61 के मुकाबले 125 मतों से और लोकसभा में 70 के मुकाबले 370 मतों से पारित हुआ। इस कदम ने सभी भारतीयों के लिए समानता के द्वार खोले हैं।' उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि यह कदम कश्मीर में शांति की दिशा में उठाया गया कदम बने। ओलसोन के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अनुच्छेद-370 के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत के इस रुख को पूरी तरह समझा था कि यह पूरी तरह संप्रभु और अंदरूनी मसला है। भारत लगातार ट्रंप प्रशासन, वहां की संसद, नागरिक समाज और अन्य के संपर्क में था।

नया देश बनने की राह पर बोगनविली

जल्दी ही दुनिया के मानचित्र पर एक और देश नजर आ सकता है। लंबे समय तक चली लड़ाई के बाद संसाधन-समृद्ध द्वीपों वाला बोगनविली पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बनने की राह पर है। 23 नवंबर को करीब दो लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता अधिक स्वायत्ता या स्वतंत्रता के लिए मतदान करेंगे। मतदान 7 दिसंबर तक जारी रहेगा।

ऐसे पड़ा नाम

बोगनविली का नाम 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी खोजकर्ता के नाम पर पड़ा। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन उपनिवेश, जर्मन न्यू गिनी का हिस्सा बना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ऑस्ट्रेलिया के नियंत्रण में आया और 1975 तक उसी के ही नियंत्रण में रहा।

आजादी क्यों

1975 में पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) को स्वतंत्रता मिली और बोगनविली एक प्रांत बना। पीएनजी बनने से कुछ समय पहले बोगनविली की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया और पीएनजी दोनों ने नजरअंदाज कर दिया था। इससे असंतोष उबल पड़ा और 1988 से अलगाव के लिए अगले नौ साल तक युद्ध चलता रहा। युद्ध की शुरुआत में इस क्षेत्र के 4,000 से 20,000 तक लोग मारे गए। रंगभेद ने भी इस लड़ाई में घी डालने का काम किया। दरअसल, बोगनविली द्वीपों पर रहने वाले श्वेत थे और उपनिवेश के नियंत्रण में रहने के कारण पापुआ न्यू गिनी में अधिकतर लोग अश्वेत थे।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध

बोगनविली प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। विशेष रूप से तांबा, जिसे 1960 में ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर निकाला गया।

देश बनने के बाद ऐसा होगा

देश बनने के बाद बोगनविली का भूमि क्षेत्रफल दस हजार वर्ग किमी होगा, जो साइप्रस से थोड़ा बड़ा और लेबनान से थोड़ा छोटा होगा। इसी तरह, इसकी गिनती दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में होगी यानी वानुतू से थोड़ी छोटी, और बारबाडोस से थोड़ी बड़ी।

शांति समझौता

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों की मदद से 1997 में लड़ाई समाप्त हो गई। बोगनविली पीस एग्रीमेंट, 2005 के तहत स्वायत्त बोगनविली सरकार का निर्माण, और स्वतंत्रता पर एक गैर-बाध्यकारी जनमत संग्रह कराने का वादा किया गया।

कई देशों की नजरें

23 नवंबर को होने वाले जनमत संग्रह पर कई देशों की निगाहें टिकी हैं। ऑस्ट्रेलिया बोगनविली का सबसे बड़ा दानदाता है और मध्यस्थता में शामिल था जिसने लड़ाई को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि वह समझौते को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन ज्यादातर बोगनविलियन मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्रता का विरोध करता है। अमेरिका और चीन भी घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन ने पहले से ही एक प्रतिनिधिमंडल भेज रखा है, जो एक नए बंदरगाह निर्माण सहित बोगनविली में निवेश करने को तैयार है।

एक्शन में सरकार

शांत रहा महानगर, 30 हजार छात्रों वाले विश्वविद्यालय में पसरा रहा सन्नाटा, बमुश्किल बचे हैं 100 छात्र

हांगकांग में 12 साल के आंदोलनकारी को कोर्ट देगी दंड !

हांगकांग, एजेंसियां : हांगकांग की अदालत ने लोकतंत्र की मांग वाले हिंसक आंदोलन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार हुए 12 साल के बालक को दोषी ठहरा दिया है। इस बालक को तीन साल हिरासत में रखकर काउंसलिंग देने की सजा सुनाई जा सकती है। यह बालक पुलिस द्वारा छह महीने के आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला और दंडित किया जाने वाला सबसे कमउम्र आंदोलनकारी होगा। पुलिस के सख्त रुख के चलते गुरुवार को भी हांगकांग में शांति रही।

आंदोलनकारियों के गढ़ रहे हांगकांग पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय में सन्नाटा छाया रहा। 30 हजार छात्रों वाले इस विश्वविद्यालय में बमुश्किल 100 छात्र बचे हैं। एक हजार से ज्यादा छात्र पुलिस ने रविवार रात से यहां जारी कार्रवाई में गिरफ्तार किए हैं। ज्यादातर आंदोलनकारी छात्र यहां से विभिन्न रास्तों से निकल भागे। भागने का एक जरिया सीवर पाइपलाइन भी थी। पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय में पुलिस को बड़ी संख्या में पेट्रोल बम मिले हैं, जो छात्रों ने पुलिस से मुकाबले के लिए बनाए थे। इसके अतिरिक्त ज्यादातर क्लास रूम बर्बाद कर दिए गए हैं लेकिन पुस्तकालय की सभी पुस्तकें सुरक्षित हैं। बिजली और पानी की पाइपलाइनों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। पुलिस को तलाशी में वो फेस मास्क और काले छाते नहीं मिले हैं, जिन्हें लेकर छात्र आंदोलन किया करते थे। माना जा रहा है कि छात्रों ने इन्हें कहीं छिपा दिया है। मीडिया से बातचीत में आंदोलनकारियों ने पुलिस के आगे समर्पण की संभावना को नकार दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे फिर एकजुट होंगे और लोकतंत्र के लिए फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। विश्वविद्यालय की दीवारों पर लिखा हुआ है- हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है...हमारी व्यवस्था (सिस्टम) में कोई हिस्सेदारी नहीं है...। जाहिर है छात्र सब कुछ गंवाकर भी कुछ पाना चाहते हैं।

हांगकांग में गुरुवार को पॉलिटिक्निक यूनिवर्सिटी से घायल प्रदर्शनकारी छात्र को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते सुरक्षाकर्मी। एपी

चीन ने नए कानून पर अमेरिका को चेताया

चीन ने हांगकांग पर अमेरिकी संसद में पारित प्रस्ताव को कानून बनने से रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वीटो लगाने की मांग की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने कहा कि हांगकांग की स्थिति की वार्षिक समीक्षा का कानून बनने का दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर गंभीर असर पड़ेगा। पारित प्रस्ताव के अनुसार हांगकांग को विशेष कारोबारी क्षेत्र के दर्जे की मान्यता को जारी रखने के लिए अमेरिका प्रति वर्ष वहां पर मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करेगा। वहां पर मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले हांगकांग और चीन के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश पर पकड़े गए पांच भारतीय

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे पांच भारतीयों को हिरासत में लिया गया है। इसी तरह के मामलों में पकड़े गए 145 भारतीयों को हाल में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

अमेरिका के सीमा गश्ती अधिकारियों ने गत 15 नवंबर को भारत से आए पांच लोगों और एक संदिग्ध तस्कर को न्यूयॉर्क में पकड़ा था। अधिकारियों के अनुसार, इन भारतीयों को लेकर जा रहा वाहन न्यूयॉर्क के मौरिसटाउन के पास की जांच चौकी से बचकर निकल गया था। इस वाहन का ड्राइवर अमेरिकी नागरिक था। सीमा गश्ती विभाग के अधिकारियों ने आग्डेंस्बर्ग में इस वाहन को एक पार्किंग में खोज निकाला और सभी को हिरासत में ले लिया। भारत से आए पांचों लोगों के पास कोई आव्रजन दस्तावेज नहीं था। सभी को पकड़कर आस्डेंस्बर्ग बॉर्डर पेट्रोल स्टेशन के हवाले कर दिया गया है।

ट्रंप ने अपना रखा है सख्त रवैया : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने वालों को लेकर सख्त रवैया अपना रखा है। उन्होंने यह वादा किया है कि अवैध आव्रजन रोकने के लिए सीमा पर दो साल में दीवार खड़ी कर दी जाएगी।

- हाल में 145 भारतीयों को अमेरिका से किया गया था प्रत्यर्पित
- 15 नवंबर को पांच भारतीय लोगों और एक संदिग्ध तस्कर को पकड़ा गया था

2018 में पकड़े गए थे नौ हजार भारतीय

सीमा गश्ती बल ने साल 2018 में दक्षिण-पश्चिम सीमा से अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने के प्रयास में 113 देशों के नागरिकों को पकड़ा था। इनमें नौ हजार से ज्यादा भारतीय नागरिक भी थे। यह आंकड़ा वर्ष 2017 की तुलना में बहुत ज्यादा था। 2017 में करीब 3100 भारतीय पकड़े गए थे।

कुछ इस तरह बनाई जाती है गुलाबी गेंद • जागरण

गुलाबी गेंद से ही डे-नाइट टेस्ट क्यों

आज भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुलाबी गेंद का पदार्पण होगा। सबके मन में सवाल होगा कि जब डे-नाइट वनडे और टी-20 मुकाबले में सफेद गेंद का इस्तेमाल होता है तो फिर डे-नाइट टेस्ट में ऐसा क्यों नहीं होता है। हम आपको बताते हैं क्यों डे-नाइट में गुलाबी गेंद का इस्तेमाल क्यों होता है और क्यों ये लाल और सफेद गेंद से अलग है-

टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली लाल गेंद रात में दूधिया रोशनी में अच्छे से दिखाई नहीं देती। सफेद गेंद का सीमित ओवरों के डे-नाइट क्रिकेट में प्रयोग करते हैं, लेकिन डे-नाइट टेस्ट में उसका प्रयोग नहीं करते

वनडे-टी-20 में खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहनते हैं इसलिए सफेद गेंद का इस्तेमाल होता है। टेस्ट में सफेद कपड़े पहनते हैं खिलाड़ी। ऐसे में अगर सफेद गेंद का इस्तेमाल होगा तो वह दिखाई नहीं देगी इसलिए गुलाबी गेंद का इस्तेमाल होता है

इसको लेकर काफी शोध किए गए। नारंगी और पीले रंग की गेंद भी इस्तेमाल करके देखी गई, लेकिन निष्कर्ष निकला कि जब सफेद ड्रेस में रात में खेलेंगे तो गुलाबी गेंद ज्यादा बेहतर होगी

ज्यादा स्विंग क्यों

- >> ग्लॉस फिनिश और प्लास्टिक कोट होने के कारण गुलाबी गेंद ज्यादा चमकीली होती है और लाल गेंद से ज्यादा स्विंग करती है
- >> इस कारण यह गेंद देर से पुरानी होगी और लाल गेंद की तरह इसे एक तरफ से पुराना करके रिवर्स स्विंग हासिल करने में परेशानी होती है। यह 50-60 ओवर के पहले रिवर्स स्विंग नहीं करेगी
- >> गुलाबी रंग चढ़ाने के कारण गेंद को अतिरिक्त चमक देनी पड़ती है। एसजी की गेंद पर एक रंग की अतिरिक्त एक परत चढ़ाई जाती है। इस कारण भी यह लाल गेंद की अपेक्षा काफी सख्त होती है
- >> तेज गेंदबाज हवा से मिल रही मदद से बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। स्विंग करने वाले गेंदबाजों को मदद करती है
- >> डे-नाइट टेस्ट मैच के दौरान बल्लेबाज अगर बल्ले और पैड के बीच जगह छोड़ेंगे तो उन्हें मुश्किल का सामना करना होगा
- >> डे-नाइट टेस्ट मैच में अभी तक अंगुली के स्पिनरों से जयादा कलाई के स्पिनर सफल रहे हैं

चलो गुलाबी हो जाएं...

- भारत और बांग्लादेश के बीच डे-नाइट टेस्ट मैच आज से
- 11 डे-नाइट टेस्ट में से नौ जीते हैं मेजबान टीमों ने

अभिषेक त्रिपाठी • कोलकाता

तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे...

कैसर-उल जाफरी का यह शेर कोलकातावासियों पर मुफीद बैठता है, क्योंकि रबींद्रनाथ टैगोर का शहर इस समय गुलाबी खुमार में है। 1943 में बना हावड़ा ब्रिज 2019 में गुलाबी होकर भारत और बांग्लादेश के बीच शुक्रवार को ईडन गार्डेंस में होने वाले पहले डे-नाइट टेस्ट मैच का गवाह बनने को तैयार है। यह ब्रिज जब बना था तो बांग्लादेश, भारत का ही हिस्सा था। जब यह दोनों टीमें पहली बार गुलाबी गेंद से डे-नाइट टेस्ट मैच खेलेंगी तो रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे राष्ट्रगान जन गण मन... और अमार सोनार बांग्ला... गाएंगी। कुल मिलाकर अगले तीन-चार दिन (टेस्ट मैच तीन-चार दिन ही चलने की संभावना) भारत और बांग्लादेश ही नहीं, वैश्विक क्रिकेट के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये टेस्ट मैच की दशा और दिशा तय करेंगे।

गुलाबी गेंद बनाम भारतीय टीम: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में भले ही गुलाबी गेंद से होने वाले डे-नाइट टेस्ट के भविष्य पर ज्यादा खुशी नहीं जताई हो, लेकिन सौरव गांगुली के नेतृत्व वाला बीसीसीआइ और क्रिकेट की शीर्ष संस्था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ज्यादा से ज्यादा डे-नाइट टेस्ट मैच कराकर इस खेल के सबसे पुराने प्रारूप को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर इस मैच की बात करें तो बांग्लादेश टीम काफी कमजोर है और यह मुकाबला भारत बनाम बांग्लादेश की जगह टीम इंडिया बनाम गुलाबी गेंद नजर आ रहा है।

भारत का भी टेस्ट: 2016 से अभी तक 11 डे-नाइट टेस्ट हुए हैं और उसमें नौ मेजबान टीम ने जीते हैं। दो मैचों की सीरीज का पहला मैच इंदौर में पारी और 130 रनों से जीत चुकी भारतीय टीम का पलड़ा यहां भी भारी है और ऐसा लग रहा है कि वह आसानी से डे-नाइट टेस्ट के मेजबान की झोली में जाने के रिकॉर्ड को ही बरकरार रखेगी। हालांकि, यह भारतीय टीम खासकर उसके बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्यास्त के समय भारतीय टीम के बल्लेबाजों को गुलाबी गेंद से खेलने में दिक्कत आ रही है और यह उनकी सबसे बड़ी समस्या है। बुधवार को जब अभ्यास सत्र में विराट सूर्यास्त के समय दूधिया रोशनी में बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्हें गुलाबी गेंद को समझने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि, गुरुवार को सुबह अभ्यास करते समय हालांकि विराट पहले से बेहतर नजर आए। दूसरे दिन शमी अभ्यास के लिए नहीं आए थे और विराट ने इशांत शर्मा और थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट के खिलाफ काफी देर तक अभ्यास किया। दिन के समय बाकी भारतीय बल्लेबाज भी गुलाबी गेंद को आसानी से समझ ले रहे थे।

पहले दिन लगेगा मेला: भारतीय टीम घरेलू टेस्ट सीरीज में लगातार 12वीं जीत की तैयारी में है। हालांकि, इस बीच बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने इस मैच को दर्शकों के लिए एक मेले की तरह बनाने के पूरे प्रबंध किए हैं। गुलाबी गेंद, शुभंकर, मैच में गेंद देने के लिए सेना के पैराट्रूपर, जानी-मानी खेल और राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति से इस मेले को सजाया जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घंटा बजाकर मैच चालू करने की घोषणा करेंगी।

कुलदीप या अश्विन: भारतीय तेज गेंदबाजों की तिकड़ी मुहम्मद शमी, इशांत शर्मा और उमेश यादव ने पिछले मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया था और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, शमी ने गुरुवार को अभ्यास नहीं किया। इसके अलावा ओपनर रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल भी शानदार फॉर्म में हैं। तेज गेंदबाजों ने इंदौर में 14 विकेट लिए और उनके लिए ईडन में उस प्रदर्शन को दोहराना मुश्किल नहीं होगा। मयंक, रोहित और कुलदीप को गुलाबी गेंद से दलीप ट्रॉफी मुकाबला खेलने का अनुभव भी है। गुरुवार को कुलदीप ने गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी का भी अभ्यास किया, जबकि अश्विन ने कुछ खास नहीं किया। गुलाबी गेंद से कुलदीप के खिलाफ खेलना मुश्किल होगा। ऐसे में कुलदीप को इस टेस्ट मैच में खिलाने का चांस है। गुलाबी गेंद से कलाई के स्पिनर ज्यादा घातक साबित होते रहे हैं। वहीं, रवींद्र जडेजा ने अभी तक गेंद के साथ बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में टीम प्रबंधन स्पिन विभाग में जडेजा और कुलदीप के संयोजन के साथ उतर सकता है।

बांग्लादेश टीम कमजोर: बांग्लादेश की टीम बेहद कमजोर है और ऐसे में वह अपने पहले डे-नाइट टेस्ट में कितने समय तक खुद को बचाकर रख पाएगी यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इंदौर में बांग्लादेश की बल्लेबाजी लचर साबित हुई थी। सिर्फ मुशफिकुर रहीम ही 50 से अधिक रन बना सके थे। शाकिब अल हसन के निलंबन के बाद कप्तानी संभाल रहे मोमिनुल हक दबाव का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मोमिनुल ने बांग्लादेश के बाहर एक भी टेस्ट शतक नहीं लगाया है। ऐसे में उनको रन बनाकर अपनी टीम का नेतृत्व करना होगा। बांग्लादेशी टीम ने इंदौर में सामान्य परिस्थितियों में जैसे लाल गेंद से भारतीय गेंदबाजों का सामना किया उससे तो लगता है कि गुलाबी गेंद से उनके लिए वही काम करना और भी दुरूह हो जाएगा। उसके दोनों ओपनर इंदौर में औसतन प्रत्येक पारी में छह रन से ज्यादा नहीं बना पाए। बांग्लादेश टीम तैजुल इस्लाम और इबादत हुसैन की जगह मुस्तफिजुर रहमान और अल अमीन हुसैन को खिला सकती है।

<< अभ्यास सत्र के दौरान गेंद पकड़ने की कोशिश करते भारतीय कप्तान विराट कोहली • एएनआइ

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, रिषभ पंत, मुहम्मद शमी, इशांत शर्मा, उमेश यादव, हनुमा विहारी, कुलदीप यादव और शुभमन गिल।

बांग्लादेश: मोमिनुल हक (कप्तान), लिटन दास, मेंहदी हसन, नईम हसन, अल अमीन हुसैन, इबादत हुसैन, मुसद्दक हुसैन, शादमान इस्लाम, तैजुल इस्लाम, अबू जाएद, इमरूल काएस, महमूदुल्लाह, मुहम्मद मिथुन, मुशिफकुर रहीम, मुस्तफिजुर रहमान।

पिच का मुआयना करते बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल व कोच डोमिंगो • प्रेट्र

पिच रिपोर्ट

शायद पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि पिच से ज्यादा गेंद की चर्चा हो रही है। जहां तक पिच की बात है तो उसमें करीब छह मिमी घास छोड़ी जाएगी और आउटफील्ड भी पूरी तरह हरी है। अमूमन भारत में पिच पर घास होती ही नहीं है, लेकिन गुलाबी गेंद के कारण ऐसा किया जा रहा है, जिससे वह जल्दी पुरानी और गंदी ना हो। सीम गेंदबाज इस पर कमाल करेंगे और उन्हें खेलना आसान नहीं होगा।

कोलकाता की गुलाबी नजर आ रही एक इमारत पर सौरव गांगुली का प्रदर्शित फोटो • प्रेट्र

मौसम रिपोर्ट

कोलकाता में इस समय सुहाना मौसम है। दोपहर में हल्की धूप है और शाम चार बजे से ठंडक बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी के साथ सूरज अस्त होने लगता है। अगले पांच दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सूर्यास्त के समय विकेटों का ढेर लगेगा।

हमें गुलाबी गेंद से अभ्यास मैच का मौका नहीं मिला और जब यह तय हुआ तो हमारे पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था। हम सिर्फ इसके लिए मानसिक तौर पर ही तैयार हो सकते थे। लेकिन, हां अगर आप गुलाबी गेंद से टेस्ट खेल रहे हो तो अभ्यास मैच जरूर होना चाहिए।
मोमिनुल हक, कप्तान बांग्लादेशी टीम

सबसे बड़ी चीज यही है कि डे-नाइट टेस्ट से स्टेडियम तक दर्शक पहुंचेंगे, यही टेस्ट क्रिकेट में नई चीज है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि कितनी ओस मैदान पर है और क्रिकेट के स्तर के साथ समझौता तो नहीं किया जा रहा है।
सचिन तेंदुलकर, पूर्व भारतीय कप्तान

लाल गेंद से क्रिकेट खेलने और गुलाबी गेंद से क्रिकेट खेलने में बड़ा अंतर है। समय के हिसाब से ही खिलाड़ियों को मैदान पर संतुलन बैठाना मुश्किल होगा। वहीं गुलाबी गेंद पर भारी परत होती है, जिससे स्पिनरों को काफी परेशानी होगी।
वीवीएस लक्ष्मण, पूर्व भारतीय बल्लेबाज

सौरव गांगुली से पहले एक और भारतीय कप्तान थे जिन्होंने यह पद संभाला था, वह थे एसजी (सुनील गावस्कर), जिन्होंने ढाई महीने तक यह पद संभाला। अब गांगुली के पास 10 महीने हैं और मुझे उम्मीद है कि वह गुना ज्यादा सफल होंगे। उम्मीद है यह एसजी (सौरव गांगुली) उस एसजी (सुनील गावस्कर) से ज्यादा सफल रहेंगे।
सुनील गावस्कर, पूर्व भारतीय कप्तान

लाल गेंद क्रिकेट में तेज गेंदबाजों का सुबह जल्दी इस्तेमाल होता है, लेकिन डे-नाइट टेस्ट में तेज गेंदबाजों का दूधिया रोशनी में इस्तेमाल होना चाहिए। तब तेज गेंदबाज ज्यादा प्रभावी नजर आएंगे।
गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय बल्लेबाज

27 नवंबर से एक दिसंबर 2015 के बीच पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेला गया। यह मुकाबला एडिलेड ओवल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया था

03 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने इस करीबी मुकाबले को जीता था। यह एक लो-स्कोरिंग मैच था, जिसमें तेज गेंदबाजों का दबदबा देखा गया। खास तौर पर सूरज ढलने के बाद तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिली, लेकिन तीन दिन तक चले इस टेस्ट मैच में आए दर्शकों की संख्या को देखकर अंदाजा हुआ कि यह आइडिया काम कर सकता है

11 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले गए हैं अभी तक। सभी मैचों के नतीजे निकले हैं। इसमें से नौ मैच मेजबानों ने जीते हैं। 2017 में दुबई में पाकिस्तान अपनी घरेलू सीरीज में श्रीलंका से और 2018 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज की टीम श्रीलंका से हारी थी

08 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, जिंबाब्वे अब तक डे-नाइट टेस्ट खेल चुके हैं

03 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले गए हैं एडिलेड ओवल पर। सबसे ज्यादा डे-नाइट टेस्ट इसी मैदान पर हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल चार डे-नाइट टेस्ट हुए हैं। इसमें एक मैच ब्रिसबेन में हुआ

05 वर्षों में बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों का औसत और स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा है और यह मैच तेज गेंदबाजों का ही होगा। यह बांग्लादेश के लिए खराब खबर है

2018 दिसंबर में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद मयंक अग्रवाल 858 रन बना चुके हैं। उन्होंने 2016 में ग्रेटर नोएडा में गुलाबी गेंद से हुए दलीप ट्रॉफी के मैच में भी शानदार शतक लगाया था

01 शिकार दूर हैं भारतीय विकेटकीपररिद्धिमान साहा टेस्ट क्रिकेट में 100 शिकार पूरे करने से। उनके नाम 88 कैच व 11 स्टंप हैं

पहले दिन के कार्यक्रम

- **दोपहर 12 : 15 बजे :** बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ईडन गार्डेंस स्टेडियम के क्लब हाउस में आगमन। बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली व बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन उनकी अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राउंड में जाएंगी और वहां कतारबद्ध दोनों टीमों के कप्तान अपने खिलाड़ियों से उनका परिचय कराएंगे।
- **दोपहर 12 : 28 बजे :** शेख हसीना व ममता ईडन के क्लब हाउस में स्थित हॉस्पिटलिटी बॉक्स में पहुंचेंगी।
- **दोपहर 12 : 30 बजे :** टॉस होगा।
- **दोपहर 12 : 53 बजे :** शेख हसीना और ममता बनर्जी ईडन गार्डेंस के क्लब हाउस के पास लगा घंटा बजाकर मैच की शुरुआत करेंगी।
- **दोपहर 12 : 54 बजे :** दोनों टीमें ग्राउंड पर अपने-अपने राष्ट्रगान के लिए खड़ी होंगी।
- **दोपहर 1: 00 बजे :** मैच शुरू होगा और पहला सत्र दोहपर तीन बजे तक चलेगा।
- **दोपहर 3 : 10 बजे :** भोजनकाल के 40 मिनट के ब्रेक के दौरान सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले और वीवीएस लक्ष्मण को लेकर टॉक शो।
- **दोपहर 3 : 40 बजे** से शाम 5 :40 बजे तक : दूसरा सत्र।
- **शाम 5 : 43 बजे :** चायकाल के ब्रेक के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान व अन्य खेलों के मशहूर खिलाड़ी गोल्फ कार्ट में बैठकर स्टेडियम का चक्कर लगाएंगे। बंगाल के राज्यपाल भी गोल्फ कार्ट में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वाद्य यंत्र कार्यक्रम की प्रस्तुति।
- **शाम 6 : 00 से रात 8 :00 बजे तक :** अंतिम सत्र का खेल।
- **रात 8 : 10 बजे :** बांग्लादेशी गायिका रूना लैला परफॉर्म करेंगी। 250 डांसर परफॉर्म करेंगे।
- **रात 8 : 25 बजे :** भारत व बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मौजूदा खिलाड़ियों व पूर्व भारतीय कप्तानों व अन्य खेलों से जुड़े खिलाड़ियों का शेख हसीना व ममता बनर्जी के हाथों सम्मान।
- **रात 9 : 15 बजे :** संगीतकार जीत गांगुली की ओर से संक्षिप्त संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति।

इंग्लैंड की मजबूत शुरुआत

माउंट माउंगानुई, एएफपी : इंग्लैंड ने यहां बे ओवल मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को अपनी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने के समय बेन स्टोक्स 114 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 67 और ओली पोप 23 गेंदों पर चार चौकों की बदौलत 18 रन बनाए नाबाद लौटे।

दोनों बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट के लिए अब तक 38 रनों की साझेदारी हो चुकी है। न्यूजीलैंड की ओर से कोलिन डि ग्रैंडहोम ने दो और नील वेगनर तथा टिम साउदी को अब तक एक-एक विकेट मिले हैं।

इससे पहले, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मेहमान टीम को पहला झटका 52 के स्कोर पर अपना पदार्पण मैच खेल रहे डॉम सिब्ले (22) के रूप में लगा। इसके बाद जो डेनली (74) और रोरी बर्न्स (52) ने दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की। डेनले ने इसके बाद स्टोक्स के साथ भी चौथे विकेट के लिए 83 रन जोड़े। बर्न्स ने 138 गेंदों पर छह चौके, डेनले ने 181 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्का जबकि सिब्ले ने 63 गेंदों पर चार चौके लगाए।

मैच के दौरान शॉट खेलते जो डेनली। एपी

अनुभव एशिया में गुलाबी गेंद से खेले गए पहले मैच में अंपायर रहे प्रेमदीप चटर्जी से खास बातचीत

अंपायरों के लिए भी चुनौतियां पेश करेगी गुलाबी गेंद

विशाल श्रेष्ठ • कोलकाता

गुलाबी गेंद बल्लेबाज व गेंदबाज ही नहीं, मैदानी अंपायरों के लिए भी नई चुनौतियां पेश करेगी। एशिया में गुलाबी गेंद से खेले गए पहले मैच में मैदानी अंपायर रहे प्रेमदीप चटर्जी ने खास बातचीत में यह बात कही।

बीसीसीआइ के वरिष्ठ अंपायरों में शुमार प्रेमदीप ने कहा, 'ईडन में भारत-बांग्लादेश के बीच भारत के पहले डे-नाइट टेस्ट मैच के दौरान मैदानी अंपायरों को हर पल बेहद सजग रहना होगा। हरेक गेंद पर खास नजर रखनी होगी। उन्हें मैच के दौरान शायद ही चैन की सांस लेना का पल मिले।'

अब तक तीन गुलाबी गेंद वाले मैचों में अंपायरिंग कर चुके प्रेमदीप ने पहले मैच का अनुभव साझा करते हुए कहा, 'एशिया के पहले गुलाबी गेंद वाले मैच का आयोजन ईडन में 18 से 21 जून, 2016 तक हुआ था। चार दिवसीय वह मैच कोलकाता सुपर लीग का फाइनल था, जो मोहनबगान और भवानीपुर के बीच था। उस मैच में मेरे साथी मैदानी अंपायर अभिजीत भट्टाचार्य थे। मोहनबगान ने खिताबी मैच जीता था। विजयी टीम की ओर से मुहम्मद शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए एक पारी में पांच विकेट चटकाए थे, वहीं अरिंदम घोष ने गुलाबी गेंद से एशिया में पहला शतक लगाया था।

बीसीसीआइ की छत्रछाया में हुए करीब 500 मैचों में अंपायरिंग कर चुके प्रेमदीप ने आगे कहा, 'चूंकि एशिया में पहली बार गुलाबी गेंद से कोई मैच होने जा रहा था, इसलिए सबके मन में यही सवाल था कि गुलाबी गेंद कैसा बर्ताव करेगी। वह बल्लेबाजों व गेंदबाजों के लिए कितनी आसान या मुश्किल होगी। बतौर मैदानी अंपायर, मेरे मन में भी कई सवाल उमड़ रहे थे, इसलिए उस मैच से पहले मुझे भी काफी तैयारियां करनी पड़ी थी। मैंने गुलाबी गेंद से उस समय तक हुए सारे अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैचों का गहराई से अध्ययन किया था।' 50 वर्षीय प्रेमदीप ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई कूकाबुरा गेंद से वह मैच खेला गया था। मैच जब शुरू हुआ तो मैंने देखा कि गेंद काफी स्विंग कर रही थी। शाम ढलने के वक्त जब फ्लड लाइट की दूधिया रोशनी फैल रही थी, तब स्पिनरों को गेंद से मदद नहीं मिल रही थी। कुछ देर में ओस भी गिरनी शुरू हो गई, जिससे गेंदबाजों की परेशानी बढ़ गई थी।' हालांकि, प्रेमदीप मानते हैं कि कोलकाता टेस्ट में गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों को उस तरह की समस्या नहीं होगी क्योंकि मैच कूकाबुरा नहीं, बल्कि एसजी गेंद से खेला जाएगा। उन्होंने कहा, 'कूकाबुरा का सीम गेंद के साथ लगा रहता रहता है, जबकि एसजी गेंद का सीम गेंद पर उभरा रहता है, यही कारण है कि भारतीय स्पिनर एसजी गेंद से गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसे ग्रिप करने में आसानी होती है।'

प्रेमदीप चटर्जी • जागरण

घातक साबित होगी ऑर्मर गेंद: प्रेमदीप का अनुमान है कि 'आर्मर' गेंद बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हो सकती है। यह गेंद टप्पा खाने के बाद स्किड करके इतनी तेजी से अंदर आएगी कि बल्लेबाजों के लिए उसे खेलना काफी मुश्किल हो जाएगा। रवींद्र जडेजा इस तरह की गेंद डालने में माहिर हैं, इसलिए वह बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं, मध्यम गति के गेंदबाजों को ज्यादा प्रयोग न करके लाइन व लेंथ पर ध्यान देना चाहिए।

बल्लेबाजों को हर वक्त रहना होगा सतर्क: 2006 से बीसीसीआइ के अंपायरों के पैनल में शामिल प्रेमदीप ने कहा, 'बल्लेबाजों को मैच के दौरान हर वक्त सजग रहना होगा। आमतौर पर दिन में होने वाले टेस्ट मैचों के पहले घंटे का खेल हो जाने के बाद बल्लेबाज थोड़े सहज हो जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि शाम ढलने के बाद गेंद का मूवमेंट अचानक बढ़ सकता है। स्लिप के क्षेत्ररक्षकों के लिए भी कैच पकड़ना आसान नहीं होगा। लाल व सफेद गेंद की तुलना में गुलाबी गेंद की रंगत बरकरार रखने के लिए उसकी डबल कोटिंग की जाती है, इसलिए वह ज्यादा चिकनी होती है और फिसलती है।' बंगाल के शांतिनिकेतन के रहने वाले प्रेमदीप ने कहा, 'मुझे यकीन है कि यह मैच टेस्ट क्रिकेट में नई क्रांति लाएगा। टेस्ट क्रिकेट का आयाम ही बदलकर रखा देखा। टेस्ट मैच देखने के प्रति लोगों का नजरिया बदल जाएगा।'

ईडन देता है प्यार

मोहिंदर अमरनाथ

रिवर्स स्वीप

ईडन गार्डेंस में गुलाबी गेंद से टेस्ट ने जबरदस्त तमाशे का वादा किया गया है, इससे टेस्ट क्रिकेट दोबारा से जागृत हो सकता है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हूं कि ईडन गार्डेंस में सभी टिकट बिक चुकी हैं।

सच यही है कि जितना प्यार ईडन क्रिकेट को देता है, उतना कोई और मेजबान स्टेडियम नहीं देता है और जिस तरह की जिज्ञासा गुलाबी गेंद को लेकर है, इससे साफ है कि प्रशंसक मैदान तक पहुंचेंगे। यह चौकाने वाला था कि भारतीय सेट-अप ने डे-नाइट टेस्ट मैचों के आयोजन का विरोध किया था और इसके लिए सौरव गांगुली बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बीसीसीआइ अध्यक्ष पद के अपने छोटे से कार्यकाल में इसको करके दिखाया। यह अंतर रखता है जब आप बीसीसीआइ अध्यक्ष हों और भारत के लिए ऊंचे स्तर तक टेस्ट क्रिकेट खेले हों। यह गांगुली के लिए भी एक खास पल है क्योंकि यह आयोजन उनके शहर में हो रहा है। डे-नाइट टेस्ट के परिणाम को देखते हुए और ओस के महत्व को देखते हुए मुझे लगता है कि बल्लेबाज गुलाबी गेंद क्रिकेट में ढलने के लिए कुछ समय लेंगे। यह नवंबर है और मुझे नहीं लगता कि ओस इस टेस्ट में कोई फैक्टर होगा। साथ ही परिस्थितियां दोनों ही टीम के लिए बराबर होंगी। भारत ही बांग्लादेश के खिलाफ यह टेस्ट जीतने का दावेदार है, खासकर जिस तरह से बांग्लादेश ने इंदौर में तीन दिन के अंदर घुटने टेक दिए थे। मौजूदा समय में दो फैक्टर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के दिमाग में चल रहे हैं। पहला उनका टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा सीमित ओवर क्रिकेट में ध्यान देना और दूसरा उनके वरिष्ठ खिलाड़ियों की टीम में गैरमौजूदगी। इसी के साथ भारतीय तेज गेंदबाज तिकड़ी इशांत शर्मा, उमेश यादव और मुहम्मद शमी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।

#WhatDrivesYou
EXIDE

दिल्ली ने महाराष्ट्र को 77 रन से हराया

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी

सूरत, प्रेट्र : सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की खराब फॉर्म जारी रही, लेकिन दिल्ली ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी-20 टूर्नामेंट के अपने पहले सुपर लीग मैच महाराष्ट्र को 77 रन से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में महाराष्ट्र की टीम 17.2 ओवर में 90 रन पर आउट हो गई। काम चलाऊ ऑफ स्पिनर नीतिश राणा ने 17 रन देकर चार विकेट लिए।

धवन 22 गेंद में 24 रन ही बना सके। उन्होंने शुरूआत अच्छी की और हितेन दलाल के साथ 44 रन की साझेदारी की, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके। क्षेत्ररक्षण के समय उन्हें बायें घुटने में चोट भी लगी और उन्हें चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। बाद में उन्होंने पट्टी लगे बायें घुटने की तस्वीर ट्विटर पर भी डाली। ऑफ ब्रेक गेंदबाज शमशुजामा काजी ने सातवें ओवर में उनका विकेट चटकाया। दिल्ली का स्कोर दो विकेट पर 44 रन हो गया। तीसरे नंबर पर आए अनुज रावत (10) भी सस्ते में आउट हो गए, लेकिन कप्तान ध्रुव शौरी ने 37 गेंद में नाबाद 48 रन बनाए। राणा ने 21 और हिम्मत सिंह ने 32 रन बनाए। महाराष्ट्र के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। युवा बल्लेबाज रितुराज (42) को छोड़कर महाराष्ट्र का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका।

हैरिस शील्ड मैच में सारे बल्लेबाज जीरो पर आउट

मुंबई, प्रेट्र : एक अभूतपूर्व क्रिकेट मैच में अंडर-16 हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में एक टीम का कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना सका और उसे 754 रन से हार को विवश होना पड़ा।

स्वामी विवेकानंद स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल के बीच यह मैच खेला गया था। चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल का कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना सका। सारे बल्लेबाज शून्य पर आउट हो गए, हालांकि टीम ने अतिरिक्त के सात रन बनाए। इसमें एक बाई और छह वाइड थे। बोरिवली के स्वामी विवेकानंद स्कूल ने 45 ओवर में चार विकेट पर 761 रन बनाए थे।

स्क्वॉश खिलाड़ी घोषाल क्वार्टर फाइनल में

सरे (इंग्लैंड) : भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी सौरव घोषाल इंग्लैंड के टॉम रिचर्ड्स को 11-3, 11-5, 11-5 से हराकर पीएसए विश्व टूर गोल्ड टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। घोषाल अच्छी लय में दिख रहे थे, उन्होंने दूसरे दौर में जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया। अब सातवीं वरीय भारतीय का सामना शीर्ष वरीय मुहम्मद एल शोरबागी से होगा। दोनों विश्व चैंपियनशिप में कुछ दिन पहले ही आमने-सामने हुए थे।

डे-नाइट टेस्ट आयोजित कराना पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की एक और बड़ी उपलब्धि है।
– दिलीप वेंगसरकर, पूर्व भारतीय कप्तान

न्यूज गैलरी

भारतीय गोल्फर चौरसिया ने की यूरोपीय टूर में वापसी

तारागोना (स्पेन) : भारतीय गोल्फर एसएसपी चौरसिया ने यहां ल्यूमिन गोल्फ क्लब के दो कोर्स में छह राउंड के 108 होल में खेली गई क्यू स्कूल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहते हुए गुरुवार को फिर यूरोपीय टूर कार्ड हासिल कर लिया। यूरोपीय टूर पर चार बार के विजेता चौरसिया 2020 में शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर के साथ इस टूर पर तीसरे भारतीय खिलाड़ी होंगे। शुभंकर को 2018 सत्र में दो जीत के कारण यूरोपीय टूर में खेलने का अधिकार मिला है, जबकि भुल्लर ने 2017 में इस टूर पर खिताब जीता था और वह 115वें स्थान के साथ कार्ड बरकरार रखने वाले अंतिम खिलाड़ी थे। शुभंकर रेस टू दुबई में 65वें जबकि चौरसिया 173वें स्थान पर रहे थे। चौरसिया ने छह दौर में 69, 66, 71, 67, 69 और 69 के स्कोर से कुल 17 अंडर 411 के स्कोर से चौथा स्थान हासिल किया। (प्रेट्र)

गोल्फर राशिद खान भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ

कोटा किनाबालू (मलेशिया) : गोल्फर राशिद खान ने गुरुवार को सबाह मास्टर्स के पहले दौर में चार अंडर 67 का कार्ड खेला, जिससे वह भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ संयुक्त पांचवें स्थान पर चल रहे हैं। तीन अन्य भारतीयों अमन राज, उदयन माने और खलिन जोशी ने तीन अंडर 68 का कार्ड खेला, जिससे शुरुआती दिन वे शीर्ष 10 में बने हुए हैं। थाइलैंड के युवा प्रतिभाशाली गोल्फर फचारा खोंगवाटमाई सहित चार खिलाड़ी पांच अंडर पार 66 के कार्ड से बढ़त बनाए हैं। अन्य भारतीयों में ज्योति रंधावा संयुक्त 22वें, आदिल बेदी संयुक्त 32वें, करणदीप कोचर संयुक्त 44वें, अभिजीत और हिम्मत सिंह संयुक्त 60वें, प्रियांशु सिंह संयुक्त 87वें, जीव मिल्खा सिंह संयुक्त 100वें और लक्ष्य मुदगिल संयुक्त 122वें स्थान पर बने हुए हैं। (प्रेट्र)

कोरिया मास्टर्स से श्रीकांत और समीर बाहर

ग्वांग्जू (कोरिया) : किदांबी श्रीकांत और समीर वर्मा के गुरुवार को पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में सीधे गेम में हारने से कोरिया मास्टर्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। छठे वरीय श्रीकांत बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट में जापान के दुनिया के 14वें नंबर के खिलाड़ी कांता सुनेयामा से 14-21, 19-21 से पराजय का मुंह देखना पड़ा। समीर ने हालांकि स्थानीय शटलर किम डोंगहुन (112वीं रैंकिंग) से 19-21, 12-21 से हारने से पहले 40 मिनट तक मशक्कत की। श्रीकांत बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में दुनिया के 11वें नंबर पर खिसक गए थे। (आइएएनएस)

भारतीय महिलाओं ने किया वेस्टइंडीज की टीम का 5-0 से सूपड़ा साफ

महिला क्रिकेट ▶ भारत ने 61 रनों से जीता पांचवां और आखिरी टी-20 मुकाबला

भारत के लिए वेदा कृष्णामूर्ति और रोड्रिग्ज ने खेली अर्धशतकीय पारियां

प्रोविडेंस, प्रेट्र : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पांचवां और आखिरी टी-20 मैच 61 रन से जीतकर वेस्टइंडीज को पांच मैचों की सीरीज में 5-0 से हरा दिया। भारत के लिए वेदा कृष्णामूर्ति ने नाबाद 57 और जेमिमाह रोड्रिग्ज ने 50 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 117 रन जोड़े और जीत में अहम भूमिका अदा की।

भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 134 रन बनाए। भारतीय महिला टीम के दो विकेट चौथे ओवर में 17 रन पर गिर गए थे। शेफाली वर्मा नौ और कप्तान स्मृति मंधाना सात रन बनाकर आउट हो गईं। फिर रोड्रिग्ज ने 56 गेंद में 50 रन बनाए, जबकि कृष्णामूर्ति ने 48 गेंदों की पारी में चार चौके लगाए। वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 73 रन ही बना सकी। उसके आधे बल्लेबाज 53 रन पर आउट हो गए थे। वेस्टइंडीज की ओपनर काइशोना नाइट शीमैन ने सर्वाधिक 22 रन का योगदान दिया, जबकि कैंपबेल 19 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारत के लिए अनुजा पाटिल ने तीन रन देकर दो विकेट लिए, जबकि राधा यादव, पूनम यादव, पूजा वस्त्राकर और हरलीन देओल को 1-1 विकेट मिला।

विजेता ट्रॉफी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम। ट्विटर

रोड्रिग्ज व राधा यादव टी-20 रैंकिंग में शीर्ष भारतीय

दुबई, प्रेट्र : भारत की जेमिमाह रोड्रिग्ज गुरुवार को ताजा जारी आइसीसी महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग की बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गईं जबकि स्पिनर राधा यादव गेंदबाजों में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। रोड्रिग्ज के अलावा वेस्टइंडीज पर 5-0 से क्लीन स्वीप करने में अहम भूमिका निभाने के बाद युवा शेफाली वर्मा ने भी रैंकिंग में प्रगति की है। रोड्रिग्ज तीन पायदान के फायदे से चौथे स्थान पर पहुंच गई, जबकि शेफाली को 57 पायदान का लाभ मिला, जिसे वह 30वें स्थान पर पहुंची। भारत ने आइसीसी महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल कर वेस्टइंडीज को पछाड़ दिया। वेदा कृष्णामूर्ति को भी रैंकिंग में फायदा मिला है जो 61वें से 49वें स्थान पर पहुंच गई।

छेत्री की जगह कोई नहीं ले सकता : इगोर स्टिमक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

▶ भारतीय फुटबॉल टीम के कोच ने कहा, 29 साल के खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं सुनील

भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमक को लगता है कि करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री 29 साल के खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं और अगले कुछ वर्षों तक उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।

हाल के वर्षों में 35 साल के छेत्री ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सितंबर में ओमान के खिलाफ मिली 1-2 की हार में भारत के लिए एकमात्र गोल करने के बाद वह 2022 फीफा विश्व कप क्वालीफाइंग अभियान के पिछले तीन मैचों में गोल नहीं कर सके। यह पूछने पर कि क्या भविष्य में छेत्री की जगह लेने के लिए उन्होंने भारत में कोई खिलाड़ी ढूंढ लिया है तो स्टिमक ने कहा, 'मैं नहीं जानता कि लोग सुनील की जगह लेने का जिक्र क्यों करते हैं। वह कहीं नहीं जा रहा। वह फिट है और शानदार कर रहा है। वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वह 29 साल के खिलाड़ी की तरह फिट है। जब तक वह ऐसे ही ट्रेनिंग कर रहा है और भारतीय टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है, वह हमारे साथ रहेगा। मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं।' उन्होंने कहा, 'उसके (सुनील) पास कुछ अच्छे मौके थे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी एक मौका था और सामान्य रूप से सुनील 10 में से नौ बार गोल करता है। लेकिन ऐसा उस दिन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके खेल में कुछ बदलाव हुआ है। यह फुटबॉल में होता है।'

हम निराश होकर स्वदेश लौटे : स्टिमक ने कहा कि वे पिछले कुछ मैचों में टीम के प्रदर्शन से निराश हैं और विश्व कप की दौड़ से टीम के बाहर होने का मुख्य कारण उन्होंने अहम खिलाड़ियों की चोट को बताया। उन्होंने कहा, 'पिछले दो मैचों के बाद हम कुछ निराश होकर स्वदेश लौटे हैं, लेकिन इससे इस पर हमारा भरोसा नहीं डिगा है कि हम क्या कर सकते हैं। विरोधी और मौसम को लेकर हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चोटों की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा थी। सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी संदेश झिंगन, रोवलिन बोर्गेस और अमरजीत सिंह की सेवाएं नहीं मिली और इसके बाद शुरुआती मैचों में प्रणय हलधर भी नहीं खेला। ओमान मैच के दौरान वह चोटिल भी हो गया, इन सभी का नतीजे पर असर पड़ा।' फीफा विश्व कप क्वालीफाइंग में भारतीय खिलाड़ियों के कम गोल दागने पर कोच ने कहा, 'क्या आप किसी भी क्लब के खिलाड़ी का नाम ले सकते हैं जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वह गोल दाग रहा है? आप यह उम्मीद क्यों कर रहे हो कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल करेंगे जबकि घरेलू लीग में भी हमारा कोई स्ट्राइकर गोल नहीं कर रहा। मैं रोज खिलाड़ियों के साथ काम नहीं करता। मैं सिर्फ मैच से पांच दिन पहले उनके साथ काम करता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम मौके बना रहे हैं।'

भारतीय टीम के कोच स्टिमक। फाइल फोटो

आइलीग का 13वां चरण लांच : आइलीग का 13वां चरण 30 नवंबर को आइजोल में राजीव गांधी स्टेडियम में पूर्व चैंपियन मोहन बागान एफसी और आइजोल एफसी के बीच मुकाबले के साथ शुरू होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) ने गुरुवार को आइलीग के 13वें चरण को लांच किया। इस सत्र में लीग में 11 टीमें शिरकत करेंगी जिसमें पिछले चरण की हीरो सेकेंड डिविजन की विजेता टीआरएयू एफसी को शामिल किया गया है। एआइएफएफ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा, 'हमें टीआरएयू एफसी का आइलीग के 13वें चरण में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है।' लीग की विजेता टीम को एक करोड़ रुपये का चेक मिलेगा जबकि उप विजेता टीम 60 लाख रुपये का पुरस्कार जीतेगी। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को क्रमशः 40 और 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस सत्र में भाग लेने वाली टीमें इस प्रकार हैं। चेन्नई सिटी एफसी, पंजाब एफसी, आइजोल एफसी, नेरोका एफसी, टीआरएयू एफसी, मोहन बागान और क्वेस ईस्ट बंगाल, गोकुलम केरला एफसी, चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा, इंडियन एरोज और रीयल कश्मीर एफसी।

मनु, इलावेनिल और दिव्यांश ने जीते निशानेबाजी में स्वर्ण

विश्व कप फाइनल

पुतियान, प्रेट्र : भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर के नाम गुरुवार को एक और बड़ी सफलता जुड़ गई। आइएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में हरियाणा की मनु ने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा इलावेनिल वेलारिवन और दिव्यांश पंवार ने भी अपने-अपने वर्ग में सोने का तमगा हासिल किया।

चीन के पुतियान में चल रही इस चैंपियनशिप में 17 साल की मनु ने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में रिकॉर्ड 244.7 का स्कोर कर बड़ी जीत दर्ज की। कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन मनु ने 244.7 स्कोर के साथ 10 मीटर स्पर्धा का महिला जूनियर विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन की रेंक्शिन जियान के नाम था।

वहीं, वेलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में 250.8 स्कोर के साथ सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं, दिव्यांश पंवार ने पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल में 250.1 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इन तीनों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ही भारत तीन स्वर्ण के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके अलावा महिला वर्ग के 10 मीटर इवेंट में सर्बिया की अरुनोविच ने 241.9 अंक के साथ रजत और चीन की कियान वांग ने 221.8 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं भारत की ही यशस्विनी सिंह देसवाल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वह फाइनल में छठे स्थान पर रहीं। इसके अलावा पुरुष वर्ग के 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अभिषेक वर्मा और सौरभ चौधरी ने फाइनल के लिए अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। अभिषेक 588 अंक के साथ शीर्ष पर रहे, जबकि सौरभ को 581 अंक के साथ सातवें स्थान से संतोष करना पड़ा।

उपराज्यपाल से मिले डीडीसीए प्रमुख रजत शर्मा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

▶ डीडीसीए में हाल में हुए घटनाक्रम की जानकारी दी

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रजत शर्मा ने गुरुवार को सरकार द्वारा नामित निदेशकों के साथ मिलकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की और उन्हें हाल में संघ में हुए घटनाक्रम की जानकारी दी।

शर्मा ने डीडीसीए के निदेशकों के साथ मिलकर बैजल को डीडीसीए की ओर से 10 लाख रुपये का चेक सौंपा, जो दिल्ली पुलिस के शहीद कोष में जमा कराया जाएगा। शर्मा ने शनिवार को खींचतान और दबाव के कारण अपने पद पर बने रहने से इन्कार करते हुए इस्तीफा दे दिया था। डीडीसीए के लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बदर दुरेज अहमद ने रविवार को हालांकि उन्हें दोबारा अपने पद पर बरकरार कर दिया। उन्होंने इसके अलावा इस मुकाबले की औपचारिक सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की। शीर्ष परिषद को हालांकि यह फैसला पसंद नहीं आया और उसके 16 में से नौ सदस्यों ने मंगलवार को लोकपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने इस मामले को सुना जिसमें वे हालात भी शामिल रहे जिनके कारण शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा लोकपाल के आदेशों के खुले विरोध और उनके अधिकारों पर कुछ सदस्यों के सवाल उठाने की जानकारी भी दी गई। डीडीसीए के सरकार द्वारा नामित निदेशकों राजन तिवारी और आरपी सिंह ने भी बैजल को शीर्ष परिषद के कुछ सदस्यों के आचरण और गतिविधियों की जानकारी दी और उन्हें बताया कि आखिर क्यों उन्होंने लोकपाल को पत्र लिखकर शर्मा का इस्तीफा वापस लेने को कहा।

विविध

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ को चुनौती देगी पंजाब सरकार

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

▶ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की जांच का मामला

▶ प्रदेश सरकार व सीबीआइ में टकराव के कारण इंसाफ में होगी और देरी

▶ सीबीआइ से केस वापस लेने का विधानसभा में पारित हो चुका है प्रस्ताव

बरगाड़ी (फरीदकोट) में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में इंसाफ मिलना अभी कोसों दूर है। सीबीआइ ने मोहाली की विशेष अदालत में बुधवार को कहा था कि वह पंजाब सरकार द्वारा उससे केस वापस लेने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ के खिलाफ डटने का फैसला कर लिया है।

राज्य सरकार के गृह विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने दैनिक जागरण को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ की याचिका का पूरा जवाब दिया जाएगा। पिछले तीन सालों से सीबीआइ ने इस केस की जांच में कोई प्रगति नहीं की है। केस वहीं लटका हुआ है। हमने यही दलील पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी दी थी। कोर्ट ने भी हमारी दलील से सहमति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि प्रदेश सरकार सीबीआइ से केस वापस लेकर खुद एसआइटी गठित कर इसकी जांच करवाती है तो उसे कोई ऐतराज नहीं है। राज्य सरकार ने केंद्र के कार्मिक विभाग को सीबीआइ से केस वापस लेने संबंधी पत्र भी लिख दिया था। अब बुधवार को सीबीआइ ने अदालत में कहा है कि जब तक वह इस केस में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे देती, तब तक केस की सुनवाई स्थगित की जाए। पंजाब सरकार सीबीआइ के इस फैसले से सहमत नहीं है। प्रदेश सरकार के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि जब हम कानूनी तौर पर मजबूत हैं तो फिर पीछे क्यों हटें? जिस केस का हवाला देते हुए सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, उससे बरगाड़ी बेअदबी कांड का कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में सीबीआइ किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट जा रही है यह समझ से परे है। अगर सीबीआइ ऐसा करती है तो यह विधानसभा में पारित उस प्रस्ताव का भी अपमान होगा जिसमें सीबीआइ से केस वापस लेकर एसआइटी से जांच करवाने की बात की गई थी। ऐसे में सीबीआइ को मानहानि केस का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा सीबीआइ से केस वापस लेने का फैसला 25 जनवरी को सुनाया था जिसे आज दस महीने हो चुके हैं। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने का समय भी खत्म हो चुका है। किसी भी फैसले के खिलाफ अपील तीन माह के अंदर ही दायर की जा सकती है।

लंदन के टॉवर ब्रिज पर जुटीं सुंदरियां

मिस इंडिया 2019 सुमन रतन सिंह राव। एएफपी

ये 69वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले रही सुंदरियां हैं। गुरुवार को लंदन में 120 देशों से जुटी इन सुंदरियों ने टॉवर ब्रिज के पास फोटो शूट कराया। इस सालाना प्रतियोगिता का फाइनल 14 दिसंबर को होना है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व मिस इंडिया 2019 सुमन रतन सिंह राव कर रही हैं। सुमन राजस्थान की रहने वाली हैं। वहीं मिस इंग्लैंड के रूप में भारतीय मूल की भाषा मुखर्जी भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। एएफपी

मिस इंग्लैंड भाषा मुखर्जी। रायटर

कांग्रेस सरपंच ने विधायक का मोबाइल नंबर किया ब्लॉक

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन

▶ नशा तस्करों पर कार्रवाई न होने पर उठाया कदम

▶ विधायक ने फेसबुक पर पोस्ट डाल सरपंच को नंबर अनब्लॉक करने को कहा

नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई न होने से गुस्साए गांव सरहाली कलां के सरपंच ने हलका पट्टी के विधायक हरमिंदर सिंह गिल का मोबाइल नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उधर, विधायक ने सरपंच से संपर्क कायम रखने के लिए फेसबुक पर पोस्ट डालकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का वास्ता दिया है। साथ ही कहा है कि यदि वह उन्हें अनब्लॉक नहीं करना चाहते तो कोई और नंबर दे दें ताकि बातचीत तो होती रहे।

गांव सरहाली कलां की आबादी सात हजार के करीब है। तीन वर्ष में कोई ग्रांट नहीं मिली। साथ ही नशा तस्करों पर कार्रवाई करने की मांग भी अनसुनी कर दी गई। सरपंच अमोलकजीत सिंह ने छह माह पहले विधायक गिल से नाराजगी जाहिर करते हुए उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। गिल ने गांव का कामकाज प्रभावित होता देख सरपंच से कई बार संपर्क करना चाहा, परंतु नंबर नहीं लगा। अब विधायक ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर सरपंच को नंबर अनब्लॉक करने को कहा है। उन्होंने इसका कारण गलतफहमी को बताया और कहा कि इसे जल्द दूर कर लिया जाएगा।

विधायक ने पोस्ट में यह लिखा : 'लोग कहते हैं कि 2022 के चुनावों में आप मेरी मदद करने वाले हैं। 2017 के चुनाव में आपके परिवार ने पूरी मेहनत करके मुझे विजयी बनाने में भूमिका निभाई थी। मैं आपके परिवार का सदा ऋणी रहूंगा। मैं औरों की तरह घटिया राजनीति नहीं करता। बच्चों की तरह मत रूठो। गांव में होने वाले विकास कार्यों की लिस्ट बनाओ। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर आपने मेरा मोबाइल नंबर ब्लॉक लिस्ट से नहीं निकाला तो किसी और का मोबाइल नंबर दे दो। मैं उस पर आपसे बात कर लिया करूंगा। मुझे आपके पॉजीटिव जवाब का इंतजार रहेगा। परमात्मा आपको सदा चढ़ती कला में रखें।'

दुखी होकर ब्लॉक किया विधायक का मोबाइल नंबर : सरपंच

सरपंच अमोलकजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने चार बार गांव में नशा बेचने वालों की सूची विधायक हरमिंदर सिंह गिल को सौंपी, परंतु उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के विकास लिए विधायक द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही। गांव के वह सरपंच हैं। जवाबदेह हैं। उन्होंने दुखी होकर विधायक हरमिंदर सिंह गिल का मोबाइल नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला है।

विधायक गिल बोले, जल्द ही खत्म होगी गलतफहमी

विस हलका पट्टी के विधायक हरमिंदर सिंह गिल कहते हैं कि सरपंच अमोलकजीत सिंह उनके भाई सम्मान हैं। उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, जो मिल बैठकर जल्द दूर कर ली जाएगी।

एसएसआइ सहित छह पुलिस कर्मी निलंबित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हत्यारोपित के होटल में मौजूद होने का यूपी पुलिस ने किया था पर्दाफाश

▶ आरोपितों को कानपुर और लखनऊ में पेशी के लिए लेकर गई थी पुलिस टीम

लखनऊ के एक होटल में सीरियल किलर सोहराब की खिदमत में लगे दिल्ली पुलिस के छह कर्मियों को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस ने बुधवार रात होटल में छापा मारकर घटना का पर्दाफाश किया था। स्थानीय पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक एसएसआइ व एक हेड कांस्टेबल सहित चार कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। उन पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप है। उधर दिल्ली पुलिस ने आरोपित सोहराब को लाने के लिए तीसरी बटालियन की अन्य टीम को लखनऊ भेजा है।

दरअसल सोहराब, रुस्तम और सलीम नाम के तीन भाई सीरियल किलर के तौर पर कुख्यात हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश व दिल्ली में हत्या सहित कई जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल सोहराब दिल्ली के मंडावली, रुस्तम तिहाड़ और तीसरा भाई सलीम फतेहगढ़ जेल में बंद है। उन पर दिल्ली में गौरव गंभीर की हत्या का आरोप है।

बुधवार को दिल्ली पुलिस की तीसरी बटालियन के पुलिसकर्मियों की टीम सोहराब और रुस्तम को पेशी पर कानपुर लेकर गई थी। गुरुवार को दोनों की लखनऊ में पेशी थी। यूपी पुलिस को सूचना मिली कि सोहराब एक होटल में ठहरा हुआ है। वहां सोहराब की पत्नी, बहन और उनके बच्चे भी मौजूद हैं। बिरयानी खिलाई जा रही है और सभी मौज-मस्ती कर रहे हैं। सूचना के आधार पर यूपी पुलिस ने छापामारी कर आरोपित की पत्नी और बहन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, दिल्ली पुलिस के एएसआइ रामकृष्ण, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार सहित कांस्टेबल अनिल कुमार, दीपक वीरेंद्र और सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल के तीन कमरे बिना पहचान पत्र के स्थानीय निवासी सोनू रावत ने बुक कराए थे। लापरवाही के मामले में यूपी पुलिस ने होटल के मैनेजर अंकित मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया।

उधर, स्थानीय पुलिस ने जब पेशी के लिए सोहराब के साथ गए रुस्तम का पता लगाया तो उस वक्त उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके साथ मौजूद दिल्ली पुलिस कर्मियों के फोन नंबर भी बंद आ रहे थे। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी व एसीपी अनिल मित्तल ने बताया कि दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर इसकी विभागीय जांच कराई जा रही है।

सौ नंबर की कॉल रिकॉर्ड के आधार अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

▶ पत्नी की हत्या कर पुलिस कंट्रोल (100) को दी थी सूचना

जिला अदालत ने महिला की हत्या मामले में आरोपित पति को उम्र कैद की सजा सुना दी। दस हजार का जुर्माना भी दोषी को देना होगा, नहीं देने पर छह माह की सजा अतिरिक्त काटनी होगी। इस मामले में गवाह मुकर गए थे मगर एडिशनल डिस्ट्रिक एवं सेशन जज प्रशांत राणा की अदालत ने आरोपित द्वारा पत्नी की हत्या कर पुलिस कंट्रोल (100) को दी थी गई जानकारी की रिकार्डिंग को आधार बना सजा सुना दी।

मुमताजपुर निवासी हरिओम (32) ने 13 अप्रैल 2018 को घरेलू झगड़े के दौरान अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद हरिओम ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर बताया था कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची और हरिओम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के सामने हरिओम के दोनों बच्चों ने भी कहा था कि मां की हत्या उनके पिता ने की है। इसके अलावा भी पुलिस ने कई सबूत जुटाए थे। अदालत के सामने हरिओम ने पत्नी की हत्या करने से मना कर दिया था। वहीं इस मामले में सभी गवाह भी पुलिस को दिए बयान से मुकर गए। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने वह ऑडियो टेप पेश किया जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर वह बता रहा कि पत्नी का काम तमाम कर दिया है। दरअसल पुलिस कंट्रोल में कॉल करने वाले की बातचीत ऑटोमेटिक रिकार्ड हो जाती है। उसी को आधार बना अदालत ने कठोर सजा सुना दी।

मौसम विशेष

पंजाब और उत्तरी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा संभव है। शेष भागों तथा दिल्ली में मौसम आंशिक बादलों के साथ आरामदायक बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा तथा बर्फबारी हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी हिमपात की संभावना है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/23/आंबा	अहमदाबाद	33/22/आंबा
कोलकाता	30/17/आंबा	बड़ौदा	33/20/आंबा
चेन्नई	28/22/आंबा	नागपुर	31/15/आंबा
हैदराबाद	30/21/आंबा	इन्दौर	30/19/आंबा
बंगलूरू	29/19/आंबा	रांची	30/20/ए
त्रिवेन्द्रम	33/22/आंबा	पटना	31/19/आंबा
गुवाहाटी	26/19/रसा	जमशेदपुर	30/19/आंबा
जंगटोक	12/03/आंबा	पुणे	29/18/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 22 नवंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की हत्या

1963 में आज ही अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के डलास शहर में केनेडी अपने काफिले में थे और इस दौरान उन्हें एक इमारत से दो गोली मारी गईं। उनकी हत्या के आरोप में ली हार्वे ओसवल्ड को गिरफ्तार किया गया था।

मशहूर एनीमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी रिलीज हुई

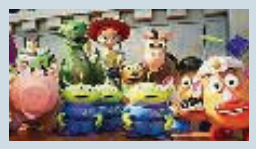

1995 आज ही जानी-मानी कंप्यूटर एनीमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी रिलीज हुई थी। यह पहली ऐसी फीचर फिल्म थी, जिसमें एनीमेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म को पिक्सर एनीमेशन स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था।

महान टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर को जन्मदिन मुबारक हो

दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में गिने जाने वाले बोरिस बेकर का जन्म 1967 में आज ही जर्मनी में हुआ था। बोरिस सिर्फ 17 साल की उम्र में विंबलडन में मेन्स सिंगल्स चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के टेनिस खिलाड़ी बने। बोरिस बेकर ने अपने करियर में 49 सिंगल्स और 15 डबल्स चैंपियनशिप जीतीं। बोरिस टेनिस खेलते समय बहुत ही तेजी से सर्विस किया करते थे, जिसके कारण उनके फैंस ने उनका निकनेम बूम-बूम रख दिया था। उन्होंने साल 1992 में माइकल स्टिश के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। 25 जून, 1999 वह रिटायर हो गए।

गधों के अस्तित्व पर लटकी चीन की तलवार

28% 2007 से ब्राजील में गधों की संख्या में कमी

37% बोत्सवाना में गधों की संख्या में गिरावट

53% किर्गिस्तान में इस जानवर की संख्या में आई कमी

76% 1992 से चीन के घरेलू गधों की संख्या में आई गिरावट

तेजी से घट रही संख्या

गधों के चमड़े के व्यापार और चीनी परंपरागत दवाओं में इस्तेमाल के चलते दुनिया भर में इनकी संख्या तेजी से गिर रही है। केन्या और घाना में भी इनकी संख्या में गिरावट की आशंका है।

दुनिया में गधों की कुल संख्या 4.4 करोड़ है। अगले पांच साल में इनकी यह संख्या आधी रह सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाली चैरिटी संस्था डंकी सेंक्चुअरी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गधों के अंगों-प्रत्यंगों से बनने वाली चीनी परंपरागत दवाओं के लिए हर साल 48 लाख गधों की जरूरत है। चीन के इस परंपरागत उद्योग को इजियाओ कहते हैं। इस उद्योग की जरूरत के लिए हर साल चीन में लाखों की संख्या में गधों को मार दिया जाता है। पिछले तीन दशक के दौरान चीन में इस जीव की संख्या तीन चौथाई कम हो चुकी है। अब चीन दुनिया के तमाम गधा बहुतायत देशों से इनका आयात कर रहा है।

भयावह स्थिति

रिपोर्ट बताती है कि यह जानवर अलग-अलग देशों में अलग-अलग समुदायों की आजीविका का साधन हुआ करता था। पूरा परिवार इस जानवर की कमाई पर आश्रित रहता था। अब इस समुदायों से इसे औने-पौने दामों में खरीदकर लंबी यात्रा पर भेज दिया जाता है। तस्करी जैसा यह काम संगठित गिरोह द्वारा किया जाता है। इस यात्रा में गधों को भोजन और पानी भी नहीं दिया जाता। लिहाजा 20 फीसद गधे तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। जब लंबी यात्रा के बाद इन्हें वाहन से उतारा जाता है तो ज्यादातर के पैर टूटे होते हैं। खुर चोटिल हुए रहते हैं। कान और पूंछ पकड़कर उन्हें उतारने के लिए धक्का दिया जाता है।

दर्दनाक हकीकत

रिपोर्ट बताती है कि चीन की परंपरागत दवाओं में इन जानवरों के अंगों की इतनी मांग है कि गर्भवती गधी, गधे के बच्चों और बीमार और चोटिल गधों को भी नहीं बक्शा जा रहा है। इन्हें भी मार दिया जा रहा है।

चीन में परंपरागत औषधियों के लिए सुखाई जाती गधों की खालें ● ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल

बहुत उपयोगी है गधा

जिस गधे को दुनिया अनुपयोगी मानती रही है, चीन उससे भी अमानवीय तरीके से अपनी दुकान चमका ले रहा है। इसकी खाल से जिलेटिन बनाया जाता है। जिसका इस्तेमाल वहां की परंपरागत औषधियों में हजारों साल से किया जा रहा है। माना जाता है कि इसके सेवन से रक्त परिसंचरण सुधरता है और एनीमिया (खून की कमी) से मुक्ति मिलती है।

गधा मालिकों की मुसीबत

दुनिया के अतिपिछड़े करीब 50 करोड़ लोगों की आजीविका गधे से चलती है। खाल उद्योग के लिए इनकी बढ़ती मांग ने इनकी कीमतें आसमान पर पहुंचा दी है। नए गधे को खरीदने में इनके पसीने छूट रहे हैं। 2016-19 के बीच केन्या में इनकी कीमतों में 15 हजार रुपये का इजाफा हो चुका है।

संख्या बढ़ाने की चुनौती

डंकी सेंक्चुअरी के अनुसार गधों की संख्या बढ़ाने की बहुत जरूरत है, लेकिन इजियाओ उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए इसमें 20 साल लगेंगे। गधों का प्रजनन चक्र बहुत धीमा है। इस जानवर की मादा बच्चे को एक साल तक गर्भ में रखती है। इनमें धीरे-धीरे परिक्वता आती है। इनकी प्रजनन दर भी बहुत कम है। इन वजहों से इनकी संख्या बढ़ाने को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं।

देशों ने दिखाई सख्ती

गधों की गिरती संख्या से चिंतित दुनिया के 18 देशों ने इनके मारने पर पाबंदी लगा दी। घाना और माली जैसे देश ने तो इनके बूचड़खाने तक बंद करा दिए लेकिन दूसरे देशों को निर्यात के द्वारा इनका मारा जाना बदस्तूर जारी है।

इधर-उधर की

37 हजार फीट की ऊंचाई पर की शादी

केनबरा,एजेंसी : न्यूजीलैंड की कैथी और ऑस्ट्रेलिया के डेविड ने सिडनी से ऑकलैंड जाने वाली 37 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रही कमर्शियल जेटस्टार फ्लाइट 201 में शादी की। विमान में मौजूद सभी मुसाफिर इस अनोखी शादी के गवाह बने। एयरलाइन ने इस शादी के लिए दंपती कोई शुल्क नहीं लिया, बल्कि उनकी इच्छा के मुताबिक पूरा सहयोग दिया। सिडनी से उड़ान भरते ही दूल्हा-दुल्हन ने हवा में अपने प्यार का इजहार किया और साथ जीने-मरने की रस्में निभाईं। फ्लाइट जैसे ही आधे रास्ते पर पहुंची शादी की रस्म अदा की गई। इस शादी की जानकारी फ्लाइट में सफर कर रहे सभी यात्रियों को यात्रा के पहले ई-मेल के जरिए दे दी गई थी। उन्हें यह ऑफर भी किया गया था कि यदि वह अपनी फ्लाइट बदलना चाहें तो बदल लें।

शोध अनुसंधान

फली वाले अनाज के सेवन से दिल को फायदा

फली वाले अनाज जैसे विभिन्न दालें एवं सोयाबीन के सेवन से दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर की आशंका कम होती है। हालिया शोध में यह बात सामने आई है। विज्ञान पत्रिका एडवांसेज इन न्यूट्रिशन में इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। इस संबंध में हुए विभिन्न अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया कि फली वाले अनाज के सेवन से दिल की बीमारियों एवं हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 10 फीसद तक कम हो जाता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि दिल की बीमारियां दुनियाभर में असमय मौत की बड़ी वजह हैं। ऐसे में खानपान में हल्के बदलाव से इनसे बचना संभव हो सकता है। फली वाले अनाज में फाइबर, प्लांट प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा के कारण दिल को फायदा होता है। कम वसा होने और कोलेस्ट्रॉल नहीं होने के कारण भी इन्हें बेहतर पाया गया है। -एएनआइ

अंतरिक्ष में दिखी अब तक की सबसे चमकीली गामा किरण

अद्भुत ▶ सामान्य प्रकाश से एक लाख करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जावान

वाशिंगटन, प्रेट्र : रहस्यों से भरपूर ब्रह्मांड में शोधकर्ताओं को पहली बार अब तक की सबसे शक्तिशाली और चमकीली गामा किरणें देखने को मिली हैं। इसमें सामान्य प्रकाश की तुलना में एक लाख करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा बताई जा रही है। अंतरिक्ष में मुक्त होने वाले इस तरह की चमकीले ऊर्जा को गामा-रे बर्स्ट (जीआरबी) और इन घटनाओं को विद्युतचुंबकीय कहा जाता है।

जर्नल नेचर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, पूर्व में किए गए सैद्धांतिक अध्ययनों में इस तरह की बेहद उच्च ऊर्जा के उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया था। यह माना गया था कि इतनी शक्तिशाली ऊर्जा की उत्पत्ति तारों की टक्कर या ठंडे होते दो तारों के विलय से होती है। इस घटना को हालांकि, इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस साल 14 जनवरी को एक शक्तिशाली विस्फोट की पहचान की थी और इसे जीआरबी 190114सी नाम दिया था। इसके बाद किए गए एक सहयोगात्मक प्रयास में एक स्रोत से विकिरण आते देखा गया। इसके लिए दुनियाभर में 20 से ज्यादा ऑब्जरवेटरी और उपकरणों का प्रयोग किया गया। शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने जीआरबी 190114सी के बारे में जानकारी एकत्र की और गामा-रे बर्स्ट की उत्पत्ति का पता लगाया। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस तरह के खास विस्फोट की उत्पत्ति किसी चमकीली आकाशगंगा के केंद्र में बेहद घने वातारण से होती है। यह केंद्र इतना दूर है, जहां पहुंचने में पांच अरब वर्ष लगेंगे। शोधकर्ताओं ने बताया कि जीआरबी महज कुछ सेकेंड के लिए दिखाई दिया और इसकी उत्पत्ति महा शक्तिशाली विस्फोटों से हुई।

कार्टोसैट-3 और 13 नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण अब 27 को

बेंगलुरु, प्रेट्र : कार्टोसैट-3 व अमेरिका के 13 वाणिज्यिक नैनो उपग्रहों का प्रेक्षण अब 27 नवंबर को किया जाएगा। पहले इनका प्रक्षेपण 25 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:28 बजे किया जाना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उपग्रहों के प्रक्षेपण तिथि में बदलाव की जानकारी गुरुवार को दी। इसरो ने नवीनतम बयान में कहा, '25 नवंबर 2019 को सुबह 9:28 बजे कार्टोसैट-3 को लेकर जाने वाले पीएसएलवी-सी47 का प्रक्षेपण अब 27 नवंबर को सुबह 9:28 बजे किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसएचएआर के दूसरे लांच पैड से किया जाएगा।' उपग्रहों को भारत के पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी)-सी47 द्वारा प्रक्षेपित करके सूर्य समकालिक कक्षा (एसएसओ) में स्थापित किया जाएगा।

अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि कार्टोसैट-3 तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है, जिसमें हाई रिजॉल्यूशन इमेजिंग क्षमता है। उसने कहा कि उपग्रह को 509 किलोमीटर की कक्षा में 97.5 डिग्री के झुकाव पर स्थापित किया जाएगा। कार्टोसैट का कुल वजन 1,625 किलोग्राम और मिशन की अवधि पांच वर्ष है। यह व्यापक तौर पर शहरी योजना, ग्रामीण संसाधन और आधारभूत ढांचे का विकास, तटीय भूमि उपयोग आदि की बढ़ती मांगों को पूरा करेगा। अमेरिका के 13 वाणिज्यिक नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण अंतरिक्ष विभाग के न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत हो रहा है। इसरो ने कहा है कि यह एसडीएससी एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से 74वां प्रक्षेपण यान मिशन होगा।

फिल्म रिव्यू

फ्रोजन 2

हिंदी डबिंग : प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, देवेन भोजानी, मनीष पॉल
निर्देशक : क्रिस बक और जेनिफर ली
अवधि : 1 घंटे 43 मिनट

जादू की दुनिया, इमोशन कम

वर्ष 2013 में आई एनिमेटेड फिल्म 'फ्रोजन' की कहानी दो बहनों एल्सा और आना की थी। बड़ी बहन एल्सा एरनडेल की रानी है, जिसे बर्फीली शक्तियां प्राप्त हैं। उसका हाथ यदि किसी को छू जाए तो वह बर्फ बन जाता है। वह बर्फ की दुनिया रच सकती है। उनके साथ आना का ब्वॉयफ्रेंड क्रिस्टॉफ, हिरन स्वेन और बर्फ से बना ओलाफ जुड़ते हैं। छह साल बाद आई सीक्वल 'फ्रोजन 2' में इन किरदारों के साथ कुछ नए किरदार जुड़ते हैं और कहानी नए पड़ाव की ओर बढ़ती है। हालांकि यहां लेखक व निर्देशक कन्फ्यूज दिखते हैं। यहां भी कहानी का आगाज एल्सा और आना के बचपन के फ्लैशबैक से होता है। उनके पिता उन्हें बताते हैं कि उन्होंने मायावी जंगल देखा है। वह बताते हैं कि जंगल में एक कबीला रहता था। कबीले के लोगों ने उनके दादाजी महाराज रोनाल्ड से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। दादा ने अमन के तोहफे के तौर पर बांध बनाया। जंगल में जश्न के दौरान कबीले और रोनाल्ड की सेना के बीच मार-काट मच जाती है। जंगल पर कोहरे की चादर बिछ जाती है। एल्सा को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। युवा एल्सा उस आवाज की खोज में जाने का फैसला करती है...। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्मों की खास शैली होती है। उनकी दुनिया, परिवेश और वीएफएक्स का प्रयोग कुछ नया पेश करते हैं। यहां पर एल्सा के जादू के साथ उनकी कल्पना दूर तक उड़ान भरती दिखती है। फिल्म में एल्सा का समुद्र की लहरों पर बर्फ के घोड़े की सवारी करने के दृश्य मनोरम हैं। वे लाइव एक्शन फिल्मों की तरह लगते हैं। जीव-जंतुओं की भाव-भंगिमाएं आपके चेहरों पर मुस्कान ले आती हैं। इस सीरीज की बड़ी खूबी महिला पात्रों एल्सा और आना का सशक्त होना है। इस बार भी निर्देशन क्रिस बक और जेनिफर ली ने किया है। परीकथा सरीखी कहानी में एडवेंचर और इमोशन की कमी अखरती है। रहस्यमयी आवाज को ढूढ़ने के एल्सा के सफर में रोमांच नहीं है। कहानी में पर्यावरण व ऐतिहासिक गलतियों जैसे विषयों को शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें प्रभावशाली तरीके से व्यक्त नहीं किया गया। सीक्वल में किरदारों को ज्यादा विकसित दिखाने की कोशिश होती है, यहां पर लेखक पिछड़े हुए दिखते हैं। वह क्रिस्टॉफ के किरदार को विस्तार नहीं दे पाए हैं। फिल्म में गानों की अधिकता है। हिंदी में सुनिधि चौहान की आवाज में गाए गाने कहानी को बयां करते हैं। हिंदी में एल्सा की डबिंग प्रियंका चोपड़ा जोनास, जबकि आना की उनकी चचेरी बहन परिणीति चोपड़ा ने की है। बहनों की आवाज उनके किरदारों पर जंची है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

हिटलर का हैट 40 लाख में नीलाम

जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का हैट 55, 310 डॉलर (करीब 40 लाख रुपये) में नीलाम हो गया। ग्रासबर्न में नाजी शासनकाल की अन्य वस्तुओं की भी नीलामी की गई। हालांकि, यूरोपीय यहूदी संघ ने हिटलर से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी की निंदा की है। संघ ने कहा कि रक्त से सने हैट की नीलामी से पैसा जुटाना गलत है। जर्मनी में नाजी प्रतीकों के प्रदर्शन की मनाही है। ऐसे में हिटलर से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी को लेकर यहां विवाद छिड़ गया है। जर्मनी के नाजी शासन काल में सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साइकिल की भी नीलामी की गई। एएफपी

स्क्रीन शॉट

'फोर्स 3' के निर्माण के अधिकार अब जॉन अब्राहम के पास...

मौलिक कहानियों को ढूंढ़ने पर वक्त और मेहनत करने की बजाय पहले से ही हिट हो चुकी फिल्मों की फ्रेंचाइजी पर फिल्में बनाने का ट्रेंड इन दिनों जोरों पर है। इस साल 'हाउसफुल 4' के बाद 'दबंग 3', 'कमांडो 3' जैसी फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। ऐसी ही एक फ्रेंचाइजी है फिल्म 'फोर्स' की। वर्ष 2011 में रिलीज हुई 'फोर्स' और 2016 में आई 'फोर्स 2' दोनों में जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे। इन दोनों फिल्मों का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया था। अब इस फिल्म की फ्रेंचाइजी जॉन अब्राहम ने खरीद ली है। यानी अब 'फोर्स 3' का निर्माण जॉन करेंगे। विपुल शाह का कहना है कि 'फोर्स' से वह अब नहीं जुड़ेंगे। इस फ्रेंचाइजी को अब जॉन अब्राहम आगे लेकर जाएंगे। 'फोर्स 3' के सारे अधिकार उन्होंने जॉन को दे दिए हैं। विपुल ने जॉन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि जॉन जल्द ही एक बेहतरीन 'फोर्स 3' फिल्म बनाएं। 'फोर्स' और 'फोर्स 2' में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। ऐसे में 'फोर्स 3' को लेकर उम्मीदें ज्यादा हैं। जॉन लगातार एक्शन फिल्मों से ही जुड़ रहे हैं। इस वर्ष उनकी 'रोमियो अकबर वॉल्टर' व 'बाटला हाउस' रिलीज हुई हैं। 'पागलपंती' में वह कॉमेडी करते दिखेंगे। अगले साल वह 'मुंबई सागा' और 'सत्यमेव जयते 2' में नजर आएंगे।

बड़की को याद आया धारावाहिक 'हम लोग'...

भारतीय टेलीविजन के सबसे चर्चित शो 'हम लोग' का जिक्र आज भी लोगों की जुबान पर है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला यह शो वर्ष 1984 में शुरू हुआ था। 154 एपीसोड वाले इस धारावाहिक में सूत्रधार की भूमिका अशोक कुमार ने निभाई थी। इस साल दिसंबर में इस शो को 35 साल पूरे हो जाएंगे। शो की बड़की यानी अभिनेत्री सीमा पाहवा ने उस धारावाहिक के कलाकारों की एक ब्लैक ऐंड व्हाइट तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसका उन्होंने कैप्शन दिया है, 'क्या आप बड़की को पहचान सकते हैं?' शो में तीन बहनों में सबसे बड़ी गुणवंती यानी बड़की का किरदार सीमा ने निभाया था। उन्होंने इस पोस्ट के साथ हैशटैग वर्ल्ड टेलीविजन डे भी टाइप किया। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नंवबर को था।

डाकू ददुआ पर फिल्म बनाएंगे तिग्मांशु धूलिया...

फिल्ममेकर तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बनने वाली अगली फिल्म डाकू शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ की जिंदगी पर आधारित होगी। करीब 35 वर्षों तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर ददुआ का आतंक था। तिग्मांशु के मुताबिक, उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर ली है, अब वह एक्टरों की तलाश में हैं। यह फिल्म पुलिस और डाकू के बीच की रस्साकशी पर आधारित होगी। बांदा-चित्रकूट क्षेत्र के कुख्यात डाकू ददुआ का खौफ 35 वर्षों तक कायम रहा था। वह वीरप्पन से भी बड़ा डाकू था। यह फिल्म बताएगी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने ददुआ के आतंक का खात्मा कैसे किया। साल 2007 में ददुआ को स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ में मार गिराया था। कुछ लोग ददुआ को रॉबिनहुड और क्रांतिकारी भी कहते थे। तिग्मांशु धूलिया इससे पहले 'साहब बीवी और गैंगेस्टर' सीरीज, 'बुलेट राजा' और 'पान सिंह तोमर' जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके हैं। ब्रिटिश सीरीज 'डॉक्टर फॉस्टर' पर आधारित वेब सीरीज 'आउट ऑफ लव' के पहले दो एपिसोड का निर्देशन तिग्मांशु ने किया है। उसमें रसिका दुग्गल और पूरब कोहली अहम भूमिका में हैं।

चिंताजनक

उभरचर, जलचर, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी आदि सभी किसी न किसी रूप से ध्वनि प्रदूषण से हो रहे प्रभावित, जानवरों का एक दूसरे से संकेतों के आदान-प्रदान करने में हो रही मुश्किल

100 से अधिक प्रजातियों के लिए खतरा है ध्वनि प्रदूषण

लंदन, प्रेट्र : मानव निर्मित ध्वनि प्रदूषण से विभिन्न जानवरों की 100 से अधिक प्रजातियों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें उभयचर, पक्षी, जलचर, स्तनधारी और सरीसृप सभी शामिल हैं। हाल ही में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में कहा गया है कि मानव निर्मित शोर को 'वैश्विक प्रदूषक' माना जाना चाहिए। यह अध्ययन बायोलॉजी लेटर्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि शोर प्रदूषण का एक खतरनाक रूप है। अध्ययन में पाया गया कि ध्वनि प्रदूषण केवल मनुष्यों पर ही प्रभाव नहीं डालता, यह सभी तरह के जानवरों को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बना रहा है।

ब्रिटेन की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के शोधकर्ताओं ने शोर के प्रभावों का 100 से अधिक प्रजातियों पर अध्ययन किया और इन जानवरों को सात समूहों- उभयचर, पक्षी, जलचर, स्तनधारी, सरीसृप, मोलस्क (घोंघे व सीप आदि), सन्धिपाद (सितारा मछली, सूत्रकृमि आदि) में विभाजित किया। क्वीन्स यूनिवर्सिटी के हंसजार्ग कुंक ने कहा कि अध्ययन से स्पष्ट प्रमाण मिला कि ध्वनि प्रदूषण प्रजातियों के सभी सातों समूहों को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण को हर हाल में वैश्विक प्रदूषक माना जाना चाहिए और जानवरों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए रणनीति विकसित करनी चाहिए।

शोधकर्ताओं ने कहा, ध्वनि प्रदूषण को 'वैश्विक प्रदूषक' माना जाना चाहिए। प्रतीकात्मक

इस तरह प्रभावित होती हैं प्रजातियां : शोधकर्ताओं ने बताया कि उभयचर, पक्षी, कीट और स्तनधारियों की कई प्रजातियां एक दूसरे से संपर्क के लिए ध्वनिक संकेतों का उत्पादन करती हैं। इन संकेतों से वे आपस में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं। जैसे- संभावित खतरे के प्रति आगाह करना, परिवार बढ़ाने के लिए नर या मादा का चुनाव करना इत्यादि।

अगर ध्वनि प्रदूषण उनके संकेतों पर प्रभाव डालेगा तो इससे उनके अस्तित्व पर खतरा पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण की वजह से कुछ जानवर शिकार नहीं कर पाते तो कुछ अपने शिकार से बच नहीं पाते। चमगादड़ और उल्लू जैसे पक्षी अपना अधिकतर काम आवाज के भरोषे ही करते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण से इन प्रजातियों में गिरावट आ सकती है। वहीं, जलीय जीवन में मछली का लार्वा अपना घर शैल-भित्तियों के द्वारा उत्सर्जित ध्वनि के आधार पर ही पाते हैं। जहाजों की वजह से समुद्र में ध्वनि प्रदूषण होने से मछली के लार्वा को अपना घर ढूंढना मुश्किल हो जाता है।